

Fourth Series, No.43

Friday, April 18, 1969  
Chaitra 28, 1891 (Saka)

# LOK SABHA DEBATES

Seventh Session  
(Fourth Lok Sabha)



सत्यमेव जयते

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi

## CONTENTS

<i>No. 43—Friday, April 18, 1969/Chaitra 28, 1891 (Saka)</i>	COLUMNS
Oral Answers to Questions :	
*Starred Questions Nos. 1171 to 1174 and 1177	1—37
• Short Notice Question Nos. 75	37—43
Written Answers to Questions :	
Starred Questions Nos. 1175, 1176 and 1178 to 1200 ...	43—63
Unstarred Questions Nos. 6742 to 50, 6752 to 55, 6757 to 6805, 6805 to 32, 6834 to 6904 and 6908 to 6940 ...	63—230
Papers Laid on the Table	230—232
Public Accounts Committee—	
Forty-sixth and Fifty-first Reports	232
Committee on Public Undertakings :	
Forty-second Report ... ..	232
Statement by Member Under Direction 115 and Minister's reply thereto ... ..	232—235
Shri Hukam Chand Kachwai	232—233
Shri Parimal Ghosh ...	233—234
Demands for Grants ...	235—325
Ministry of Informotion and Broadcasting ... ..	235—325
Shri J. Mohamed Imam ... ..	237—43
Shri Nardeo Snatak ... ..	243—47
Shri Bharat Singh Chauhan ... ..	257—53
Shri Tulshidas Jadhav ... ..	253—59
Shri Ishaq Sambhali ... ..	259—72
Shri Inder J. Malhotra ... ..	273—79
Shri K. Anirudhan ... ..	279—84
Shri I. K. Gujral ... ..	284—97
Shri S. M. Joshi ... ..	303—10
Shri Samar Guha ... ..	311—16
Shri Prem Chand Verma ... ..	316—19
Shri Randhir Singh ... ..	319—21
Shri Achal Singh ... ..	321
Shri Prakash Vir Shastri ... ..	321—23

\*The sign\* marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.



## Bill Introduced

1. Constitution (Amendment) Bill [Amendment of article 39] (Bill No. 33 of 1969) by Shri Om Prakash Tyagi	...	...	...	325
2. Constitution (Amendment) Bill [Amendment of article 39] (Bill No. 32 of 1969) By Shri Om Prakash Tyagi	...	...	...	325
3. Identity Card Bill By Shri Maharaj Singh Bharati	...	...	...	326
4. Salaries and Allowance of Members of Parliament (Amendment) Bill (Amendment of sections 4, 5 etc.) By Shri P.L. Barupal	...	...	...	326—32
Enlargement of the Appellate (Criminal) jurisdiction of the Supreme Court Bill By Shri A. N. Mulla—referred to Select Committee				
	...	...	...	332—67
Motion to Consider	...	...	...	332—67
Shri A. N. Mulla	...	...	...	332—42
Shri N. C. Chatterjee	...	...	...	342—44
Shri Hanumanthaiya	...	...	...	344—47
Shri K. M. Koushik	...	...	...	347—48
Shri Randhir Singh	...	...	...	348—50
Shri Hamayun Kabir	...	...	...	350—52
Shri Rabi Ray	...	...	...	352—53
Shri Tenneti Viswanatham	...	...	...	353—55
Shri Shivajirao S. Deshmukh	...	...	...	355—57
Shri M. N. Reddy	...	...	...	357—58
Shri S. M. Krishna	...	...	...	358—60
Shri Erasmo de Sequeira...	...	...	...	360—61
Shri George Fernandes	...	...	...	361—63
Shri Govinda Menon	...	...	...	363—65
Constitution (Amendment) Bill—(Amendment of articles 75, 164, etc.) By Shri Kameshwar Singh				
	...	...	...	368—76
Motion to consider	...	...	...	368—76
Shri Kameshwar Singh	...	...	...	368—76
Half-An-Hour Discussion :				
Per Capita availability of Power in Bihar...	...	...	...	377—78

LOK SABHA

Friday, April 18, 1969; Chaitra 28, 1891  
(Saka).

*The Lok Sabha met at Eleven of the  
Clock.*

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

SHRI SITA RAM KESRI : On a Point  
of order.....

MR. SPEAKER : No point of order  
during Question Hour. I shall allow you a  
supplementary.

मध्याह्निक चुनावों के सम्बन्ध में दौरे पर गए  
मंत्रियों के साथ सरकारी पदाधिकारी

\*1171. श्री श्रीमप्रकाश त्यागी :

श्री राम स्वरूप बिष्टार्षी :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा  
करेंगे कि :

(क) मध्याह्निक चुनावों के दौरान  
कितने केन्द्रीय मंत्री चुनाव दौरों पर गये थे  
तथा उनमें से प्रत्येक के साथ कितने सरकारी  
अधिकारी गये थे ;

(ख) इन दौरों के लिये कर्मचारियों को  
दैनिक भत्ते तथा यात्रा भत्ते के रूप में  
क्रमशः कितनी-कितनी राशि दी गई थी ;

(ग) क्या सरकार सत्तारूढ़ दल से  
इस राशि को वसूल करने के प्रश्न पर विचार  
करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण  
हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI  
K. S. RAMASWAMY) : (a) and (b). The  
information is being collected and will be  
laid on the Table of the House.

(c) and (d). Even while a Minister is on  
election tour, he continues to be in charge  
of public affairs and has to attend to several  
official matters. He can therefore, take his  
Personal Assistants and peons with him on  
such tours in order to facilitate the dis-  
charge of his official duties. Such staff is  
entitled to draw travelling allowance as  
for journeys on official tour. The ques-  
tion of recovering the amount paid to  
the employees as daily allowance and  
travelling allowance in connection with  
these tours from the party in power does  
not therefore, arise.

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष  
महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जब  
मंत्रीगण ग्राम चुनावों या मध्याह्निक चुनावों  
के अवसर पर शुद्ध रूप से चुनाव के उद्देश्य  
को लेकर ही दौरों पर जाते हैं उस समय  
उनके साथ प्लेन-क्लोड सी० आई० डी०  
और पुलिस के आदमी और पर्सनल स्टाफ  
के आदमी जाते हैं तो उनके भत्ते आदि  
पर जितना खर्चा होता है वह सत्तारूढ़  
पार्टी देती है या गवर्नमेन्ट की ओर से  
दिया जाता है ?

SHRI K. S. RAMASWAMY : Sir,  
even while the Ministers go on tour for

election purposes, they have to discharge their official duties. They are not debarred from this. So, they take their P.As. and Peons with them. So, there is no question of recovering the amount from the Party.

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :** जब यहां से प्रधान मन्त्री जाती हैं तो सैकड़ों सी० आई० डी० (प्लेन-क्लोड) के आदमी जाते हैं, और जहां पर वे जाती हैं उस जिले के ही नहीं बल्कि चारों तरफ की जिलों की सी० आई० डी० और पुलिस के आदमी आते हैं जबकि वे केवल चुनाव के दृष्टिकोण से ही गई हुई होती हैं। मुझे इस बात पर भी एतराज नहीं है, जब प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री जायें तो उनके इन्तजाम के लिए सरकारी आदमी आयें बड़ी खुशी के साथ लेकिन उनपर जो खर्चा होता है, चूंकि गवर्नमेन्ट से उस काम का कोई ताल्लुक नहीं रहता, वह खर्चा सत्तारूढ़ पार्टी क्यों न दे ? इस बात का आप उत्तर दीजिए।

**SHRI SHEO NARAIN :** It is their duty to protect their Prime Minister.

**SHRI K. S. RAMASWAMY :** It is the duty of the State Government to protect the Prime Minister or other VIPs who go on any tour. Officers accompanying them are not expected to take part in the election campaign either directly or indirectly. They have to be impartial. There is no question of recovering any amount from any party.

**SHRI BAL RAJ MADHOK :** I seek your protection...

**MR. SPEAKER :** What I have been able to gather is that there is no question of recovering the expenses from the Party.

**SHRI BAL RAJ MADHOK :** When the Prime Minister goes on election tour, she goes as Congress leader and the Congress has its own protection. We go as Jan Sangh leaders and we have our own protec-

tion. But when officials go in thousands and hundreds, who makes payment for their expenses ? The Prime Minister may take about one thousand people. But who pays their expenses ?

**SHRI K. S. RAMASWAMY :** Government protection is given not only to the Prime Minister, but also VIPs and M.Ps...(Interruptions)

**SHRI N. K. SOMANI :** Which M.P. is given protection ?

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :** अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मध्यावधि चुनाव में प्रधान मन्त्री जी जहां जहाँ दौरे पर गई वहां उनके साथ प्लेन क्लोड सी० आई० डी० का कितना स्टाफ गया और कितना उनका पर्सनल स्टाफ गया और उनकी तनख्वाह, भत्ते और किराये इत्यादि पर कुल कितना एस्टीमेट आपकी दृष्टि से बैठा है, वह बताने की कृपा कीजिए ?

**SHRI K. S. RAMASWAMY :** I cannot say how many people accompanied her on a particular occasion. But due protection was given to her.

**SHRI S. K. TAPURIAH :** We seek your protection now.

**MR. SPEAKER :** No protection from me.

**श्री जार्ज करनेन्डीज :** अध्यक्ष महोदय, आप क्वेश्चन का पार्ट (बी) देखिए उसमें स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया है। मन्त्री महोदय उसका स्पेसिफिक उत्तर दें।

**MR. SPEAKER :** After all, they may not know how many people went with the Prime Minister, how many CID and other staff went. They may not have the information readily.

**SHRI BAL RAJ MADHOK :** But this was the very question tabled.

MR. SPEAKER : Even in answer to that, he has said they are collecting the information and will place it on the Table.

AN HON. MEMBER : How long they will take ?

MR. SPEAKER : Because the Prime Minister went to so many places, naturally they will take time to collect details.

श्री रामस्वरूप बिद्यार्थी : अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन की नोटिस दिसम्बर में दी गई थी—दिसम्बर से लेकर अप्रैल तक चार महीने हो गए हैं—तो सरकार को अभी और कितना समय चाहिए ?

मंत्री महोदय कहते हैं कि एलेक्शन दौरे पर जो मिनिस्टर्स जाते हैं वे उस वक्त पब्लिक का काम करने के लिए जाते हैं इसलिए कुछ सरकारी कर्मचारी उनके साथ जाने आवश्यक हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जब प्रधान मंत्री दौरे पर गईं तो क्या यह हकीकत नहीं है कि प्रधान मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी मि० कपूर ने यू०पी० के ग्रन्दर जाकर एक मीटिंग में उद्घाटन किया और कांग्रेस के हक में भाषण भी दिया, पेपर्स में भी वह चीज आई ? अगर यह चीज सही है तो मैं जानना चाहता हूँ कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, क्या सरकार उनका दुरुपयोग अपनी पार्टी के काम के लिए करना बन्द नहीं करेगी ? अगर नहीं करेगी तो फिर क्या उसका परिणाम यह नहीं होगा कि देश में भ्रष्टाचार फैल जायेगी और एलेक्शन ठीक ढंग से नहीं हो पायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : मैं अधिकृत रूप से कह सकता हूँ कि कोई भी सरकारी अधिकारी ने ऐसा काम नहीं किया जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री तुकम चन्द कछवाय : उसका भाषण अखबार में आया है।

श्री बिद्या चरण शुक्ल : मैं इसका खंडन करता हूँ। किसी सरकारी अधिकारी ने ऐसा काम नहीं किया।..... (श्ववधान).....

श्री रामस्वरूप बिद्यार्थी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि दिसम्बर में सवाल की नोटिस दी थी, चार महीने के बाद भी जवाब नहीं दिया तो अभी और कितना समय चाहिए ?

दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि पब्लिक के काम के लिए गई जबकि अखबार में ये नोटिस निकलती है कि प्रधान मंत्री का एक्शन टूवर है तो फिर उसमें सरकारी कार्य का कहीं सवाल पैदा होता है ? मैं जानना चाहता हूँ कि अगर एलेक्शन टूर में सरकारी कर्मचारी और तमाम दूसरा पैराफर्नेलिया जाता है तो वह पब्लिक का कौन सा काम करता है, वह बताने की कृपा करें।

श्री बिद्या चरण शुक्ल : अगर माननीय सदस्य मूल उत्तर को सुनते तो फिर इतने प्रश्न पूछने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती।

उसमें साफ कह दिया है कि जब भी कोई मंत्रीगण बाहर जाते हैं दौरे पर तो यह नहीं होता कि मंत्री का काम ही नहीं करते, उन्हें सरकारी काम भी करना पड़ता है, वे चाहें एक दिन के लिए दौरे पर जायं या दस दिन के लिए दौरे पर जायं। चूंकि उनको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है और वे उस कार्य को सुविधापूर्वक कर सकें इसलिए कुछ सरकारी अधिकारियों को जोकि उनके स्टाफ में रहते हैं उनको भी ले जाना पड़ता है। जो उनके साथ निजी स्टाफ जाता है वह सरकारी काम के सिलसिले में ही जाता है, एलेक्शन के काम के सिलसिले में नहीं जाता है। चूंकि वे सरकारी काम के लिए ही जाते

हैं इसलिए जो खर्चा उन पर होता है वह सरकार देती है।

**SHRI RANGA :** That is far-fetched.

**SHRI PILOO MODY :** Is he suggesting that they do not work in Delhi ?

श्री नारायण स्वरूप शर्मा : मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि एक मिनिस्टर हमेशा आफिशल इयूटी पर ही रहता है। बस्ती जिले में जब इन्दिरा जी गई थीं तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर का आफिशल काम जो कुछ भी उन्होंने किया होगा, उसका तो कोई पता नहीं लेकिन एलेक्शन के सम्बन्ध में जो वहां पर मंच बना था जहां से कि उन्होंने एलेक्शन मीटिंग एड्रेस की थी, उसको पी. डब्ल्यू. डी. के इंजीनियर्स ने बनाया था और मैंने स्वयं उसको बनते हुए देखा था। इसके अतिरिक्त नेहरू जी के समय में जो कभी नहीं हुआ वह बस्ती के बाजार में दोनों श्रीर वुडन वैरियस लगा दिए गए, प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए, यह बात तो ठीक है लेकिन जनता के दूर हटाने के लिए भी इतना पैसा खर्च करना पड़े, इस तरह का जो सिद्धांत आपने बना लिया है, मैं जानना चाहूंगा कि कम से कम एलेक्शन टाइम में तो इस प्रकार का पैसा का दुरुपयोग बन्द किया जायेगा ?

श्री बिद्याचरण शुक्ल : हमेशा इयूटी में रहने का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा जब चुनाव के दौरे में जाते हैं तो वहां पर सरकारी काम भी करना पड़ता है इसलिये निजी स्टाफ को ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। न केवल प्रधान मंत्री बल्कि विरोधी दल के मंत्री, जैसे श्री नम्बूदरीपाद हैं, उन के साथ भी उन के काम करने वाले आते थे, उन्हें भी काम करना पड़ता था। और जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने डायस का इन्तजाम किया तो वह सुरक्षा का इन्तजाम था और सुरक्षा का इन्तजाम करने की जिम्मेदारी पूरी राज्य सरकार की है। और न केवल प्रधान मंत्री के लिये नै माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता

हूँ कि केरल के मुख्य मंत्री श्री नम्बूदरीपाद गये उन के लिये भी उसी तरह राज्य सरकार को इन्तजाम करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष दल के मंत्री के लिये करना पड़ा। सुरक्षा के इन्तजाम की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है। राज्य सरकार स्वयं विवेक से करती है कि कितना इन्तजाम करना चाहिये। उस के ऊपर आप लोग तरह-तरह की बातें लौंइं यह ठीक नहीं है।

श्री नारायण स्वरूप शर्मा : पहले नेहरू जी के जमाने में नहीं किया जाता था, वुडन बैरियर नहीं बनते थे। लेकिन अब बनते हैं।

**MR. SPEAKER :** I am not allowing a discussion on it now.

श्री सीताराम केसरी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो मंत्री लोगों ने यात्रा की मान लीजिये जो कांग्रेस की तरफ से गये या जिस दल की तरफ से गये तो क्या संगठन ने उन की यात्रा के लिये कुछ कीमत या पैसा आप को दिया है कि नहीं, इस की खबर है कि नहीं ?

श्री बिद्याचरण शुक्ल : जो मंत्री लोग और हैं जहाँ तक मुझे सूचना है उनके लिये संगठनों ने या उन्होंने स्वयं उसका खर्चा दिया है। सरकार ने उस पर कोई खर्च नहीं दिया।

**SHRI PILOO MODY :** This Government has become so shameless that it has lost all sense of proportion in matters like this. It has been published in the papers that the Prime Minister's expenditure in Bihar over and above the requirements of security was in the neighbourhood of Rs. 4—6 lakhs; her two-day visit to Bengal over and above the requirements of security cost Rs. 98,000. Now, Mr. Chavan came to my constituency during the elections and he was also doing the same as I was doing; there was a motorcade of seven cars with officials

and others going along with him. He was only going to address a public meeting seven miles from Godhra and return back again and he could not possibly have done any work on his way. But he had officials of all types accompanying him; in addition steel helmeted policemen also. I want to know whether this Government wants to establish as precedent in this country that anybody who has authority is allowed to use every type of machinery of Government in order to further his political ends or are they even at this belated stage going to lay down some code of conduct consistent with human decency and decencies of public life so that things like that do not happen in future.

**SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :** I am sorry the hon. Member did not pay any attention to my replies and I shall repeat them so that he can understand what arrangements are made when Ministers go on non-official tours like this. Whenever Ministers go on non-official tours the State Governments make arrangements; it is not for any Minister or Mr. Chavan to specify which officer should accompany him or should not come with him or how many policemen and securitymen should go with him; it is all to be decided by the State Government. If they decide to send some officials and securitymen it is not for the Minister concerned to object to that. It is not unhealthy traditions are being laid by any such things. A code of conduct had been laid down for the Ministers that whenever they go on non-official tours how many officials or their personal staff can go with them and who will pay for their expenditure. All these things are laid down properly by the Government.....

**SHRI PILOO MODY :** Are they consistent with public decency ?

**SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :** The principles we have laid down are healthy and we are following them.

**SHRI PILOO MODY :** Most unhealthy.

**SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :** The only difficulty is, the hon. Members are unnecessarily mixing up the functions

of the Central Government and the functions of the State Governments when the Ministers go on tour.

**SHRI PILOO MODY :** Sir, just one moment. I gave two specific instances in Bihar and West Bengal, where expenditure was incurred over and above the needs of security. As a matter of fact, the Governor of Bihar was in a real predicament, because he did not know whom he was going to charge this money to. That has not been replied to.

**SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :** As far as this particular matter is concerned, any bill which is not borne by the Central Government or the State Governments will definitely be paid by the party or by the Prime Minister herself. So, there is no question of its being paid by Government. (*Interruption*).

**SHRI JAIPAL SINGH :** Mr. Speaker, Sir, in this cry of decency, code and everything else, the basic issues are being missed. It is all a question of security, whether it is the Prime Minister or the Minister of Tourism and Civil Aviation, Dr. Karan Singh. I had the privilege of going round with the Ministers and hosting them. Now, the whole question is these security arrangements are necessary not only for those undeserving Ministers there but are as necessary for Mr. Piloo Mody also. The hon. Minister of State has made it clear that the arrangements are made by the State Governments. It is not that the Prime Minister or Dr. Karan Singh have demanded that there should be a motorcade, a lot of vehicles or a cavalcade.

**MR. SPEAKER :** What is the question ?

**SHRI JAIPAL SINGH :** My question is this : this question should not be raised here.

श्री हुकमचन्द कच्छबाय : आपके घर में जाकर पूछें ?

श्री जयपाल सिंह : बँडो ।

**MR. SPEAKER :** Do not provoke him, Mr. Kachwai.

**SHRI JAIPAL SINGH :** My point is this, and my grievance is this : that (b) should have been answered. But at the same time, this question of local arrangements is a matter for the States. They do not arise here at all.

**MR. SPEAKER :** That is what the Minister said. Shri Hem Barua.

**SHRI HEM BARUA :** Apart from Ministers attending election meetings with all the official paraphernalia, there are instances of Ministers attending the AICC meetings outside Delhi along with official tour programmes. The *Statesman* of Delhi has come out with a list of Ministers who have done it and with the amount of money they spent on official tours. They fix official programmes round about the city where the AICC meetings are held. This is an instance of corruption of the worst type. In view of all this, may I know—fortunately the Prime Minister is not present—whether the Government propose to instruct the Ministers concerned not to misuse their official position by taking official paraphernalia with them when they go out on non-official business like addressing public meetings in the course of elections or attending the AICC meetings? There should be some morality in this.

**SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :** I have already stated that instructions already exist for such purposes, and I do not think any misuse has been made. So, there is no question of issuing any fresh instructions.

As far as the question of attending the AICC meetings along with some official engagements is concerned, it is normally not done. Somewhere it might have happened that the Minister concerned might have had to attend some official engagement either on the way or the way or nearabout that place. But that is not done deliberately.

**SHRI PILOO MODY :** What about the Prime minister?

**SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :** Well, nobody should try and connect these two things together. All I can say is

that, as far as possible, Ministers should try to avoid this kind of thing. Some Hon. Members (*Rose*)

**MR. SPEAKER :** Shall we spend the whole hour on this question?

This is a question where he has given his answers with which you do not agree. He is not going to change his views now.

**SHRI BAL RAJ MADHOK :** If you are satisfied, we are satisfied.

**MR. SPEAKER :** It is not a question of my being satisfied. Should we lose the Question Hour in this controversy?

**SHRI RANGA :** What about the code of conduct for the ministers?

**MR. SPEAKER :** If there is a code of conduct for the ministers, the minister may later on give the information.

#### Foreign Collaboration in Hotel Industry

\*1172. **SHRI BEDABRATA BARUA :** Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign collaborations in Hotels have been approved in the past ;

(b) If so, what existing hotels in India are run by foreigners and Indians jointly ; and

(c) whether any good results have followed such collaborations ?

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SAROJINI MAHISHI)** (a) Yes, Sir.

(b) At present, only one hotel, the Oberoi Intercontinental in New Delhi, is being run by East India Hotels Ltd. in collaboration with Intercontinental Hotels Corporation of U. S. A.

(c) Yes, Sir. Hotels belonging to an international chain are an obvious advantage in the development of foreign tou-

rist traffic as they stimulate the increased flow of tourist traffic into the country and also result in substantial foreign exchange earnings.

**SHRI BEDABRATA BARUA :** There are reports of fresh collaboration agreements with Hiltons, Tata Intercontinental, etc. I think we ought to have a second look at the question of foreign collaboration. By and large, foreign collaborations have not helped our industries. They have demoralised our engineers and helped some people to make easy money. So far as tourist trade is concerned, I am prepared to examine it on merits. Will the minister see whether it really leads to increase in tourist trade and whether we are going to get much more foreign exchange than what we spend? Can we justify it on this ground?

**THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) :** Yes, Sir. As I said in the main reply, certainly an international collaboration chain does have very definite advantages. We have only one such hotel to present in India Oberoi Intercontinental in Delhi. This single hotel earns us Rs. 1 crore a year in foreign exchange. It is functioning at almost 95 to 98 per cent occupancy. More than 50,000 people stayed in it during 1968.

**SHRI JYOTIRMOY BASU :** At the cost of Ashoka!

**DR. KARAN SINGH :** The point is, the investment that is made is basically Indian investment. But we earn a great deal of foreign exchange. Therefore, the new collaborations—all the three of them are in the Gateway city of Bombay—In tercontinental, Sheraton and Hiltons—will certainly result in a substantial increase in foreign exchange earning and also in tourist traffic.

**SHRI PILOO MODY :** The answer is incomplete. Shall I supplement it?

**SHRI BEDABRATA BARUA :** May we know something about the terms of the collaboration with these foreign companies, whether they include facility for training, at least for the management of Ashoka and other hotels and whether actually we are going to benefit from this type of training? May I know whether we have the capacity to use the training

for other purposes like extending the chain of hotels in our own country and starting our own chain of hotels in the Afro-Asian countries in collaboration with them?

**DR. KARAN SINGH :** The point about training is very important. In these collaborations, it is expected that in the private sector at least, there would be a good deal of additional training as a result of these projects coming up. These collaborations have nothing to do with the public sector. These are with the private sector. Even in the public sector, as I submitted on an earlier occasion here we are trying to build up a chain in the public sector, and for that purpose we are at present in negotiation with a foreign firm for some technical expertise—not collaboration—in our building up of a hotel chain. We hope to set up a training institute ultimately which would serve the needs both of the public sector and private sector so that we can develop.

On the second point, with regard to our own chains abroad, I entirely agree. After all, if American chains can collaborate with us here there is no reason why Indian chains cannot collaborate in foreign countries.

**SHRI PILOO MODY :** In Ethiopia?

**DR. KARAN SINGH :** Not necessarily in Ethiopia. We can build hotels in Japan, Australia and other countries also. The whole point is, that will have to be done in two ways, either through the private sector or once our public sector gets established we can consider that also.

**SHRI S. K. TAPURIAH :** Sir, I will not at all hesitate in complimenting the Government for the pragmatic approach they have taken in building up new hotels. But I am not very clear about one thing that he said in his reply. In the reply it was said that one hotel with collaboration is running. Probably, because he used the word 'running' he did not consider the three collaborations which probably have been passed, according to newspapers, recently. There are three types of collaboration terms in vogue in the country. One is a flat rate at which



booking is given and the collaborator has no participation in management. The second is a percentage of profit and the third is, according to the one granted recently, in which the foreign company would manage the hotel and take a percentage of turnover. I would like to know from the Government, since the Minister mentioned that with collaboration only one hotel has been working now, what is the idea of allowing foreigners to manage hotels in the country and, secondly, if we granted more liberal terms than what we have now will it not affect good terms in our favour in the future ?

**DR. KARAN SINGH :** The question was about existing hotels in India run with foreign collaboration. There is only one hotel and that is the Oberoi Inter-continental in Delhi. The new collaborations are in Bombay. One is with Sheratans, a second with Inter-continental and a third with Hiltons. All the three are in the Gate-way City of Bombay which urgently needs hotels. The actual terms of each vary because of the negotiations which the Indian partner and the foreign firm have entered into. There is not any rigid pattern which we can impose upon every collaboration. It is a negotiation which takes place between them. For example, on the question of Hilton itself, they had negotiated certain terms and when they came to Government, the Government rejected them. It is after two years, after Hiltons have agreed for depreciation charges, interest charges and such other charges to be deducted that we have agreed. So there is no rigid pattern. It depends upon the company concerned and the Indian party and we naturally try to get the best terms possible.

**श्री शशि भूषण :** अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में यह होटलों की व्यवस्था काफी पुरानी है। हमारे देश के नागरिक फ्रांस में इंग्लैंड में और दूसरे देशों में बहुत अच्छे होटल चलाते हैं। इसी तरह हम लोगों ने स्वदेशी को अपना कर लड़ कर देश के लिए आजादी प्राप्त की लेकिन उस के बाद से एक हमारे में ऐसा मीनिया बन गया है कि चाहें लिपिस्टिक हो, रबड़ हो, चाय हो,

कॉज्यूमर्स गुड्स हों या डालडा हो, सब के लिए फॉरेन कोलैबोरेशन हम करने लगे हैं। उसके बाद होटल जैसी चीज जोकि हजारों, लाखों आदमी इस देश में चला सकते हैं उसके लिए फॉरेन कोलैबोरेशन किया जाता है। दूसरे मुल्कों के लोग हमारे यहाँ होटल इसलिए चलाने को आ जाते हैं कि हमारे यहाँ इसमें 200 और 300 गुना फायदा होता है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम विदेशियों को इस देश में शोषण करने के लिए होटल जैसे क्षेत्र में भी बुलायें। मैं मंत्री महोदय से आप के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो यह विदेशी कोलेबोरेशन का मीनिया है उस को वह खत्म करें और अपने देश के लोगों से अपनी इंडस्ट्री बिल्ड करें जिस पर कि हमें स्वाभिमान हो सके।

**डा० कर्ण सिंह :** माननीय सदस्य ने जो कहा है कि इसमें विदेशी कोलैबोरेशन की आवश्यकता नहीं है तो मेरा कहना है कि यह टूरिज्म में चैन बुकिंग का बहुत लाभ होता है। जब एक टूरिस्ट अपना प्रोग्राम बनाता है अमरीका, यूरोप से अथवा और कहीं से तो वह यहाँ आकर अपनी बुकिंग नहीं करता है बल्कि वह वहाँ बैठ कर जोनल एजेंट के जरिये करता है। जब एक चैन बुकिंग होती है तो उसमें पब्लिसिटी वगैरह का हमें बहुत लाभ होता है। पब्लिसिटी जिसके लिए कि हमें लाखों और करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं हमें उस फर्म के जरिये पब्लिसिटी मिल जाती है। हमें कोई मीनिया नहीं है यह बात नहीं है कि हम विदेशी लोगों को यहाँ बुलाना चाहते हैं, हम तो अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को देश में फैलाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा लाभ होता है क्योंकि चैन कोलेबोरेशन में तो ट्रैवल एजेंट के द्वारा काम होता है और वह पैसा हमें उनको फॉरेन एक्सचेंज में देना पड़ता है। यहाँ आकर एक्सचेंज करके वह रुपये में पे कर सकते हैं। इसलिए हमको इसका भी लाभ होता है। तीसरी बात यह है कि अगर जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर है। स्टार वाले होटलों का, उस तरह से पांच या सात होटल इस

देश में बन जाएँ तो हमारी होटल इण्डस्ट्री का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और कोई विशेष बात इस में नहीं है।

1967 का सचेतक सम्मेलन

1173. श्री सुरज भान :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री रणजीत सिंह :

श्री बृज भूषण लाल :

क्या संसदीय-कार्य मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 में हुए सचेतकों के सम्मेलन में जो सिफारिशें की गई थीं ; उनका व्यौरा क्या है ;

(ख) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) A copy of the recommendations adopted at the Sixth All India Whips' Conference held at Simla in October, 1967 was placed on the Table of the House on 14th November, 1967 in reply to Unstarred Question No. 199.

(b) and (c). The recommendations are of such a nature as would require consideration and implementation by the Government and Presiding Officers of Legislatures both at the Centre and in the States. They were accordingly communicated to the State Governments and the Presiding Officers of Parliament and State Legislatures for implementation to the extent feasible in their sphere of functions connected with the working of Parliamentary machine. Up-to-date reports about their implementation are still awaited from them. The position will be reviewed at the next All India Whips'

Conference. In so far as the Central Government is concerned, some of the recommendations stand implemented and others are under active consideration.

श्री सुरज भान : व्हिप्स की कॉफ़ेंस की एक रिक्मेंडेशन यह थी कि डिफेन्स खत्म हो जाये, फ्लोर-क्रासिंग खत्म हो जाये और इसके लिये एक सब पार्टियों की कमेटी भी बनी थी। डिफेन्स के ऊपर उसकी अपनी रिपोर्ट थी। मैं जानना चाहता हूँ कि इन डिफेन्स को खत्म करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SRI RAGHU RAMAIAH) : As the House is aware, in pursuance of the Resolution moved by Shri P. Venkatasubbaiah in the Lok Sabha, the Ministry of Home Affairs have set up a high level committee to examine this problem. The report of that committee was laid on the Table of the House on 18.2.69. Subject to allotment of time by the Business Advisory Committee this report is likely to be discussed after the Demands are voted.

श्री सुरज भान : वहाँ एक रिक्मेंडेशन यह भी थी कि ग्रापोजीशन की रिक्मेंडेशन पार्टियों के जो व्हिप्स होने हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटी दी जाय, बल्कि उनको डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा दिया जाये। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में उनके क्या विचार हैं ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : Whatever recommendations are made regarding opposition whips as well as regional whips they are under very active consideration.

श्री बृज भूषण लाल : दो सालों के अन्दर जो दल-बदल या डिफेन्स लेजिस्लेचर्स में हुए हैं उनसे अपनी नेशनल स्टेबिलिटी के लिये बड़ा भारी खतरा है। इस बात को अदेनजर रखते हुए जो व्हिप्स की कॉफ़ेंस हुई थी उसमें कांसेन्सस ग्राफ़ प्रोपीनियन यह थी, कि इन डिफेन्स को कानून

द्वारा रोका जाय। जैसा मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि एक रिपोर्ट आई हुई है और उस पर गौर हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बूक तत्काल इस कांग्रेस सरकार को यह दल-बदल का मामला पसन्द आ रहा है और उनके हित में है, इस लिये इसमें देर की जा रही है और इस कानून को बनाने में संकोच हो रहा है ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : I think the Congress Party has suffered more on account of defections,

श्री मौलू प्रसाद : बिहार में फायदा हो रहा है।

MR. SPEAKER : It is a two-way traffic now. Previously, it was only one way traffic.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : There are two ambiguous sentences in this statement, Paragraph 9(b) says that young legislators should be encouraged to undertake study tours and paragraph 10(b) says that young legislators should be encouraged to serve on various committees. May I know the age limit below which Members are supposed to be chicken-hearted and need to be encouraged ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : I think, my hon. friend knows that better.

SHRI RANGA : May I know whether at the last meeting, if not at the earlier meeting, any consideration has been given to maintaining decorum, decency and order in the House and co-operating with the Speaker with the co-operation of the whip ? I am all in favour of all the privileges being given to the whips but, at the same time, there should be certain duties also to be performed by whips as well as their leaders but most especially by whips because they are in charge of maintaining discipline among themselves,

Secondly, would any consideration be given also to the need for the whips not to try to entice away Members of other

parties and if they were to admit anyone at all belonging to some other party into their own party would they have adequate consultations with the leaders of the parties concerned and the whips concerned also ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : A number of suggestions have been made in regard to the first point raised by the hon. Member, Shri Ranga. I might be allowed to point out that the Conference, while emphasizing that the privilege of raising points of order should not in any way be curtailed, recommended that such a privilege should not be utilised merely to catch the eye of the Speaker. This is one of the measures by which this Conference tries to regulate decorum in the House if I may say so. There are various other things. It is already laid on the Table on the House.

MR. SPEAKER : That is the most important recommendation.

SHRI RAGHU RAMAIAH : As regards taking away Members through the whips and all that, whether it is done through the whips or otherwise, defection is defection and we are all against it. I have already indicated that the matter will come up for consideration again.

श्री सु० प्र० झा : डिफेन्स की बीमारी ज्यादातर सन् 1967 के एलेक्शन्स के बाद शुरू हुई है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस बीच में कितने डिफेन्स कांग्रेस से अपोजीशन पार्टीज को हुए हैं और कितने अपोजीशन पार्टीज से कांग्रेस को हुए हैं ?

श्री सु० कु० तापड़िया : सब से पहले कहां हुए हैं ?

श्री सु० प्र० झा : मैंने सवाल माननीय सदस्य से नहीं, मिनिस्टर साहब से किया है ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : I do not have the figures.

MR. SPEAKER : Shri Banerjee.

श्री मु० झ० खां : मेरे सवाल का जबाब नहीं मिला ।

MR. SPEAKER : He has said, he has no figures.

श्री मु० झ० खां : उनके पास यह फिगर्स होने चाहिए । अगर हैं तो उनको सदन की मेज पर रक्खा जाये ।

SARI RAGHU RAMAIAH : I have already said that I do not have the figures now because the figures go on varying from day to day.

श्री मु० झ० खां : मैं तो आज तक के फिगर्स चाहता हूँ । अगर उनके पास वह फिगर्स हैं तो क्या वह सदन-पटल पर रखे जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कल भी पंजाब में हुआ है ।

How could he give you the figures when there were some changes only yesterday ?

SHRI S. M. BANERJEE : I remember at this particular meeting, which was attended by me along with my hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta, and others, we had a discussion on defections and I said in that meeting itself that defection had a long history, Vibhisana was the first defector who defected from Ravana and joined Rama. That is there in the *Ramayana*. So, it is a very serious problem.

Apart from that, there were many recommendations, such as, that non-officials should be chairmen of the various committees in the States which are being presided over by district magistrates or officials. The entire committee, whether the Congress side or this side, was unanimous and Dr. Ram Subhag Singh, who presided over this conference, was also of the view that Members of Parliament or of State Legislatures should be given adequate representation and some respect and that they should not suffer at the hands of the district authorities who are always chairmen of those committees.

I would like to know whether this was forwarded to the State Governments and, if so, what is the reaction of the State Governments.

SHRI RAGHU RAMAIAH : This has been, along with other recommendations, forwarded to them. We have not yet got a complete reply from all the States.

शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ, पुस्तिकाएँ तथा प्रतिवेदन

\*1174. श्री मोलूह प्रसाद : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं तथा वार्षिक, मासिक तथा पाक्षिक प्रतिवेदनों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये हैं ;

(ग) क्या निकट भविष्य में इन सभी पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं को अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ;

(ङ) यदि नहीं, तो पत्रिकाओं और प्रतिवेदनों को अंग्रेजी में प्रकाशित करने की क्या उपयोगिता है जब कि भारत के बहुसंख्यक लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, और

(च) इन प्रकाशनों को अंग्रेजी में प्रकाशित करके जनता के धन को व्यय करने का क्या औचित्य है ?

शिक्षा तथा युवकसेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त बर्दान) : (क) से (च). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

## विवरण

(क) और (ख). मंत्रालय और उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों ने हिन्दी और अंग्रेजी में निम्नलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित कीं :—

अलावा हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशन निकालने का निर्णय प्रकाशन विशेष के महत्व को देखते हुए किया जाता है ; और सामान्य नीति यह रही है कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशनों की संख्या बढ़ाई जाय।

	वार्षिक	अर्धवार्षिक	त्रैमासिक	मासिक	कुल
केवल हिन्दी	—	—	1	2	3
हिन्दी और अंग्रेजी	7	—	2	—	9
केवल अंग्रेजी	21	3	7	2	33
कुल	28	3	10	4	45

इसके अलावा समय-समय पर तथा तदर्थ रूप से अनेक प्रकाशन और निकाले जाते हैं, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संदर्शिकाएं और फोल्डर : भारतीय प्राणिविज्ञान तथा मानवविज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा अभिलेख, स्मारिकाएं तथा वैज्ञानिक निबंध, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तकनीकी निबंध, पुस्तिकाएं, उच्चार-भाटा सारणियाँ आदि। परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार इन प्रकाशनों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। इनमें से कुछ हिन्दी में भी हैं।

(ग) और (घ). वे पत्रिकाएं तथा अन्य प्रकाशन जो केवल अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए होते हैं या जिनकी प्रकृति अत्यधिक तकनीकी होती है, या जो सीमित संख्या में विशेषज्ञों के लिए ही तैयार किए जाते हैं, सामान्यतया केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जाते हैं। लोकप्रिय पत्रिकाएं या पुस्तिकाएं, जो बड़ी संख्या में अंतर्देशीय वितरण के उद्देश्य से तैयार की जाती हैं हिन्दी में भी प्रकाशित की जाती हैं ; और जहाँ जरूरी हो अन्य भारतीय भाषाओं में भी। अंग्रेजी के

इस समय केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित होने वाली 33 पत्रिकाओं में से :

—30 या तो अत्यधिक तकनीकी प्रकार की हैं या अंतर्राष्ट्रीय उपयोग की ; और

—तीन का प्रकाशन हिन्दी में करने का विचार है।

(ङ) और (च). अंग्रेजी के प्रकाशन वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के पाठकों के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए हैं।

श्री मोरारू प्रसाद : जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उस में बताया गया है कि हिन्दी में त्रैमासिक 1, मासिक 2 पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। हिन्दी और अंग्रेजी में वार्षिक 7 और त्रैमासिक दो होती हैं। केवल अंग्रेजी में वार्षिक 21, अर्धवार्षिक 3, त्रैमासिक 7 और मासिक दो होती हैं। इन्होंने इस विवरण में यह भी कहा है कि जो 33 अंग्रेजी में केवल प्रकाशित होती हैं उन में से तीस या तो अत्यधिक तकनीकी प्रकार की हैं या

अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग की है। इस में इन्होंने यह भी बताया है कि इनके अलावा समय-समय पर तथा तदर्थ रूप से अनेक प्रकाशन और निकाले जाते हैं, जैसे भारतीय पुरा-तत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संदर्शिकायें और फोल्डर, भारतीय प्राणिविज्ञान तथा मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा अभिलेख, स्मारिकायें तथा वैज्ञानिक निबन्ध, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तकनीकी निबंध, पुस्तिकायें, उच्चार-भाटा सारणियाँ आदि। परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार इन प्रकाशनों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। इन में से कुछ हिन्दी में भी हैं।

अंग्रेजी में प्राय 33 पत्रिकायें प्रकाशित करते हैं। इनको सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए प्रसारित किया जाता है। प्राय देखें कि बहुसंख्यक लोग हमारे देश में अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वह भारतीय भाषायें जानते हैं, क्षेत्रीय भाषायें जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप परसेंटेज बता दें कि अंग्रेजी कितने परसेंट लोग जानते हैं और हिन्दी, उर्दू, तमिल, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगला, आदि जो हमारी क्षेत्रीय भाषायें हैं इनको कितने प्रतिशत जानते हैं। उस प्रतिशत के आधार पर ये पत्रिकायें अथवा पुस्तकें प्रकाशित कराने का क्या आपका विचार है ?

श्री भक्त बर्षान : श्रीमान् इस सम्बन्ध में यह नीति निश्चित की गई कि पत्रिकायें अथवा जो पुस्तकें आदि अथवा रिपोर्टें जो कि विदेशों को भेजने के लिए होती हैं वह आमतौर से अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती हैं और जो हमारे देश के अन्दर के लिए होती हैं, अथवा देश में ही जिनका व्यवहार होना होता है वे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में की जाती हैं। आपने विवरण में देखा होगा कि कुछ पत्रिकायें ऐसी हैं जो केवल हिन्दी में ही प्रकाशित की जाती हैं।

आवश्यकताओं के अनुसार ऐसा किया जाता है। मैं अश्वत्थसन देना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजी में प्रकाशन हो रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जितने अधिक से अधिक हिन्दी में प्रकाशित हो सकें, उनको हिन्दी में भी प्रकाशित कराने का प्रयत्न किया जाए।

श्री मोल्हू प्रसाद : परसेंटेज बता दें कि अंग्रेजी जानने वालों का कितना है और भारतीय भाषाओं को जानने वालों का कितना है।

श्री भक्त बर्षान : श्रीमान् इसको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह जनसंख्या के आँकड़ों में देखा जा सकता है। मैं निवेदन कर चुका हूँ कि जो अंग्रेजी में केवल प्रकाशित की जाती हैं, वे केवल अंग्रेजी जानने वालों के लिए होती हैं।

श्री मोल्हू प्रसाद : अंग्रेजी जानने वालों का परसेंटेज बता दें।

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा सप्लीमेंटरी पूछें।

श्री मोल्हू प्रसाद : मैं जानना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई 1968 को जो आदेश जारी किये हैं उनके अनुसार आपने क्या प्रगति की है, प्रगति की गति क्या है ?

श्री भक्त बर्षान : श्रीमान् मैं अश्वत्थसन देना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। हमारा मंत्रालय अच्छी प्रगति कर रहा है; बल्कि मैं कहूँगा कि कुछ और मंत्रालयों से अधिक प्रगति कर रहा है।

श्री मोल्हू प्रसाद : जरा आप प्रशासन शाखा के सचिव, संयुक्त सचिव, उप-सचिव, आदि की संख्या बता दें जो कि हिन्दी में नोटिंग और डाइफिटिंग करते हैं। इसका स्पष्ट उत्तर मैं चाहता हूँ।

**श्री भक्त बर्षान :** श्रीमान यदि पूर्व सूचना इसकी दी जायगी, तो इसका उत्तर भी मैं दे दूंगा।

**श्री रवि राय :** जो उत्तर दिया गया है उसमें सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इसमें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का जिक्र है। जवाब में कहा गया है कि हिन्दी या दूसरी भाषायें। मैं जानना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की जो दूसरी भाषायें हैं उनमें कितने प्रकाशन होते हैं। मंत्री महोदय की यह मान्यता है कि तकनीकी और साइंटिफिक जो सामग्री है वह सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों के लिए छपवानी जरूरी होती है। क्या जिस चीज को आप अंग्रेजी में प्रकाशित कराते हैं, उसकी दूसरे लोगों को जरूरत नहीं होती है जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं? जो चीज आप अंग्रेजी में छपाते हैं उसको दूसरी भाषाओं में भी प्रकाशित कराने का आप प्रयत्न करेंगे?

**श्री भक्त बर्षान :** श्रीमन् यह तो मैं अभी नहीं बता सकता कि हिन्दी के सिवा अन्य भारतीय भाषाओं में कितने प्रकाशन किए गए हैं। लेकिन यह मैं बतलाना चाहता हूँ कि शिक्षा आयोग का जो प्रतिवेदन है, जोकि एक बहुत मोटा वॉल्यूम है, उसका अनुवाद करीब करीब सभी क्षेत्रीय भाषाओं में कराया जा चुका है या कराया जा रहा है। एक कठिनाई यह है कि तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली अभी पूरी नहीं बन पाई है इस वास्ते उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए कठिनाई हो रहा है। ज्यों ही वह आ जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा।

**श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि ३३ पत्रिकाएं जो केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होती हैं वे तकनीकी प्रकार की हैं और अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए हैं। तीन हिन्दी में भी प्रकाशित होती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि

तीन के सिवा बाकी जो अंग्रेजी जानने वालों के लिए प्रकाशित होती हैं, उनका क्या दूसरी भाषाएं जानने वालों के लिए कोई उपयोग नहीं है? यदि है तो क्या आप उनको हिन्दी में भी प्रकाशित कराने की योजना बनाएंगे?

**श्री भक्त बर्षान :** श्रीमन् मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूँ और उसको मैं दुहरा देना चाहता हूँ कि जो सूची है उसकी फिर से समीक्षा की जाएगी और इनमें से अधिक अधिक प्रकाशनों को हिन्दी में भी प्रकाशित कराने की कोशिश की जाएगी।

**THRI DINKAR DESAI :** There is a feeling that the periodicals published by the Government are very inefficiently conducted, and as a result of that, the circulation of these periodicals is very small. May I know from the hon. Minister what is the average circulation of these periodicals?

**SHRI BHAKT DARSHAN :** Sir, I have not got that information just now with me.

**श्री प्रेमचन्द शर्मा :** मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ। इन पब्लिकेशंस में बहुत वेस्टेज होता है। 1964-65 के साल के बारे में पी ए सी की रिपोर्ट के पेज 10 पर यह बताया गया है कि एक साल में जितनी ये छपीं उनमें से केवल 24 परसेंट बिकीं और 68 परसेंट 31 तारीख तक नहीं बिकीं और पड़ी रहीं। साथ ही उसी में एक नोट में यह भी बताया गया है कि जो पचास हजार छपीं उनमें से सतरह हजार रहीं में बेची गईं यानी वन थर्ड नहीं बिक सकीं, उनका कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। यह पी ए सी की रिपोर्ट में है।

मैं जानना चाहता हूँ कि जितनी पब्लिकेशंस एक साल में आपने छपीं उन पर कितना रुपया खर्च आया और एक साल के

बाद कितनी बची रहती, कितनी उनमें से बिकी, कितना आपको मिला और कितना घाटा हुआ ? जो बची रहती वे रद्दी में बेची गई क्या ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान पी ए सी की तरफ आकर्षित किया है और मैं उसको देख लूंगा। बिना देखे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : May I know whether these publications are meant mainly for the majority of the Indian people who are illiterates or they are meant for the educated intelligentsia of India from the various linguistic areas, and if they are for the latter, may I know whether the publications in Hindi are meant only to cater to the fanaticism of the Hindi protagonists rather than to serve any useful purpose ?

SHRI BHAKT DARSHAN : Sir, I do not think that this questions requires any answer.

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि एक साल में केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले प्रकाशनों की संख्या 33 है और इसका यह कारण है कि ये दूसरे देशों में भी जाते हैं। भारतवर्ष के लिए प्रकाशित होने वाले प्रकाशन केवल बारह हैं जिनमें अंग्रेजी और हिन्दी दोनों हैं। विदेशों के लिए प्रकाशित होने वाले प्रकाशनों की संख्या 33 है। मैं जानना चाहता हूँ कि शिक्षा मन्त्रालय के जो प्रकाशन हैं क्या ये अधिकांश विदेशों के लिए ही हैं, भारतवर्ष में उपयोग के लिए नहीं हैं ? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो बात लिखी है कि उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है तो वह कार्यक्रम क्या है, उसकी भी रूपरेखा बताएं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केवल विदेशों के लिए ही ये नहीं हैं। बल्कि ये वैज्ञानिक और

तकनीकी विषय बहुत कठिन हैं—जैसे कि ज्वोलौजिकल सर्वे है या और भी सर्वे आफ इण्डिया के बहुत से विषय इतने कठिन और तकनीकी हैं कि उनका हिन्दी अनुवाद करना भी बड़ा कठिन हो रहा है, इस वजह से यह कठिनाई है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है।

Adverse Observations against Former Chief Justice of India

1177. SHRI GEORGE FERNANDES : SHRI JYOTIRMOY BASU :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the recent judgement by Shri P. B. Mukherjee of the Calcutta High Court in connection with litigation involving a Haridas Mundhra concern, M/s. Turner Morrison and Co., in which certain adverse observations have been made regarding the association of a former Chief Justice of India. Shri B. P. Sinha, with the Mundhra concerns.

(b) if so, whether Government have sought any explanation from Shri Sinha; and

(c) whether Government would consider taking necessary steps to discontinue payment of pension to the former Chief Justice in view of his employment with the Mundhra concerns ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). Government have seen the judgement delivered by Shri Justice P. B. Mukherjee of the Calcutta High Court in the case referred to. The remark of the High Court do not reveal a *Prima facie* case of misfeasance, fraud or other misconducts specified in section 388B of the Companies' Act, 1956. The Department of Company Affairs are, however, being requested to examine the matter further in the light of the provisions of the Companies Act.



(c) In view of the proviso to article 125 (2) of the Constitution the rights of a Judge of the Supreme Court in respect of pension cannot be varied to his disadvantage after his appointment. It would not, therefore, be permissible for the Central Government to discontinue payment of pension to Shri B. P. Sinha, former Chief Justice of India.

**श्री जार्ज फरनेन्डो :** अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि मंत्री महोदय ने संविधान का ही आधार यहां पर लिया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले कई वर्षों से पार्लियामेंट की कई समितियों ने, पब्लिक एकाउंट्स समिति ने, एस्टीमेट्स समिति और पब्लिक ग्रैंड-टेकिंग समिति ने ऐसी सिफारिशें नहीं का हैं कि जो अफसर हैं वह रिटायर होने के बाद निजी कंपनियों में नौकरियां न लें, इसके बारे में सरकार को कोई अपनी नीति बनानी चाहिए क्योंकि अगर यह तौर तरीका चलता रहा तो इन अफसरों के सरकारी नौकरियों में रहते हुए कई किस्म के रिश्ते इन कंपनियों के साथ जम जाते हैं ? तो आज जब यह अदालत के और वह भी सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व चीफ जस्टिस के बारे में मामला हम लोगों के सामने आया है तो क्या संविधान में अगर कोई जरूरी तरमीम करने की आवश्यकता हो तो वह तरमीम करके ऐसी परिस्थिति फिर कभी हमारे देश के सामने न आवे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के बारे में कोई एक अदालत इस किस्म की टीका टिप्पणी करे, क्या यह काम करेंगे ?

**श्री बिद्याधरन शुक्ल :** माननीय सदस्य ने जो अफसरों के बारे में कहा मैं समझता हूँ वह बिलकुल ठीक कहा है कि अफसर यदि सरकारी नौकरियों में काम करने के बाद और तुरन्त रिटायर होने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना चाहें तो उससे हो सकता है कि इस तरह की प्रवृत्ति फैल जाय कि वह सरकारी नौकरी में रहते वक्त

प्राइवेट कंपनी वालों को कुछ फायदे दे और बाद में उन के यहाँ नौकरी करे। इसको रोकने के लिए हमने जो इन्तजाम किया है उसके अन्तर्गत जिन अफसरों को पेंशन मिलती है उनके ऊपर यह रोक लगाई गई है कि बिना सरकार की अनुमति पाये वह किसी भी प्राइवेट कंसर्न में रिटायर होने के बाद दो साल तक नौकरी नहीं कर सकते। दो साल बाद तक नौकरी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह की रोक हम ने लगा रखी है। इसलिए जो भी पेंशनबल जाँस हैं उस पर काम करने वाले अफसर रिटायर होने के दो साल के अन्दर नौकरी करना चाहें तो वह हमारे पास दरखास्त देते हैं उनकी दरखास्त को हम लोग देखते हैं और यदि वह किसी ऐसी कंपनी के साथ है जिससे किसी तरह का सम्बन्ध उसके कैरियर में नहीं रहा है और कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, उनको अनुमति दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं।

जहाँ तक जजेज का सवाल है वह बड़ा जटिल सवाल है। जहाँ तक उन की पेंशन को घटाने या बढ़ाने का सम्बन्ध है, संविधान में यहाँ साफ लिखा गया है कि उसे घटाया नहीं जा सकता है जिससे कि उस जज को नुकसान हो और वह इसलिए रखा गया है कि उसकी स्वतंत्रता के ऊपर किसी तरह की बाधा न पहुँचे। यदि सरकार के हाथ में, किसी भी सरकार के हाथ में यह अधिकार आ जाय कि जज के रिटायर होने के बाद उस को सजा के तौर पर उसकी पेंशन घटा दी जा सके तो उससे हो सकता है कि जजेज के मन में इस तरह की भावना हो कि हम जैसा काम करते हैं उसमें हमारे रिटायर होने के बाद सरकार हमारी पेंशन घटा सकती है, तो उसकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ सकती है, इसलिए संविधान में यह काम किया गया ताकि उसके मन में यह भावना न हो। जहाँ तक

इस बात का सम्बन्ध है यह दुर्भाग्यपूर्ण बात जिसके बारे में प्राज्ञ प्रश्न उठाया गया है पर ऐसी बातें मैं प्राशा करता हूँ कि प्रागे नहीं होंगी। परन्तु जैसा मैंने अपने मूल उत्तर में कहा इसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहें हैं कि इस बारे में कोई कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं।

श्री जज फरनेन्डोज : मेरे प्रश्न को शायद मंत्री जी समझ नहीं सके या मेरे से कहने में कोई गलती रह गई। मैं यह पूछ रहा था कि संविधान में ऐसी तरमीम क्यों न की जाय कि वह जज रिटायर होने के बाद नौकरी ही न करे। उनको ऐसी पेंशन की व्यवस्था हो जिससे उनको नौकरी करने की जरूरत न हो, यह मेरा प्रश्न था।

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूँ, जब यह जजमेंट प्राया इस पर प्रापने कहा कि कम्पनी ला डिपार्टमेंट की प्राोर से कुछ देख-रेख प्राोर पूछताछ की जा रही है। क्या गृह विभाग की प्राोर से इस जजमेंट के बारे में पूरी जांच करके कि इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिनमें भले ही कम्पनी नियमों के अन्तर्गत कोई गलत काम श्री बी० पी० सिन्हा ने न किया हो, लेकिन वहां शिष्टाचार की बात प्राती है, प्राोप्राइटी की बात प्राती है, वहा उनके हाथों जो गलत काम हुआ है, उसके लिए कोई कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री बिद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जजेज की नौकरी का सवाल है रिटायर होने के बाद इसके संबंध में एक कोड आफ कान्डक्ट जजेज की कान्फ्रेंस ने बनाया हुआ है कि कोई जज जिस कोर्ट से रिटायर हो वहां प्रैक्टिस न करे, सुप्रीम कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए यह सब चीजें उस में ले डाउन हैं। बाकी प्राइवेट एम्प्लायमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस बारे में जहां तक मैं जानता हूँ उन्होंने कुछ कहा नहीं है। परन्तु जो हमारे

न्यायालयों के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं अपेक्षा तो हम करते ही हैं कि इसके बारे में वह सोच समझ कर काम करेंगे। हर चीज के बारे में कोई नियम कानून बनाया जाय, संविधान को बदला जाय यह हम उचित नहीं समझते। हम तो उन्हें जिम्मेदार समझते हैं प्राोर उनकी जिम्मेदारी मानकर उनकी भावनाओं का प्राादर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें अक्सर होती नहीं हैं।

जहां तक उनके दूसरे प्रश्न का सवाल है उन्होंने जहां तक मुझको याद है यह पूछा कि हम ने जो निर्णय हुआ है हाईकोर्ट का उसकी जांच पड़ताल करके यह तय करने की कोशिश की है कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने बताया कि हमने उस निर्णय को देखा, जांच पड़ताल की प्राोर यह कोशिश की जानने की हम लोग क्या कर सकते हैं ? इसके ऊपर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसे हम कम्पनी ला डिपार्टमेंट के पास भेजें प्राोर उनसे कहें कि वह देखें कि कम्पनी ला कानून का कोई भी उल्लंघन हुआ है तो वह कार्यवाही करें। बाकी दूसरी तरह का उल्लंघन कोई हमारी दृष्टि में नहीं प्राया है प्राोर हम इसके ऊपर कोई दूसरी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister tell us how many High Court and Supreme Court judges..... (Interruption)

SHRI S. M. BANERJEE : They retire at the age of 65; it may be 70 sometimes. I don't know how they work after that age.

MR. SPEAKER : Only some people.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister tell this House as to how many retired High Court and Supreme Court judges have accepted employment after retirement? Will the hon. Minister tell us also what is the total value of the salaries and perquisites of this gentleman, Mr. B. P. Sinha. That is part (a).

Part (b) of my question is this : I want to know whether Government's attention has been drawn to an Article, leading article, published in a Calcutta Weekly, *Darpan* in its issue date the 28th March against the former Law Minister Shri Ashok Sen. He had taken advantage of his position and had acted against the interest of the Government and he took money from the parties against whom cases are pending before the Law Ministry.

MR. SPEAKER : What has that to do with the question ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : His action may be enquired into.

MR. SPEAKER : That portion the Minister need not answer.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I beg your pardon, Sir. It is very serious.

MR. SPEAKER : That does not arise out of this. It may be serious. You may put a separate question. Offhand, you cannot get up and put some question.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It must be expunged.

MR. SPEAKER : The Minister need not reply to that portion.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As far as the first part of the question is concerned, there is no rule or regulation by which the judges have to inform the Government when they accept any private employment. We do not have any statistics about it.

MR. SPEAKER : Normal moral conduct is there. They need not inform the Government.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I said in my earlier reply that we expect from the judges of the Supreme Court or High Courts that they will maintain their conduct in such a level so that there is no public criticism in their conduct after their retirement.

MR. SPEAKER : Sheo Narain.

SHRI JYOTIRMOY BASU : What

is the total value of the salaries and perquisites of them ?

MR. SPEAKER : He has no information. It may be Rs. 23,000; I may not be quite correct; but I think roundabout Rs. 23,000 per annum is the pension for Chief Justice, I think so, roughly.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Sir, that man is purchased at a far higher value.

MR. SPEAKER : I don't know. Now, Mr. Sheo Narain.

SHRI S. K. TAPURIAH : Why does he equate everybody with himself ?

MR. SPEAKER : Shri Sheo Narain.

श्री मृत्युंजय प्रसाद : एक बात की प्रोर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

MR. SPEAKER : I have called Shri Sheo Narain already.

श्री मृत्युंजय प्रसाद : मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं आप से एक बात कहना चाहता हूँ।

MR. SPEAKER : Shri Sheo Narain is holding the floor. I cannot ask him to sit down, Yes, Shri Sheo Narain.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मारल केरेक्टर और इंटिग्रिटी इस देश में सम्मानित होती है। मैं सरकार से भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुधि ले, अब तक आप ने जो कुछ किया, जो बनाया सो बनाया, यह कामन सेइंग है, कन्ट्री भर की यह डिमांड है कि जितने सरकारी अफसर रिटायर हों, चाहे वह जज हों चाहे कलेक्टर हों एस. पी. हों या मिलिट्री के अफसर हों, कोई हों, वह किसी प्राइवेट कंसर्न में नौकरी न करने पायें। इसके लिए सरकार तैयार है कानून बनाने के लिए या नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं समझता हूँ कि संविधान के अनुसार इस तरह का

कानून हम नहीं बना सकते। पर जो भी हम इस तरह का बन्धन लगा सकते हैं जिस से कि किसी तरह की नैतिकता का खण्डन न हो, वह बन्धन हम लगाते हैं और आगे भी लगाएंगे।

#### SHORT NOTICE QUESTION

##### Failures of Generator Units at Barauni

\*15. SHRI S. K. TAPURIAH :  
SHRI BHOGENDRA JHA :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there have been frequent failures in most of the generator units at Barauni during recent weeks resulting in reducing the already exceptionally low supply of power in North Bihar to about 25 per cent of the normal;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) the remedial measures taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) Yes, Sir. The reduction in the availability of power was approximately 30%.

(b) and (c). The failures were due to breakdown in the insulation of one generator and some trouble in the economiser tubes and draft fans of one boiler. Repairs have been effected in one unit and the other unit is under repair. Further, two generating units of 50 MW each are now under installation at Barauni. As soon as the first 50 MW unit is commissioned by end of June 1969, the power shortage conditions prevailing in North Bihar will be overcome. A transmission line is also being built to connect Gaya with Barauni via Mokameh so that breakdown of one or two generating units at Barauni may not affect the power supply in North Bihar.

SHRI S. K. TAPURIAH : As has been pointed out, the reduction in power supply is about 30 per cent and certain reasons have also been given for the

breakdown. I want to know whether the large amount of breakdowns was only because of these failures or is it spread over a number of periods and one breakdown leads to another and so on ? What is the ratio that you maintain in regard to spare parts in order to see that spare parts are available quickly and what are your future programmes to find out where the major breakdowns take place and what are the preventive maintenance steps that you are taking ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : As such the power shortage is already there and added to that the three units that were supplied by Yugoslavia were giving a lot of trouble from time to time. Normally, we keep one machine as stand-by. The power generated by two machines is not adequate. I accept it and that is why the trouble was there.

SHRI S. K. TAPURIAH : The Minister just now said about the faulty machines supplied by Yugoslavia. I want to know (a) what compensation you have received and whether you have applied for it or whether it is under negotiation with the suppliers, and (b) since such breakdowns have become very frequent not only at Barauni but in a number of power stations all over the country resulting in the loss of production especially in those units where there has to be a continuous flow, will the Government consider the question of giving compensation to the industrial consumers ? There was a time when the private sector was running generators they used to pay compensation to the industrial consumers for the period of breakdown in respect of the loss that they have suffered. May I know whether the Government will direct these generating stations to pay compensation to the agricultural and industrial consumers for the periods of breakdown and for the loss they have caused to them ?

DR. K. L. RAO : These machines have got a period of guarantee. During this period the repairs have been done at the expense of the suppliers, namely, Yugoslavia. But now the guarantee period is over and any further repairs that we do will be at our expense. Regarding the

guarantee of power, it is not possible for us to give because we do not have all-India grid connected with various stations.

For example, in Barauni, we are expecting to connect it with Gaya, as my colleague has said. If that line is put in, even if there is a breakdown, still power can be supplied. This line is expected to be completed in another two or three months. When that line is completed, there will be certainty of supply.

Similarly in other parts of India, the guaranteed type of supply will have to be postponed for some period till we are able to have sufficient number of lines in the country.

**SHRI S. K. TAPURIAH :** That is not the answer to my question. My question says this : Just as it was done in the past in respect of compensation to consumers for the loss they suffer because of breakdown will Government reintroduce this policy of compensating the consumers, industrial or agricultural, for the loss they suffer during the period of breakdown due to lack of maintenance, repairs etc, whatever it may be ?

**DR. K. L. RAO :** That is exactly what I answered. I do not know what exactly he has in view when he mentioned about the past. In big cities like Calcutta, Madras or Bombay, that is possible. But when you are taking the country as a whole, it is not possible to ask for guarantee at this stage. First of all we must have duplicate lines and then we must have connections with various States so that if one power station fails, power can be supplied from the others. Therefore, it is not possible to guarantee for anybody to pay compensation at this stage.

**SHRI S. K. TAPURIAH :** If duplication was there, compensation will not arise. What are they going to do now ?

**श्री मृत्युंजय प्रसाद :** अध्यक्ष महोदय, मुझे फरवरी, मार्च और अप्रैल तक काफी दिनों तक उत्तर बिहार में रहना पड़ा—मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ—वहाँ पर

शाम को साढ़े 6 बजे के करीब बत्ती बन्द हो जाया करती थी और फिर रात को दो बजे या सुबह तक घाती थी जबकि किसी को उसकी जरूरत नहीं रहती। किसी को इस बात का पता नहीं रहता कि कब बिजली चली जाएगी और कब आएगी। मैंने बारहा पूछ-ताछ की, इंजीनियरों से भी पूछा लेकिन कोई साफ जवाब नहीं। यह बात भी उस समय की है जब कि कोई बड़ा ब्रेक-डाउन नहीं था। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप बिहार एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यह सुझाव देंगे कि जब कभी ऐसी स्थिति हो कि उन्हें ज्यादा दिनों तक रोक रोक कर बिजली की सप्लाई देनी पड़े तो वे पहले से एनाउन्स कर दें घोषणा कर दें कि इतने घंटे बिजली की सप्लाई इस दिन मिलेगी और बाकी दिन नहीं मिलेगी या इतने दिनों तक इतने घंटे बिजली बन्द रहेगी ताकि लोग उसी के अनुसार अपना इन्तजाम कर लें। वरना आप दो बजे सुबह बिजली देते हैं और वह भी जाड़ों की रात में, शाम को देते नहीं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है।

**DR. K. L. RAO :** In North Bihar, we are short of power as compared to the demand. The transmission lines there are also inadequate. In fact, we are having a half hour discussion today on the subject when I will be able to give more information.

I quite appreciate what the hon member has said. When the load is very heavy specially during evening hours, this occurs. I think the only solution is to introduce more power and better transmission lines.

**श्री मृत्युंजय प्रसाद :** अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि क्या आप उनको सुझाव देंगे कि जब कभी कहीं पर बिजली सप्लाई की राशनिंग करनी पड़े तो वे उसकी इतना पहले से ही पब्लिक को दे दें, उसकी घोषणा कर दें कि हफ्ते में किस सब-स्टेशन से कितने दिन सप्लाई बन्द रहेगी और किसकी जारी रहेगी ?

DR. K. L. RAO : That can be done. We will find out.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Though the Government of India have taken credit for having increased power production in the country very much, from the hon. Minister's ans., we find that that is not so. In some States like MP, they have surplus power and do not know how to consume it while in others, they do not have enough of it. This Barauni plant is a thermal plant, not a hydro-electric one. If it were a hydro-electric plant, they would plead insufficiency of water supply when supply is cut down. But in Barauni, there is abundant coal supply, no dearth of it. Will Government take particular care to see that such plants are so managed that this kind of reduction or failure of supply does not take place because raw material is there in plenty.

DR. K. L. RAO : I have submitted already that Barauni station is an isolated station; it is not connected with any other system. The power also is very small quantity compared to the needs of Bihar. There are only three units of 15 mws each. I accept that there has been a slip in the provision of power for North Bihar.

श्री क० ना० तिवारी : मैं दो बातें जानना चाहता हूँ। नार्थ बिहार को गंडक प्रोजेक्ट से पावर मिलती है और बरोनी से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या डिमान्ड है नार्थ बिहार की? कितनी सप्लाई करने की पोजीशन में हैं मैसालोटन से और कितनी बरोनी से?

DR. K. L. RAO : There is no power in Gāndak available; a small station had been constructed to supply power in the project construction stage. When the regular power station is completed and it generates some power it will go to Nepal. India will not get and power from the Gandak project.

श्री क० ना० तिवारी : भ्राजकल नर-कटिया गंज, रामनगर, बगहा को सप्लाई हो रही है मैसालोटन से और उधर बरोनी से मोतिहारी, बेनिया और दूसरी जगहों को

सप्लाई कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि नार्थ बिहार में कितनी डिमान्ड है और कितनी सप्लाई है? यदि मैसालोटन से कन्टीन्यू करेगे तो कितनी वहाँ से और कितनी बरोनी से करेगे? या सभी जगह बरोनी से ही सप्लाई करेगे, और कितनी डिमान्ड है और कितनी सप्लाई है?

DR. K. L. RAO : I thought I could speak on this during the half an hour discussion later on. In Gandak we do not have any power. We have a power station now to supply power for the construction of the project there; there is a very little quantity available which is being sent to other places. Otherwise, it is not a guaranteed power source. In Barauni we have three units of 15 mws each and the total power supply at present including some other sources comes to 34 mws as against the demand of 40 mws; there is therefore this shortage. There is a proposal to have two machines to generate 50 mws and when it is implemented there will be more supply of power.

SHRI S. S. KOTHARI : Would the shortage of power affect the production in Barauni Refineries? Have the Barauni Refineries put up any proposal that they would like to generate their own electricity?

DR. K. L. RAO : The Barauni refinery is actually generating its own power and they are supplying to the grid about 2-3 mws.

श्री सु० शं० साँ : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहाँ अभी पूरे तौर पर गाँवों और कस्बों में बिजली सप्लाई की गई है वहाँ का जो लोकल स्टाफ है वह करप्शन की वजह से जो पावर लाइन है उस को बन्द कर देता है कुछ समय के लिए चूँकि वहाँ पर ऐसा है कि कुछ इन्जन पावर के लगे हुए हैं और कुछ इन्जन तेल से चलने वाले लगे हुए हैं। तो तेल से इन्जन चलाने वाले जो प्रोप्राइटर्स हैं वह लोकल प्रचारिटीज को रिक्वट दे कर पावर लाइन रुकवा देते हैं। तो क्या मंत्री जी उस तरफ ध्यान देंगे

कि इस किस्म का करप्शन जो बिजली के प्रन्दर है कि वह महज फायदा उठाने के लिए तेल से इंजन चलाने वाले पावर लाइन को रुकवा देते हैं, जैसा मेरे साथी ने बताया कि शाम 6 बजे से लेकर दो बजे तक बिजली बन्द रहती है, इस का कारण यह है कि वकिंग टाइम में आयल इंजन वाले लोकल थ्रारिटीज को रिस्वत देकर उस लाइन को वक्तन-फ्रवक्तन कटवा देते हैं। तो यह करप्शन दूर हो सके और पावर लाइन सही तौर पर काम कर सके ऐसा इन्तजाम मंत्री जी करने ?

DR. K. L. RAO : I am not aware of this ; I shall make enquiries about it.

श्री श्री सिंह सहगल : आपने ग्रिड सिस्टम लागू किया है। विहार से लेकर और दूसरे प्रान्तों को जोड़ने में आप को कितना वक्त लगेगा जिस में इस प्रकार का ग्रिड सिस्टम ग्राल इण्डिया में कर सकें ?

MR. SPEAKER : That is a different question entirely. Papers to be laid.

#### WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

##### Amalgamation of I. A. C. and Air India

\*1175 SHRI J. B. SINGH :  
SHRI SHRI GOPAL SABOO :  
SHRI SHARDA NAND :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount will be saved if the Indian Airlines and Air India are amalgamated ;

(b) If so, to what extent ;

(c) whether Government propose to amalgamate these Corporation ; and

(d) If not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN

SINGH) : (a) to (d). While there is need for close cooperation and coordination between the two air corporations, which is sought to be achieved by a common board of directors, there is no proposal at present to amalgamate the two, Amalgamation, it is felt, may lead to unwieldiness without commensurate gain.

##### Faculty of Pharmacy

\*1176 SHRI R. K. AMIN :  
SHRI D. R. PARMAR :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a separate Faculty of Pharmacy needs to be introduced in the Universities according to the view held by the 20th Conference of All India Pharmaceutical Congress ; and

(b) if so, reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). The Indian Pharmaceutical Congress, at its 20th Conference held in December, 1968, has recommended that for the development of pharmaceutical education and research along correct lines, there should be a separate faculty for this subject-field in our universities.

The recommendation is being referred to the University Grants Commission and the All India Council For Technical Education for consideration in consultation with universities.

Indian Institute of Technology, Kanpur

\*1178. SHRI A. SREEDHARAN :  
SHRI K. LAKKAPPA :  
SHRI YASHPAL SINGH :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 3,000 employees of the Indian Institute of Technology, Kanpur are on daily rates basis for the last three years ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken or proposed to be taken to make their service on regular basis ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) No, Sir. The Institute had 2193 employees on 31-3-1969, of whom only 135 persons are working on daily wage basis for the last three years.

(b) and (c). Since the Institute is still in a developmental stage, daily wage workers have been employed for construction, horticulture, sanitation and other works recording to the actual needs from time to time. These workers are considered for regular appointment against the vacancies available.

**दिल्ली प्रशासन के कार्यों में केन्द्र द्वारा तथाकथित हस्तक्षेप**

\*1179. श्री श्रीकार सिंह :

श्री बंश नारायण सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनसंघ के कुछ संसद सदस्यों का एक शिष्टमण्डल उनसे मिला था तथा उन्होंने यह शिकायत की थी कि दिल्ली प्रशासन के कार्यों में केन्द्रीय सरकार अनुचित हस्तक्षेप करती है;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल द्वारा क्या-क्या मांगें रखी गई थी; और

(ग) उन मांगों के बारे में शिष्टमण्डल को क्या आश्वासन दिया गया था ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनसंघ के संसद सदस्यों का एक शिष्टमण्डल गृह मन्त्री से मिला था। शिष्टमण्डल ने विभिन्न विषयों, जैसे नई दिल्ली नगरपालिका के

लिए नामजदगी, नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली प्रशासन के बीच सम्बन्ध, दिल्ली प्रशासन के प्रति केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण इत्यादि, पर अपने विचार रखे। गृह मन्त्री ने उनको आश्वासन दिया कि दिल्ली प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण सदैव उदार तथा सहयोगपूर्ण रहा है और रहेगा।

**Allotment of Funds for Social Education**

\*1180. SHRI GADILINGANA GOWD Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Group at the Centre recommended an outlay of Rs. 22.80 crores for Social Education including expansion of Libraries etc. in the States but the States have only allocated Rs. 7.42 crores for the purpose ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken in this direction ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir, the Planning Group had recommended an outlay of Rs. 22.80 crores, but in the draft proposals of the States the corresponding allocations added up to Rs. 7.42 crores only.

(b) and (c). The reasons have not been intimated to the Central Government. Presumably, this is due to limited financial resources of the States and greater emphasis on other branches of education. However, the attention of the States has been repeatedly drawn to the need for speedier eradication of illiteracy.

**भारत में विदेशी धार्मिक मिशनों का भारतीयकरण**

\*1181. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :



क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी धार्मिक मिशनों का उत्तरोत्तर भारतीयकरण करने की दिशा में गत 21 वर्षों में प्रति वर्ष सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला और इस बारे में भावी योजना का व्योरा क्या है,

(ख) गत 21 वर्षों से भारत में कितने विदेशी धार्मिक मिशन सक्रिय रहे हैं और उनके माध्यम से कितना विदेशी धन भारत में आया;

(ग) प्रति वर्ष इन मिशनों के उत्तरोत्तर भारतीयकरण का क्या परिणाम रहा है; और

(घ) क्या सरकार इन्डियन नेशनल चर्च के ज्ञापन पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृहकार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल :) (क) और (ग). विदेशी ईसाई धर्म प्रचार संस्थाओं के उत्तरोत्तर भारतीयकरण के उद्देश्य प्राप्त के लिए अब केवल ऐसे ही नये विदेशी पादरियों को अनुमति दी जाएगी जो विशिष्ट योग्यताएं रखते हों अथवा विशेष अनुभव वाले हों, और इस कार्य के लिए उपयुक्त भारतीय उपलब्ध न हों। यह निर्णय सन् 1954 में लिया गया था। एक विवरण जिसमें सन् 1953 से भारत में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों की संख्या बताई गई है सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रख दिया गया। रेसिए संख्या LT—806 /69] विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों की संख्या में धीरे-धीरे कमी हुई है।

भविष्य में इस सम्बन्ध में इसी नीति का अनुसरण करने का विचार है।

(ख) सन् 1953 से भारत में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों की संख्या के बारे में सूचना उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में दे दी है। इससे पहले के वर्षों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

जहां तक विदेशी धन का सम्बन्ध है, ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं द्वारा प्राप्त बाहर से भेजी गई राशि का आदान-प्रदान लेखा में अलग से वर्गीकरण नहीं किया जाता है। ये बाहर से आने वाली राशियाँ सामान्य शीर्ष "निजी दानों" के अधीन आती हैं। इस शीर्ष के अधीन एक उप-शीर्ष में धर्म-प्रचारकों, धर्मार्थ संस्थानों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्तियों का लेखा रखा जाता है। इस उप-शीर्ष के अधीन 1966 और 1967 में रखे गए लेखे में पी. एल. 480 के शीर्ष II और III तथा राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना के अधीन प्राप्तियाँ भी सम्मिलित हैं। जुलाई, 1955 से 1967 तक की अवधि में, जिसकी सूचना उपलब्ध है, उक्त उप-शीर्ष में रखे गए विदेशों से प्राप्त राशियों के लेखे का एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रख दिया गया। रेसिए संख्या LT—806/69]

(घ) इन्डियन नेशनल चर्च से कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और उनमें उल्लिखित बातों पर यथोचित ध्यान दिया गया है।

त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान

\*1182. श्री प्रकाशचौर शास्त्री :

श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को उसका समुचित स्थान देने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या संस्कृत की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उनके मन्त्रालय का इस सम्बन्ध में कुछ नये निर्णय करने का विचार है।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त वरुण) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में संस्कृत के अध्ययन के महत्व को सरकार समझती है। शिक्षा आयोग तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की वर्तमान विचारधारा यह है कि संस्कृत तथा अन्य श्रेष्ठ भाषाओं को त्रिभाषा सूत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न कारण-वश इस सूत्र को केवल आधुनिक भारतीय भाषाओं तक ही सीमित रखना पड़ा। फिर भी, भारत सरकार इस मामले पर और विचार कर रही है, इसी बीच, संस्कृत के विकास और प्रचार के लिए चौथी आयोजना की अवधि के दौरान अधिक राशि नियत की गई है।

**World Tourists' Attraction to wild life of India**

\*1183. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only one per cent of world tourists and 3.5 per cent of the tourists in India are only attracted by the wild life of India which has fascinating population of wild animals and birds ; and

(b) if so, the reasons why proper facilities are not provided to attract more tourists to visit our National Parks ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) While no statistics of tourists visiting game sanctuaries are kept, it is undoubtedly true that Indian wild

life is viewed by far too small a number of tourists, both domestic and foreign.

(b) Within available resources, efforts, are being made to improve facilities in game sanctuaries. A provision of Rs. 50.00 lakhs has been made in the Fourth Five-Year Plan for this purpose. Besides, as Forests is a State subject, co-ordination with the State Forest Departments is also necessary.

**दिल्ली में बिक्री-कर अधिनियम का सरलीकरण**

\*1184 श्री कंधार लाल गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कह सच है कि दिल्ली में बिक्री कर अधिनियम को सरल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इसके किन पहलुओं पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो कब और किन पहलुओं के बारे में ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री विचारण शुक्ल) : (क) से (घ). दिल्ली में लागू वर्तमान बिक्री-कर कानून को एक नये अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करने का एक प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। दिल्ली प्रकाशक अधिनियम, 1966 की धारा 22(1)(क) के अधीन महानगर परिषद् को विचार-विमर्श करने तथा ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने का अधिकार है। परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित कोई निश्चित प्रस्ताव भारत सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

**दिल्ली में चुंगी पद्धति का समाप्त  
किया जाना**

\*1185. श्री महाराज सिंह भारती :  
क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह  
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क  
परिवहन को तेज और सुगम बनाने हेतु  
दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र  
में चुंगी पद्धति को समाप्त करने का प्रस्ताव  
किया है ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को दिल्ली  
नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन  
किये बिना क्रियान्वित नहीं किया जा  
सकता ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त  
अधिनियम में समुचित संशोधन करना  
चाहती है ?

संसद कार्य और नौबहन तथा परिवहन  
मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क)  
संभवतया प्रश्न उस सीमा-कर  
का उल्लेख करता है जिसे दिल्ली नगर  
निगम दिल्ली में लाये जाने वाले माल पर  
लगाती है। इस कर को समाप्त करने के  
लिये दिल्ली प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त  
नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते  
हैं।

**Primary Education Commission**

\*1186. SHRI SHRI CHAND GOYAL :  
Will the Minister of EDUCATION AND  
YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the teachers of the  
Primary Schools of the country have  
demanded the appointment of a Primary  
Education Commission ;

(b) whether there are problems of  
the Primary teachers which need an exa-  
mination ; and

(c) the reaction of Government to  
the demand ?

THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF EDUCATION  
AND YOUTH SERVICES (SHRI  
BHAKT DARSHAN) : (a) to (c).  
Teachers of Primary Schools have been  
demanding the appointment of a Primary  
Education Commission ; but the func-  
tions proposed to be entrusted to the  
Commission have been different. The  
Kothari Commission has recently made  
a comprehensive study of all the various  
problems of education, including that of  
Primary education. The appointment of  
a fresh Commission for problems of  
primary education is, therefore, not  
considered to be necessary.

**पाकिस्तानी लोगों द्वारा ले जाये  
गये पशु**

\*1187. श्री भारत सिंह चौहान :  
श्री रा० कृ० बिरला :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की  
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर,  
और दिसम्बर, 1968 में तथा जनवरी,  
1969 में पश्चिम बंगाल में मालदा जिले  
के रविपुर बूलमादी सीमा से पाकिस्तानी  
बड़ी संख्या में पशुओं को पाकिस्तान ले  
गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने  
पाकिस्तान राइफल के सशस्त्र कर्मचारियों  
की सहायता से सीमा का उल्लंघन किया  
था ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की  
गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार  
क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव  
चव्हाण) : (क) और (ख). दिसम्बर,  
1968 के महीने में पूर्व पाकिस्तान राइफल  
की सहायता से पाकिस्तानी राष्ट्रक जिला

मालदा के थाना हबीबपुर के अन्तर्गत अशरफपुर फालीमारी सीमा (न कि रविपुर फूलमासी सीमा) क्षेत्र से 136 पशुओं को ले गये। इस क्षेत्र से नवम्बर, 1968 अथवा जनवरी, 1969 के महीनों के दौरान कोई पशु नहीं ले जाये गये।

(ग) सीमा सुरक्षा दल तथा स्थानीय पुलिस ने इस क्षेत्र में निगरानी कड़ी कर दी है।

**सोफिया युवक समारोह में टिप्पण लेनिन द्वारा भारत को स्वतन्त्रता की प्राप्ति**

\*1188. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस समाचार की जांच करायेगी कि सोफिया में नवें युवक समारोह में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मण्डल के एक सदस्य ने भारत-उज्बेक मैत्री संघ द्वारा आयोजित समारोह में कहा था कि "भारत को लेनिन के कारण स्वतन्त्रता मिली" ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी. के. झार. बी. राव.) :** (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो कि सोफिया के नवें युवक समारोह में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडल के किसी सदस्य ने ऐसी कोई टिप्पणी की थी।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

**Police Excesses In Minicoy**

\*1189. SHRI BABURAO PATEL :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) The names and designations of

the Police Officers who practised repression on the residents of Minicoy Island and the nature of atrocities committed by them with names of ten prominent victims ;

(b) The details of the findings of the report submitted by the Senior Police Officers who inquired into the affairs ; and

(c) the steps taken against the culprits ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). A statement is laid on the Table. [Placed in Library. See. No. LT 807, 69].

**India's Membership In Berne Convention**

\*1190. SHRI ONKAR LAL BERWA :  
SHRI N. R. LASKAR :  
SHRI R. BARUA :  
SHRI CHENGALRAYA NAIDU :  
SHRI RABI RAY :  
SHRI SRINIBAS MISRA :  
SHRI S. M. KRISHNA :  
SHRI S. KUNDU :  
SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH :  
SHRI RAMAVTAR SHARMA :  
SHRI R. V. NAIK :  
SHRI J. MOHAMED IMAM :  
SHRI K. P. SINGH DEO :  
SHRI LOBO PRABHU :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U. K., one of the principal beneficiaries of the Berne Convention on Copyright, has declined to relax its copyright hold and accept the concessions formulated by common agreement for the benefit of the developing countries;

(b) If so, whether the U. K. Government has conveyed to the Indian Govern-

ment that it did not intend admitting the application of the protocol regarding developing countries annexed to the Stockholm version of the Berne Convention ; and

(c) If so, whether the Government of India have decided to discontinue its membership of the Berne Convention.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The matter is under consideration.

#### Port Development Programme

\*1191. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA :  
SHRI MUHAMMAD SHERIFF :

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that his Ministry had submitted to the Planning Commission a Port development programme to be included in the Fourth Plan ;

(b) If so, whether the same has since been approved ; and

(c) The broad details thereof ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) :  
(a) Yes, Sir.

(b) and (c). The proposals have not yet been finalised as the Fourth Plan has still to be approved.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया को  
ग्वाल्थर में प्लॉट का आवंटन.

\*1192. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह-  
कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वाल्थर के जयविलास महल की भूमि के एक प्लॉट को राजमाता

विजयाराजे सिंधिया को प्लॉट करने की केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Text Books in Indian Languages .

\*1193. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR :  
SHRI LATAFAT ALI KHAN :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the progress made so far in the preparation of standard text books in Indian languages on technical and scientific subjects ; and

(b) what amounts have been given to the States and the Universities for this purpose ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Presumably, the Member is referring to the standard text books at university level. Information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

(b) The following grants were made available during the year 1968-69 to State Governments for production of text books at university level in regional languages :

<i>Name of State Government</i>	<i>Amount of grant Rs.</i>
Rajasthan	5,00,000.00
Bihar	5,00,000.00
Uttar Pradesh	2,00,000.00
Haryana	2,00,000.00
Andhra Pradesh	10,00,000.00
Madhya Pradesh	1,00,000.00
Tamil Nadu	1,72,000.00
West Bengal	32,778.00
Kerala	43,050.00
Mysore	5,00,000.00
Maharashtra	1,00,000.00
Assam	1,00,000.00
<b>Total</b>	<b>34,47,828.00</b>

No separate allocation out of this grant was earmarked for production of standard text books on technical and scientific subjects. Subject wise allocation has to be made by the State Governments in consultation with the universities.

**Programme of Conservation and Chemical Preservation of Buddha Images and Paintings at Bamiyan (Afghanistan)**

\*1194. SHRI HARDAYAL DEVGUN :  
SHRI BENI SHANKER  
SHARMA :  
SHRI BAL RAJ MADHOK :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the Archaeological Survey of India will carry out programme of conservation and chemical preservation of the world-famous Buddha images and paintings at Bamiyan in Afghanistan during 1969-70;

(b) if so, the details of the programme chalked out with the estimated expenditure ; and

(c) who is going to bear the cost of the programme ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) (a) Yes, Sir, it is proposed to start the work of conservation and chemical preservation of the Buddha images and paintings at Bamiyan during 1969-70,

(b) The programme includes : (i) structural repairs such as diversion of the course of water that flows on the rock-facade, filling in of the cracks and fissures in the rock-facade, repairing of the damaged portions of the Buddha images and the caves around them and (ii) chemical preservation of the paintings involving the cleaning of the painted surface, stabilization of the plaster carrying the painting included the filleting of the broken edges and application of a preservative over the painting. The estimated expenditure on work amount to Rs. 20.30 lakhs.

(c) It is expected that UNESCO will assist in this project. The Afghan Government is likely to bear the local costs. Negotiations are a foot.

**Age limit for recruitment to Government Service**

\*1195. SHRI D. C. SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission has considered the question of revising age limit for recruitment to Government service ;

(b) whether the entire question of personnel appointments, transfers and retirement and a number of suggestions to improve the employment position have also been considered ;

(c) if so, what are their recommendations ; and

(d) the recommendations accepted by Government and the steps taken to implement the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). The Administrative Reforms Commission have not yet finalised their views on these items.

**Central pay scales to Himachal Pradesh non-gazetted employees.**

\*1196. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Himachal Pradesh non-gazetted staff through their non-Gazetted Service Federation have represented to the Centre for the grant of Central pay scales ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS : (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) (a) Yes Sir.

(b) The demand was not accepted.

**Archaeological Investigations in  
Central Asian States**

\*1197. SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government have any plans for undertaking archaeological investigations in the Central Asian States ;

(b) if so, whether the concerned Governments have been approached ; and

(c) their reactions thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) The Archaeological Survey of India is investigating the possibility of undertaking archaeological excavations at some prospective sites in Iran, Afghanistan and Soviet Central Asia.

(b) and (c). The Archaeological Survey of India has informally approached the Director Generals of Archaeology in Iran and Afghanistan as also the Chairman of the Soviet Committee on the Study of Civilization of Central Asia and Director of the Institute of Asia, Academy of Sciences of the U.S.S.R. Reactions of the parties addressed are awaited.

**संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग**

\*1198. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :  
श्री ब्रिजिबाबू :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी को माध्यम के रूप में अपना लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हिन्दी को कब तक परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) संघ लोक सेवा आयोग की

परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं को अपनाये जाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रिजिबाबू शुक्ल) : (क) से (ग). संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू करने के निर्णय को बाद में अंग्रेजी के अनिश्चित संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को माध्यम के रूप में संघ लोक सेवा आयोग की अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए लागू करने के निर्णय में बदल दिया गया था। अक्टूबर, 1969 में होने वाली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में निबन्ध और सामान्य ज्ञान के पत्रों के उत्तर अंग्रेजी या संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक में, जिनमें हिन्दी भी शामिल है, दिये जा सकते हैं। 1964 से 'निबन्ध' और 'सामान्य ज्ञान' के पत्रों के लिए असिस्टेंट ग्रेड और निम्न श्रेणी लिपिक की परीक्षाओं के लिए हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग करने की भी आज्ञा दी जा चुकी है।

आशा की जाती है कि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 1969 में होने वाले अनुभव से आगे चल कर आयोग क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरे विषयों के भी पत्रों के उत्तर लिखने की आज्ञा दे देगा। इस समय यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है कि यह कब तक किया जा सकेगा।

**Arrangements Made During P. M.'s  
Election Tours**

\*1199. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether his attention has been

drawn to the reports that during the Prime Minister's recent election tours, local authorities in various States had made certain arrangements like setting up stockades, fencings etc. and posting policemen on round-the-clock duty;

(b) whether these arrangements were paid for by the concerned State Governments; and

\* (c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) Yes, Sir.

(b) and (c). Arrangements for the protection of the Prime Minister and for maintenance of order in any public assembly are made by the State Governments. Information regarding the expenditure on provision of rostrums, lighting, loudspeakers etc. in connection with Prime Minister's election meetings is being ascertained from the State Governments concerned.

#### Recognition Of Past Government Service Of Displaced Persons

\*1200. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to recognise past Government service of displaced persons from Pakistan, who have had to come to India under compelling circumstances, for the purpose of continuity in service for pensionary and other terminal benefits ;

(b) if so, how many cases of displaced persons from West-Pakistan and East Pakistan, separately since 1948, have been considered ;

(c) how many more such cases from both part of Pakistan are under consideration of Government; and

(d) what steps are being taken to expedite those cases and if no steps have been taken, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) to (d). A statement is placed on the Table of the House.

#### STATEMENT

According to the information furnished by the Ministry of Finance who are primarily concerned with the subject matter of the question, the position is as follows :—

(a) The permanent displaced Government servants belonging to the former Provincial Governments of Sindh or the N. W. F. P. who migrated to India before 31st December, 1951 owing to peculiar circumstances prevailing after the 15th August, 1947 in Sind and after the 1st March, 1947 in the N. W. F. P. and were appointed in the Government of India before attaining the age of 55 years have been allowed full pension calculated on the basis of qualifying service rendered in Sind or N. W. F. P. combined with the service rendered under the Government of India whether in temporary or permanent capacity.

(b) Government of India have no scheme for admitting to pension displaced Government servants belonging to the former Provincial Government of undivided Bengal who opted for service in Pakistan and who migrated to India on or after 15-8-1947. No information is available in regard to the number of displaced Government servants belonging to Sind or N. W. F. P. which were considered since 1948. These persons became eligible for pension from the date of retirement from the service of the Government of India and the information will, therefore, have to be collected from the various pension sanctioning authorities scattered all over India and will entail much time and labour.

(c) and (d). No information in regard to the number of pension cases pertaining to displaced Government servants from Sind and N. W. F. P. which are under consideration is available. The pension cases of displaced Government servants like other Central Government servants are processed in the normal manner in the sense that action to finalise a pension case is initiated before 12 months of the date of retirement of the Government



servant. The pension cases are finalised by the pension sanctioning authority concerned.

**Mining Engineers seeking Employment  
Abroad.**

6742. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the number of Indian Mining Engineers who have secured employment in foreign countries during the last two years, country-wise ;

(b) the number of Mining Engineers still unemployed in the country and the reasons therefor ;

(c) the rate at which we are turning out annually new Mining Engineers through the various institutions and the steps taken to check this supply seeing that there is no demand for them in the country ; and

(d) the reasons why Government do not survey annually the requirements of Scientists, Engineers and Specialists in various fields and inform candidates and their parents of the demand from year to year ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) According to the information available, no Indian mining engineer has secured employment in foreign countries during the last two years through the efforts of the Ministries/Departments of the Government of India.

(b) 325 mining engineers were on the live register of the Directorate of Employment on 31st December, 1968.

(c) Admissions to the degree course in mining engineering were reduced to 77 students in 1968-69 as against 140 in the previous year.

(d) The demand for mining engineers is constantly under review and admissions to the institutions are being related as far as possible to the estimated demand.

**Flying Clubs**

6743. SHRI BABURAO PATEL :  
SHRI R. K. BIRLA :  
SHRI MANUBHAI PATEL :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of Flying Clubs in the country and their location with subsidy and subvention paid annually by Government, club-wise ;

(b) the names and qualifications of Instructors at these clubs, club-wise, and the number of licensed pilots turned out by them annually and club-wise during the last two years ;

(c) how many of such pilots were absorbed in commercial flying during the last two years ;

(d) whether any other Government institute for training commercial pilots exists in addition to these flying clubs, and if not, the reasons therefor ;

(e) the total expense of a trainee in these clubs till he qualifies himself to get a licence for commercial flying ; and

(f) the basic age and educational and other qualifications necessary to take up training in commercial flying with the total period of training ?

THE MINISTER ON TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) There are 24 subsidised flying clubs in the country. A statement giving their names, location and the amounts received by them by way of subsidy and subvention during the years 1966-67 and 1967-68 is laid on the Table of the House [Placed in library. See No. L.T.—808/69]

Flying Clubs have to do a minimum of 800 hours of Instructional flying per year to be eligible for subsidy and subvention at prescribed rates as per statement laid on the Table of the House: [Placed in library. See No. L.T.—808/69] Where the performance of a subsidised club falls below the prescribed limit, due to circum-

tances beyond its control, its fixed subsidy is reduced *pro-rata*.

(b) and (c). Requisite information is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in library*. See No. L. T.—808 /69].

(d) No, Sir. At present, there is no such institution in the country. However, the question of setting up a full-fledged training institution to train Commercial Pilots and other categories of flight crew, is under consideration of Government.

(e) A candidate for a Commercial Pilot's licence has to complete 250 hours' flying within a period of five years immediately preceding the date of application. Flying fees are payable at Rs. 25/- per hour, or Rs. 40/- per hour, subject to certain other restrictions on the quantum of flying which can be done at subsidised rates. Details thereof are given in the statement laid on the Table of the House [*Placed in library*. See No. L.T.—808 /69].

Besides payment of flying fees, the trainees have to incur expenditure on their board and lodging and other incidentals.

(f) The requirements for issue of a Commercial Pilot's licence are laid down in Section D. Schedule II to Air Craft Rules, 1937. According to these rules, an applicant for a Commercial Pilot's Licence shall be not less than 18 years of age on the date of application. No educational qualification has been prescribed in these Rules, but a sound knowledge of English is necessary. He has also to produce, on the prescribed form, a certificate of physical fitness from an approved Medical Board, after undergoing a medical examination, in compliance with the requirements notified by the Director General of Civil Aviation, from time to time.

**Cases referred to C. B. I.  
In Gujarat State**

6744. SHRI S. M. SOLANKI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number and nature of cases referred to the Central Bureau of Investigation during the year 1968 in Gujarat State ; and

(b) the number out of them decided by the Central Bureau of Investigation during 1968 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) 41 cases relating to various allegations of demand for illegal gratification, false claim of Overtime allowance, misappropriation of Government money, evasion of payment of duty, forgery of import licences, misutilisation of stainless steel sheets imported on Actual User's licence, etc. were referred to the Central Bureau of Investigation during 1968 in Gujarat State.

(b) The position of these cases during 1968 is given below :—

- (i) Cases recommended for Disciplinary Proceedings 15 cases.
- (ii) For Appropriate Departmental Action ... 1 case,
- (iii) Sent up for Trial In Court and Ended in Conviction. 1 case.
- (iv) investigation ending at the end of 1968. ... 24 cases.

**Visas Granted to Tourists Coming  
from Israel**

6745. SHRI BRIJRAJ SINGH (Kotah) : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that no visas are granted to tourists coming from Israel *en route* to Nepal or the Far East ;

(b) the estimated number of such potential tourists that could be added to India thus benefiting our country's foreign exchange ; and

(c) the steps Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) No, Sir. Our Missions abroad do issue tourist visas to persons from Israel coming on private visits to India or in transit.

(b) and (c). Does not arise.

#### Indian Council for Cultural Relations

6746. SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that receptions and functions are arranged for foreign dignitaries by the Indian Council for Cultural Relations ;

(b) if so, whether liquor has ever been served to the invitees at the function ;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, whether it was served with the prior permission of Government ; and

(d) the expenditure incurred on liquor and other items served at the functions ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No such permission is necessary beyond observance of the normal excise regulations.

(d) A statement is laid on the Table of the House. [*Pleased in Library. See No. L. T.—809/69*]

#### Violation of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964

6747. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of cases that have come to Government's notice of Government's servants violating Rule 4 of the Central Civil Services (Conduct) Rules

1964, during the past three years (year-wise), *i. e.*, pertaining to employment of near relatives in private companies enjoying Government patronage ;

(b) whether a strict check is maintained to see that these rules are fool-proof ; and

(c) what other measures Government have taken to see that senior officials of Government do not misuse their official positions with regard to employment of their relatives or for their own employment in private companies while on the verge of retirement from the Government service ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHURLA) :

(a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House, as soon as possible.

(b) and (c). Government servants are expected to observe scrupulously the provisions in the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. Any violation of the provisions for taking disciplinary action against the Government servant concerned. Such action is possible only if any violation of the said rule comes to the notice of the competent authority.

As regards Government servants seeking employment with private firms while on the verge of retirement orders have been issued that no Government servant should negotiate for commercial employment while in service without the prior permission of the competent authority and such permission should not be given unless there are any special reasons for doing so. Apart from this, under Article 531-B of the Civil Service Regulations Officers of Central Civil Services, Class I are required to obtain the previous sanction of the President for acceptance of commercial employment within two years of their retirement. No pension shall be payable to any such pensioner who accepts a commercial employment within the said period without the prior sanction of the President, in respect of any period for which he is so employed or for such

longer period as the President may direct.

All requests for such permission are examined with reference to well defined criteria and decision taken after careful consideration of all relevant aspects.

**बेरी आयोग का प्रतिवेदन \***

• 6748. श्री मोठा लाल मीना : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सब है कि बेरी आयोग ने जिसने मार्च, 1967 में जयपुर में गोली-कांड पर रिपोर्ट दी है, अपने प्रतिवेदन में पुलिस कार्यवाही को जिसमें पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना शामिल है अनावश्यक बताया है और सम्बन्धित अधिकारियों को दोषी पाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) आयोग ने जोहरी बाजार और सिरेहदियोदी बाजार में गोली चलाने को बिल्कुल अन्यायपूर्ण और कोतवाली पर गोली चलाने को विनियमित व नियन्त्रित और बिल्कुल न्यायपूर्ण ठहराया है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार प्रतिवेदन का परीक्षण कर रही है ।

**Thefts in Chitra Gupta Road and Aram Bagh, New Delhi**

6749. SHRI P. ANTONY REDDY :  
SHRI G. S. REDDI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there have been a number of thefts and burglaries from the houses at Chitra Gupta Road and Aram Bagh area in New Delhi recently ;

(b) whether it is also a fact that a Police Station is located very near these areas ; and

(c) the action taken to prevent such incidents ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) Only one case of theft was reported to the Police from these areas during the period 1.1.1969 to 31.3.1969. There was no case of burglary during the same period.

(b) Yes, Sir.

(c) Patrolling is being done intensively in the area consisting of Chitra Gupta Road and Aram Bagh.

**Issue of Warrant of Tickets to Employees**

6750. SHRI P. ANTONY REDDI :  
SHRI G. S. REDDI :

Will the Minister of HMOE AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had announced in 1956 that a warrant of ticket would be issued to the Central Government employees under the Home Leave Travel concession ; and

(b) if so, the reasons why the warrants of tickets have not yet been issued ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) Yes Sir. It was stated in the original orders introducing the scheme of Leave Travel Concession to Central Government employees that it was proposed to make arrangements with the Ministry of Railways for the issue of special warrants or special tickets orders

to enable the Government servants and their families to whom these concessions are admissible to purchase railway tickets for the journeys at concessional rates.

(b) This was considered and it was decided not to pursue the proposal having regard to the fact that the issue of special ticket warrants will involve considerable additional amount of work on the part of the Railways involving considerable calculations and employment of extra staff (especially since the Government servants availing of the concession are allowed to perform the journey to home town and back by any mode of travel and by any route.)

#### **Installation of Radars during Forth Plan**

6752. SHRI RAMACHANDRA VEE-RAPPA :

SHRI K. P. SINGH DEO :

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that eight powerful radars are likely to be installed in the country during the Fourth Plan period ;

(b) if so, what would be the estimated cost and capacity of each radar ; and

(c) by what time a final decision is likely to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) A scheme for installation of eight powerful storm-warning radars along the east and west coasts of India has been included in the draft Fourth Plan of the India Meteorological Department.

(b) The estimated cost of each radar is Rs. 17.46 lakhs. These radars are capable of detecting and tracking cyclones within a radius of 400 kilometers.

(c) One radar is likely to be installed at Visakhapatnam during 1969-70. A decision on the installation of the remaining seven radars will be taken after the Fourth Five Year Plan allocation has been finalised.

#### **Construction of Bridges in Tripura**

6753. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that before Tripura's road system can become a comprehensive, inter-linked and operable net-work, at least ten major bridges are required to be built ;

(b) if so, the steps so far taken in that direction, the details of the programme, if any, for the construction of these bridges, indicating the location thereof, and by what time these bridges will be completed ; and

(c) the provision being made under 1969-70 plan and the Fourth Five Year Plan for the purpose ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) to (c). The information is being obtained from the Tripura Administration and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

#### **Cases Pending in Judicial Commissioner's Court of Manipur and Tripura**

6754. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that since 1962 at least a thousand cases relating to Tripura have all along been pending with the court of the Judicial Commissioner of Manipur and Tripura ;

(b) if so, whether Government have considered or are considering the question of setting up a separate court of Judicial

Commissioner for Tripura and if so, the decision, if any, in this regard ; and

(c) if the reply to part (b) above in the negative the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA)  
(a) No, Sir.

(b) and (c). The question of appointing a separate Judicial Commissioner for Tripura has been considered by Government but the work involved in Tripura does not justify such appointment.

#### Arms Recovered in Tripura

6755. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Statement of Tripura Chief Minister made in October, 1968 following the recovery of an arms dump with Pakistan markings, in a forest near Govindbari in Tripura, to the effect that Sangkark members were receiving training and equipment of Kachalung in East Pakistan ;

(b) the steps since taken to mop up such elements and to liquidate their activities ;

(c) how many persons have been apprehended and prosecuted in that connection ;

(d) the nature of arms and ammunition seized from them indicating their probable origin ;

(e) whether their organisational centres and operational headquarters have been traced; and

(f) if so, where and whether any of them are found to be in Pakistan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) to (f). Information is being colle-

cted and will be laid on a table of the House.

#### Selection of Candidates for Overseas Scholarships

6757. SHRI SIDDAYYA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the schemes formulated by his Ministry for the award of Overseas Scholarships ;

(b) the procedure followed for selection of the candidates;

(c) whether it is a fact that only in the case of the scheme for the award of Overseas Scholarships for the Scheduled Castes Tribes and other Backward Classes, the candidates are selected by the U. P. S. C.; and

(d) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES ( Dr. V. K. R. V. RAO) : (a) The scheme relates to the award of Overseas Scholarship to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Denotified, Nomadic and semi-nomadic Tribes for studies abroad.

(b) The scheme is advertised and given wide publicity through the Press and information is also sent to the State Governments and Universities. Applications received are scrutinised and all eligible candidates are called for interview. A Selection Committee is constituted with experts in specific fields for interviewing the candidates and making recommendations, which are put up to the Minister for approval.

(c) From 1954-55 to 1963-64, selections were made by the U. P. S. C., but from 1964-65 onwards, they are made by a Selection Committee set up by the Ministry for the purpose.

(d) Does not arise.

**Difficulty Experienced by Tourists  
Visiting Assam**

6758. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that tourists visiting Assam have to undergo much trouble going from Gauhati Airport to Shillong, the capital of Assam, over 75 miles by road and on the account often refrain from visiting the tourist attractions in the region ;

(b) whether, in order to remove this difficulty, Government are planning to set up an aerodrome at Bara Pani, as a step towards promotion of tourism in Assam ;

(c) the estimated cost of the scheme and whether it would be included in the Fourth Five Year Plan; and

(d) if the answer to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). A proposal for developing the existing airport near Barapani has been included in the draft Fourth Five Year Plan of the Civil Aviation Department. The project is estimated to cost more than one crore of rupees and can be executed only in phases. A decision regarding the schemes to be included in the Fourth Five Year Plan within the ceiling fixed by the Planning Commission is expected to be taken shortly.

(d) Does not arise.

**Retirement of Class I and II Officers  
at the age of 50 years**

6759. SHRI S. D. SOMASUNDARAM : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued orders to retire the Class I and Class II Officers at the age of fifty in the public interest, if necessary ;

(b) if so, the number of officers likely

to be affected in each Ministry during 1969 ; and

(c) the reasons which prompted Government to issue such orders when Government refused to accede to the request to reduce the retirement age from 58 to 55 years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) It has been decided to provide in the relevant rules for (1) retirement of Central Government servants in Class I and II Services/posts, other than those the age-limit for the purpose of direct recruitment to which is 35 years and above, on attaining the age of 50 years, if it is necessary to do so in the public interest by giving three months' notice and to confer a corresponding right on such Government servants to so retire voluntarily; and

(2) retirement of Central Government Servants in Class III services/posts, who are not governed by any pension rules, after they have completed thirty years of service, if it is necessary to do so in the public interest, by giving three months' notice and to confer a corresponding right on such Government servants to so retire voluntarily. Orders in this behalf will be issued shortly.

(b) The Ministry of Home Affairs have no information about the number of officers who would attain the relevant age or complete the relevant years of service, during 1969. Collection of this information in respect of such Government employees throughout India will involve considerable time and labour.

(c) It will be observed from the reply to part (a) of the question that while the age of superannuation of the Central Government employees would remain at 58, only powers are being taken by the Government to retire a Government servant after he has attained a specified age or has completed a specified period of service, if it is necessary to do so in the public interest and to confer a reciprocal right to the Government servant to so retire voluntarily.

### राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ

6760. श्री बलराज मधोक :

श्री भोम प्रकाश त्यागी :

श्री हरदयाल बेबगुण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को एक राजनैतिक दल समझती है न कि एक सांस्कृतिक संगठन ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा किसी पंचाट के सम्बन्ध में पारित किये गये संकल्प पर सरकार को आपत्ति है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा किसी पंचाट के सम्बन्ध में पारित किये गये ऐसे ही संकल्पों का सरकार को पता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या आर्य समाज को भी एक राजनैतिक संस्था घोषित करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिष्णाचरण शुक्ल) : (क) सरकार के विचार में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गति विधियां इस किस्म की हैं कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनमें भाग लेने से केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 के उपनियम 1 के उपबन्ध लागू किये जा सकते हैं। इस नियम के अधीन कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल अथवा राजनीति में भाग लेने वाली किसी संस्था का सदस्य नहीं होगा अथवा किसी अन्य प्रकार से उससे संबद्ध नहीं होगा जो किसी राजनीतिक आन्दोलन अथवा गतिविधि में भाग लेती है, सहायतायें चन्दा देती है अथवा किसी अन्य रीति से सहायता देती है।

(ख) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा 23 और 24 मार्च, 1968 को कच्छ पंचाट के सम्बन्ध में पारित संकल्प सरकार के ध्यान में आया है। संघ के विधान के अनुच्छेद 4 (ख) में बताया गया है कि "संघ में कोई राजनीति नहीं है और केवल सांस्कृतिक कार्य में लगा हुआ है"। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उद्घोषित उद्देश्य के संदर्भ में कच्छ पंचाट के बारे में संकल्प स्पष्टतः राजनीतिक स्वरूप का है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जुम्मे की नमाज के पश्चात् भारत विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक राजनीतिक भाषण

6761. श्री बलराज मधोक :

श्री भोमप्रकाश त्यागी :

श्री हरदयाल बेबगुण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के नगरों में मस्जिदों में जुम्मा की नमाज के बाद शेख अब्दुल्ला और अन्य मुस्लिम राजनीतिक नेताओं द्वारा राजनीतिक भाषण दिये जाते हैं और भारत विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक प्रचार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई ऐसी उपयुक्त व्यवस्था करने का है ताकि जुम्मा की नमाज के बाद राजनीतिक भाषण न दिये जा सकें ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जुम्मा की नमाज राजनीतिक सभा घोषित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?



गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को शेर अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग द्वारा मस्जिदों में दिये गये कुछ भाषणों की जानकारी है जो राजनीतिक किस्म के थे। मस्जिदों में किसी अन्य मुस्लिम राजनीतिक नेता द्वारा दिये गये ऐसे भाषण गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, नागालैंड, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्कदीव मिनिक्वय तथा अमिनदिवी द्वीप समूह, मनीपुर, नेफा और त्रिपुरा की राज्य सरकारों 'संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में नहीं आए हैं। शेष राज्यों 'संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा है।

(ख) से (घ). खेद है कि कुछ धार्मिक स्थानों को राजनीतिक प्रचार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। किन्तु इससे जुम्मे की नमाज के बाद की सब तकरीरों के बारे में ऐसा व्यापक अर्थ लगाना भी अनुचित होगा। प्रबुध जनमत धार्मिक स्थानों को राजनीतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने का विरोध करता है।

#### **Ahmedabad Mayor's Remarks**

6762. SHRI R. K. AMIN :

SHRI D. R. PARMAR :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Mayor of Ahmedabad City said at the time of meeting of the All India Mayors' Conference held at Baroda recently that one should burn off the Constitution of India because it favours only one per cent population having large properties ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTTR OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SAUKLA) :  
(a) According to information received from the State Government the Mayor of

Ahmedabad did not make any such statement in the meeting of Mayors held at Baroda on 27th September, 1968.

(b) Does not arise.

#### **Recruitment Rules in Laccadive Administration**

6763. SHRI P. M. SAYEED : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the rules governing the recruitment of officials in all ranks in the Laccadive Administration :

(b) whether the service conditions of the local recruits and the recruits from Kerala and other States are different; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) Recruitment rules for posts under the Laccadives Administration are framed in consultation with the Union Public Service Commission by the administrative ministries concerned in respect of Class I and Class II posts and by the Laccadive Administration in respect of Class III and Class IV posts. These rules are notified in the official gazette as and when they are promulgated. As there are numerous categories of posts which require various types of experience, detailed information in this respect is not readily available,

(b) and (c). The conditions of service of the employees of the Laccadives Administration are the same except for certain concessions like Island Special Pay, rent free accommodation, and free sea passage with joining time during leave, allowed to persons belonging to the mainland and recruited from the mainland for service in the islands or persons deputed for service in the islands from State or Central Government Departments on the mainland. These concessions have been sanctioned to attract qualified and experienced persons from the mainland for service in the islands, where conditions of living are not comparable to those obtaining on the mainland.

**"Damage to an Indian Tanker"**

6764. SHRI SHRI CHAND GOYAL ;  
Will the Minister of SHIPPING AND  
TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether an Indian tanker was  
damaged in the collision with a Japanese  
ore-carrier in Uraga Channel in Tokyo  
Bay ; and

(b) the extent of the loss caused ?

THE MINISTER OF PARLIAMEN-  
TARY AFFAIRS AND SHIPPING AND  
TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMA-  
IAH) : (a) The Indian Tanker M. T. "Adi  
Jayanti" suffered damage as a result of a  
collision with a Japanese vessel M. V.  
"Tomiura Maru" in the Bay of Tokyo on  
the 5th December, 1968.

(b) The loss due to repair of the  
Indian Tanker and loss of its cargo is  
estimated to be Rs. 2,63,000/—.

**कालसू धन**

6765. श्री भोलू प्रसाद :

श्री श्रीमप्रकाश त्यागी :

श्री राम चरण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा  
करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने  
चौथी लोक-सभा के छठे सत्र में कहा  
था कि पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में सूचना  
देने वाले व्यक्तियों को इनाम देने के लिये  
उनके पास फालतू धन नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार  
के मंत्रियों तथा छोटे और बड़े अधिकारियों  
की विदेश यात्राओं पर तथा विभिन्न मंत्रा-  
लयों द्वारा गोष्ठियां आयोजित करने पर  
धन व्यय किये जाने का कोई औचित्य है ;

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित  
व्यक्तियों द्वारा 1968 में विदेशों में तथा  
देश के अन्दर कितने दौरे किये गये और ये

यात्राएं किस-किस समय की गई थीं ;  
और

(घ) क्या पाकिस्तानी एजेंटों का पता  
न लगाने का कारण यह है कि पाकिस्तान  
के प्रति सरकार का नरमी का रवैया है ।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) सम्भवतः  
माननीय सदस्य के ध्यान में वह है जो 13  
दिसम्बर, 1968 को इस सदन में तारंकित  
प्रश्न संख्या 724 के पूरक प्रश्नों के उत्तर  
देने समय गृह मंत्री ने कहा था । उन्होंने यह  
नहीं कहा था कि उनके पास उन व्यक्तियों  
को पुरस्कार देने को फालतू धन नहीं है जो  
पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में सूचना देने  
हैं । जब यह पूछा गया कि सरकार उन  
व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देगी जो  
जम्मू व कश्मीर में धुसपैठियों का पता  
लगाने में मदद करते हैं तो गृह मंत्री ने कहा  
था कि सरकार धन को इस प्रकार नहीं  
बहा सकती है और धन का उचित प्रयोग  
करना पड़ेगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

**सेवा रिकार्ड आवि का हिन्दी में रखना**

6766. श्री भोलू प्रसाद : क्या मौबहान  
तथा परिबहान मंत्री यह बताने की कृपा  
करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने राजभाषा  
अधिनियम तथा गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा इस  
अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये  
आदेशों के अनुसरण में (1) अपने सभी  
प्रकाशनों को हिन्दी में प्रकाशित करने,  
(2) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा  
पुस्तकों को हिन्दी में लिखने, (3) अनुवाद  
कार्य बढ़ जाने के कारण अतिरिक्त अनु-  
वादकों तथा हिन्दी टाइपिस्टों की भरती के

लिये प्रतिरिक्त धनराशि का नियतन प्राप्त करने, (4) हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रथम जनवरी, 1961 को 45 वर्ष से नीचे की आयु वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये कार्यक्रम तैयार करने (5) हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों के लिये सरकारी कामकाज हिन्दी में करना अनिवार्य करने, (6) हिन्दी में कामकाज आरम्भ करने की योजना और हिन्दी प्रशिक्षण योजना को क्रियान्वित करने के लिये संयुक्त सचिवों, उपसचिवों तथा अवर सचिवों के पदों पर हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करने के बारे में क्या कार्यवाही की है;

(ख) किन तारीखों को उक्त कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय में हिन्दी विरोधी वातावरण को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संसद-कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) और (ख). समय-समय पर राजभाषा पर अधिनियम, 1963 के अनुसरण में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेश सभी संबद्धों को प्रसारित किये गये थे और यथा संभव कार्यान्वित किये गये। राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 पर आधारित 6 जुलाई, 1968 के नवीनतम वृद्ध आदेशों को इस मंत्रालय ने 18 अक्टूबर, 1968 को परिभाषित किया। उठाये गये विशेष मामलों की स्थिति इस प्रकार है :

(1) गृह मंत्रालय के दिनांक 6-7-1968 को उल्लिखित नवीनतम आदेशों के अनुसार संकल्प, सामान्य आदेश, नियमावली, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और दूसरी रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद में पेश किये जाने वाले कागजात, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, नोटिस और निविदा के प्रपत्र को अंग्रेजी व हिन्दी दोनों में किये जाने

चाहिए। 30-9-68 और 31-12-68 को अन्त होने वाले दो त्रैमासिकों के इस मंत्रालय के विवरण यह सूचित करते हैं कि इस अवधि में 8 संकल्प और 90 अधिसूचनाएं जारी किये गये और ये दोनों अंग्रेजी और हिन्दी में जारी किये गये।

(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पंजियों में भविष्य में प्रविष्टियां हिन्दी में होनी चाहिए इस संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश वाला का० ज्ञा० दिनांक 14-8-1968 समय पर इस मंत्रालय को नहीं मिला और हाल में ही प्राप्त किया गया और अब उनको यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(3) अनुवादकों और टाइपिस्टों की प्रतिरिक्त आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा चुका है और अधिक धन प्राप्त कर या अन्यथा इन पदों की मंजूरी का प्रश्न विचाराधीन है।

(4) सेवा की आवश्यकताओं के अधीन समय-समय पर हिन्दी शिक्षा योजना के अन्तर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर भेजे गये हैं वर्तमान स्थिति यह है कि योजना के अधीन 100 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। 10 प्रशिक्षण हो रहे हैं और लगभग 119 को अभी प्रशिक्षण लेना है।

(5) चूंकि राजभाषा अधिनियम (यथा संशोधित) में अनुमानित द्विभाषीय योजना के अन्तर्गत राजकीय कार्य के लिये अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग करने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की स्वेच्छा है अतः यह संभव नहीं है कि हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को राजकीय कार्य के लिये केवल हिन्दी में काम करना अनिवार्य किया जाय।

(6) हिन्दी का ज्ञान, अवर सचिव, उप सचिव या संयुक्त सचिव की नियुक्ति

के लिये कसौटी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

(ग) इस मंत्रालय में हिन्दी विरोधी वातावरण नहीं है और इसलिये इसके निवारण का प्रश्न नहीं उठता है।

शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले  
अधिकारी

6767. श्री जी० ब० सिंह :

श्री राम सिंह अयरवाल :

श्री बलराज मधोक :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासनिक अनुभागों में इस समय काम कर रहे अनु-भाग अधिकारियों तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अनुभाग अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है और वे किन-किन अनुभागों में कार्य कर रहे हैं ;

(ग) यदि अब तक प्रशासनिक अनु-भागों में कोई अनुभाग अधिकारी तथा कर्मचारी तैनात नहीं किये गये हैं तो क्या सरकार का विचार उन्हें प्रशासनिक अनु-भागों में तैनात करने का है ताकि वे अधिक कार्यकुशल बन सकें और उन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राय) : शायद माननीय सदस्यों का आशय मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग से है। स्थिति इस प्रकार है :—

(क) अनुभाग अधिकारी — 11  
अन्य श्रेणियों के  
कर्मचारी — 182

(ख) अनुभाग अधिकारी—कोई नहीं। अन्य श्रेणियों के कर्मचारी — अनुसूचित जाति के 9 कर्मचारी। वे ई-I, ई-III, ई-IV सी० आर०, रोकड़-I और एस० एण्ड एस० अनुभागों में कार्य कर रहे हैं। अनुसूचित आदिम जाति का कोई कर्मचारी नहीं है।

(ग) और (घ). प्रशासन प्रभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों को नियुक्त करने पर कोई पाबन्दी नहीं है। नियुक्तियां, रिक्त स्थान तथा उस समय अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार की जाती हैं।

शिक्षा मंत्रालय में अवर डिप्टीजन क्लर्क

6768. श्री जी० ब० सिंह :

श्री राम सिंह अयरवाल :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अवर डिप्टी-जन क्लर्कों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ;

(ग) क्या गृह-कार्य मंत्रालय के आदेश के अनुसार उपयुक्त जातियों के लिए निर्धारित कोटा पूरा कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) 90

(ख) अनुसूचित जाति : 11

\* अनुसूचित आदिम जाति : कोई नहीं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के अनुसार, प्रवर श्रेणी लिपिकों के वर्ग में होने वाले स्थायी रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां चयन (सिलैक्ट लिस्ट) में शामिल व्यक्तियों में से वरीयता क्रम से की जाती हैं। प्रवर श्रेणी लिपिकों के वर्ग में अस्थायी स्थानों पर नियुक्तियां ऐसे स्थायी अवर श्रेणी लिपिकों में से, अवर श्रेणी लिपिक वर्ग की वरीयता-क्रम के आधार पर की जाती हैं, जिन्होंने कम से कम आठ वर्ष की अनु-मोदिन सेवा की हो और जिन्हें अनुपयुक्त नहीं पाया जाए। इसलिए विशेष संरक्षण आदेश, इस मामले पर लागू नहीं होते हैं।

#### प्रशासनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग

6769. श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :

श्री राम चरण :

श्री बलराज मधोक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के चतुर्थ-श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश, स्पष्टीकरण, पदोन्नति और सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य मूलतः हिन्दी में करने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने में क्या कठिनाइयां हैं ;

(ख) क्या यह भी ठीक है कि उनके मंत्रालय के तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के प्रशासनिक विभागों में गैर-तकनीकी किस्म का कार्य हिन्दी में नहीं

किया जा रहा है क्योंकि उक्त विभागों के अधिकारी हिन्दी-विरोधी हैं और अंग्रेजी से प्रतियां करने की सुविधा भी प्राप्त है ;

(ग) क्या अपने मंत्रालय के प्रशासनिक विभाग में सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करना सुनिश्चित करने का उनका विचार है ; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस विषय के अनुदेश पहले ही मौजूद हैं कि हिन्दी-भाषी श्रेणियों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के, सेवा की शर्तों में संबंधित सामान्य आदेश, आरोप पत्र तथा अनुदेशात्मक आदेश, उनसे प्राप्त याचिकाओं के उत्तर और उनकी सेवा-पंजियों में सभी प्रविष्टियां हिन्दी में होंगी।

(ख) और (ग). जी नहीं, श्रीमान्। संशोधित राजभाषा अधिनियम में जिस द्विभाषिक योजना की व्यवस्था की गई है उसके अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी या अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिल्ली प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य

6770. श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

श्री प० मु० सईद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के इस वक्तव्य

की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन के मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) रक्षित विषयों के सिवाय राज्य तथा संवर्ती सूचियों के विषयों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक सामान्य नीति निर्धारित की है कि दिल्ली प्रशासन के साथ उदारता तथा सहयोग के साथ व्यवहार किया जाय और उसे केन्द्रीय सरकार के एक अधीनस्थ निकाय के रूप में न समझा जाय। सरकार को दिल्ली के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में किसी अनावश्यक हस्तक्षेप की जानकारी नहीं है।

**पन्त पोलिटेक्निक, दिल्ली के छात्रों को छात्रवृत्ति**

6771. श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन्त पोलिटेक्निक के, जो दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाया जाता है, कुछ छात्रों को 1967-68 में छात्रवृत्तियों की राशि का भुगतान नहीं किया गया था यद्यपि 1966-67 में उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी और उन्हें 1966-67 की वार्षिक परीक्षा में 55 से 60 प्रतिशत तक अंक प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो उन छात्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाई जा रही ग्रन्थ दो पोलिटेक्निकों में ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशियों का भुगतान किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो पन्त पोलिटेक्निक के इन छात्रों के साथ भेदभाव बरते जाने के क्या कारण थे और क्या सरकार उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इन छात्रवृत्तियों का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) जी हां ।

(ख) 13 नामों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या LT-810/69]

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ): छात्रवृत्तियों के नवीयन का निर्णय निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है और एक पोलिटेक्निक तथा दूसरे पोलिटेक्निक में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। दिल्ली प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी छात्रों के मामलों का पुनर्विलोकन किया जा चुका है और अभी तक दस छात्रों की छात्रवृत्तियों का नवीयन कर दिया गया है।

**केन्द्रीय हिन्दी निवेशालय द्वारा प्रपत्रों तथा गियमाचलियों का अनुवाद**

6772. श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :

कुमारी कमला कुमारी :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री राम स्वरूप बिद्यार्थी :  
श्री बलराज मधोक :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को अब तक श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय से अनुवाद के लिए कितने प्रपत्र तथा नियमावलियां प्राप्त हुई हैं ;

(ख) ये प्रपत्र तथा नियमावलियां किस तारीख को प्राप्त हुई थीं तथा इनमें से कितनी अनुवाद करके वापिस भेज दी गई हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इनके अनुवाद में अनावश्यक विलम्ब हुआ है, यदि हां तो क्या इनका शीघ्र अनुवाद करके वापिस भेजने के लिये कार्यवाही की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त वर्मान) : (क) और (ख) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय से 1961 से 1968 वर्षों के दौरान विभिन्न तारीखों पर अनुवाद के लिए 582 प्रपत्र और 75 नियमावलियां प्राप्त हुई थीं। अब तक 509 प्रपत्रों और 62 नियमावलियों को अनुदित करके वापिस भेज दिया गया है। बाकी प्रपत्र और नियमावलियां अनुवाद के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) और (घ) क्योंकि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से संबंधित संहिताओं, नियमावलियों और प्रपत्रों और अन्य विधितर साहित्य को अनुदित करने की जिम्मेदारी निदेशालय की है, इसलिए कभी-कभी विभिन्न कारणों से देरी हो ही जाती है। अनुवाद कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए, बाहर की एजेंसियों को भी कुछ अनुवाद कार्य ठेके पर देने का निर्णय किया गया है।

पन्त पोलिटैक्निक, दिल्ली के छात्रों से शुल्क लिया जाना

6773. श्री श्रोम प्रकाश त्यागी :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री रामस्वरूप बिद्यार्थी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1968 में उन छात्रों से शुल्क वसूल किया गया था जिन्हें भोखला स्थित पन्त पोलिटैक्निक में जो दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है छात्रवृत्ति प्रदान की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नियमों के अनुसार उन छात्रों से जिन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है शुल्क नहीं लिया जाता ;

(ग) यदि हां, तो उन छात्रों से लिया गया शुल्क उन्हें कब लौटा दिया जायेगा ; और

(घ) उनको अब तक शुल्क की राशि न लौटाए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त वर्मान) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां, वे छात्र जिन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, शिक्षा शुल्क की भ्रदायगी से भी मुक्त होते हैं और पहले भ्रदा की गई फीस उन्हें वापिस कर दी जाती है।

(ग) और (घ) फीस वापिस कर दी गयी है।

कच्छ क्षेत्र का विकास

6774. कुमारी कमला कुमारी :

श्री श्रोम प्रकाश त्यागी :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री रामस्वरूप विद्याधी :  
श्री रघुनाथ सिंह शास्त्री :

सुधार तथा वृद्धि के लिए योजनाएं ।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ के समूचे क्षेत्र का विकास करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो उसकी रूप रेखा क्या है :

(ग) कच्छ के रन में से पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा की जाने वाली तस्करी को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) पाकिस्तानी घुसपैठियों को कच्छ में घूमने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याधरण शुक्ल) : (क) और (ख). गुजरात सरकार के अनुसार कच्छ क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं :

राज्य क्षेत्र :

1. सिंचाई कूपों को खोदना तथा बिजली के पम्प सेट लगाना ।
2. नल-कूप खोदना ।
3. सिंचाई हीजों का निर्माण ।
4. मध्यम सिंचाई योजनाएं ।
5. मत्स्य-पालन का विकास ।
6. औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना ।
7. ग्रामीण उद्योग प्रयोजना ।
8. गुजरात राज्य के सामूहिक विद्युत ग्रिड के साथ कच्छ को मिलाना (धुवरन से भुज तक संचारण लाइन) ।
9. ग्रामीण विद्युतीकरण ।
10. सड़क विकास ।
11. शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में

केन्द्रीय क्षेत्र :

1. कांडला बन्दरगाह का विकास ।
2. कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र ।
3. सामरिक महत्व की सड़कें और पुलों का निर्माण ।

(ग) और (घ). सीमा-सुरक्षा दल द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है और तस्करी तथा किसी घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य सरकार ने भी कच्छ जिले में जिला पुलिस दल तथा गुप्तचर एकाई की संख्या में वृद्धि की है ।

Private Business run by Border Security Force Personnel

6775. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Border Security Force personnel are running private business in colonies of Delhi ;

(b) whether it is permissible for a Government employees to run private business in the form of Coal Depot. etc. under the Conduct Rules ;

(c) whether any complaints have been received by the Department of Civil Supplies, Delhi Administration against the personnel, who are running such business without the valid permit or licence from the Civil Supplies Department ;

(d) whether any inquiries have been made on such complaints and ; if so, the results of such inquiry ; and

(e) what action Government propose to take against these employees ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) No, Sir.



(b) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, require that a Government servant should obtain previous sanction of the Government before engaging directly or indirectly in any trade or business. They further require that every Government servant should report to the Government if any member of his family is engaged in a trade of business ;

(c) to (e), A complaint was received by the Delhi Administration against an official of the Border Security Force alleging that he was running a coal depot without licence. Inquiries made by the Delhi Administration revealed that the wife of the official concerned was running a fire-wood shop on a licence issued by the Municipal Corporation of Delhi and not a Coal Depot, as alleged, As the official concerned did not report about the running of a fire-wood shop by his wife, as required by the Rules, disciplinary action is being taken against him.

उत्तर प्रदेश में स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में से कटौती

6776. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री रणजीत सिंह :

श्री सूरज भानु :

श्री बृज भूषण लाल :

श्री हुकम चन्द कछबाय :

श्री जार्ज फरनेन्डजी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री 22 नवम्बर, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 1710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव कोष के लिए अनिवार्य रूप से अध्यापकों के वेतन में से कटौती किये जाने के मामलों के बारे में इस बीच जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० शरार० बी० राव) : (क) से (ग). जिन 12 जिला परिषदों के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी की निधि के लिए स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में से कटौतियाँ करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं उनमें से 7 की जांच पड़ताल के परिणाम प्राप्त हो गए हैं। इन सात में से तीन के विरुद्ध शिकायतें सही पाई गई थीं। शेष चार के बारे में स्थिति संक्षेप में नीचे दी गई है :

गोंडा : कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि शिकायतें सही थीं या गलत।

जौनपुर : जिला परिषद के अध्यक्ष ने अध्यापक संघ की कार्यकारी समिति से कांग्रेस चुनाव निधि के लिए धन देने की व्यक्तिगत रूप से अपील की थी। उस अपील के परिणाम स्वरूप अध्यापकों ने अपने आप ही उक्त निधि के लिए धन दिया था और इस प्रकार काफी धन एकत्र हो गया था। अध्यक्ष की व्यक्तिगत अपील के लिए सरकार की नापसन्दगी जाहिर करने का प्रस्ताव है।

इलाहाबाद : विस्तृत जांच-पड़ताल की जा रही है। प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से पता चलता है कि अगस्त और सितम्बर, 1968 के महीनों के अध्यापकों के वेतनों में से 10 रुपये लिए गए।

बदायुँ : प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से पता चलता है कि जिला परिषदों के बहुत से अध्यापकों ने कांग्रेस चुनाव निधि के लिए धन दिया था। किन्तु यह स्थापित नहीं हो सका कि अध्यक्ष ने कोई अपील की थी या अध्यापकों ने अपनी इच्छा से धन दिया था। चन्दे की मात्रा का भी पता नहीं चल सका।

2. इस संबंध में प्राप्त होने वाली प्रीर सूचना, प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

श्री ए० जी० नूरानी द्वारा काश्मीर के बारे में लिखी गई पुस्तक

6777. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

• श्री रणजीत सिंह :

श्री राम गोपाल शालवाले :

श्री सूरज भान :

श्री बृज भूषण लाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अक्टूबर, 1968 के "भार्गनाइजर" में प्रकाशित इस समाचार की प्रोर दिलाया गया है कि एक पत्रकार श्री ए० जी० नूरानी द्वारा काश्मीर के बारे में लिखी गई पुस्तक में पाकिस्तान के दृष्टिकोण का समर्थन करने वाली सामग्री है ;

(ख) क्या श्री नूरानी को 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान गिरफ्तार किया गया था ; प्रीर

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिष्ठा चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रीर (ग). महाराष्ट्र सरकार ने भारत रक्षा नियमों के नियम 30 के अधीन 8 सितम्बर, 1965 को श्री ए० जी० नूरानी को नजरबन्द किया था प्रीर 25 दिसम्बर, 1965 को रिहा कर दिया ।

श्री गिबसन को पद्मश्री से विभूषित करना

6778. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ;

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री रणजीत सिंह :

श्री रामगोपाल शालवाले :

श्री सूरज भान :

श्री बृज भूषण लाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1966 को मेयो कालिज, प्रजमेर के प्राध्यापक श्री गिबसन को 'पद्मश्री' से विभूषित किया गया था :

(ख) क्या यह भी सच है कि इंग्लैंड की महारानी उनको पहले ही प्री० बी० ई० उपाधि प्रदान कर चुकी हैं ; प्रीर

(ग) यदि हां तो एक विदेशी को किस प्राधार पर 'पद्मश्री' से विभूषित किया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री बिष्ठा चरण शुक्ल) : (क) मिस्टर गिबसन को 26 जनवरी, 1965 को 'पद्मश्री' से विभूषित किया गया था ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए मिस्टर गिबसन को 'पद्मश्री' से पुरस्कृत किया गया था । विदेशी को पद्मश्री पुरस्कार देने में कोई रोक नहीं है ।

भारतीय नौबहन की स्थिति

6779. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री रणजीत सिंह :

श्री रामगोपाल शालवाले :

श्री सूरज भान :

श्री बृज भूषण लाल :

क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के समुद्री नौबहन में तथा भारतीय यात्रियों तथा माल को लाने से जाने में भारतीय नौबहन का स्थान तथा स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने भारत की भौगोलिक स्थिति तथा आर्थिक दशा को दृष्टि में रखते हुए नौवहन के विशेष विकास तथा विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) पहली जुलाई, 1968 को विश्व के 22 देशों में से, जिनकी नौवहन भारक्षमता 10 लाख टन से अधिक है उसमें भारत का सत्रहवाँ स्थान है और उसका कुल टन भारसंसार के समस्त टन भार का लगभग 1 प्रतिशत है।

जहाँ तक भारतीय जहाजों द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन का सम्बन्ध है उपलब्ध नवीनतम आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

**समुद्रपार यातायात :**

**माल :** जबकि भारतीय अनेमी पोत और खुले माल वाहक पोत किसी भी समुद्री मार्ग पर, जहाँ कहीं माल प्राप्त होता है, चलाए जाते हैं, वहाँ प्रायः भारतीय सभी लाइनर जहाज अब भारत के समुद्रपार व्यापार के लाइनर मार्गों पर नियमित रूप से चलते रहते हैं। 1967-68 के दौरान भारत के समुद्रपार व्यापार की कुल मात्रा 497.91 लाख टन थी जिसमें से 77.28 लाख टन माल भारतीय जहाजों द्वारा ले जाया गया अर्थात् अपने औचित्य भाग 50 प्रतिशत के विरुद्ध लगभग 15.5 प्रतिशत।

**यात्री :** भारतीय जहाज यात्रियों को केवल तीन ही मार्गों पर ले जाते हैं अर्थात् बम्बई-पूर्वी अफ्रीका, मद्रास-मलेशिया और बम्बई-नालसागर। 1967 के वर्ष में भारतीय जहाज इन मार्गों पर कुल 98,684 यात्री ले गए।

**तटीय यातायात :**

**माल :** 1967 में तट पर सूखे माल

यातायात की मात्रा 23.14 लाख टन थी जो पूर्णतः भारतीय जहाजों द्वारा ले जाया गया। इसके अतिरिक्त 28.01 लाख टन परिष्करण पदार्थ (तेल पोत माल) का यातायात हुआ जिसमें भारतीय जहाज केवल 6.31 लाख टन अर्थात् लगभग 22.5 प्रतिशत ले गए।

**यात्री :** तट पर केवल बम्बई-पनजी, बम्बई-सौराष्ट्र और कलकत्ता-अन्दमान यात्री सेवाएँ चल रही हैं। इन सब सेवाओं में भारतीय जहाज प्रयुक्त होते हैं जो 1967 में 8,09,616 यात्री ले गए।

(ख) से (घ). पोत परिवहन के विकास का नियोजन विभिन्न पंच वर्षीय योजनाओं के लिए देश का एक अंग है। चतुर्थ योजना जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, नई योजना अवधि के अन्त तक वर्तमान 21 लाख टन भार की अपनी क्षमता तक को 40 लाख टन भार क्षमता बढ़ाने का विचार है। इसमें से 35 लाख टन भार क्षमता वास्तविक रूप से चासू है जब कि शेष 5 लाख टन भार क्षमता के लिए निश्चित प्रादेश दिया जायगा और अगली योजना के अन्तर्गत सौंप दिया जाएगा।

**समाचारपत्रों के विरुद्ध दायर मुकद्दमों**

6780. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

**श्री रणजीत सिंह :**

**श्री सूरज भाव :**

**श्री बृज भूषण लाल :**

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :**

**श्री राम स्वरूप बिष्टार्थी :**

**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

**डा० रानेन सेन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों में भारतीय दंड संहिता

की धारा 153-क के अन्तर्गत में समाचारपत्रों के विरुद्ध कितने मुकद्दमें दायर किये गये ;

(ख) कितने समाचारपत्रों को दंड दिया गया ; और

(ग) इस धारा की कुछ उपधाराएं किन-किन मामलों में बेकार साबित हुईं और प्रत्येक मामले में कौन-सी उपधारा बेकार साबित हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) 11 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 1046 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क के अन्तर्गत समाचार पत्रों के विरुद्ध चार मामलों में सजायें दी गईं एक उत्तर प्रदेश में और तीन दिल्ली में।

(ग) छोड़ने अथवा मुक्त कर देने के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

भारत में ईसाई धर्म प्रचारक

6781. श्री प्रकाशश्री शास्त्री :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत में आने वाले विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों की संख्या कम हो गई है ;

(ख) भारत छोड़ के जाने वाले विदेशी धर्मप्रचारकों के स्थान भारतीय धर्मप्रचारकों द्वारा पूरी नहीं करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रयास किये हैं कि इन धर्मप्रचारकों द्वारा पिछले तीन

वर्षों से धर्मप्रचार कार्य के लिये प्राप्त धन का उपयोग धर्मप्रचार के लिये ही किया गया ; और

(घ) धर्मप्रचार कार्य के हेतु पिछले तीन वर्षों से विदेशों से कुल कितनी धन राशि तथा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) वर्तमान धर्मप्रचारकों के स्थान पर आने वाले विदेशी धर्मप्रचारकों को भारत में केवल तभी आने दिया जाता है जब वे असाधारण योग्यता अथवा विशिष्ट अनुभव के व्यक्ति हों और जब कि ऐसे काम के लिए कोई भारतीय उपलब्ध न हो।

(ग) ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक धर्मप्रचारक को अपने द्वारा किये गये खर्च का लेखा रखना और उसे संबीक्षा के लिए प्रस्तुत करना पड़ता हो। अतः पूछी गई सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है।

(घ) केवल धर्मप्रचारक संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त की गई राशियों के पृथक आँकड़े नहीं रखे जाते हैं। आदान-प्रदान लेखों में ये बाहर-से आई हुई रकमें सामान्य शीर्ष "निजी दानों" के अन्तर्गत आती हैं। इस शीर्ष के अधीन एक उप-शीर्ष में धर्मप्रचारकों, धर्मार्थ संस्थानों और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा रखा जाता है 1966 और 1967 के दौरान इस उप-शीर्ष में पी० एल० 480 के शीर्ष II और III और राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना के अधीन प्राप्त राशियाँ भी सम्मिलित हैं। इस उप-शीर्ष के लेखे में सन् 1965, 1966 और 1967 में डाली गई कुल रकम क्रमशः 1,227 लाख रुपये 6,886 लाख रुपये और 6,630

लाञ्छन रूपसे थी (विनियम की चासू दर पर)।

अन्य प्रकार की प्राप्त सहायता के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

**Central Advisory Board of Education**

6782. SHRIMATI SAVITRI SHYAM : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have recently constituted a 14-member Standing Committee for the Central Advisory Board of Education ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) Atoms, objects and duties of the standing Committee.

The Committee will supervise the implementation of the Resolutions of the Central Advisory Board and the National Policy on Education. It will help the Centre and the States to work together continuously in formulating and implementing the Fourth Five Year Plan in Education.

**Personnel :**

1. Union Education Minister—Chairman.
2. Dr. B. D. Nag Chaudhuri, Member (Education), Planning Commission.
3. Dr. D. S. Kothari, Chairman, University Grants Commission.
4. Shri S. Chakravarty, Secretary, Ministry of Education and Youth Services.
5. Education Minister, Andhra Pradesh.
6. Education Minister, Maharashtra.
7. Education Minister, Rajasthan.
8. Education Minister, Orissa.

9. All Education Ministers in the Zone in which the Committee meets.

10. Shrimati Durgabai Deshmukh.

11. Shri K. P. Subramania Menon, M. P.

12. Dr. S. Misra, Vice-Chancellor, Utkal University.

13. Dr. T. Sadasivan, University of Madras.

14. Shri J. P. Naik, Adviser, Ministry of Education and Youth Services—Member Secy.

**Term of Office :**

The term of the office of the Committee will be one year or until the next meeting of the Board, whichever is earlier.

**Programme of work for 1969-70.**

The immediate work before the Committee in the beginning of the year 1969-70 is to review the Fourth Five Year Plans in education of the Centre, States and Union Territories and to advise the Centre and the States on their implementation.

**Rural Universities**

6783. SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the criteria and considerations fixed by his Ministry for starting Rural Universities financed by the Central Government ;

(b) in view of the largely rural character of Faizabad Division in U. P. and the absence of a University in the Division, whether Government propose to consider establishing a Rural University in Faizabad ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) There is no scheme in

the Ministry of Education and Youth Services for starting and financing of Rural Universities. However, the Ministry gives financial assistance to Rural Institutes set up under the scheme of Rural Higher Education.

(b) and (c). There is no proposal under consideration of the Government of Uttar Pradesh, who are concerned with the setting up of universities in the State, to establish a Rural University in Faizabad.

In Uttar Pradesh there is already one Rural Institute at Bichpuri and the State Government have already under consideration the establishment of a second Rural Institute at Allahabad during the 4th Plan period. There is no proposal under consideration of Government at present to establish a Rural Institute in Faizabad.

#### Appointments in Laccadives

6784. SHRI P.M. SAYEED : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to lay a statement showing the following details of the persons appointed in Laccadive administration during the period 1962—65, rank-wise, i.e., Class I, II, III, and IV :

(a) the names, qualifications, any competitive examination passed, mode of appointment (direct or on deputation) and the place to which they belong ;

(b) the number out of them who are still on deputation ; and

(c) the number out of them who have been made permanent ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The information is contained in Statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—811/69]

(b) and (c). The information is contained in Statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—811/69].

#### Air-India

6785. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) when the Air India Corporation was set up and what were the objects to be achieved as a result thereof ;

(b) whether the targets of setting up units and development targets were achieved and, if so, when and how and, if not, the reasons therefor ; and

(c) whether there are any difficulties with which the Corporation is faced at present and, if so, how do Government propose to remove them ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). Air-India was established in June, 1953 under the Air Corporations Act 1953 (27 of 1953) for taking over the Air-India International Ltd. and to under-take international air transport services. This object has been achieved, as Air-India has established itself as one of the foremost international airlines in the world. The difficulties, if any, are met by the Corporation and Government as and when they arise.

#### Restrictions on Foreign Tourists in Assam

6786. SHRI BEDABRATA BARUA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign tourists are not allowed to visit the plains of Assam except some specific localities like the Kaziranga Wild Life Sanctuary ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to do away with these restrictions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Under the Foreigners (Restricted

Areas) Order, 1963, foreigners desiring to visit any place in Assam are required to obtain special permits. Such permits are granted liberally to tourists for visits to Kaziranga and Manas and Shillong which are considered to be of tourist interest.

(b) For reasons of security.

(c) No such proposal is under consideration.

#### Flying Club, Chandigarh

6787. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to start a Flying Club at Chandigarh ;

(b) whether such a proposal was ever conceived and worked upon ;

(c) whether there is a persistent demand from the people of Chandigarh for starting a Flying Club ; and

(d) if so, when it is likely to materialise ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) No such proposal has been received by the Director General of Civil Aviation.

(b) No Sir.

(c) No such request has been received by Government.

(d) Does not arise.

#### Vacancies in Punjab and Haryana High Court, Chandigarh

6788. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of vacancies existing on the Bench of the Punjab and Haryana High Court at Chandigarh ;

(b) the dates from which the vacancies have been existing ;

(c) the reasons for delay in filling up the vacancies ; and

(d) the date from which an additional post has been created and the date by which it is likely to be filled up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Four.

(b) 1st from 11.4.1968.  
2nd from 16.11.1968.  
3rd and 4th from 28.1.1969.

(c) Proposals to fill the vacancies are awaited from the State authorities.

(d) From 16th November, 1968. The post will be filled after proposals are received from the State authorities.

#### Allotment of Plots to Journalists in Chandigarh

6789. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of the journalists, along with the names of the papers or agencies represented by them who have been allotted residential plots or plots for their offices in the Union Territory of Chandigarh ;

(b) the price at which the plots have been allotted ;

(c) whether scheme had been under consideration to establish a Journalists Colony at Chandigarh ; and

(d) if so, the progress there of ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). A statement is placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See No. LT-812/69.*]

(c) and (d). The erstwhile Punjab Government had under its consideration a scheme of setting up press colony and of allotment of land for residential purposes to a leading news papers and its staff but none except the Tribune responded. Accordingly the Tribune Management purchased land for the construction of press-cum-office. Only six working journalists were allotted plots in pursuance of the decision of the erstwhile Punjab Government. The Chandigarh Administration also approved a scheme for allotment of plots to journalists and approved the names of (10) journalists for the purpose. Out of (10) five have since been allotted plots. Two journalists namely S. S. P. Madhawan Nair and Capt. Anant have been allotted plots under a separate scheme as members of Sahitya Academy.

#### Renovation of Dwarkadish Temple

6790. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the work of repair and renovation of historic temple of Dwarkadish at Dwarka has been taken up ;

(b) if so, the progress made in the repair work ; and

(c) if the reply to part (a) above be in negative, the reasons for the delay ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) Yes Sir. The work of structural repairs, and not renovation, of the Dwarkadish Temple at Dwarka has been taken up.

(b) The repair works are in progress. Expenditure of Rs. 25,214/- has been incurred upto the end of February, 1969. The repair work will be continued during the current financial year. The items of repairs executed so far are removal of accretionary plaster from the pillars, lintels etc., on the ground floor; cutting and removing decayed pieces of stone from the outer face of the plinth; providing new stones in the plinth of the required six

duly dressed, moulded and finished as per the original, etc.

(c) Does not arise.

#### पुंछ क्षेत्र में पाये गए पाकिस्तानी वायरलेस सेंट

6791. श्री भारत सिंह चौहान :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968 के प्रथम पक्ष में पुंछ में मनडौली के पास पाकिस्तानी वायरलेस सेंट पाया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त महीने में उसी स्थान पर गोला बारूद भी बरामद हुआ जिस पर पाकिस्तान का निशान था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान् । जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिला पुंछ में एक वगैर लाईसेन्स का ट्रांजिस्टर बरामद हुआ था ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् । फिर भी राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिला पुंछ के एक गाँव में एक व्यक्ति से तीन हथगोले बरामद किये थे ।

(ग) हथगोलों की बरामदगी के सिलसिले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तथा अस्त्र अधिनियम के अधीन दर्ज एक मामले की जांच की जा रही है ।



**दुर्व्यवहार के आरोप में निलम्बित  
अधिकारी**

6792. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय सेवाओं में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको जनता के साथ दुर्व्यवहार करने तथा अन्य कारणों से निलम्बित किया गया है; और

(ख) इस समय निलम्बित किए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है और ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध विभागीय और न्यायिक कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये  
गये मामले**

6793. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पहली जनवरी, 1966 से अब तक कुल कितने मामलों की जांच-पड़ताल की है ;

(ख) सरकार ने जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया है और कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया है ; और

(ग) उनमें राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक नेता और संसद् सदस्यों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1 जनवरी 1966 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये गये मामलों की संख्या वर्ष वार निम्न-लिखित है :—

1966	3805 मामले
1967	3839 मामले
1968	3680 मामले

(ख) इस अवधि में 2590 व्यक्तियों पर मुकद्दमें चलाये गये तथा 1075 व्यक्तियों को सजा दी गई ।

(ग) उनमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

**अभिव्योजित सिद्धबोध**

(1) प्रशासनिक अधिकारी	7	3
(2) अन्य राजपत्रित अधिकारी	102	33
(3) अराजपत्रित अधिकारी	887	518
(4) राजनैतिक नेता	1	—
(5) संसद् सदस्य	5	4

**Explosion In Cartridges Factory  
In Delhi.**

6794. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an explosion took place in cartridges factory in Delhi in December, 1968 resulting in injury to some persons ;

(b) whether Government conducted any inquiry into the explosion ;

(c) if so, the causes of the explosion ; and

(d) the action taken to stop the recurrence of such explosions in future ?

THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) and (b). Yes, Sir.

(c) The police investigation revealed that the explosion appeared to be due to some accidental sparks within the steel filling machine.

(d) A statement showing the various steps taken by Delhi Administration to stop the recurrence of such explosions in future is laid on the Table of the House.

#### STATEMENT :

1. It has been decided not to grant such licences in congested localities of Delhi.
2. The Sub-Divisional Magistrates concerned have been directed to inspect the premises of such licencees falling in their respective jurisdictions, twice a year in order to ascertain that rules and conditions of the licences are not being violated by the licencees.
3. All holder of licences in form IX of the Arms Act have been required to obtain licences under the Explosives Rules in addition, as the conditions under the latter are more stringent.
4. It has been decided to grant such licences in future only one the production of trade licences from the Corporation Municipal authorities.
5. It has been decided that meetings of the District Magistrate, Additional District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates and Chief Inspector of Explosives, Agra should be held periodically to discuss ways and means to improve the conditions of safety in such factories.

#### Grants to Various Universities and Colleges of Bihar.

6795. SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether grants have been given by the University Grants Commission to

the various Universities and Colleges in Bihar during 1967-68 and 1968-69 ; and

(b) if so, the amount of the grant and the names of Universities and Colleges in Bihar which have received these grants ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-813/69]

#### Opening of New Colleges in Delhi

6796. SHRI B. K. DASCHOWDHURY :  
SHRI D. C. SHARMA :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether there is any proposal with Government to open new Colleges in the Union Territory of Delhi in view of the increasing number of students :

(b) if so, the number and location of the new colleges to be opened ; and

(c) if not, the measures Government propose to take to tackle the situation ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). The Delhi Administration has tentatively decided to open two new colleges in Delhi from the ensuing academic session. The question of their location is under consideration of the Administration.

(c) Does not arise.

#### Use of Maharshi Bhavan as Rabindra Bharati University

6797. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether many well known litterateurs of West Bengal and elder members of the Tagore family objected to the use of 'Maharshi Bhavan', the ancestral home of Rabindra Nath Tagore, as the class-

building for the Rabindra Bharati University ;

(b) whether they requested the authority concerned to preserve 'Maharshi Bhavan' as a National Museum with collections from the days of Ram Mohan to Rabindra Nath as reminiscent of the glorious renaissance period of Bengal and India ;

(c) whether request was also made to use the garden of Maharshi Bhavan as an open theatre stage ;

(d) whether Tolstoy's House at Yasnaya Polonia, Coethe's House at Frankfurt, Shakespeare's Stratford-on-Avon and residential Houses of other international genius of art and culture have been preserved as national museums of their respective countries ; and

(e) if so, whether Government propose to shift the Rabindra Bharati University from Maharshi Bhavan to some new site and preserve this Bhavan as a National Museum under the control of a National Trust, to be constituted for the purpose ?

**THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) :** (a) No, Sir. Only one of the relatives of Rabindra Nath Tagore objected to the use of Maharshi Bhavan for teaching purposes. A new building was in the course of construction but due to paucity of funds this has been delayed. With the increase in classes, the University reluctantly decided to use the rear portion of the Bhavan for holding classes. This is only a temporary measure. When the building is completed, these classes will be shifted there and the Maharshi Bhavan will be used as a Museum.

(b) and (c). No such request has been received. It is proposed to use the entire Maharshi Bhavan for the expansion of the existing Museum and exhibition Hall, etc.

(c) Yes, Sir. But the question of setting up an open air theatre in the campus will be taken up when the Vishva Bharati Publication Department vacates properties it occupies in the campus of Rabindra Bharati.

(d) The homes of Tolstoy, Goeth and Shakespeare are being maintained as Memorial Museums by their respective Governments. Information regarding homes of other international geniuses of art and culture is not readily available.

**Qualifications and Allowances of Chairman of India Tourism Development Corporation, Ashoka Hotels Ltd. and Janpath Hotels Ltd. :**

6798. **SHRI BABURAO PATEL :** Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the qualifications of Shri Romesh Thapar who was within a period of one year from 1st October, 1967 to 5th October, 1968 made the Chairman of three public sector enterprises viz., India Tourism Development Corporation, Ashoka Hotels Ltd., and Janpath Hotels Ltd.

(b) the amount of allowances—by way of Director's fees, daily allowance and travelling allowance—which Shri Thapar received from each of the three undertakings so far ; and

(c) whether, as a Chairman of these three public sector enterprises, Shri Thapar is entitled to free accommodation and, if so, the details of accommodation provided and the rent payable per month ?

**THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) :** (a) Shri Romesh Thapar is an intellectual and journalist of 25 year's standing.

(b) The only payments made to Shri Thapar by the three undertakings right from October 1967 have been as under :—

	Sitting fees for attending meetings of the Board of Directors and Sub-Committees Rs.	Daily allowance Rs.	Travelling allowance Rs.	Total Rs.
India Tourism Development Corporation	525.00	916.57	Nil	1,441.57
Ashoka Hotels Ltd.	650.00	Nil	Nil	650.00
Janpath Hotels Ltd.	175.00	Nil	Nil	175.00
<b>Total</b>	<b>1,350.00</b>	<b>916.57</b>	<b>Nil</b>	<b>2,266.57</b>

(c) No, Sir.

**Appointment of Chairman of Air India and Indian Airlines**

6799. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state ;

(a) whether it is proposed to appoint Shri Romesh Thapar as the Chairman of Air India and Indian Airlines ; and

(b) if so, when ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). The question of appointing new Chairman for the Air-India and Indian Airlines Boards, or reappointing the present Chairmen, will arise only after the terms of the present Boards expire.

**Integration Councils At State Level**

6800. SHRI B. K. DAS CHOWDHURY : SHRI RAGAUVIR SINGH SHASTRI :

SHRI Y. A. PRASAD :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have asked the Chief Ministers to set up Integration Councils at the State level ;

(b) if so, the reactions of the Chief Ministers in this connection ; and

(c) whether any pattern has been suggested for such Councils ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a). Yes, Sir.

(b) The State Governments of Maharashtra, Mysore, Orissa, Manipur and Tripura have set up Integration Councils at the State Level. The matter is under consideration in other States.

(c) As per scheme approved by the Standing Committee of the National Integration Council, State level Integration Councils may be broadly in the pattern adopted for the National Integration Council,

giving representation to the State, district and municipal level leadership. It has been envisaged that the Chief Minister at the State Level and the Collectors/District Magistrates at the District level could take the initiative for the purpose. The major functions of the State level Councils would be to give impetus to activities of official and non-official organisations and groups for promoting national integration and to keep the National Integration Council informed of the pace of implementation of its recommendations at the grass roots, and the obstacles and difficulties, if any, encountered in the process.

**Home Minister's Discretionary Fund**

6801. SHRI B. K. DAS CHOWDHURY Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total amount of grant given to persons out of the Home Minister's Discretionary Fund during the year 1966-67 and 1967-68; and

(b) the names of the persons to whom these grants were given and the reasons for the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS : (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a)	1966-67	Rs. 171,478.00.
	1967-68	Rs. 198,900.00.

(b) It has been our practice not to disclose the names of the beneficiaries with a view to avoid the embarrassment that might be caused to them.

**Communal Riots in Cuttack**

6802. SHRI ONKAR LAL BERWA : SHRI N. R. LASKAR : SARI CHENGALRAYA NAIDU:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there were communal riots at Kendrapara, the Sub-Divisional town in Cuttack during 1969;

(b) the number of persons killed and injured in the firing ;

(c) whether communal forces are active in this town; and

(d) if so, the steps Government propose to take to crush these communal tendencies in the State ?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :**

(a) According to information received from the State Government a communal incident took place at Kendrapara on 30th January, 1969.

(b) Four persons were killed and three persons injured due to firing by police.

(c) According to information furnished by the State Government such forces are not active at present.

(d) The district authorities have taken steps to maintain law and order and to ensure peace among the communities.

**Air Services Agreement of 1947 between India And France**

6803. **SHRI ONKAR LAL BERWA :**  
**SHRI N. R. LASKAR :**  
**SHRI CHENGALRAYA NAIDU :**

Will the Minister of **TOURISM AND CIVIL AVIATION** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governments of India and France have amended the air services agreement of 1947 ;

(b) if so, the main points of the amendments; and

(c) to what extent these amendments will be useful to both the countries ?

**THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) :** (a) Yes, Sir. The India-France Air Services Agreement of 1947 was amended in July, 1967.

(b) and (c). Under the new arrangements Air France was permitted with

immediate effect to have three frequencies a week through Delhi and one frequency a week through Bombay in lieu of their earlier right to have three frequencies a week through Delhi and one through Calcutta. It was also agreed that Air France could operate an additional, i.e. fifth, frequency through Bombay with effect from April 1969. In return Air-India was given the right to operate immediately five frequencies a week through Paris in lieu of their previous right to operate only four frequencies a week. It was also agreed that Air-India would operate a sixth frequency through Paris from April 1969. Air-India was thus given a frequency advantage in return for the right conceded to Air France to serve Bombay in lieu of Calcutta.

**International Conference on Central Asia**

6804. **SHRI B. K. DASCHOWDHURY :**  
**SHRI SHIVA CHANDRA JHA :**  
**DR. SUSHMA NAYAR :**  
**SHRI K. LAKKAPPA :**  
**SHRI A. SREDHARAN :**

Will the Minister of **EDUCATION AND YOUTH SERVICES** be pleased to state :

(a) whether an International Conference on Central Asia was held in New-Delhi on the 11th February, 1969 ;

(b) the names of the countries which participated in the Conference ; and

(c) the broad out lines of the matters discussed and the decisions arrived at in the Conference ?

**THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) :** (a) Yes, Sir. It was held from the 11th to the 15th February, 1969.

(b) Afghanistan, Iran, India, Italy, Mongolia, Turkey, U. S. A., U. K., and U. S. S. R.

(c) The main theme of the conference was "Movement of peoples and ideas bet-

were the countries of Central Asia from pre-historic times to the modern period". Developments in Archaeology, Historical Studies, Literature and Arts in Central Asia were discussed. The History of Ideas in Central Asia received special attention in papers and discussions at the conference. As regards the decisions arrived at in the conference, a statement indicating the conclusions and recommendations is laid on the Table of the House. [*Placed in Library.* \*See No. LT—814/69].

**Awards to Government Staff Learning Hindi**

6805. SHRI SITARAM KESRI :  
SHRI BHARAT SINGH  
CHAUHAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to give awards to Government Staff learning Hindi ;

(b) if so, the nature of awards to be given ; and

(c) the amount earmarked for the purpose during the year 1969-70 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The following awards are sanctioned for the Central Government employees learning Hindi under the Hindi Teaching Scheme :

*Cash Awards* : Cash awards ranging from Rs. 100 to Rs. 300 are granted to non-Hindi knowing employees who acquit themselves creditable in the Praveen and Pragya examinations. Cash awards are also granted to the employees who pass the Hindi Typewriting and Hindi Stenography examinations meritoriously.

*Lump Sum Awards* : Lump sum awards had been sanctioned in 1965 to the operational staff who cannot be spared to attend the Hindi classes, during office hours, on their passing the prescri-

bed Hindi examinations by their own efforts. The scale of the lump sum awards has been increased from December, 1968 examinations. The increased rates are :

Prabodh	Rs. 250.00
Praveen	Rs. 250.00
Pragya	Rs. 300.00

A new Scheme of Lump Sum awards has been introduced from December, 1968 examination for passing of Hindi examinations by such employees who are posted at places where there are no Hindi Teaching centres under the Hindi Teaching Scheme. The rates of the lump sum awards are the same as now sanctioned for the operational staff.

(c) An amount of Rs. 1,75,000 has provided in the budget estimates for the year 1969-70 for grant of cash awards. The expenditure on the lump sum awards is incurred by the Ministries/Departments of Government of India concerned.

**Development of Inland Water Transport**

6807. SHRI YASHPAL SINGH :  
Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether any amount has been sanctioned by the World Bank for the development of Inland Water Transport in the country ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

**Ban on Recruitment to Lower-Level Posts**

6808 SHRI D. C. SHARMA :  
SHRI BENI SHANKER SHARMA :  
SHRI HARDAYAL DEVGUN :  
SHRI RANJIT SINGH :  
SHRI BAL RAJ MADHOK :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a virtual ban on fresh recruitment to lower-level posts in the Central Government offices has been imposed to tackle the problem of surplus staff the number of which now runs into several hundreds ;

(b) if so, the number of such persons category-wise and department-wise ; and

(c) the steps taken to absorb them elsewhere ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) In order to facilitate the redeployment of staff rendered surplus as a result of introduction of administrative reforms by the Department of Administrative Re-

forms studies conducted by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance, *suo-moto* studies of work measurement and from abolishing and winding up of permanent or long term organisations, certain restrictions have been imposed since 1966 on filling of all posts ; whether by promotion or direct recruitment, unless a certificate is obtained from the Cell that it has no suitable candidates to offer. These restrictions do not, however, apply to recruitment to ministerial cadres through normal channels like the annual competitive examinations held by the Union Public Service Commission.

(b) The total number of persons on the rolls of the Central (Surplus Staff) Cell as on 14.4.1969 was 63. The category-wise and department-wise details of these 63 persons are given below :

Department	Category			Total
	Class I	Class II	Class III	
(i) Min. of Information & Broadcasting	—	1	1	2
(ii) Min. of Labour Employment & Rehabilitation (Deptt. of Rehabilitation)	—	—	61	61
	—	1	62	63

(c) Out of 63 persons awaiting redeployment as on 14.4.1969, 37 persons have been sponsored against Vacancies in other organisations. The remaining 26 will also be sponsored as soon as suitable vacancies are reported to the Cell.

the Centre to create its own Special Police Force to enforce its laws in the States was under consideration ;

(b) if so, the outcome thereof ; and

(c) the action proposed to be taken in the matter ?

Creation of Central Special Police Force

6809. SHRI D. C. SHARMA :

SHRI BENI SHANKER SHARMA :

SHRI HARDAYAL DEVGUN :

SHRI RANJIT SINGH :

SHRI BAL RAJ MADHOK :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the question of examining the constitutional permissibility for

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) to (c). The Central Government are examining the question whether it would be competent for Parliament to entrust, by law, to a Central investigating agency powers to investigate and prosecute offences under laws relating to items in the Union List, and certain specified classes of offences under laws relating to items in the Concurrent List.

**Nationalisation of Shipping Industry**

6810. SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in some daily papers wherein it has been stated that the revolutionary Government of Burma have taken over 24 private shipping agencies operating in that country ; and

(b) if so, whether the Government of India propose to take similar steps here also ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) The news item in question has not come to our notice but we do have information otherwise that 24 private shipping agencies were nationalised by the Revolutionary Government of Burma during 1969.

(b) No, Sir.

**National Policy on Education**

6811. SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Dr. P. V. Cherian, Governor of Maharashtra in his convocation address of the Osmania University, Hyderabad, has stated that 'nearly 20 years have gone but we have not been able to agree even on a national policy on education ; and

(b) if so, the reaction of Government in the matter ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) On the basis of the Report of the Education Commission and the discussions held thereon, the Government of India has issued a Resolution on the National Policy on Education which was

laid on the Table of both the Houses of Parliament on 24th July, 1968.

**Gopal Sena in Kerala**

6812. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of the Central Government that an organisation known as Gopal Sena has been operating in Kerala for some time past ;

(b) whether it is also a fact that this organisation has set up training centres in different areas of Kerala and the curriculum for the trainees includes training in fire-arms and recitation of Mao's thoughts ;

(c) whether Government have sought the help of the Kerala Government in curbing the activities of this organisation ; and

(d) if so, the Kerala Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Attention is invited to the answer to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 731, dated 16th February, 1968.

(b) According to information received from the state government the volunteers are being given training in squad drill, lathi exercises, bayonet charging, unarmed combat etc. They are being given regular study classes by marxist leaders.

(c) and (d). The state government has given strict instructions to the police to take action against those who violate law.

**Passenger Traffic Carried by Road Transport**

6813. SHRI HARDAYAL DEVGUN : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :



(a) the passenger traffic carried by road transport in 1961 and 1969 ;

(b) the total passenger traffic in the country ;

(c) the total capital investment in the State Transport Undertakings and the gross revenue therefrom ; and

(d) the gross return on the capital ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) The estimates of passenger traffic by road during the relevant period are as under :—

Year	Traffic	
1960-61	57,000	million passenger Kms.
1968-69	100,000	-do

(b) The estimated total passenger traffic in the country (rail and road) is as follows :—

Year	Rail	Road	Total
1960-61	77,665	57,000	134,665
1968-69	113,000	100,000	213,000

(c) The total capital investment in the State Road Transport Undertakings and the gross revenue therefrom for the year ending 31.3.1968 are estimated at over Rs. 208 crores and Rs. 200 crores respectively.

(d) The gross return on capital for the year 1967-68 is estimated at over 5%.

**Central Ministers' entry into Bombay not Allowed consequent to Border disputes Between Maharashtra and Mysore**

6814. SHRI YAJNA DATT SHARMA ;  
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR ;  
SHRI MOHAMMAD ISMAIL ;  
SHRIMATI SUSEELA GOPALAN ;  
SHRI UMANATH ;  
SHRI C. K. CHAKRAPANI ;  
SHRI YASHWANT SINGH  
KUSHWAH ;  
SHRI A. K. GOPALAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister and her Cabinet colleagues were not allowed to enter the city of Bombay and in the presence of the Ministers, the public over there were tear-gassed, lathi-charged and firing was resorted to ;

(b) whether it is also a fact that the trouble arose because of indecision on the part of the Central Government to settle the border dispute between the States of Maharashtra and Mysore ;

(c) if so, the decision taken by Government in the matter ; and

(d) the steps Government propose to take in the shape of legislation or arranging conference with the States in the country in order to ensure that the Central Ministers are assured freedom of movement and the legitimate protection in the discharge of their official duties ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) It is not correct that the Prime Minister and Members of the Union Council of Ministers were not allowed to enter Bombay. According to information furnished by the State Government, the police did not use teargas or resort to firing in the presence of Central Ministers to disperse mobs. However when a riotous mob was pelting stones on the convoy of the Deputy Prime Minister, the police resorted to canecharge on February 7, 1969 to disperse the mob.

(b) The Shiv Sena had announced an agitation on the Maharashtra-Mysore border dispute.

(c) No decision has yet been taken but Government are anxious to settle this delicate and complicated matter as expeditiously as possible.

(d) All the State Governments make necessary security arrangement in connection with the visits of Central Ministers to States.

**राज्य सरकारों के कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर मंहगाई भत्ता देना**

6815. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने 1 जनवरी, 1968 से अपने कर्मचारियों को उतना ही मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की है जितना कि केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का देती है ;

(ख) कौन-कौन सी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बराबर मंहगाई भत्ता दे रही हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश सरकारों ने, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की है, अराज-पत्रित तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में प्रतिनियुक्त अराजपत्रित तथा अन्य कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का अभी तक भुगतान नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकारों के कर्मचारियों को यह धन-राशि न देने के क्या कारण हैं, तथा उन्हें इस राशि का कब तक भुगतान कर दिये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने 1-1-1968 से अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरें केवल एक बार अर्थात् 1-9-1968 से संशोधित की है । निम्नलिखित राज्य बिल्कुल इन्हीं

(केन्द्रीय) दरों पर प्रत्येक के सामने दिखाई गई तारीखों से मंहगाई भत्ता दे रहे हैं :—

1. हरियाणा	1-9-1968
2. पंजाब	1-9-1968
3. राजस्थान	1-9-1968

इसके प्रतिरिक्त निम्नलिखित राज्य केन्द्रीय दरों पर कुछ पट्टियों (स्लैबों) में मामूली भिन्नता के साथ मंहगाई भत्ता दे रहे हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश	1-2-1969
2. मद्रास	1-1-1969

(90-109 रु० की पट्टी में 90 रु० की दर है और 1000-1018 की पट्टी में 100 रु० की दर है)

(आन्ध्र प्रदेश और मद्रास दोनों के लिए) ।

3. मैसूर 1-4-1969 (90-109 रु० की पट्टी में 85 रु० की दर है और 1000-1018 की पट्टी में 100 रु० की दर है) ।

4. मध्य प्रदेश 1-3-1969 (100-1018 रु० की पट्टी में 100 रु० की दर है)

(ग) और (घ). विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले राज्य सरकारों के कर्मचारी, यदि वे राज्य सरकार के वेतन-मानों को रखे रहते हैं अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों के वेतनमान में वेतन लेते हैं, क्रमशः राज्य सरकारों के नियमों के अधीन अथवा केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन मंहगाई भत्ते के पात्र होंगे । यदि किसी राज्य सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते की दरें संशोधित की जाती हैं तो राज्य सरकार के वेतनमानों को रखने के लिए बनने वाले केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में उक्त संशोधित

आदेशों को, प्रशासनिक मंत्रालयों। विभागों कार्यालयों द्वारा जहां वे प्रतिनियुक्ति पर हैं, लागू किया जाएगा। मंहगाई भत्ते के न दिये जाने के बारे में किसी मामले की सूचना गृह-मंत्रालय को नहीं मिली है।

#### Youth Activities

6816. DR. SUSHILA NAYAR : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the different youth activities proposed to be handled by the new youth services department of his Ministry ;

(b) whether, at a recent meeting of the Education Ministers, some suggestions had been made that more attention should be paid to the development of youth programmes ; and

(c) if so, the salient features of the proposals ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) The following schemes have been included in the Fourth Five : Year Plan in respect of youth services programmes :

1. Campus Works Projects.
2. Planning Forums.
3. Scouting and Guiding.
4. Assistance to Voluntary Organisations working in the field of youth services.
5. Exchange of visits by students from one part to students in other parts.
6. Assistance to Youth Welfare Boards set up by universities.
7. National Service Corps and National Sports Organisation.

This Ministry is considering preparation of a comprehensive plan the details of which are being worked out.

(b) and (c). The Conference of State Education Ministers held at New Delhi in April, 1967 recommended inter alia

that adequate facilities in NCC, National Service Corps or Sports should be made available to every student. Accordingly a programme of National Service Corps and National Sports Organisation has been formulated for the purpose of promoting national consciousness and a sense of discipline and dignity of labour among the university and college students. The scheme provides that male student in the first and second year of the degree course will participate in one or the other of the three programmes viz. NCC, NSC, NSO, though the NSO programme will be confined to selected students showing marked proficiency in sports and games.

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद

6817. श्री भीठालाल भीना : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद विकट आर्थिक कठिनाई में है ;

(ख) क्या यह सच है कि सम्मेलन को जो वित्तीय सहायता दी जाती थी वह पिछले कुछ समय से नहीं दी जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) यदि अब भी वह वित्तीय सहायता दी जाती है तो कब दी गई और कितनी; और

(ङ) क्या सहायता की राशि सम्मेलन के लिये पर्याप्त है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त वरुण) : (क) जी नहीं। जहां तक केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को जानकारी है, ऐसा नहीं है।

(ख) से (ङ). हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद को अब अनुरक्षण अनुदान रूप में, वित्तीय सहायता उसके दिन प्रति-

दिन के कार्य में हुए वार्षिक घाटे के आधार पर दी जा रही है, अन्तिम अनुदान 1966-67 वर्ष के लिए 1967-68 में दिया गया था। बाद के वर्षों के लिए अनुदान इसलिए स्वीकृत नहीं किए जा सके, क्योंकि सम्मेलन ने अभी तक सम्पूर्ण जांचे हुए लेखे पेश नहीं किये हैं।

**जम्मू तथा काश्मीर में अध्यापकों की पदोन्नति**

6818. श्री प्रकाशबीर शास्त्री : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1968 में असन्तुष्ट प्रशिक्षित काश्मीरी पंडित स्नातक अध्यापकों से उन्हें कोई अग्र्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही का गई ;

(ग) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23 अप्रैल, 1968 के निर्णय को, जिसका उल्लेख उपरोक्त अग्र्यावेदन में किया गया है, पूर्णता क्रियान्वित किया है ;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सभी 81 अपीलकर्ताओं को पदावनत कर दिया गया है ;

(ङ) यदि सभी को पदावनत नहीं किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ;

(च) क्या केवल साठ कनिष्ठ अध्यापकों (अपीलकर्ताओं) को ही पदावनत किया गया है और वे प्रधानाध्यापक तथा तहसील शिक्षा अधिकारियों के रूप में अब भी अपने पुराने पदों पर काम कर रहे हैं ; और

(छ) क्या इक्यासी अध्यापकों के बदले केवल साठ अध्यापकों के पदावनत करने के आदेश जारी करने के बाद जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है, जिनका 1951 से अधिक्रमण किया गया है और जो अपनी वरिष्ठता के आधार पर राजपत्रित संवर्ग में पदोन्नत किये जाने के हकदार हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) :** (क) जी हां। संदर्भाधीन अग्र्यावेदन की एक प्रति मुझे हाल ही में लोक सभा के एक सदस्य से प्राप्त हुई है।

(ख) से (छ). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के ये आदेश थे कि 81 व्यक्तियों को दी गई पदोन्नतियां अर्वाध हैं और प्राथियों को खर्चा दिया जाए। राज्य सरकार ने बताया है कि जून, 1968 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसरण में सभी 81 अध्यापकों को पदावनत कर दिया गया है और खर्च के सम्बन्ध में प्राथियों ने अपने दावे तैयार नहीं किए थे।

**जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कनिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति**

6819. श्री प्रकाशबीर शास्त्री :

श्री उमानाथ :

श्री गणेश घोष :

श्री अ० कु० गोपालन :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करते हुए 23 अप्रैल,

1968 के बाद, उन्हीं साम्प्रदायिक तथा प्रादेशिक भावनाओं के आधार पर पुनः प्रायः तीन दर्जन कनिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति की है और क्या यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 16(1) तथा (4) के विरुद्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे यह सिद्ध होता है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के शब्दों तथा भावनाओं को पूरी तरह लागू नहीं कर रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1947 से उस राज्य की सरकार द्वारा सेवाओं में पदोन्नतियों के मामले में अपनई जा रही साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की नीति के परिणामस्वरूप राजपूत्रित संवर्ग में अपनी पदोन्नति से 200 से अधिक वरिष्ठ प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक बंचित हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पदोन्नतियों के मामले में इन 200 से अधिक इन प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की चिरकाल से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० झार० बी० राव) : (क) से (घ) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**दिल्ली भ्रराजपूत्रित पुलिस कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन**

6820. श्री रामाबतार शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली भ्रराज-पूत्रित पुलिस कर्मचारी संघ ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी मांगें स्वीकार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

**Inter-University Board of India and Ceylon**

6821. SHRI MADHU LIMAYE :

SHRI SHASHI BHUSHAN :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the functions of the Inter-University Board of India and Ceylon and what the Board has done since its inception ;

(b) the amount of grant given by his Ministry and how it has been utilised by the Board ;

(c) in what Capacity did the Board's Secretary undertake tours to the U. S. A., Australia and Hong Kong within a span of one and a half years ;

(d) whether his visits have in any way contributed towards the improvement of higher education in the country ; and

(e) when the Chairman of the Board, who is actively associated with the administration of higher education did not represent the country abroad, while the Secretary, who is not concerned with influencing higher education, was sent as India's representatives ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) A statement giving the functions of the Board is laid on the

Table of the House. [*Placed in library.*  
 See No. L.T.—815 /69]

The Board has been undertaking various Programmes and activities in keeping with its functions.

(b) The following grants were paid to the Board to meet a part of their maintenance expenditure during the last five years :—

	Rs.
1964-65	10,000
1965-66	28,000
1966-67	46,843
1967-68	50,000
1968-69	50,000

The Grants were utilised for the purpose for which they were sanctioned.

(c) The Secretary of the Board was invited to visit the universities in U. S. A. by the Danforth Foundation in 1967. In August, 1968, he attended the Tenth Congress of Commonwealth Universities held in Australia as a Member of the Indian delegation. The Secretary's visit to Hong-Kong was undertaken in a private capacity. In all the cases, his visits abroad were approved by the Board.

(d) The visits have helped the Secretary and consequently the Board in understanding the present trend of changes taking place in higher education in other countries. It has also helped the Board in keeping a liaison with sister institutions/agencies for exchange of information.

(e) The Secretary of the Board who was formerly a University teacher is actively associated with the programmes of higher education in the country. He however, did not represent the country during his visit to the U. S. A. For visit to Australia he was nominated by the Board as a member of the Indian delegation.

#### Encounter with Rebel Nagas in Monglhan in Manipur

6822. SHRI BALRAJ MADAOK : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a large gang of Naga hostiles armed with light machine guns and other automatic weapons surprised a village volunteer force post at Monglhan in the Northern part of Ukhrul sub-division of Manipur on the 29th January, 1969 and took away eight rifles and ammunition from the post after a brief gun battle ;

(b) if so, the details of the incident ; and

(c) the action taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) to (c). On the 29th January, 1969 about ten armed hostiles suspected to be Mizos/Kukis attacked the post of the Village Volunteers at Monglhan in Sadar sub-division of Manipur and took away 8 rifles and some ammunition. The gang was chased and intercepted on 4th February, 1969. Six of the eight rifles were recovered along with some of the ammunition and two hostiles were captured. A case has been registered by the police. Three persons have been arrested and further, investigation is in progress.

#### Clandestine Radio Transmitting Stations

6825. SHRI BALRAJ MADHOK :

SHRI BENI SHANKAR SHARMA :

SHRI RANJIT SINGH :

SHRI D. C. SHARMA :

SHRI HARDYAL DEVGUN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether he is aware that there are clandestine radio transmitting stations or instruments in India, which transmit secret information to foreign countries, especially to Pakistan from time to time ;

(b) if so, the steps taken to unearth the same and take suitable measures to deal with them ; and

(c) if no steps have been taken, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA):

(a) According to information furnished by the State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore, Nagaland, Orissa, Rajasthan and West Bengal and from the Union Territories no such clandestine transmitting station or equipment has come to notice. Information from the State Governments of J. & K., Kerala, Madras, Punjab, U. P. and the Union Territory of Himachal Pradesh is awaited.

(b) and (c). Do not arise.

**Recommendations of Education Commission on Development of Science Subjects in Higher Secondary Schools**

6824. SHRI K. LAKKAPPA :  
SHRI A. SREEDHARAN :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether all the recommendations of the Education Commission pertaining to the development of Science subjects in Higher Secondary Schools in the country have been implemented ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). This is the concern of the State Governments to whom the recommendations of the Commission were forwarded for the consideration and implementation.

The Ministry of Education and Youth Services has helped the States in strengthening science laboratories of secondary schools and in-service of science teachers through an assistance of Rs. 6.78 crores during 1964-69. This scheme has been transferred to the State Sector in the 4th Plan. The National Council of Educational Research and Training has prepared model syllabi and some text-

books for existing higher secondary schools ; and these have been forwarded to the States for such use as they think best.

**क्लास फोर म्यूचल बेंनीफिट सोसायटी कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली**

6825. श्री अजुन सिंह भदौरिया :  
श्री श्रीकार लाल बेरबा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'क्लास फोर म्यूचल बेंनीफिट सोसाइटी,' भारत सरकार कस्तूरबा नगर के प्रधान तथा इसके अन्य कार्यकर्त्ताओं का व्यवहार वहां के निवासियों के प्रति अच्छा नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं करने का विचार है, तो इसके क्या कारण है ;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त सोसाइटी को भंग करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग). कस्तूरबा नगर की दो कल्याण संस्थाओं में से एक भारत सरकार चतुर्थ श्रेणी पारस्परिक सहयोग समिति है जिसका गठन 1966-67 में पुरानी कल्याण संस्था की प्रतिद्वन्दी संस्था के रूप में किया गया था। हाल में समिति के कार्य कर्त्ताओं द्वारा कथित असन्तोषजनक व्यवहार के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस प्रकार की शिकायतों का आना कोई

असाधारण बात नहीं है, जहाँ किसी एक क्षेत्र में एक से अधिक संस्थाएँ चल रही हों। चूँकि समिति सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करती है तथा मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः कोई कारवाई करने का विचार नहीं है।

(घ) और (ङ). भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

#### मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्र

6826. श्री गं० च० दीक्षित : क्या पर्यटन तथा अर्थसैनिक उद्घुयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कुछ नये महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो वे पर्यटक केन्द्र किस-किस स्थान पर स्थापित किये जायेंगे और उनके नाम क्या-क्या होंगे ; और

(ग) सरकार का कब तक इस योजना को क्रियान्वित करने का विचार है ?

पर्यटन तथा अर्थसैनिक उद्घुयन मंत्री ( डा० कर्ण सिंह ) : (क), से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में, खजुराहो, कान्हा-किसली और सांची का समकित विकास करने का अनन्तिम रूप से प्रस्ताव किया गया है। साधनों के परिसीमित होने के

कारण मध्य प्रदेश में किन्हीं नये पर्यटक केन्द्रों के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

#### मध्य प्रदेश में इण्डियन सिविल सर्विस/ भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की संख्या

6827. श्री गं० च० दीक्षित : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1969 को मध्य प्रदेश में इण्डियन सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी थे ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने अधिकारी थे ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों की संख्या उनके लिये नियत कोटे के अनुरूप है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क)  
भारतीय सिविल सेवा के 8;  
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 205;  
भारतीय पुलिस सेवा के 173;

(ख)

	अनुसूचित जातियों के	अनुसूचित आदिम जातियों के
भारतीय सिविल सेवा	...	...
भारतीय प्रशासनिक सेवा	12	3
भारतीय पुलिस सेवा	10	3

(ग) और (घ). भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के कोटे में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण अखिल भारतीय आधार पर किया जाता

है न कि राज्यवार। पिछले कुछ वर्षों में उनकी भर्ती, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक की जा रही है। उन भर्ती किये व्यक्तियों की आनुपातिक संख्या, मध्य प्रदेश को धारदित की जाती है।



**मध्य प्रदेश में पुरातत्वीय सर्वेक्षण तथा  
खुदाई कार्य**

6828. श्री गं० च० दीक्षित : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 और 1968-69 में मध्य प्रदेश में पुरातत्वीय सर्वेक्षण अथवा खुदाई कार्य करने के अधिक प्रयत्न किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर यह कार्य आरम्भ किया गया था और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में नर्वंदा घाटी सभ्यता के बारे में प्रयोगात्मक कार्य आरम्भ करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहानाबारा जयपाल सिंह) :  
(क) और (ख). 1967-68 के दौरान भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण ने जबलपुर जिले में पुरावस्तुओं की खोज का कार्य गांव-गांव में जारी रखा और पाषाण युग से लेकर मध्यकालीन युग की पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाया। कार्य को 1968-69 के दौरान भी जारी रखा गया था। तथापि, इन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के किसी स्थान पर भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा खुदाई का कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि 1967-68 के दौरान दक्कन कालेज और उत्तर-स्नातक अनुसंधान संस्थान, पूना के सहयोग से सागर विश्व-विद्यालय, और विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा क्रमशः त्रिपुरी जिला जबलपुर और कायथ, जिला उज्जैन

में खुदाई की गई थी। इन खुदाइयों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व 1967-68 में प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा, राज्य पुरातत्व विभाग और सागर विश्वविद्यालय द्वारा दमोह, रायसेन से सतना और उज्जैन जिलों में इक्का-दुक्का स्थान पर खुदाई की गई थी।

सागर विश्वविद्यालय ने 1968-69 के दौरान त्रिपुरी में खुदाई जारी रखी। अन्य संस्थाओं (एजेन्सियों) द्वारा किए गए कार्यों की प्रतीक्षा है।

(ग) भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में अपने आप कोई खुदाई नहीं कराई क्योंकि वहां केवल एक खुदाई शाखा है जो इन पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य कार्यक्रमों में पूर्ण रूप से व्यस्त थी।

(घ) फिलहाल भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**मध्य प्रदेश में बंगे**

6829. श्री गं० च० दीक्षित : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से 31 जनवरी, 1969 तक मध्य प्रदेश में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए तथा उनमें कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ख) क्या सरकार ने स्वयं अथवा राज्य सरकार के माध्यम से इस बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1967 से रतलाम में 28 सितम्बर, 1967 को ;

मंदसौर जिले के मन्सा में 2 नवम्बर, 1967 को ; मंदसौर में 19 मार्च, 1968 को, रतलाम में 9 और 10 अप्रैल, 1968 को और इन्दौर में 31 दिसम्बर, 1968 से 3 जनवरी, 1969 तक साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में कोई व्यक्ति नहीं मारा गया।

(ख) और (ग). उपरोक्त पहली तीन घटनाओं के सिलसिले में 99 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाए गये हैं। चौथी घटना के सम्बन्ध में तीन मामले दर्ज किये गये। पांचवीं घटना के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा 287 के अधीन 319 व्यक्ति और दण्ड प्रक्रिया संहिता के निवारक उपबन्धों के अधीन 32 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

#### Hippies in India

6830. SHRI DEVEN SEN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of hippies who have come to India since 1967 uptill now, with the names of their counties of origin ;

(b) the source of their income and how they maintain themselves ;

(c) how many of them are men and how many women and what is the purpose of their visit to this country ;

(d) whether Government have any report as to whether any of them is involved in any spying activities in India ; and

(e) whether there is any report of any of them indulging in any un-social activities injuring the moral health of the surrounding people ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) to (c). No separate statistics are

maintained of the arrival etc., in India of Hippies, which term presumably refers to foreign nationals who do not conform to the normally accepted standards of dress etc. The information asked for is not, therefore, available.

(d) No Sir.

(e) Some such foreigners have come to notice for certain unlawful activities like illicit possession of drugs, unlicensed arms etc.

#### ग्राम्भ प्रवेश में पादरी फेरर द्वारा धार्मिक प्रचार

6831. श्री रामगोपाल शालबासे : क्या गृह-कार्य मंत्री 30 अगस्त, 1968 के अति-रक्षित प्रश्न संख्या 6618 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पादरी फेरर को ग्राम्भ प्रदेश में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्राम्भ प्रदेश की (केन्द्रीय दक्षिण) ग्राम्य प्रतिनिधि सभा ने इसका कड़ा विरोध किया है तथा कई अन्य संगठनों और गणमान्य नागरिकों ने भी इसका विरोध किया है ; और

(ग) जन-भावना की अवहेलना करके उन्हें राष्ट्र विरोधी कार्यवाही करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बताया जाता है कि पादरी फेरर सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए आये हैं।

(ख) मध्य दक्षिण हैदराबाद की ग्राम्य प्रतिनिधि सभा और कुछ अन्य दूसरे व्यक्तियों ने उनके ग्राम्भ प्रदेश में ठहरने का विरोध किया, ऐसा बताया जाता है।

(ग) उनकी कोई राष्ट्र विरोधी गति-विधियां ध्यान में नहीं आई हैं।

**Curtailment of Distance between  
Bikaner and Delhi**

6832. DR. KARNI SINGH : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government are aware that for the benefit of tourists and other road traffic, the distance between Bikaner and Delhi can be curtailed by about 60 miles if the gravelled portion of the road about 28 miles long from Jhumpa (Haryana) and Hissar (Haryana) was tarred and completed in all respects for diversion of traffic ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to remove this obstacle ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The construction of the Jhumpa-Hissar portion of the road as a black-topped road has already been taken up and 50% of the work was completed up to December, 1968.

**Murder of a Harijan in Bangalore**

6834. SHRI DEVEN SEN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Halappa, a Harijan member of the village panchayat of Kyaasnakre in Bangalore was murdered 22 days after he had appealed for protection sensing danger to his life ;

(b) whether it is a fact that the said Halappa wrote to the Prime Minister and the Union Food Minister on the 6th September, 1968 seeking their protection ; and

(c) if so, the steps taken in the matter by the Central Government and the State Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). Facts are being ascertained from the State Government.

**भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों  
की गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाना**

6835. श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग में केवल श्रेणी-1 के अधिकारियों को ही कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार प्राप्त है, जबकि सम्बन्धित कर्मचारी उनसे पद के अनुसार बहुत नीचे हैं तथा उनके साथ इन कर्मचारियों का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता और जबकि इन कर्मचारियों के कार्य की देखभाल तथा अधीक्षण करने के लिये अन्य बहुत से राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारी विद्यमान हैं ; और

(ख) क्या यह प्रक्रिया गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 31 अक्टूबर, 1961 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ—51/14/60 एस्टेब्लिशमेंट (ए) का कंडिका के अनुबन्धों का उल्लंघन नहीं करती, जिसमें यह बात बहुत स्पष्ट कर दी गई है कि केवल वही अधिकारी कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट लिख सकता है जिसके अधीन वह कर्मचारी सीधे कार्य करता हो, भले ही वह अधिकारी राजपत्रित हो अथवा अराजपत्रित ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री भक्त बर्षन ) : (क) अभी तक, क्षेत्रीय दलों (फील्ड पार्टीज) के कार्यभारी अधिकारियों द्वारा ही क्षेत्रीय दलों के सभी सदस्यों की गोपनीय रिपोर्ट लिखे जाने की प्रथा रही है क्योंकि विभिन्न शिविर अधिकारियों के अधीन प्रत्येक सत्र में शिविर दलों के कर्तव्य

अक्सर बदलते रहते रहते हैं। अचल (सकिल) कार्यालयों और ड्राइंग कार्यालयों के मामलों में भी इसी प्रथा का पालन किया जाता है जहाँ क्रमशः उप निर्देशक और अधीक्षक सर्वेक्षक रिपोर्ट लिखते हैं।

(ख) विभाग को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वह भविष्य में गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-51/14/60 एस्टेंस (ए), दिनांक 31-10-1961 के उपबन्धों का कठोरता से पालन करें।

**Writ Petitions filed by officers of former Madras State**

6836. SHRI A. K. GOPALAN :  
SHRI VISHWANATHA  
MENON :  
SHRI K. ANIRUDHAN :  
SHRI K. M. ABRAHAM :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) how many writ petitions were filed in the Kerala High Court by the officers allotted from the former Madras State to Kerala consequent on the reorganisation of States ; and

(b) how many of such petitions have been disposed of ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Construction of Tuticorin Harbour**

6837. SHRI S. XAVIER : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the progress made so far in the construction of Tuticorin harbour ;

(b) the amount which has been spent so far in this respect ;

(c) the allotment of funds for 1969-70 ; and

(d) how long will it take to complete the construction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) :  
(a) The progress of works is as follows :

*Preliminary and Shore Works :*

The preliminary works such as Field Investigations, Land Acquisition, approach roads, internal roads, roads to quarries, railway siding to quarries, 1st and 2nd stage of quarters (232 quarters), temporary offices, water supply, sewerage, electrification, filling in low area etc. have been completed.

**Off-shore Works :**

*1. Construction of North Breakwater.*

The work on the construction of North Breakwater for a length of 1215 m out of a total length of 4142m from shore has been completed. The work on the reach 1215m to 1365m is in progress.

*2. Construction of South Breakwater.*

The work on the construction of South Breakwater for a length of 1143m out of a total length of 3767m from the shore has been completed. The work on the reach 1143m to 1321m is in hand.

*3. Approach Arm.*

The work of reclaiming the approach arm from chart datum to -2m is complete.

(b) A gross expenditure of Rs. 960 lakhs has been incurred on the Project to the end of March, 1969 from its inception.

(c) Rs. 300.00 Lakhs.

(d) The work is being progressed on basis of annual allocations for the project which are made from year to year in the light of the resources available and in consultation with the Planning Commission.

#### Attendance in Post-Graduate Classes

6838. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he is reported to be credited with the view that it is no longer essential to insist on attendance in the post-Graduate classes ;

(b) whether his views reflect any Government move in reforming the existing system particularly in the Central Universities ; and

(c) if not, whether the desirability of implementing the suggestion has been considered in collaboration with the Vice-Chancellors of the Central Universities ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V.K.R.V. RAO) : (a) and (b). A suggestion to this effect was made by me while inaugurating a seminar on examination reform and compulsory attendance in the University of Delhi on March 1, 1969. In my opinion, abolition of the present system would be one useful way for promoting the efficiency of higher education.

(c) No, Sir.

#### Deployment of C. R. P. in Asansol

6839. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the deployment of the Central Reserve Police had to be resorted to in the coal mine areas in Asansol during the last six months ;

(b) if so, whether as a result of the stay of the C. R. P., the situation in the coal mine areas has improved ; and

(c) the circumstances which had necessitated the deployment of the C.R.P. and what extent those factors have been mitigated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). Information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House when received.

#### कलकत्ता के निकट पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

6840. श्री झोंकार लाल बेरबा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 मार्च, 1969 को पाकिस्तानियों का एक दल कलकत्ता के निकट भारत-पाकिस्तान सीमा पर, भारतीय नागरिकों की फसल काट कर हजारों रुपये की फसलें ले गया ; और

(ख) उस सीमा पर लगाये गये हमारे सीमा सुरक्षा गाड़ों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(ख) भारत पाकिस्तान सीमा की रक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सीमा बाहरी चौकियाँ स्थापित की गई हैं । इस ब्यौरे को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

#### Grants to Universities in Orissa

6841. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the amount of grant allocated to Utkal, Sambalpur and Behrampur Universities in Orissa separately for the year 1969-70 ; and

(b) the names of projects for which such grants have been allocated for these three Universities in Orissa ?

**THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) :** (a) The University Grants Commission does not allocate grants to universities on yearly basis. This is, however, done generally for a plan period on the recommendations of the Visiting Committees, which are appointed to assess the development requirements of the universities. Grants are released in the light of the progress made in the implementation of the approved projects and the expenditure incurred on them.

The Commission on the recommendation of the Visiting Committees appointed to assess the developmental needs of the universities in Orissa has allocated the followings grants for the five year period ending 1970-71 :

	(Rs. in lakhs)
Utkal University ...	78.92
Berhampur University ...	37.70
Sambalpur University ...	48.26

In the light of the likely allocation of the Commission for the period 1966-67 to 1970-71 the Universities have been advised to indicate schemes which could be implemented within 70 percent of the above allocation. While the programmes of the Utkal University, to be accommodated within 70% of the allocation, have been accepted by the Commission. the same from the other two universities are still awaited.

The Commission has allocated grants for the appointment of additional staff for Departments in Science subjects, Humanities and Social Sciences, Library books and Journal; equipments, departmental buildings, students hostels and other amenities, staff residence and certain other miscellaneous programmes.

#### National Highway No. 39

**6842. SHRI M. MEGHACHANDRA :** Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the amount sanctioned for the repair of the National Highway No. 39 for both Nagaland and Manipur sector during the years 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the amount actually spent out of the amount sanctioned during the said period by the P. W. D. of Nagaland and Manipur ; and

(c) any amount surrendered being unused during the said period ?

**THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) :** (a) and (b). The information is as follows :

State	Amount sanctioned during		Amount actually spent during	
	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69
	Rs. lakhs			
Nagaland	8.00	24.00	8.68	Actuals not yet available.
Manipur	7.00	10.04	12.57	—do—

(c) A sum of Rs. 25 lakhs was originally earmarked for allotment to the Government of Nagaland during 1968-69. On receipt of intimation in this regard, the State Government reported their final demand at Rs. 24 lakhs, which was sanctioned. The balance of Rs. 1 lakh was diverted elsewhere.

#### National Highway No. 39

**6843. SHRI M. MEGHACHANDRA :** Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Highway No 39. was blocked with heavy land-slide during the year 1968 for many days and usual traffic was consequently dislocated ;

(b) if so, whether any measure has been adopted to check the same road block this year ;

(c) whether the Manipur State Transport had to incur heavy expenses in transporting thousands of food bags for Manipur at an exorbitant rate of transport per bag ;

(d) if so, the total number of bags so transhipped and the amount spent in the said transaction during the days of road block ; and

(e) whether the transaction was handled by the M. S. T. direct or by some firms on contract ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT ( SHRI IQBAL SINGH ) : (a) Yes, Sir. Some portion of the 42nd mile of National Highway No. 39 in Nagaland.

(b) The section from Piphima to Kohima falls in a geological fault line and is subject to frequent subsidence and slips—the most vulnerable portion being between the 40th and 44th miles. Immediate relief was provided for by repairing the bypass constructed in this area during the World War II, and by making it suitable for jeeps and 15-Cwt vehicles. Subsequently, estimates amounting to Rs. 14 lac were sanctioned for carrying out further improvements, including realignment of certain miles and strengthening and widening the rest, to make it suitable for normal traffic.

The realignment of the whole section is also under consideration in consultation with the Geological Survey of India. The reclaimed bypass would continue to be maintained, however, in a serviceable condition.

(c) Yes.

(d) (i) about 9,500 bags.  
(ii) Rs. 30,300 nearly.

(e) By a contractor only for transhipping.

#### Package Tours

6844. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether package tours from Germany and other countries in Europe do

not include India because the Indian Airlines cannot assure bookings for 60 persons on a weekly tour of places of interest in India ; and

(b) why the Indian Airlines, which is booked to capacity, do not allow foreign crafts to continue their charter flights which would bring foreign exchange from other countries ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) No, Sir. Package tours from Germany and other countries in Europe do include India. During January this year, 7 tourist charters have operated from Holland, Finland, Russia, West Germany, Bulgaria and Denmark.

During January to March 1969, Indian Airlines accommodated over 480 tourist groups averaging 23 passengers each. Out of these, there were 20 groups with a membership of more than 50, and such groups were accommodated on scheduled flights, in combination with additional flights.

(b) Normally, no country likes to allow foreign operators to operate between points within its territory. As a rule, therefore, Indian Air lines also do not allow foreign aircraft to continue the charter flights through tourist sectors within the country. If this were done, such charter flights would create vacuum on the Corporation's tourist sectors. However, as and when required, the Corporation does operate additional flights to accommodate large groups of tourists.

#### Development Loans for Tourist Hotels

6845. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise loans for the development of tourist hotels on the model of those established by West Germany in East Africa, which combine investment from different foreign sources with local investment ; and

(b) whether Government are going to provide moderate rate accommodation in places of interest to package tourists ?

**THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) :** The Hotel Development Loan Scheme was evolved after studying various such Schemes and, in the opinion of the Government, is best suited to conditions in India.

(b) A number of tourist bungalows have been setup both by the Central and State Governments where accommodation is available at moderate rates. On account of limited resources, Government cannot do very much in the matter and the gap has to be filled by the private sector to which liberal incentives have been provided.

#### **Bus Service at National Highway No. 39**

6846. **SHRI M. MEGHACHANDRA** Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the nature of the Bus Service plying at the National Highway No. 39 from Dimapur-Manipur Road to Imphal and back ;

(b) the reasons for not having 1st and 2nd class bus service at this Highway ; and

(c) whether Government propose to have such service in public interest ?

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHURAMAIAH) :** (a) to (c). The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha when it is received.

#### **Disposal of Cases in Judicial Commissioner's Court, Manipur**

6847. **SHRI M. MEGHACHANDRA** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a protracted delay in the disposal of cases in the Court of the Judicial Commissioner, Manipur, so much so that even applications for leave to the Supreme Court are pending beyond a year or so ;

(b) if so, the number of cases pending in the Court including the applications for leave to the Supreme Court ; and

(c) The steps so far taken to avoid delay in the disposal of the cases ?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :**

(a) There has been some delay in the disposal of cases in the Court of Judicial Commissioner, Manipur.

(b) 396 cases as on 1-4-69 including two applications for leave to appeal to the Supreme Court.

The latter two applications have been fixed for disposal on 23rd and 24th April, 1969.

(c) Priority is being given to old and urgent cases with a view to ensuring timely disposal.

#### **Special Translation Staff in Ministries/ Departments**

6848. **SHRI D. C. SHARMA :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is propose to have special translation staff in all the Ministries and Departments of the Central Government by the end of March to ensure that Hindi is progressively adopted for official purposes ;

(a) if so, the steps taken so far in the matter ; and

(c) the additional expenditure involved?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :** (a) There is already some staff in each Ministry/ Department to attend to Hindi translation work. This is being further strengthened to the extent necessary.

(b) Each Ministry/Department has taken or is taking necessary action to create additional staff for the purpose according to their needs. The position in



this regard is watched through the quarterly progress reports received in the Ministry of Home Affairs.

(c) According to the information available in the Home Ministry, the additional expenditure on the translation staff sanctioned after 6th July, 1968 is likely to be Rs. 5.6 lakhs approximately per annum.

#### Improvement in the Waterway Between Kakinada and Cuddalore

6849. SHRI S. K. SAMBANDHAN : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to improve the waterway between Kakinada and Cuddalore ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) to (c). Presumably the question refers to the improvement of Buckingham Canal, which runs in the States of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, and provides a navigable route between Kakinada in the north and the Markanam backwaters in the south. Cuddalore, which is further south, is not connected by this canal.

During the earlier plan periods, dredgers were purchased and some improvements such as construction of wharves, rest sheds for boatmen, bathing places and compound wall etc. were carried out by the two State Governments against the grants given by the Government of India for meeting a portion of expenditure incurred thereon.

In regard to the proposals in the Fourth Five Year Plan, the State Governments have been requested to formulate schemes for running commercially viable river services. The proposals from the State Governments of Andhra Pradesh and Tamil Nadu are awaited.

#### धर्मशाला ट्रांजिट स्कूल का बन्द करना

6850. श्री कुशोक बाकुला : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार धर्मशाला ट्रांजिट स्कूल को बन्द करने पर विचार कर रही है ।

(ख) क्या यह सच है कि अभी भी 300 तिब्बती बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनकी शिक्षा के लिये और कोई व्यवस्था नहीं है और उनकी वित्तीय स्थिति बहुत दयनीय है ; और

(ग) क्या सरकार उक्त स्कूल को बन्द करने के उपरोक्त निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त वशन) : (क) से (ग). धर्मशाला के ट्रांजिट स्कूल का सम्बन्ध भारत सरकार से नहीं है। इसको परम पावन श्री दलाई लामा जी की तिब्बती शिक्षा परिषद ने खोला था, और इसमें 655 तिब्बती बच्चे पढ़ते थे। जब उनमें से 646 बच्चों को, जो कि निश्चित रूप से "तिब्बती शरणार्थी बच्चे थे, भारत सरकार द्वारा चलाई गई तिब्बती स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित कतिपय स्कूलों में भेज दिया गया, तो परिषद ने अपने ट्रांजिट स्कूल को बन्द कर दिया। शेष नौ बच्चे, जो कि शरणार्थी नहीं हैं, उनकी देख रक्ष स्वयं वह परिषद कर रही है।

#### तिब्बती बच्चों के लिये स्कूल की सुविधा

6851. श्री कुशोक बाकुला : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मालूम है तिब्बत स्कूल समिति के पास 3000 ऐसे तिब्बती

वच्चे जिनके लिये स्कूलों में सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि तिब्बत स्कूल समिति ने भारत तथा विदेश में स्वेच्छित संगठनों से इस कार्य में सहायता करने की माँग की है ; और

• (ग) क्या सरकार उक्त समिति को वित्तीय सहायता अथवा शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तिब्बती स्कूल सोसायटी केवल तिब्बती विस्थापित बच्चों की शिक्षा का ही प्रबन्ध करती है। इस सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले तिब्बती विस्थापित छात्रों की संख्या 31 दिसम्बर, 1968 को 5512 थी। यह सोसायटी उन तिब्बती बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो विस्थापित नहीं हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) इस सोसायटी का सारा खर्च भारत सरकार द्वारा दिए सहायता-अनुदान से पूरा किया जाता है। इसके अनिश्चित खर्च सामग्री, औषधि आदि के रूप में कुछ सहायता केन्द्रीय सहायता समिति (भारत) के जरिए स्वेच्छिक संगठनों से प्राप्त होती है।

**Benefit to officers Transferred to  
Border Roads Development Board**

6852. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question Nos. 1278 and 1279 on the 26th July, 1968 regarding the Border Roads Development Board and service conditions of quasipermanent Government employees respectively and state.

(a) the number and particulars of such officers from each of the Ministries/Departments who were entitled to get the benefit of the Home Ministry's order in the matter of fixation of their seniority ;

(b) whether all of such officers have been given the due benefit according to the Home Ministry's instructions ;

(c) if not, the specific cases still not covered and the reasons therefor ; and

(d) whether immediate steps are proposed to be taken to accord justice to all officers equally without any discrimination ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The Ministry of Home Affairs have no information, since the responsibility for the implementation of the orders issued in this behalf by the Ministry of Home Affairs is that of administrative Ministries/Departments concerned.

(b) and (c). No specific case has been brought to the notice of the Ministry of Home Affairs were the instructions issued by them have not been followed.

(d) Does not arise.

**Inter Se Seniority of Government  
Employees**

6853. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there are any principles and procedure laid down for the fixation of inter se seniority of the Government employees in cases where reservation is maintained in the matter of confirmation of the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether his Ministry has ever advised any Government Department to the effect that the recruitment roster showing reserved vacancies for the Sche-

duled Castes and Scheduled Tribes would not be taken as a basis for seniority and also that the roster for confirmation of such employees would not regulate their inter se seniority ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) whether there is any provision for assignment of national seniority to officers actually confirmed later over those confirmed earlier ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) and (b). Seniority of Scheduled Castes and Tribes candidates confirmed against the reserved vacancies is determined according to the orders laid down in Home Ministry's Office Memorandum No. 9/45/60—Estt (D) dated 20th April, 1961, a copy of which is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. Lt.—816/69.*]

(c) and (d). According to the instructions issued by the late Home Department in August 1946, seniority of Scheduled Caste/Tribe candidates is not required to be fixed on the basis of the Communal roster, because the object of the roster is merely to give effect to the proportions in which candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes are to be recruited and it is not intended to regulate seniority. Therefore, the Ministries/Departments who consulted the Ministry of Home Affairs in the matter were advised accordingly from time to time.

(e) In accordance with the general principles of seniority evolved by the Home Ministry in December 1959, which are now in force, seniority in a grade amongst permanent employees is regulated in the order of confirmation. Therefore, a person confirmed earlier will be senior to a person confirmed later.

The question of grant of national seniority would arise where a junior employee is confirmed erroneously from a date earlier than the date his senior is confirmed. The principles of seniority of December, 1959 referred to above do not

contain any provision for assignment of notional seniority. Such cases are considered on merits, having regard to the facts of the case.

#### Indian Judicial Service

6854. SHRI P. R. THAKUR. Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether replies have been received from all the State Governments in regard to the proposal for constituting an Indian Judicial Service ;

(b) if so, the nature of such replies ;

(c) if not, the names of the State Governments which have replied so far and the nature of their replies ; and

(d) what steps are being taken to expedite the matter for arriving at an early decision and the formation of the Service ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) Replies have been received from all State Governments except Uttar Pradesh.

(b) and (c). The Governments of Bihar, Haryana, Kerala, Orissa, Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu are agreeable to the proposal for the formation of an All India Judicial Service ; the Governments of Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore, Nagaland and West Bengal are not in favour of the proposal.

(d) A decision will be taken after the reply from Uttar Pradesh is received. The State Government is being reminded regularly.

#### Development of Tourist Spots in Bihar

6855. SHRI BALMIKI CHOUDARY : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the names of the tourist spots proposed to be developed in Bihar under the Annual Plan for 1969-70 and also in the Fourth Five Year Plan ;

(b) the cost of each scheme ; and

(e) if not the reasons therefor ?

(c) the Central assistance in the form of loans or grants to be given for implementation thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) It is proposed to undertake the integrated development of Bodhgaya-Rajgir-Nalanda in Bihar during the Fourth Five Year Plan. Work on the installation of an aerial ropeway at Rajgir, which is a spillover scheme from the Third Plan, is to be continued during the Annual Plan for 1969-70. In addition, the State Government propose to provide more accommodation and transport facilities at selected places of tourist interest during the Fourth Plan period.

(b) Details of tourism schemes to be taken up during Fourth Plan, including their cost, can be finalised only after the Plan Outlay has been approved.

(c) With effect from 1-4-69, the system of grants to State Governments has been abolished and all Plan tourism schemes will be either wholly finance by the Centre or wholly financed by the State Governments.

#### Curtailment of Governors' Powers

6856. SHRI GANESH GHOSH :  
SHRI K. RAMANI :  
SHRI UMANATH :  
THRI A. K. GOPALAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by Shri P. Sundarayya, General Secretary, Communist Party of India (Marxist) advocating the election of Governments by the legislative Assembly ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government would consider the proposal to curtail the powers of Governors ;

(d) if so, when ; and

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Government have seen press reports of Shri Sundarayya's statement.

(b) Government do not think that any change in the existing constitutional provisions regarding the appointment of the Governor is called for.

(c) to (e). The Home Minister dealt with these aspects in the reply in the House on 31st March, 1969.

#### राजस्थान में हवाई अड्डों का विकास

6857. श्री भीठालाल मीना : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में हवाई अड्डों का विकास तथा सुधार करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया है ;

(ख) उपर्युक्त राशि में से जयपुर हवाई अड्डे का विकास तथा सुधार करने के लिये कितना धन नियत किया गया है ; और

(ग) जयपुर हवाई अड्डे के विकास तथा सुधार सम्बन्धी योजना की रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (श्री० कर्णसिंह) : (क) से (ग). हवाई अड्डों में सुधार के लिये योजना विषयक नियतन राज्यवार नहीं अपितु समस्त भारत-वर्ष में सिविल हवाई अड्डों पर प्रारंभ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के माध्यम पर किये जाते हैं। नागर विमानन विभाग के नियंत्रण में राजस्थान में—जयपुर, उदयपुर और कोटा में तीन सिविल हवाई अड्डे हैं। जयपुर में मुख्य धावनपथ को एल०सी०एन०

30 तक मजबूत बनाने और इसके और प्रागे विस्तार के लिए भूमि प्राप्त करने और साथ ही उदयपुर के मुख्य घावत-पथ के विस्तार एवं उसे मजबूत बनाने के प्रस्तावों पर, उन्हें नागर विमानन विभाग की चौथी योजना में शामिल करने के लिये विचार किया जा रहा है।

#### Dhanushkodi Pier

6858. SHRI SHASHI BHUSHAN : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction of Dhanushkodi pier is going to be revived on the recommendations made by the Tamil Nadu Government ;

(b) whether, while reviving it, aspects connected with it such as nature's fury to Dhanushkoti on the basis of past experiences, handling of Interuational traffic and inconvenience caused to it has been taken into consideration ;

(c) if so, the total amount to be spent on its revival ;

(d) whether the Railway track from Rameshwaram to Dhanushkodi is also to be redeveloped ;

(e) whether other better sites such as Mandapam North and Rameshwaram are also under consideration ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMETARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) to (c). In September, 1968, the Government of India, in consultation with the Government of Tamil Nadu, sanctioned an expenditure of about Rs. 17 lakhs for redecking the pier at Dhanushkodi to facilitate the reception of repatriates from Ceylon. This has been considered to be the quickest arrangement for restoring proper landing facilities.

(d) It has been decided not to restore

the railway line between Dhanushkodi and Rameswaram.

(e) and (f). In view of the decision to renovate the Dhanushkodi Pier the question of considering other sites does not arise.

#### Jurisdiction of High Courts in Presidency Cities of Bombay, Calcutta and Madras

6859. SHRI RAM AVTAR SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to end the original jurisdiction of High Courts in three Presidency Cities of Bombay, Culcutta and Madras ; and

(b) if so, when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

#### Control Tower at Palam Airport

6860. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the public has been put to great inconvenience because the Control Tower at Palam does not convey the exact time of arrival of planes at Palam to the Civil Aviation Authorities for being passed on to the public ;

(b) whether any inquiry has been made to find out why the Control Tower suddenly became apathetic to this public utility ; and

(c) when the normal conditions will be restored ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) The control tower at Palam is manned by the Civil Aviation Department and it does not directly

communicate such information to members of the public. Expected time of arrivals and departures and bay number on which the aircraft will be parked is passed on by the Briefing Centre to the concerned airline offices at the airport.

(b) and (c). Do not arise.

**Unserviceable Aircraft with I. A. C.**

6861. SHRI D. N. PATODIA :  
 SHRI RANJIT SINGH :  
 SHRI D. C. SHARMA :  
 SHRI HARDAYAL DEVGUN :  
 SHRI BENI SHANKER  
 SHARMA :  
 SHRI BAL RAJ MADHOK :  
 SHRI K. P. SINGH DEO :  
 SHRI R. K. SINHA :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the aircrafts with the Indian Airlines Corporation have become so old that their continuous use has become unremunerative and is leading to huge losses to the Corporation ;

(b) if so, whether any assessment has been made of the number of such planes ;

(c) what is the sale value of these aircrafts and the losses that are incurred on them annually during the last three years ; and

(d) whether Government propose to dispose of these aircrafts and, if so, when ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). The 3 DC-4 (Skymasters) aircraft have been grounded and 5 DC-3 (Dakota) aircraft, at present being used on internal scheduled services of the Indian Airlines are proposed to be replaced over the next year or two by HS-748 aircraft manufactured by Hindustan Aeronautics Limited, Kanpur.

(c) There is very little demand for piston engined aircraft like the DC-3 and the DC-4 and it is difficult to assess the price they will fetch. The losses incurred on the operation of DC-3 and DC-4 aircraft during the last three years\* was as follows :—

	1965-66	1966-67	1967-68
	( <i>Rupees in Lakhs</i> )		
DC-3	233.709	326.74	275.32
DC-4	21.47	30.35	26.18

(d) Efforts are being made by the Indian Airlines to dispose of these aircrafts.

**Dayal Commission's Report**

6862. SHRI BHOGENDRA JHA :  
 SHRI RANJIT SINGH :  
 SHRI D. C. SHARMA :  
 SHRI HARDAYAL DEVGUN :  
 SHRI BENI SHANKER  
 SHARMA :  
 SHRI BAL RAJ MADHOK :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2084 on the 7th March, 1969 regarding Dayal Commission's Report on the Communal riots and state :

(a) whether recommendations by the Dayal Commission requiring action by the Union Government have since considered ;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The matter is still under consideration.

**Legislation for giving immunity to reproduce and broadcast Proceedings of State Legislatures**

6863. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Central Government have urged upon the State Governments for initiating a legislation on the basis of the Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Act 1956 for giving immunity to the Press and the All India radio for reproducing the proceedings of the State Legislature in a representative manner ;

(b) if so, the reaction of the State Governments thereto ; and

(c) the names of the State Governments which have passed the legislation in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) and (b). The views of the State Governments were called for on a proposal to enact the necessary law to extend the protection under the Parliamentary Proceedings (Protection of publication) Act, 1956, to newspaper reports all over India concerning proceedings of State Legislatures. All the State Governments except Assam, Madras and West Bengal agreed with the proposal. As a law extending the protection available under the Act of 1956 to the publication of reports of the proceedings of only some of the State Legislatures might be impugned as discriminatory, the contemplated legislation could not be taken up.

(c) Orissa and Mysore. The Maharashtra Legislature have recently passed a similar Bill which has been received recently for the assent of the President.

#### Hindustan Shipyard Limited

6864. SHRI TENNETI VISHWANATHAM : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the management of the Hindustan Shipyard Ltd. issued a communication No. PD/10/138 dated the 9th December, 1968 to the Presidents of their (i) staff association and (ii) Labour Union intimating to them that "Leave on loss of pay will not be granted to any

employees including the office bearers Committee members to attend to the work of the Union" ;

(b) whether this communication is not at variance with the policy of Government to encourage inside Leadership and also at variance from the practice obtaining in the Post and Telegraph and Railway Departments which are considered essential services.

(c) whether the election by the Labour Union of an honorary President, who happens to be an employee of the Hindustan Shipyard Ltd., was objected to by the Management on the ground that the elected person is not an outsider ; and

(d) if so, the action Government propose to take in this connection ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes, Sir. However, the management have, on reconsideration, decided to grant to one office bearer each of the Labour Union and Staff Association, special leave without pay for a maximum period of 15 days in a calendar year for trade union activity.

(b) Railway Administrations are empowered to grant casual leave to a railway servant, who is a representative of a recognised trade union, to attend duly constituted meetings of the union subject to exigencies of work and also special casual leave to representatives of Labour Union, when they are invited to attend the meetings convened by the Railway Board. As regards the Post and Telegraph Department, special casual leave upto a maximum period of 20 days per annum is allowed to office bearers of unions for attending the Union Conferences, Executive Committee Meetings and interviews with Chairman and Ministers. The question, whether the present decision of the management would require any change, is proposed to be examined in consultation with the management of the Yard in the light also of the practice obtaining in other public sector undertakings.

The Shipyard have also decided that if the Association/Union desire to utilise the services of an office bearer on a full-time basis, the management might agree to his deputation for a minimum period of one year on foreign service terms to the Association/Union as in the case of Railways and Post and Telegraph, Department.

(c) and (d). Yes, Sir. The rules and regulations of the Hindustan Shipyard Labour Union do not permit of a person employed in the Shipyard to be elected as the Honorary President of the Labour Union. Hence the Shipyard Management did not recognise the concerned employee as such. This question is, however, being examined further by the Shipyard in consultation with the Registrar of Trade Unions, Andhra Pradesh.

#### Admission to LL. B. Course in Delhi University

6865. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) how many candidates were admitted to the Law Course of LL. B. Ist year (Evening Classes) in the Faculty of Law, University of Delhi upto 31st July, 1968 ;

(b) number of seats reserved for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates ;

(c) how many seats were filled up out of the total reserved seats ;

(d) whether it is a fact that full quota of reserved seats was not utilised from amongst the Scheduled Caste/Scheduled Tribe applicants ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) 2200.

(b) 44

(c) 32

(d) Yes, Sir.

(e) Out of the 44 candidates selected against the reserved seats only 30 accepted

admission and actually joined the Course. Another two persons were later selected for admission from out of the students kept on the waiting list. In addition, 7 Scheduled Caste/Tribe students were admitted on merit from the general pool, making a total of 39 Scheduled Caste/Tribe students admitted.

#### Verification of Antecedents of Kerala People

6866. SHRI VASUDEVAN NAIR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) how many candidates belonging to Kerala State had been selected for jobs by the Union Public Service Commission and the various Ministries of the Union Government during 1968 ;

(b) whether they were all subjected to a separate verification of character and antecedents by the Home Ministry apart from the one done by the Kerala State Government ; and

(c) whether any persons selected were refused employment on the basis of verification reports and, if so, how many ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The information is being collected and the same will be placed on the Table of the House as soon as possible.

(c) The State Government have not issued instructions to the District authorities to verify the character and antecedents of candidates selected for employment to the posts under the Central Government on the basis of the revised criteria adopted by the Central Government. Hence, the Central Government have to use their own agency to conduct verification of character and antecedents of such candidates, belonging to Kerala State.

#### Sending of Central Government Employees to States

6867. SHRI VALMIKI CHOUHDARY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :



(a) whether the Tamil Nadu Government have stopped taking of Hindi-speaking and Hindi-knowing officers from the All India Services ;

(b) the rules for sending such and other Central Government officers to the States ; and

(c) whether it is necessary to consult the State Governments concerned before sending any officer to different States ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) The Government of Tamil Nadu have not refused to take Hindi-speaking or Hindi-knowing All India Service officers allotted to the State by the Central Government.

(b) and (c). The allocation of members of Indian Administrative Service/Indian Police Service/Indian Forest Service is made by the Central Government in consultation with the State Government concerned under Rule 5 of the I. A. S./I. P. S./I. F. S. (Cadre) Rules. Central Government officers are very rarely sent on deputation to serve under a State Government which invariably is with the consent of the State Government concerned.

**Introduction of Designation Similar to Section Officer in Attached and Subordinate Offices**

6868. SHRI D. C. SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there are posts in the Attached and Subordinate Offices of the Government of India where a designation similar to that of the Section Officers of the Central Secretariat Service Scheme is used ; and

(b) if so, how is the anomaly proposed to be removed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) and (b). In the CSS Scheme in addition to the Ministries and Departments of the Government of India, most of the Attached Offices are also participating. Accordingly, the existence of the posts of Section Officer in the participating Attached Offices is within the frame work of the CSS Scheme. There are, however, some Attached and Subordinate Offices which are not participating in the Scheme and which have posts designated as Section Officer. But this has not created any anomaly.

**Central Flying Training School for Training Commercial Pilots**

6869. SHRI S. K. TAPURIAH :  
SHRI C. CHITTYBABU :  
SHRI V. NARASIMHA RAO :  
SHRI RAM AVTAR SHARMA :  
SHRI D. N. PATODIA :  
SHRI R. K. BIRLA :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that G. C. Arya Committee has recommended immediate establishment of a 'Central Flying Training School' for training commercial pilots ;

(b) the salient features of the report ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The salient recommendations relating to the setting up of a Central Flying Training School for training of Commercial Pilots are as follows :

- (1) The Flying Training School should be a full fledged training institution with the necessary expert staff and training facilities to cover various aspects of Civil

Aviation as detailed in the list below :

(i) Flying training upto Commercial Pilot's Licence.

(ii) Flying training for Instrument Rating.

(iii) Flying training for Instructor's Rating.

(iv) Flying training for conversion on basic twin-engined aircraft.

(v) Ground training upto Airline Transport Pilot level.

(vi) Training of Flight Engineers.

(vii) Training of Radio Telephony Operators.

(viii) Training for Aircraft Maintenance Engineers.

(ix) Training for any other crew category required for the Industry.

(II) Considering the needs of Indian Airlines and Air India, and those of the non-scheduled operators and the Flying clubs, but excluding those required for crop-spraying, the School should be capable of turning out 50 qualified Commercial Pilots per year each with a flying experience of 250 hours. This may be reviewed from time to time according to demand.

(c) The Committee's report is still under consideration of Government.

भारत में के० जी० बी० के समारोह

6870. श्री कंचर लाल गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि के० जी० बी० नामक रूस की एक गुप्तचर एजेंसी भारत में अपने आप एक समारोह का आयोजन कर रही है ;

(ख) क्या इस एजेंसी ने जनता को भी कुछ टिकटें बेची हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Display of Portraits at the opening of Renovated Palam Airport

6871. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the newly renovated Palam Airport had been opened after its completion by the only woman pilot in the country and a number of portraits of the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, had been displayed over there ; and

(b) the number of such portraits, the expenditure incurred thereon and the purpose of such display ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). The terminal building at Palam Airport, after renovation, was formally commissioned by the only woman commercial pilot in India. Sixteen portraits of the President and the Prime Minister have been displayed at Palam Airport at a total cost of Rs. 704.00. These portraits are displayed at aerodromes as a matter of general practice of displaying portraits of the serving Head of State and Head of Government.

लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा व्यवसायिक केन्द्र

6872. श्री राम सिंह अयरवाल : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ धनार्जन करने की सुविधा देने के लिये व्यावसायिक केन्द्र/लघु उद्योग अथवा कुटीर उद्योगों की स्थापना की गई है

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने का विचार है ;

(ग) यदि हाँ, तो कब ;

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अधीन विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात् बेरोजगार रहते हैं और ;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या ऐसे व्यावसायिक केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० झार० बी० राव) : (क) इस बारे में, भारत सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). यह सर्वदा ठीक नहीं है, यद्यपि उपलब्ध रोजगार सुविधाएं मांग के अनुरूप नहीं हैं । शिक्षा मंत्रालय के सुझाव पर, प्रायोगिक प्रायोजना के रूप में दिल्ली में एक कालेज की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने के लिये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में एक समिति नियुक्त की है । उक्त कालेज द्वितीय स्तर के कुछ चुने हुए रोजगार आमुख पाठ्यक्रम पेश करेगा ।

**Appointment of Principal, Punjab Engineering College**

6873. SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVI-

CES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of the Principal, Punjab Engineering College, fell vacant in November, 1967 ;

(b) whether this post has been filled on an *ad hoc* basis by a non-Engineering person which is against the qualifications prescribed and the rules laid down by the affiliating University ;

(c) whether it is a fact that the requisition for filling this post was sent to the U. P. S. C. and subsequently with drawn because the U. P. S. C. advised possession of engineering qualifications which the present Principal does not possess ;

(d) whether it is a fact that the present Principal is not permitted to participate in the proceedings of the Senate as he does not possess the requisite qualifications and consequently the interests of the students are being adversely affected ;

(e) when will the post be filled on regular basis and the reasons for the delay ; and

(f) the number of staff members promoted by him on an *ad hoc* basis, their names and the reasons for promotion ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The post has been temporarily filled by a senior Professor of the College, who is a specialist in applied science, but he does not possess a formal engineering qualification as prescribed by the University.

(c) Yes, Sir.

(d) Since the University has not yet recognised the present Principal, he has not been able to participate in the proceedings of the Senate. The Principal and other members of staff of the College however, are serving on the Faculty of Engineering and the Board of Studies of the University, where they are able to

look after the interests of students adequately.

(e) The post will be filled on a regular basis as soon as the question of qualifications to be prescribed is finalised in consultation with the University and the U. P. S. C.

(f) No member of staff has been promoted on an *ad hoc* basis by the Principal, but the Administration has made such promotions, in consultation with the U. P. S. C. in the interest of teaching work in the College.

### परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिये समिति

6874. श्री क० मि० मधुकर : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों के लिये परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के बारे में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी और इसके प्रतिवेदन को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पास प्रतिवेदन में की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिये और उन पर उनकी सलाह प्राप्त करने के लिए भेजा गया था ;

(ख) यहि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं जिन्होंने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया था और ये सिफारिशें किस सीमा तक क्रियान्वित की गई थीं और उनके बारे में क्या सलाह दी गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) परीक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन सुभाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितम्बर, 1957 में एक विशेषज्ञ समिति

नियुक्त की थी रिपोर्ट की प्रतियां मई, 1962 में विश्वविद्यालयों के पास उनकी सिफारिशों के लिये भेज दी गई थीं।

(ख) और (ग). समिति की रिपोर्ट के बारे में विश्वविद्यालयों से प्राप्त मुभाव और टिप्पणियां मभापटल पर रखे गए विवरण में दी गई हैं। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT—817/69] समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति के बारे में विश्वविद्यालयों में पता लगाया जा रहा है।

### पत्राचार पाठ्यक्रम

6875. श्री क० मि० मधुकर : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि देश में कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा आरम्भ किये गये पत्राचार पाठ्यक्रमों के प्रत्येक विद्यार्थी पर कितना-कितना धन व्यय होता है और इनसे कितने व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे पाठ्यक्रम आरम्भ करने के परिणामस्वरूप सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है और वांछित परिणाम नहीं निकले हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) अभी तक पत्राचार पाठ्यक्रम दिल्ली, राजस्थान और पंजाबी विश्वविद्यालयों द्वारा आरम्भ किये गये हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली

विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम में 1967-68 के दौरान प्रति विद्यार्थी खर्च 160.06 रुपये निकाला गया था। राजस्थान और पंजाबी विश्वविद्यालयों के 1968-69 वर्ष के (जिस वर्ष ये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये थे) तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 288.5 रु०

और 226.31 रु० है।

इन पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ होने से इन पाठ्यक्रमों में तीनों विश्वविद्यालयों में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित है :—

वर्ष	दिल्ली विश्वविद्यालय	राजस्थान विश्वविद्यालय	पंजाबी विश्वविद्यालय
1962-63	1,112	...	...
1963-64	2,226	...	...
1964-65	3,467	...	...
1965-66	4,424	...	...
1966-67	6,174	...	...
1967-68	8,218	...	...
1968-69	13,000	314	2,121

(ख) इन विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रमों के प्रबन्ध में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायतों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। ये पाठ्यक्रम लोकप्रिय रहे हैं और एक वास्तविक आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

### शिक्षा का विकास

6876. श्री क० मि० मधुकर : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्तरोत्तर बढ़ रहे अनुसंधान कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषीकृत शिक्षा के विकास तथा इन कार्यों के लिये अपेक्षित उपकरणों की दृष्टि से विदेशी मुद्रा की अत्यन्त कमी है जिसके कारण शिक्षा के विकास में अनेक कठिनाइयाँ हैं ;

(ख) क्या इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के पिछड़ेपन को दूर करने के बारे में सरकार का दृष्टिकोण नितान्त उपेक्षा का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो शिक्षा के लिये प्रयुक्त उपकरणों का आयात करने के लिये वर्ष 1967 से अब तक विदेशी मुद्रा की कितनी आवश्यकता थी तथा इस आवश्यकता के कितने अनुपात में विदेशी मुद्रा दी गई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख). यद्यपि विदेशी मुद्रा की कमी है, किन्तु विभिन्न सहायक कार्यक्रमों, व्यापार करारों और अपने स्वयं के स्वतंत्र विदेशी मुद्रा साधनों के जरिये, शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं की वैज्ञानिक साज-सामान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है। देश में वैज्ञानिक साज-सामान के उत्पादन के कार्य में भी काफी प्रगति हुई है।

(ग) विभिन्न एजेन्सियों से विशिष्ट प्रायोगिक सहायता के अतिरिक्त, शैक्षिक तथा अनुसंधान प्रयोजनों के लिये अनुमान लगाया था कि 1967-69 के लिये लगभग 22.60 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी, और लगभग 16.02 करोड़ रुपये का नियतन किया गया था। इस अन्तर को हृद तक, अमरीका से एक विशेष

डालर करण के जरिये कम किया जा रहा है।

#### **Increase in Hotel-Bed Capacity**

6877. SHRI MUHAMMAD SHERIFF :  
SHRI BRIJ RAJ SINGH :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the steps Government propose to take to increase hotel-bed capacity in the country to provide accommodation to tourists expected to visit the country in the years to come ;

(b) the number of present beds available for tourists ; and

(c) the incentives offered to hoteliers in the matter of land, electricity, excise-duty, loans and procedural problems ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (c). Government have offered special incentives to the private sector to encourage the flow of capital into the hotel industry including substantial Income-tax relief ; liberal depreciation rates ; grant of development rebate ; priority consideration for needs of the hotel industry ; sale of Government-owned land in the Delhi area at concessional rates, and a Hotel Development Loan Scheme for financial assistance. In the public sector also, both the India Tourism Development Corporation and Air India have plans for Hotel construction during the Fourth Plan Period.

(b) 15016 hotel beds in one to five star category hotels.

#### **Toll Roads and Bridges**

6878. SHRI MUHAMMAD SHERIFF: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state : whether Government are considering the idea of toll roads and bridges to find additional money for their constructions ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : The Government of India have no such proposal.

#### **Programme of containerisation**

6879. SHRI MUHAMMAD SHERIFF : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the Government of India propose to find finances for helping the shipping industry in adopting to the phased programme of containerisation ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) and (b). Government's policy on introduction of containerisation would be decided after the results of the studies recommended by the Seminar held in December, 1968 become available. Steps are being taken to initiate the necessary studies. The extent to which finance would be required for helping the shipping industry in adopting to the phased programme of containerisation and the source from which the finance could be found will be known only after the proposed studies are completed and Government decision taken thereon.

#### **West German Lectures at Indian Universities**

6880. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the number and places where West German lecturers are stationed at the Indian Universities ;

(b) the agreements under which they are posted in India ;

(c) whether Government are aware that the West German institutions including the West German Embassy in India are continuously interfering with out Universities in internal matters ;

(d) whether there are cases of Indian lecturers of German Language at the Delhi University being subsidized by West German organisations like Max Mueller Bhavan although in full time employment in Indian Universities ;

(e) whether functions are organised and large quantity of printed material are distributed to our students at the Delhi University on behalf of West German organisations without the University authorities knowing about this ; and

(f) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

**THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) :** (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(c) No case of interference has come to the notice of the Government.

(d) There is only one case of an Indian Lecturer in German who was initially permitted to take part-time teaching work at Max Muller Bhavan for one year. He however, continued to do teaching work at the Bhavan beyond the period of one year without informing the University. This matter including the question of the remuneration received by him from the Max Muller Bhavan is under consideration of the University.

(e) Cultural and literary functions are organised by the Departments of the University at which literature appropriate to the occasion is sometimes distributed to the audience by the University. These functions are organised with the approval of the Vice-Chancellor.

(f) Does not arise.

#### Crisis Faced by Private Airlines

**6881. SHRI MOHAMMAD ISMAIL:** Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to reduced flying condition, non-availability

of spare parts, import restrictions, high cost of operation due to devaluation etc. many of the private airlines in the country are facing considerable crisis and notably the Airways India and M/s. Jamir and Co. Ltd. are faced with imminent closure;

(b) if so, whether it is also a fact that Government have a proposal under consideration to absorb the employees of such private airlines in the Indian Airlines in the event of their closure ;

(c) whether Government have any proposal under consideration to effect complete nationalisation of the private airlines in the country ; and

(d) if so, the time by when and the details thereof ?

**THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) :** (a) A statement showing traffic figures in respect of the three main non-scheduled operators viz. Kalinga Airlines, Airways India and Jamair Co., is attached. The figures would not indicate that they are faced with imminent closure.

#### Traffic figures for 1968

	Passenger	Cargo
	(Kgs.)	
Kalinga Airlines	10,356	31,73,056
Airways (India)	14,392	33,14,841
Jamair Co. Ltd.	48,277	52,51,600

(b) Does not arise.

(c) and (d). No such proposal is under consideration of Government.

**जयन्ती शिपिंग कंपनी में श्री धर्म तेजा के शेरर**

**6882. श्री मृत्सुंजय प्रसाद :** क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री धर्म तेजा के पास जयन्ती शिपिंग कंपनी के करोड़ों रुपये के शेरर थे, वे उन्होंने नकद रुपये देकर खरीदे थे अथवा उनके मूल्य दिये बिना हम

कंपनी के संस्थापक की हैसियत में प्राप्त किये थे या उन्होंने ये शेरर अपनी सेवाओं के बदले में कुछ मामूली धनराशि देकर प्राप्त किये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ?

संसद-कार्य और नौबहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरसैया) : (क) और (ख) डा० धर्म तेजा के जयन्ती शिपिंग कंपनी में 2,12,47,200 रुपये प्रत्यक्ष मूल्य में 2,12,472 पूर्ण प्रदत्त भाग (शेरर) थे। कंपनी के रिकार्ड (अभिलेखा) के अनुसार ये सारे शेरर उन्हें बिना किसी भुगतान या कंपनी के संस्थापक की हैसियत के नाते नाम-मात्र भुगतान करके या कंपनी में उनकी सेवाओं के बदले नहीं दिये गये थे बल्कि नकद भुगतान करने पर दिये गये थे। तथापि जून, 1966 में सरकार द्वारा कंपनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिये जाने के बाद जांच पड़ताल की गई और यह पाया गया कि डा० तेजा और उनका एक साथी श्री कुलुकुंडिस गिर जो दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है। अपने शेररों की खरीद के लिए शंकास्पद लेन-देनों में फंस गये। एक लेनदेन के संबंध में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और दो अलग अलग दीवानी अभियोग जयन्ती शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने अक्टूबर 1968 में डा० तेजा के विरुद्ध बम्बई हाई कोर्ट में व्याज और 5,16,477 पौंड की वसूली के लिए दायर किए हैं। श्री कुलुकुंडिस के विरुद्ध दायर किये गए मामले में कंपनी ने उनके 70825 शेरर न्यायालय द्वारा फौसले से पूर्व ही, कुर्की कर दिये गये हैं। इसी प्रकार के आदेश डा० तेजा के 2,12,472 शेररों की कुर्की के लिए 1966 में बम्बई हाई कोर्ट द्वारा पहले ही दो दीवानी मुकदमों में किए जा चुके हैं, इनमें से एक के लिए डा० तेजा के विरुद्ध 82.92 लाख रुपये की डिग्री दी जा चुकी है।

डा० तेजा और श्री कुलुकुंडिस द्वारा शेररों की खरीद सम्बन्धित दूसरे लेनदेन के मामले की अभी जांच पड़ताल हो रही है और कार्यवाही के लिए कानूनी परामर्श लिया जा रहा है।

#### Arrest of Lal Sena's Members in Gandhidham (Kutch)

6883. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three members of the Lal Sena have been arrested in Gandhidham in Kutch during the month of March, 1969 ;

(b) if so, the reasons for their arrest ;

(c) whether any incriminating material or documents have been found on the person of those arrested ; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). According to information furnished by the State Government, there is no organisation called 'Lal Sena' anywhere in Gujarat. However, three boys were found to have put out threatening posters written in the name of the 'Lal Sena' and bearing the mark hammer and sickle in red. They were arrested on March 16, 1969 in connection with offences under sections 507, 436 and 511 IPC registered on the basis of complaints made by some prominent citizens of Gandhidham. No incriminating material has been recovered from them.

#### Discovery of Ruins of Indian Civilization in East Asian Countries

6884. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently ruins of the India civilisation of a magnitude of Ankorhatt in Cambodia and



Bordodur in Java have been discovered in Malaysia recently ;

(b) whether these ruins of the Indian civilisation are awaiting excavation and preservation in a proper way ;

(c) whether the Government of Malaysia have asked for the collaboration of the United States for performing this historical work ;

(d) whether, in view of the fact that the whole relics relate to civilisation and history of India, the Government of India, will offer collaboration for joint endeavour in excavation of the ruins and their preservation as a place of great cultural importance ; and

(e) if so, the plan of the Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) to (c). Government is not aware of the discovery nor of the steps which the Government of Malaysia intends to take for excavation and preservation of the sites.

(d) and (e). In the absence of any proposals from Government of Malaysia, it is not possible to say anything in the matter.

#### Arrest of Girl Pick-Pocket in Delhi

6885. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a girl was arrested on the 12th March, 1969, on the charge of pick-pocketing in Delhi ;

(b) if so, the valuables recovered from the lockers in her name ;

(c) whether some more arrests have been made in this connection ;

(d) whether this girl is one of the members of the inter-state pick-pockets

functioning in running Railway trains ; and

(e) the steps which Government are taking to uproot such gangs in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) A Girl was arrested on the 9th March, 1969, on the charge of pick-pocketing in Delhi.

(b) Ornaments and cash worth about Rs. 20,000/- were recovered.

(c) No, Sir.

(d) and (e). The case registered by police in this connection is still under investigation.

#### Service Conditions of Persons of Andaman Domicile

6886. SHRI K. R. GANESH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the term "persons of Indian domicile" includes persons born in the Andaman and Nicobar Islands ;

(b) if so, whether persons of Andaman domicile specifically recruited/deputed from the mainland for service in the Islands will be entitled to joining time and free sea passage during leave ; and

(c) if not the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The concessions of free sea passage and joining time once a year during leave are admissible to certain categories of Government servants serving in the Andaman and Nicobar Islands in terms of Supplementary Rule 144 read with Supplementary Rule 294-A. These concessions are intended as an attraction or incentive for securing personnel from the mainland for service in the Islands, although the term "Government servant

who is of Indian domicile" occurring in Supplementary Rule 294-A would apparently include persons born in the Andaman and Nicobar Islands also, the question whether such persons, if recruited from the mainland, should be allowed these concessions, involves interpretation of the intention behind the rule, which is under examination.

Deputy Prime Minister's Letter to Kapoor Commission

6887. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Deputy Prime Minister had in his letter to the Kapoor Commission said that Shri Balukaka Kanitkar had written no letter to the Late Shri B. G. Kher about the likely attempt on Mahatmaji's life ;

(b) whether it is also a fact that in his evidence he admitted that a letter was received by the Late Shri Kher and although it was not shown to him, the Late Shri Kher had conveyed its contents to him ;

(c) whether Shri Desai's letter would be laid on the Table of the House ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative...how do Government explain the contradiction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The said Commission have stated that the information sought in the question is in respect of a matter which is being inquired into by the Commission and upon which the Commission may have to pronounce its finding and that it would not be proper, at this stage, to make any disclosure in regard to the correctness or otherwise of the queries.

(c) to (e). Do not arise.

दिल्ली में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को वेतनों का भुगतान

6888. श्री शशि भूषण : क्या शिक्षा

तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में अनेक सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को अपना मासिक वेतन समय पर नहीं मिलता ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि रामाकृष्णापुरम्, नई दिल्ली के एक स्कूल के अध्यापकों को गत दो महीनों में वेतन नहीं मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त वर्मान) : (क) जी हां, कुछ मामलों में ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) जब कभी दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर-पालिका शिक्षा विभाग के ध्यान में ऐसी शिकायत आती है तो तुरन्त भुगतान कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

6889. श्री शशि भूषण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष देश में ऐसे क्षेत्रों अथवा नगरों से कितने पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया जिनमें प्रवेश के लिये उनके पास बीजा नहीं थे ;

(ख) जिन स्थानों के लिये उनके पास बीजा थे उन स्थानों से अन्य स्थानों में जाने का उनके उद्देश्य का पता लगाने

के लिये सरकार द्वारा की गई जांच का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**Transfer of I. A. C. Staff from Calcutta to Gauhati and vice versa**

6890. SHRI BISWANARAYAN SHASTRI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by the Indian Airlines Corporation on account of transfer of staff from Calcutta to Gauhati and *vice versa* during the year 1968-69 ; and

(b) the reason for frequent transfers ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). The total expenditure on this account is Rs. 22,237.63 out of which a sum of Rs. 14,936.50 is on movement of Engineers due to operational requirements. The balance of Rs. 7,301.13 is spent in line with the normal transfer policy for Gauhati station, evolved in consultation with Workers Unions, and includes temporary transfers as leave replacement of technical personnel.

**Cultural Activities between India and Soviet Union**

6891. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the Soviet Minister of Culture, Madame Furtseva, has suggested that there should be greater dissemination of information about the activities

of people who returned after training in music, dance and other cultural activities in each other's countries and ways and means should be devised to bring the cultures of the two countries to the masses ;

(b) whether the need for greater exchange of films was also emphasised ; and

(c) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Such exchanges from the subject matter of the Cultural Exchange Programme agreed to after discussions between the representatives of the Indian and Soviet sides. Every year efforts are made to increase cultural activities in the succeeding years. Follow-up, wherever possible is ensured by suitable Agencies, if they exist, or by Government.

**Sheikh Abdullah's Speeches**

6892. SHRI BENI SHANKER

SHARMA :

SHRI D. C. SHARMA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the speeches made by Sheikh Abdullah to the refugees in Jammu about the Gajendragadkar Commission report ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether any action is proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). Attention is invited to the statement made by Home Minister in Lok Sabha on 6th March, 1969, in response to a Calling Attention Notice by Mahant Digvijai Nath and

others and the supplementaries arising therefrom and also to the reply given in the House on 11th April, 1969, in respect of Unstarred Question No. 6170.

**Appointment of West German Firm as Consultant for setting up Hotels**

6893. SHRI K. P. SINGH DEO :  
SHRI D. C. SHARMA :

• Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to appoint as their Consultant a West German firm which runs a chain of hotels ;

(b) whether it is also a fact that Government have offered to build hotels in the neighbouring countries ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (c). Government are working out some proposals for co-operation with the Government of West Germany for the development of Tourism in India including a consultancy service for the improvement of Public Sector hotels.

(b) No, Sir.

**Memorandum from Students of Technical Training Centre, Kota (Rajasthan)**

6894. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the students of the Technical Training Centre (Kota) with a covering letter dated the 22nd March, 1969 from an M. P. ;

(b) if so, what are the main points of the memorandum ; and

(c) what action Government has taken to so revise the Scheme so that the students get real and useful practical training and the nation derives lasting benefit from the Scheme ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) The main complaint of the students is that the programme of training at the Kota Centre does not give adequate practical experience, and that it is more theoretical.

(c) An Officer of the Ministry of Education and Youth Services and another officer of the Ministry of Irrigation and Power have visited the Training Centre and reported that the programme of training has been designed on the best lines possible, and is devoted mainly to practical work. The complaint of the trainees is unjustified.

**Suspension of Schemes for Higher Studies in Agriculture and Economics in Netherlands**

6895. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government have suspended or stopped the various schemes of higher studies in Agriculture and Economics in Netherlands and if so, the reasons therefor ; and

(b) if not, the reasons why the recommendations of the State Governments during the previous two years have not been considered for sending candidates for higher studies in Economics and Agriculture in Netherlands.

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

**Motor Accidents Claims in Delhi**

6896. SHRI P. M. SAYEED : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the number of cases pending on the file of the Motor Accidents Claims Tribunal, Delhi (Teess Hazari) as on the 31st March, 1969 wherein the victims of

the motor accidents in Delhi have filed claims for compensation under the Motor Vehicles Act, 1939 ;

(b) the number of such cases which are pending ;

- ( i ) for more than six months ;
- ( ii ) for more than one year ;
- ( iii ) for more than two years ;
- ( iv ) for more than three years ;
- ( v ) for more than four years ;
- ( vi ) for more than five years separately ; and

(c) whether it is a fact that the proceedings before the Motor Accidents Tribunal, Delhi are of summary nature and whether Government have fixed or propose to fix a minimum time limit within which a case of this nature is finally decided ?

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHURAMIAH):**

(a) and (b). The information required is being collected and will be laid on the table of the Sabha, when received.

(c) Under Section 110C of the Motor Vehicles Act, the Claims Tribunal may, subject to any rules that may be made in this behalf, follow such summary procedure as it thinks fit. Government have not fixed a time limit within which a case may be finally decided by a Claims Tribunal, nor is this proposed to be done.

#### **Motor Accidents Claims in Delhi**

6897. SHRI P. M. SYEED : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Motor Accidents Claims Tribunal has no power to recover the compensation awarded to the claimant from the driver or the owner of the motor vehicle involved in the accident and whether no such provision has been made in the Motor Vehicles Act thus rendering it infructuous so far as payment of compensation to the aggrieved party is concerned ;

(b) whether Government propose to amend the Motor Vehicles Act so as to

empower the Motor Accidents Claims Tribunal to recover the compensation awarded by him from the driver and the owner of the vehicle involved in the accident ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) :** (a) Yes, Sir. Section 110B of the Motor Vehicles Act, 1939 require the Claims Tribunal to specify the persons to whom compensation shall be paid and also to specify the amount which will be paid by the insurer. Section 110E is the enforcement section under which a claimant can recover the compensation payable by the insurer only by way of arrears of land revenue.

(b) Government have already undertaken amending legislation and the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1968 has been passed by the Rajya Sabha. Clauses 60 and 63 thereof seek to amend the aforesaid sections of the Act to achieve the Object.

(c) Does not arise.

#### **Motor Accidents Claims in Delhi**

6898. SHRI P. M. SAYEED : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of cases are pending with the Motor Accidents Claims Tribunal, Delhi wherein the victims of motor vehicles accidents have file claims for compensation under the Motor Vehicles Act, 1939 ;

(b) the steps Government propose to take in order to settle the compensation cases under the Motor Vehicles Act within the shortest possible time ; and

(c) whether Government propose to appoint District Judges/Additional District Judges of Delhi as ex-officio Motor Accidents Claims Tribunals in Delhi in order to reduce the huge arrears pending before the Motor Accidents Claims Tribunal ?

THE MINISTER OF PARLIAMEN-  
TARY AFFAIRS AND SHIPPING  
AND TRANSPORT (SHRI RAGHU  
RAMAIAH) : (a), (b) and (c). The in-  
formation required is being collected and  
will be laid on the Table of the Sabha,  
when received.

**National Highway Development and  
Extension System**

\* 6899. SHRI VALMIKI CHOUDH-  
ARY : Will the Minister of SHIPPING  
AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether as a step towards affe-  
cting National Integration any programme  
to link all parts of the country by a  
National Highway system is proposed to  
be launched under the Fourth Five Year  
Plan ;

(b) If so, the details of the new  
links to be provided under the National  
Highway Development and Extension  
Scheme under the Fourth Five Year  
Plan, and which of these would be in  
Bihar ; and

(c) the total length of these links and  
how much of it would be in Bihar ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE  
DEPARTMENT OF PARLIAMEN-  
TARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF  
PARLIAMEN- TARY AFFAIRS, SHIP-  
PING AND TRANSPORT ( SHRI  
IQBAL SINGH) : (a) to (c). There is  
already a National Highway system  
including about 15,000 miles of roads  
linking various parts of the country.  
Out of about 15,000 miles, 1167 miles  
fall in Bihar. Within the available funds,  
steps are already being taken to develop  
this system to cater to the needs of  
traffic and action in this regard will  
continue to be taken in the Fourth Plan  
period also. Besides, it is proposed to  
consider making some new additions also  
to the existing National Highway system  
in the Fourth Plan period. Proposals  
in this regard are, however, under for-  
mulation and details can be indicated  
only after the Fourth Plan Allocations  
have been finalised as the extent of these  
new additions is dependent upon the

funds which might be made available for  
this purpose under the Fourth Plan.

**Disfiguring of Statues of Leaders  
in West Bengal**

6900. SHRI SAMAR GUHA : Will  
the Minister of HOME AFFAIRS be  
pleased to state :

(a) whether it is a fact that soon  
after the announcement of the mid-term  
poll results in West Bengal, the Statue  
of Netaji Subhas Chandra Bose was  
decorated with Red Flags and Insignis at  
the crossing of Shyambazar in Calcutta ;

(b) whether almost at the same time  
the 'head' of the statue of Dr. B. C.  
Roy at Durgapur was severed ; and

(c) if so, the reaction of Government  
thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS :  
(SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) According to information received  
from the state Government it was re-  
ported that the statue of Netaji Subhash  
Chandra Bose was decorated with For-  
ward Block flags and with red scarf  
around the neck after the announcement  
of mid-term election results in West  
Bengal.

(b) According to information received  
from the state government, on 16th  
February 1969 the residents of Viswa-  
karma Nagar, Durgapur noticed that  
the head of the statue of Dr. B. C. Roy  
had been severed by some unknown  
miscreants.

(c) In connection with the damage  
to the statue of Dr. B. C. Roy a case  
under sections 427, 489 and 379 of the  
Indian Penal Code was registered at  
police station Durgapur. The investi-  
gation of the case is in progress.

**Techno-Economic Survey of Himachal  
Pradesh**

6901. SHRI HEM RAJ : Will the  
Minister of HOME AFFAIRS be pleased  
to state :

(a) whether any Techno-Economic Survey of the expanded Himachal Pradesh after the reorganisation of Punjab is proposed to be undertaken ; and

• (b) if so, when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUNLA) : (a) and (b). There is no proposal to undertake a techno-economic survey of the enlarged Himachal Pradesh.

**Museum in Memory of Late Dr. Rajendra Prasad in Bihar Vidyapith, Patna**

6902. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Shri Jaya Prakash Narayan has set up a museum in the memory of late Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, in Bihar Vidyapith at Patna ;

(b) if so, whether Government propose to take it under its own management to perpetuate his memory ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir. A museum after the name of late (Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, has been set up by the Rajendra Smriti Samiti in Bihar Vidyapith at Patna of which Shri Jaya Prakash Narayan is a member.

(b) No such proposal from the Samity has been received either by this Ministry or by the State Government.

(c) As such the question of taking over the management of the museum does not arise.

**Assistance to Maoists from Chinese Embassy in India**

6903. SHRI RAM GOPAL SHALWALE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn toward the news that the Embassy of China has provided arms assistance for the Maoist revolution in Kerala ;

(b) whether it is a fact that according to the Trivandrum Radio reporter a letter of complaint has been handed over to the District Magistrate of Calicut in which the attack made on Pul-Pally and Tellicherry in November last has been discussed ;

(c) whether Shri Kunnikkal Narayanan, the first accused in the attack, had direct connection with the Embassy of China ; and

(d) if so, the reaction of Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) Government have seen some press reports regarding the charge-sheets submitted in the cases in connection with attacks on pulpally outpost and Tellicherry police station in Kerala in November, 1968. The State Government are being requested to furnish copies of such charge-sheets.

(b) The exact list of the news-item broadcast by the Trivandrum Station of All India Radio is being ascertained.

(c) According to information received from Kerala Government, during the course of investigation relating to the attacks on Pulpally outpost and Tellicherry police station it was revealed that Shri Kunnikkal Narayanan was having contacts and regular correspondence with the Chinese Embassy in New Delhi.

(d) The cases relating to attacks on Pulpally outpost and Tellicherry police Station are sub-judice.

**Teaching of South Indian Languages in Schools**

6904. SHRI V. NARASIMHA RAO : Will the Minister for EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have any proposal to introduce the teaching of South Indian languages in the Schools compulsorily ; and

(b) if so, whether Government would commend the example of U. P. to the other States in the interest of national integration ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) No such information has as yet been received from the Government of Uttar Pradesh.

(b) Does not arise.

#### Control of Bhakra Dam

6905. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Central Government have taken any initiative to resolve the question of control of the Bhakra Dam between the concerned State ;

(b) whether the Government of Haryana have recently offered to talk with other concerned States on this issue ;

(c) if so, progress which has been made by the Central Government in the matter ; and

(d) if no initiative has been taken so far, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). No offer by the Government of Haryana to have talks with other concerned States on this issue has been received by the Government of India. As there has been no agreement so far between the Governments concerned with regard to the procedure to be adopted for resolving this issue, it has not been possible for the Central Government to take any initiative in the matter.

#### महाराष्ट्र में प्राचीन अवशेष

6906. देवराव पाटिल : क्या शिक्षा

तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में प्राचीन अवशेष इस समय उपेक्षित दशा में है ;

(ख) महाराष्ट्र में प्राचीन कितने अवशेषों की देखभाल की जाती है तथा कितने अवशेषों की मरम्मत की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि माहौर स्थित भगवान दत्तात्रेय के प्राचीन मंदिर की और पुरातत्व विभाग द्वारा अविजम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है, और

(घ) यदि हाँ तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहान द्वारा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं। महाराष्ट्र के स्मारकों का रख-रखाव, उपलब्ध निधियों की सीमा में परिरक्षण की अच्छी हालत में रखा जाता है।

(ख) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा लगभग 3,500 स्थानों और स्मारकों की देखभाल की जाती है। राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों की संख्या 279 है, जिनमें महाराष्ट्र में स्थित सात प्राचीन स्थान भी शामिल हैं, जिनकी देखभाल, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। पिछले वर्ष शुरू की गई एक संरक्षण कार्यक्रम के अर्धेन महाराष्ट्र स्थित 30 स्मारकों को मरम्मत के लिये लिया गया था। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार अन्य स्मारकों से सम्बन्धित सामान्य वार्षिक अनुरक्षण कार्य भी हाथ में लिया गया था।

(ग) माहौर स्थित भगवान दत्तात्रेय का मंदिर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं और इसलिये इसकी देखभाल, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा नहीं की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।



**Naxalite Posters in Delhi University**

6908. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report appearing in the "Indian Express" dated the 7th March, 1969 about the activities of Naxalities in the Delhi University in bringing about Maoist revolution by pasting on the walls posters with the slogans like 'Power grows out of the barrel of a gun', 'Think for yourself' 'Down with rank imperialism' ; and demanding release of the Naxalite leader, Kanu Sanyal ; and

(b) if so, the reaction of the Government in regard thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) Government have seen the Press report.

(b) Inquiries were made, but the persons responsible for the display of the posters could not be traced. Strict watch on the activities of extremist elements is being kept, and wherever necessary appropriate action under the law would be taken.

**Theft of Jewellery in Indian Airlines Flight from Delhi to Hyderabad**

6909. SHRI D. B. RAJU : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether any complaint was received regarding the theft of jewellery in Indian Airlines flight from Delhi to Hyderabad on the 29th November, 1968 ;

(b) if so, the total value of the jewellery ;

(c) the steps being taken for investigation ; and

(d) the special steps Government propose to take to check such thefts ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) (a). Yes, Sir.

(b) The value of gold items declared lost was given as 49 sovereigns.

(c) Reports were lodged with the police, both at Delhi and Hyderabad, but the lost property has not been recovered so far.

(d) Under the baggage Rules passengers are required to declare the valuables carried as part of the baggage. This was not done in the present case by the passenger. Supervision by the Traffic Agent and security personnel has been tightened.

**राजस्थान से बीस परिवारों का पाकिस्तान को जाना**

6910. श्री हुकूम चन्द कछवाय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विधान परिषद् के एक भूतपूर्व सदस्य श्री हरिपद भारती के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान के सीमावर्ती गाँवों से 20 परिवार पाकिस्तान चले गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिजावरण शुक्ल) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**Fellowships to Students of Space Engineering and Rocketry**

6911. SHRI KARTIK ORAON :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government have decided to give any Post-Graduate Fellowships to the students under-going training in the country for Space Engineering and Rocketry at the Institutes approved by Government ;

(b) if so, the number thereof, Institute-wise, during 1968-69 and 1969-70 ; and

(c) the amount sanctioned per student ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) :

Number of fellowships sanctioned

Indian Institute of Science, Bangalore.

1968-69

1969-70

10

In addition to continuing the fellowships awarded to the students of 1968-69, up to ten fellowships will be awarded to new entrants.

Birla Institute of Technology, Ranchi.

8

In addition to continuing the fellowships to those students who have to complete the course, upto ten fellowships will be awarded to new entrants.

(c) The value of the fellowships at the Indian Institute of Science, Bangalore is Rs. 250 per month in the first year of the course and Rs. 300 per month in the second year of the course. At the Ranchi Institute, the value of the fellowships is Rs. 250 per month in each year of the course.

(d) the names of such tourist centres and the money allocated ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (d). A sum of Rs. 65 lakhs has been proposed under various heads for developing tourist facilities at the major centres of Buddhist importance. The detailed allocations will be made after the Plan has been finalized.

#### Development of Buddhist Tourist Centres

6912. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether separate allocations have been made for the development of Buddhist tourist centres in the country during the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the amount allocated for the purpose ;

(c) the amount that has been allocated to Orissa for the development of Buddhist tourist centres in that State ; and

#### Tourist Spots in Rajasthan

6913. SHRI BRJ RAJ SINGH KOTAH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have ever surveyed tourist spots, apart from those being frequented by tourists at present, in Rajasthan ;

(b) if so, the details thereof and the steps taken to develop these places ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). Government are aware of the tourist potential of places in Rajasthan other than those now popular with tourists. However, due to scarcity of resources in the Fourth Plan, it is not possible to give high priority to their development.

#### Commercial Helicopter Service in Bombay

6914. SHRI BRIJ RAJ SINGH KOTAH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to start a commercial Helicopter service in Bombay at Nariman Point ;

(b) if so, the broad outlines of the scheme ;

(c) if not, whether there is any other scheme by some private firms to do so ; **and**

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) :

- (a) No. Sir.  
 (b) Does not arise.  
 (c) No, Sir.  
 (d) Does not arise.

#### Air-India Plans for Touching Scandinavia

6915. SHRI BRIJ RAJ SINGH KOTAH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Air India has any plans for touching points in Scandinavia ;

(b) whether any survey is being done to explore feasibility of doing so ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). A survey team of

Air-India recently visited the Scandinavian countries to assess the traffic potential into and out of Scandinavia. The report of the team is awaited.

#### Hotels in Bombay

6916. SHRI BRIJRAJ SINGH KOTAH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of new hotels that are being planned to be located in Bombay ;

(b) the names of the hotels and full details of their collaboration ;

(c) whether the Air India is also putting up one Hotel at Santa Cruz ; and

(d) the dates by which these hotels are expected to be in operation ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (d). A number of new hotels are being planned in Bombay, including two by Air-India—one at Santa Cruz and another at Juhu Beach. These projects are likely to be completed in the Fourth Plan period.

#### मध्य प्रदेश में सड़कों का बिस्तार

6917. श्री राम सिंह अयरबालु : क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश में औसतन 100 वर्गमील क्षेत्र के लिए केवल 20 सड़कें हैं जब कि समूचे देश में 100 वर्ग मील क्षेत्र के लिए औसतन 38 मील सड़कें हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वहाँ सड़कों के बिस्तार के लिए मध्य प्रदेश को अतिरिक्त अनुदान देने का सरकार का विचार है और यदि हो तो कितनी राशि ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश द्वारा की गई औद्योगिक

गिक तथा आर्थिक प्रगति में सड़कों के योगदान का बड़ा महत्व रहा है और यदि हाँ, तो क्या उस राज्य को कोई विशेष अनुदान दिया जाएगा जिसकी एक तिहाई जन-संख्या हरिजनों तथा आदिवासियों की है, और

(घ) क्या मध्य प्रदेश में सड़कों के विस्तार के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की कुछ विशेष व्यवस्था की जायेगी ताकि औद्योगिक दृष्टि से इसका विकास हो सके क्योंकि वहाँ प्राकृतिक संसाधन तथा खनिज सम्पत्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ?

संसदीय विभाग और नौबहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं। मूल सड़क आंकड़े 1967 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग मील क्षेत्र के लिए 24 मील आती है जब कि सारे देश के लिए वह 44 मील है। तथापि जन-संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की सड़क मील दूरी लगभग वही आती है जो सम्पूर्ण देश की है अर्थात् प्रति लाख जन-संख्या के लिए लगभग 107 मील।

(ख) और (ग). जो सड़कें राज्य योजनाओं के अंग हैं उनके लिए केन्द्रीय सरकार कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है सिवाय राज्य योजनाओं के लिए कुल केन्द्रीय सहायता के रूप में और जिसे राज्य सरकारें यदि चाहें तो सड़कों पर भी प्रयुक्त कर सकती हैं। तथापि भारत सरकार अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत और केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) आरक्षण से कुछ चुनी हुई राज्य सड़कों के लिए सहायता अनुदान देती है। चौथी योजना अवधि में मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए केन्द्रीय राज्य निधि (सामान्य) आरक्षण से 30 लाख रुपये का एक सहायता अनुदान देता है। अन्तर्राज्यीय महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को कितनी सहायता दी

जाएगी यह चौथी योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही सूचित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में सड़कों ने क्या भूमिका निभाई है इससे सम्बन्धित आवश्यक सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है।

(घ) राज्य योजना की कुल उच्चतम निधि, जिसे चौथी योजना के मंजूर होने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जाएगा, के अन्तर्गत सड़कों के लिए धन नियतन के प्रश्न पर मुख्यतः राज्य सरकार ही विचार कर सकती है।

#### मध्य प्रदेश में निरक्षरता

6918. श्री राम सिंह अयरवाल : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने का करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में एक हजार लोगों में 171 लोग निरक्षर हैं जब कि अखिल भारतीय औसत 240 है और यदि हाँ तो क्या वहाँ से निरक्षरता को दूर करने के लिए उसे विशेष अनुदान देने या वहाँ पर केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाएँ खोलने का सरकार का विचार है,

(ख) क्या मध्य प्रदेश में एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है जिसमें हरिजन आदिवासी और निचले छात्रों को भोजन, रहने और पुस्तकों आदि की सभी सुविधाएँ प्राप्त हों और जहाँ उन्हें कुछ ऐसा काम दिया जाए जिससे वे अपना खर्च पूरा कर सकें, और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक और तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री बी. के. आर. बी. राव) : (क) जी, हाँ। 1961 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय औसत 24 के विरुद्ध मध्य प्रदेश में साक्षरता की प्रतिशतता 17.1 थी। ;

प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति के लिए 1960 से इंदौर में कामगार सामाजिक शिक्षा संस्थान कार्य कर रहा है। इस संस्थान को मध्य प्रदेश सरकार के जरिए, शिक्षा मंत्रालय से 100 प्रतिशत अनुदान मिलता है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना—किसान साक्षरता योजना के अन्तर्गत, रायपुर जिले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साक्षरता की कक्षाएं खोली गयी हैं। शिक्षा मंत्रालय इस प्रायोजना का 100 प्रतिशत खर्चा पूरा करता है। आगे मध्य प्रदेश के स्वैच्छिक संस्थाएं साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम की सहायता के लिए मंत्रालय की योजना का फायदा उठा सकती है।

(ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Recognition to Rowing Boat Expedition Team to Andamans**

6919. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state ;

(a) whether the two-member team of the rowing boat expedition to Andamans which completed the rowing successfully has been given any recognition ;

(b) if so the details thereof ; and

(c) The steps proposed to be taken to encourage such expeditions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) and (b). The Ministry of Education and Youth Services has sponsored a lecture tour of Lt. George Albert Duke and Shri Pinaki Ranjan Chatterjee to important university centres in India. The tour is now on. The expenditure on this travel is being borne by this Ministry. The expenditure on board and lodging is either being borne by the

State Government concerned or by the university concerned.

(c) This Ministry would be prepared to give encouragement to expeditions of this nature, the actual steps for the purpose to be determined on receipt of specific proposals and in the light of available resources.

**Air Raid Exercise in Delhi**

6920. SHRI BENI SHANKAR SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether an air raid exercise was held in Delhi on the 23rd March, 1969;

(b) whether it was a successful experiment ; and

(c) the arrangements made to hold such exercises in other principal towns of the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) Yes, Sir.

(b) The exercise was successful to a large extent.

(c) The State Governments/Union Territory Administrations have been advised to hold such civil defence exercises in selected towns once in two months.

**Delhi Administration Subordinate Ministerial Executive Service 1967**

6921. SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state ;

(a) whether Government have received certain representations regarding appointment/promotion, fixation of seniority etc. in the newly constituted Delhi Administration Subordinate Ministerial Executive Service, 1967 ;

(b) if so, the broad details thereof ; and

(c) the action taken thereon so as to do justice to the affected persons ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) Tentative seniority lists of the four grades of the Subordinate Ministerial and Executive Services of the Delhi Administration were prepared by the Administration and circulated for inviting objections. Most of the representations received related to the fixation of *Inter Se* seniority of the officers and their absorption in the Services at their initial constitution. Some representations were received from the officers who were superseded for promotion in the next higher grade.

(c) The representations received have been/or are being disposed of by Delhi Administration in accordance with the provisions of the Delhi Administration Subordinate Ministerial/Executive Service Rules, 1967.

#### Use of Foreign Money in Mid-Term Elections

6922. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state ;

(a) whether Government have ascertained the extent to which foreign money has played part in the recent mid-term elections in the country ;

(b) whether any enquiry is proposed to be conducted into this matter ;

(b) if so, the details of the proposed enquiry ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) Government have no information regarding the use of foreign money in the mid-term elections.

(b) No, Sir,

(c) and (d). Do not arise.

दिल्ली में चोरी के मामलों का संजीवन

6923. श्री रामावतार शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली के पुलिस थानों में पुलिस अधिकारी चोरी के मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते और यदि दर्ज करने भी है तो झूठी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उन पर कार्यवाही करने में संकोच करते हैं ;

(ख) क्या ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि पुलिस अधिकारी उन व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जो उनके पास शिकायतें दर्ज कराने के लिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ग) सभी स्टेशन हाउस अफसरों को विभागीय हिदायतें दी गई हैं कि सभी शिकायतों को दर्ज किया जाय और शिकायतकर्ताओं के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार भी किया जाए । इन हिदायतों के उल्लंघन पर कठोर कार्यवाही की जाती है । जब कभी ऐसी शिकायत प्राप्त होती है, उस पर गौर किया जाता है और विधि व विभागीय विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है । पर्यवेक्षी अधिकारी आकस्मिक जांच तथा नमूने के तौर पर कुछ मामलों में परीक्षणों द्वारा नियंत्रण करते हैं ।

#### Bridge on River Ganga at Patna

6924. SHRI V. NARASIMHA RAO : Will the Minister of SHIPPING

AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have renewed the request to include the bridge over the river Ganga at Patna in the Fourth Plan ;

(b) whether it is also a fact that the scheme for the bridge was first mooted in 1913 and has been considered several times since then ; and

(c) if so, at what stage the scheme is at present and whether it is proposed to take it up in the near future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS' AND IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) The Bihar Government are concerned with the proposed bridge over Ganga at Patna as it would fall on a State road. It is already included in the State Government's Fourth Plan but they are unable to finance it from their own resources. They have therefore, been pressing for financial assistance for it and have reiterated this request recently.

(b) Yes, Sir. The proposal made in 1913 was, however, really for a railway bridge at Patna which, on expert advice, could not be accepted. Subsequently, the State Government have been pressing for the construction of a road bridge.

(c) The State Government's request is being examined.

Firing by East Pak Rifles

6925. SHRI N. R. DEOGHARE :

✓ SHRI MADHU LIMAYE :

SHRI C. K. BHATTACHARYA :

SHRI D. N. PATODIA :

SHRI RAMESH CHANDRA  
VYAS :

SHRI R. BARUA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the East Pakistan Rifles opened fire on the Indian Border Security Force in the Bamungola sector in Malda District on the 22nd and 23rd March, 1969 ;

(b) if so, the number of casualties on both sides ; and

(c) the action Government propose to take in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) Three Indian police personnel sustained bullets injuries. The casualties in Pakistan side are not known.

(c) Protests have been lodged by the Sector Commander, the Inspector General, Border Security Force and the State Government with their counterparts in East Pakistan. The Border Security Force is carrying out vigorous patrolling and maintaining constant vigil in the area.

Payment of Salaries to Teachers of Aided Schools in Delhi

6926. SHRI N. R. DEOGHARE :

SHRI SHASHI BHUSHAN :

SHRI MUHAMMAD SHERIFF :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the teachers of aided Schools in Delhi have not been paid their salaries for the last three months ;

(b) whether it is also a fact that the teachers have threatened to plan an agitation to draw the attention of Government to their grievances ; and

(c) if so, the action Government propose to take in this connection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI

BHAKT DARSHAN) : (a) No, Sir.

(b) It has been so reported in some sections of the press.

(c) It is understood that a memorandum submitted to the Chief Executive Councillor, Delhi by a deputation of Government Aided Schools' Teachers Association is under the consideration of the Delhi Administration.

#### Murders in Delhi

6927. SHRI N. R. DEOGHARE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of cases of murder/ attempts to murder in Delhi during the year 1968 ;

(b) the number of persons involved and punished ; and

(c) the average per day of murder cases in Delhi during the year 1968 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) Murder cases ...86  
Attempt to Murder cases...76

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in library. See No. LT-818/69]

(c) 0.24 cases approximately.

#### शेख अब्दुल्ला

6928. श्री रामगोपाल शालबाबले : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे शेख अब्दुल्ला की रिहाई के पश्चात् यह बंगला आवंटित किया गया है जिसे सरकार ने शेख अब्दुल्ला की हिरासत के लिए शेख अब्दुल्ला को आवंटित किया था ;

(ख) क्या शेख अब्दुल्ला की इस समय दिल्ली में कोई सम्पत्ति है और यदि हां, तो

उसका ब्योरा क्या है और वह कहां पर है ; और

(ग) दिल्ली में शेख अब्दुल्ला किस स्थान पर ठहरते हैं और उसकी आय का साधन क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) शेख अब्दुल्ला पर से प्रतिबन्ध हटा लेने के पश्चात्, जिस निवास स्थान पर उन्हें नजरबन्द रखा गया था, वह उन्हीं के नाम में आवंटित है।

(ख) सरकार को किसी ऐसी सम्पत्ति की जानकारी नहीं है।

(ग) पिछली बार, जब शेख दिल्ली आये थे तो उसी स्थान पर ठहरे थे जो उन्हें आवंटित किया गया है।

शेख की आय के स्रोत के बारे में सरकार को गुप्त सूचना मिलती रहती है, ये सूचनायें जनता को बताने के लिए नहीं हैं।

शेख अब्दुल्ला पर उसकी हिरासत के दौरान किया गया व्यय

6929. श्री रामगोपाल शालबाबले : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शेख अब्दुल्ला पर उसकी हिरासत के दौरान प्रतिमास तथा मद-वार किये गये खर्च का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार शेख अब्दुल्ला की पत्नी, उसके पुत्र तथा अन्य लोगों को उक्त अवधि के दौरान वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देती रही है और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में इसका महीने वार ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि रिहा होने के बाद शेख अब्दुल्ला अपने साथ वह माल



भी ले गये जो उन्होंने सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता तथा अनुदान से खरीदा था, और यदि हां, तो उसके द्वारा ले जाये गये तथा पीछे छोड़े गये माल का पृथक-पृथक व्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिष्णा चरण शुकल) : (क) और (ख) एक विवरण रखा जाता है। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT 819/69]। इसमें वह खर्च शामिल है जो दोनू ब्रन्डुला के परिवार के उन सदस्यों तथा निकट सम्बन्धियों पर किया गया जिन्हें उसकी नजरबन्दी के दौरान सरकारी खर्च पर उसके साथ कुछ समय के लिए रहने अथवा भेंट करने की अनुमति दी गई थी।

(ग) उसको दिये गये अनुदान से उसके द्वारा की गई खरीद की सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

#### Lighting Facilities at Airports

6930. SHRI NARENDRA KUMAR SALVE : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of airports in the country which lack lighting facilities ;

(b) the reasons for the lack of such facilities at airports ; and

(c) the steps taken by Government to provide these facilities at such airports ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) None, Sir. Though some do not have electric lighting but only goose-neck flares.

(b) and (c). Electric lighting facilities are costly, but efforts are made to provide these as and when funds permit.

#### उमरसू (उत्तर प्रदेश) में गंगा नदी पर पुल का निर्माण

6931. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या नौबहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसा जापन प्रधान मंत्री को प्राप्त हुआ है जिस पर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिला पोड़ी के कांदलवालसयून पट्टी के 5000 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं और जो उन्होंने 10 जनवरी, 1969 को डाक द्वारा भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उन्होंने क्या मांगें की हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने उक्त जापन में उमरसू में गंगा नदी पर पुल बनाए जाने के बारे में मांग की है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह पुल सामरिक महत्व का होगा और इससे लोगों को लाभ भी होगा ;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(च) यदि उस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय-कार्य विभाग और नौबहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : जी, नहीं।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते हैं।

#### Dialogue on Centre-State Relations

6932. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister has shown her inclination to open dialogue on the Centre-State relations ; and

(b) if so, the concrete follow up action proposed by the Central Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS. (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The Prime Minister had indicated at the last meeting of the Standing Committee of the National Integration Council that the question could be discussed by the Committee on the basis of some working papers. It was also indicated that the Government were awaiting the report of the Administrative Reforms Commission on Centre-State relations. The Commission have been requested to expedite their report.

#### Indo-Burma Pioneer Mission in Manipur

6933. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the Indo-Burma Pioneer Mission, an American Mission applied for land in the town of Imphal in the name of running a College ;

(b) whether the said Mission has disbanded the Sielmat Christian College at Churachandpur without any reason being shown to all concerned including the Government of Manipur ;

(c) whether the Government of Manipur have given any *ad hoc* grant to this College in the past ;

(d) the action Government have taken to look into the deals of this Mission disbanding the College and applying for land in the town and such activities of the Mission which are not in the interests of this country ;

(e) whether Government have already granted land to this foreign Mission in the heart of the new Lampelet Town ; and

(f) if so, the reason therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI

BHAKT DARSHAN) : (a) Yes, Sir. An application for the grant of land in Khuman Lampak, Imphal was received by the Government of Manipur on 27-11-1968 for Sielmat Christian College run by the Indo-Burma Pioneer Mission and the Independent Church of India which are both Indian and not American Missions with headquarters at Churachandpur.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir ; Rs. 22,000 in 1966-67 only.

(d) An enquiry was made by Manipur Administration which revealed internal disputes among members of the Mission about the ownership of land and property, but no activity against the interests of the nation. The application for the allotment of land is pending with the Manipur Administration.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

#### Misuse of Government Grants by Private Educational Institutions in Delhi

6934. SHRI K. M. ABRAHAM :  
SHRI A. K. GOPALAN :  
SHRI MOHAMMAD ISMAIL :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the misuse of Government grants to private educational institutions like the Manav Sthali Higher Secondary School, New Rajinder Nagar, New Delhi ;

(b) if so, the steps Government propose to take in the matter, and

(c) Whether any steps are proposed to be taken to grant the class IV employees of these private institutions the same scale of pay as is given to class IV Government employees ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) Yes, Sir. A complaint alleging the use of school furni-

ture and science equipment by Manavsthal High School, New Rajender Nagar, New Delhi in one of the unrecognised schools run by its management was received by the Delhi Administration.

(b) A departmental enquiry has been instituted by the Delhi Administration.

(c) The scales of pay as in Government Schools are already applicable to their counterparts in aided schools.

**I. C. S./I. A. S./I. A. and A. S.  
Officers in Public Undertakings**

6935. SHRI GANESH GOSH :  
SHRIMATI SUSEELA GOPALAN :  
SHRI NAMBIAR :  
SARI K. RAMANI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Public Undertakings to which I. C. S., I. A. S., and I. A. and A. S. officers have been deputed ;

(b) the number of such officers in each of the Public Undertakings ; and

(c) the number of Public Undertakings to which no officer of the above cadres has been deputed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :  
(a) 50.

(b) As per statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-820/69.*]

(c) 34.

**Amount or National Scholarships and Central Scholarships Surrendered**

6936. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the amount of National Scholarships and other central Scholarships for educational purposes actually used and surrendered, separately, by each State during 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ; and

(b) how the above amounts were used ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) This Ministry operates only three National and Central Scholarships Schemes through the State Governments as given in three statements laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-821/69.*]

(b) The amounts were used by the State Governments for making payments in regard to fresh scholarships and renewal of scholarships awarded in previous years.

I. A. S./I. P. S. Officers of M. P. Cadre on Deputation

6937. SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of Officers of the Madhya Pradesh Cadre of I. A. S. and I. P. S. who have been on deputation to various Ministries/Organisations of the Government of India for more than three years ;

(b) the assignments held by them ;

(c) the names of Officers out of them who have been holding the same assignments in the same Ministry/Organisation for more than three years and whose tenure had been extended more than once ;

(d) whether the continuance of these Officers after a period of three years in the same Ministry/Organisation is contrary to the orders issued by his Ministry in the matter ; and

(e) if so, the reasons for extending their tenure ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library See No. LT-822/69*]

(c) to (e). The periods of tenure prescribed under the rules vary from 3 to

5 years. There are no orders which require that an officer must be given a change of assignment after he has held a post for 3 years.

#### Retrenchment in I. C. C. R.

6938. SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the Indian Council for Cultural Relations proposes to retrench some of its employees before the close of the financial year ;

(b) if so, what arrangements have been made to provide the surplus or retrenched staff with alternative jobs ; and

(c) what are the reasons for retrenchment of staff ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) to (c). The staff position in the I. C. C. R. has been examined by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance : certain surpluses have been located in the staff. The recommendations of the Staff Inspection Unit are being examined by a Committee set up by the Governing Body of the I. C. C. R. The Governing Body is the final authority in the matter.

#### Threat of Chinese Infiltration in NEFA

6939. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a growing danger of Chinese infiltration into N. E. F. A. ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to counter the move ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

#### Pro-Peking Publications in Kerala

6940. SHRI HEM BARUA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese Embassy, Delhi had written to a pro-Peking Publishing house in Calicut seeking the reaction of readers of Kerala to certain Maoist publications ; and

(b) if so, the details of this incident and whether the letter in the original is in the custody of Government and if so, whether Government propose to lay a copy thereof on the Table ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) According to information received from the State Government, among the papers seized by the police during the course of investigations relating to the attacks on Pulpally outpost and Tellicherry police Station was a letter dated 19th May, 1967 from the Embassy of the People's Republic of China in India addressed to the Marxist Publications, Calicut, in which the reaction, if any, among the readers in Kerala to certain articles had been sought.

(b) The original document is not in the custody of the Central Government. The cases registered in connection with the incidents referred to in part (a) are pending trial before the court of law.

12-14 hrs.

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

AUDIT REPORT (CIVIL) 1969 AND APPROPRIATION ACCOUNTS (CIVIL) 1967-68.

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : I beg to lay on the Table :

(1) A copy of the Audit Report (Civil), 1969, under article 151 (1) of the constitution.

(2) A copy of the Appropriation Accounts (Civil). 1967-68.

[Placed in library. See No. LT-802/69]

**NOTIFICATION UNDER ESSENTIAL  
COMMODITIES ACT**

**THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE  
COMMUNITY DEVELOPMENT AND  
COOPERATION (SHRI DERING :**  
On behalf of Shri Annasahib P. Shinde,  
I beg to lay on the Table a Copy of  
Notification No. G. S. R. 919 published  
in Gazette of India dated the 2nd April,  
1969 undersub-section (6) of section 3 of  
the Essential Commodities Act, 1955,  
rescinding the Madhya Pradesh Coarse  
Grains (Export Control) Order, 1964.  
[Placed in Library. See No. LT—803/69]

**NOTIFICATIONS UNDER INTER-  
STATE CORPORATIONS ACT**

**THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
( SHRI R. S. RAMASWAMY :**  
On behalf of Shri Vidya Charan  
Shukla, I beg to lay on the table a copy  
each of the following Notifications under  
sub-section (5) of section 4 of the Inter-  
State Corporations Act, 1957:

(1) The Council of Homoeopathic  
System of Medicine, Punjab (Reconsti-  
tution and Reorganisation) Order 1969,  
published in Notification No. S. O. 1301  
(English version) and S. O. 1304 (Hindi  
version) in Gazette of India dated the  
31st March, 1969.

(2) The Punjab Labour Welfare Board  
(Reconstitution and Reorganisation)  
Order 1969 published in Notification No.,  
S. O. 1302 (English version) and  
S. O. 1305 (Hindi version) in Gazette of  
India dated the 31st March 1969.

(3) The Punjab Bhudan Yagha Board  
(Reorganisation) Order, 1969, published  
in Notification No. S. O. 1303 (English  
version) and S. O. 1306 (Hindi version) in  
Gazette of India dated the 31st March,  
1969. [Placed in Library. See No. LT—  
804/69]

**ANNUAL REPORT OF SCHOOL OF  
PLANNING AND ARCHITECTURE,  
NEW DELHI**

**THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF EDUCATION AND  
YOUTH SERVICES (SHRIMATI  
JAHANARA JAIPAL SINGH) :**  
I beg to lay on the Table a copy of  
the Annual Report of the School of  
Planning and Architecture, New Delhi,

for the year 1967-68 a long with state-  
ment of accounts. [Placed in Library. See  
No. LT—805/69]

**PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE  
FORTY-SIXTH AND FIFTY-FIRST  
REPORTS**

**SHRI DATTATRAYA KUNTE**  
(Kolaba): I beg to present the follo-  
wing Reports of the Public Account-  
Committee:—

(1) Forty-sixth Report on action  
taken by Government on the recommen-  
dations contained in their Fifty-seventh  
Report (Third Lok Sabha) on expenditure  
incurred by the External Publicity Divi-  
sion of the Ministry of External Affairs.

(2) Fifty-first Report on action taken  
by Government on the recommendations  
contained in their Fifteenth Report on  
Appropriation Accounts (Defence Services)  
1965-66 and Audit Report (Defence Ser-  
vices), 1967.

**COMMITTEE ON PUBLIC UNDER-  
TAKINGS  
FOURTY-SECOND REPORT**

**SHRI G. S. DHILLON (Taran  
Taran) :** I beg to present the Forty-  
second Report of the Committee on Pub-  
lic Undertakings on Mazagon Dock Limi-  
ted, Bombay.

12. 16 hrs.

**STATEMENT BY MEMBER UNDER  
DIRECTION 115 AND MINISTER'S  
REPLY THERETO**

**श्री हुकमचन्द कल्लवाह (उज्जैन) :**  
अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23-4-68 को तारां-  
कित प्रश्न संख्या 1384 के उत्तर में श्री परि-  
मल घोष ने कहा कि मैंने ग्राम चुनाव 1967  
के पूर्व उन सभी फर्मों से त्यागपत्र दे दिया  
था जिनमें मैं डायरेक्टर तथा पदाधिकारी  
था।

इसी प्रश्न के सम्बन्ध में 7 मई, 9168  
को अतारंकित प्रश्न संख्या 10042 के उत्तर  
में औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्री  
श्री फलरुद्दीन अली अहमद ने बताया कि  
श्री परिमल घोष 28 मई, 1967 तक  
कलकत्ता के मैसर्स हिमालय पेपर एण्ड बोर्ड  
मिल्स प्राइवेट लि० के डायरेक्टर थे।

उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के स्पष्ट विरोध के आधार पर मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी। किन्तु मुझे उसकी अनुमति नहीं दी गई और इसके सम्बन्ध में मंत्री द्वारा मुझे के स्पष्टीकरण की सूचना मुझे लोक-सभा सचिवालय द्वारा दी गई। इससे मेरे प्रश्न की गम्भीरता और भी बढ़ गई है। उनके अभी के स्पष्टीकरण के अनुसार :

(1) उन्होंने अपना त्याग-पत्र दिनांक 1 अप्रैल, 1967 को दिया, यह श्री घोष के दिनांक 23 अप्रैल के वक्तव्य से सर्वथा विपरीत है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि श्री घोष ने 13 मार्च, 1967 को मंत्री पद की शपथ ले ली थी अर्थात् यदि 1 अप्रैल के त्याग पत्र की बात को भी मान लिया जाय तो भी वे मंत्री बनने के बाद निदेशक बने रहे।

(2) काउंसिल ऑफ प्रोसेसिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लि० 4, क्लाइव रोड, कलकत्ता-1 के निदेशक ने अपने 7 फरवरी, 1969 के पत्र में स्पष्ट लिखा है कि श्री परिमल घोष का कोई त्यागपत्र उन्हें नहीं मिला। बोर्ड की 26-4-67 की बैठक में अनुपस्थित होने की अनुमति श्री परिमल घोष को कम्पनी से मिली। उसके बाद 1 सितम्बर, 1967 से श्री परिमल घोष को कम्पनी के निदेशक पद से मुक्त किया गया तथा इसकी पुष्टि रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के यहाँ 883 नं० दिनांक 29-9-67 को की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री परिमल घोष ने जानबूझ कर असत्य बयान द्वारा सदन को गुमराह किया है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI PARIMAL GHOSH) : In the Notice under Direction 115 it has been alleged that I tried to mislead the House by making false statements deliberately. In that connection, it has been stated (i)

that I continued to be a Director in the Himalaya Paper and Board Mills (P) Ltd., Calcutta, even after I became Minister, and (ii) that I was relieved from the Directorship of Messrs. Card-Board Printing and Processing Industries Ltd., 4, Clive Row, Calcutta-1, from 1st September, 1967, and that the Registrar of Companies was duly informed about this *vide* letter No. 883 of 29-9-1967.

Re. (i) : It is true that in the statement made by me on 23-4-1968 I stated that I had resigned from the Directorship of the two Companies, namely, the Himalaya Paper (Machinery) Private Ltd., and the Himalaya Paper and Board Mills (P.) Ltd., before contesting the elections. It is submitted that this statement of mine is correct only in respect of the Directorship in the Himalaya Paper (Machinery) Private Ltd., as I ceased to be its Managing Director with effect from the 10th January, 1967. However, it is regretted that due to inadvertence the Directorship in the Himalaya Paper and Board Mills (P.) Ltd., was also mentioned in the statement made by me on 23-4-1968.

Re. (ii) Regarding my Directorship in the Card-Board Printing and Processing Industries Ltd., Calcutta, I had already clarified that I ceased to be a Director of the Company with effect only from 1st September, 1967, though my association with this Company ceased after 1st February, 1967. In that connection, I produced a true copy of the letter dated 7th February, 1969. This letter speaks for itself. What has been stated by the Hon'ble Member is mostly a reproduction of what is already stated in the letter dated the 7th February, 1969. So far as this is concerned, there appears to be no need for any further clarification.

In the circumstances, it is submitted the allegation made against me that I tried to mislead the House by making false statements deliberately is entirely without substance.

SHRI RANGA (Srikakulam) : He has expressed his regret. It is for the House or the Speaker to see whether the

[Shrf Rango]

regret is satisfactory or not and whether it can be accepted.

MR. SPEAKER : If there is any further inaccuracy, any hon. member can bring it to my notice.

Now, we will take up the demands of the information and Broadcasting Ministry.

#### DEMANDS\* FOR GRANTS *Conid.*

#### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): 3 hours have been allotted for this. The Minister of Information and Broadcasting is also in charge of Communications. We think the demands of the Department of Communications may not be discussed at all and may be guillotined. Therefore, I request that the members may be permitted to raise certain points regarding communications also during the debate and the minister may be asked to reply to those points. The time allotted may also be increased.

MR. SPEAKER : Yesterday in the Business Advisory Committee, nobody suggested it. Otherwise, I would have discussed it with other party leaders also. There is also another point. Nobody has given any cut motion to the Demands of the Communications Department. Therefore, it will not be proper for me to say offhand that it will also be included.

The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 62 to 64 and 122 relating to the Ministry of Information and Broadcasting for which 3 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. They will be treated as moved if they are otherwise admissible.

#### DEMAND NO. 62—MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

MR. SPEAKER : Motion moved :

That a sum not exceeding Rs. 19,82,000 be granted to the President TO COMPLETE THE SUM NECESSARY TO DEFRAY the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970, in respect of 'Ministry of Information and Broadcasting'."

#### DEMAND NO. 93—BROADCASTING

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 9,93,82,000 be granted to the President To complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970, in respect of 'Broadcasting'."

#### DEMAND NO. 64—OTHER REVENUE EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

MR. SPEAKER : Motion moved.

"That a sum not exceeding Rs. 5,39,81,000 be granted to the President To complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Information and Broadcasting'."

#### DEMAND NO. 122—CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

MR. SPEAKER : Motion moved.

"That a sum not exceeding Rs. 4,31,70,000 be granted to the President To complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1970, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Information and Broadcasting'."

3 hours have been allotted for this

\*Moved with the recommendation of the Presidents.

ministry. We have got 2½ hours day—half an hour in the forenoon and 2 hours after lunch from 2 to 4 p. m. These 2½ hours are available for members to speak. At 4 p. m. private members, business will start. The half an hour which remains will be taken by the Minister for his reply on Monday. On Monday, no more speeches will be allowed.

श्री प्रेम चन्द्र वर्मा (हमीरपुर) :  
मिनिस्ट्री आफ इन्फारमेशन एण्ड ब्राड-  
कास्टिंग की बढ़ी इम्पोर्टेन्ट मिनिस्ट्री है।  
इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका टाइम  
थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए।

MR. SPEAKER : It cannot be done.  
Now, Mr. Imam.

SHRI J. MOHAMED IMAM  
(Chitradurga) : Sir, the Ministry of  
Information and Broadcasting plays an  
important role in the national integration  
of the country and also in ensuring the  
safety and integrity of the country. It  
is a very powerful means of communi-  
cation for dissemination of information  
and news and also for educating the  
public.

Sir, the Ministry of Information and  
Broadcasting mainly deals with three  
modes of communication. They are :  
broadcasting, newspaper and films. Broad-  
casting is the most important one. But  
at present our broadcasting is confined  
only to sound broadcasting. Television  
broadcasting is still in its infancy and it  
is confined only to Delhi and its suburbs.  
On the other hand, mere sound broad-  
casting is supposed to be archaic and out  
of date. So to come to the level of other  
countries the Ministry should take care  
to see that there is a powerful set up of  
television.

This Ministry, no doubt, has been  
trying to disseminate information to a  
certain extent and also in educating the  
youth of the country. But I must bring to  
its notice that there is a growing feeling  
among the public that this Ministry is  
being taken advantage of by some Com-  
munist countries to spread their own

doctrine and their own ideas in this  
country. They have been taking advan-  
tage of the softness of the Government  
of India.

12.27 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I may substantiate my point with  
some events that have happened in this  
country. Perhaps the Minister remembers  
and recalls to his mind the commotion  
that was created in this House when the  
question of the agreement entered into  
with Novosty by the Government was  
raised in this House. There were a series  
of questions and the Minister was asked  
to declare and elucidate under what prin-  
ciple he entered into this agreement with  
Russia. It was said that it was on an  
understanding that Indian literature  
should be circulated in Russia and Russian  
literature should be circulated in India. I  
would like to know how much of Indian  
literature has been circulated in Russia  
and with what advantage, what effect has it  
got, to what extent has Indian life and  
Indian way of living been reflected in  
Russia and what effect it has on the  
Russian people. All these were uncalled  
for. But, on the other hand, I must say  
that Russia has taken full advantage of  
the opportunity that has been given to it.  
Every Member of this House will agree  
with me when I say that the entire coun-  
try is flooded with Russian literature.  
They are circulated in every nook and  
corner of the country, in the villages and  
in all languages. They are circulated in  
the form of magazines, booklets, pamph-  
lets and so on. We have given them the  
best occasion to impose their own ideol-  
ogy, to impose their own formulas on  
our people. This has been going on  
unhampered, unbridled, unchecked and  
unscrutinised. Hundreds of copies of  
literature are brought in by Russians.  
Has the Home Ministry or the Law Mi-  
nistry cared to scrutinise them before  
they are published here ? They are full of  
Russian ideologies. I am sorry the Gov-  
ernment has not realised the danger of  
such widespread Russian literature in this  
country, unless they want that Com-  
munism should come into this country.

I may give you another instance  
where this Government is almost a party



[Shri J. Mohamed Imam]

to this kind of Communist propaganda. There is a society called the Films Division Society. It has entered into an agreement with Russia to produce a film called Black Mountain depicting that India is a land of elephants, that India is a land of tigers, that India is a land of Maharajas and so on.

It also contains many events, many views which are not complimentary to Indian life and this is being done with Russian collaboration. Shooting will be done partly in India and partly in Russia and the director will be a Russian. What was the object of entering into an agreement and preparing a film for the sake of children on Russian lines with Russian collaboration? I am sure, the Russians will not be interested in such a venture unless it helps them to spread their doctrine. Lenin once said: catch hold of the mind of the children; they will become good permanent Communists. That is what is happening. This film is being shown in India and other countries. I know what kind of impression this film will give to the minds of people of other countries. When the children see this film it will create a permanent impression in their mind which cannot be effaced. Is this not an attempt that is being made by the Russians through the Government of India to spread communism?

I will give another example where the Government of India is actively encouraging communistic propaganda. Recently there was a talk in "Spotlight" of All India Radio by one Shri C. R. Das, who is an avowed Communist. I do not think the Home Minister has seen the script of that talk. I have it with me and, if so desired, I can lay it on the Table. In that talk there is nothing but wholesale condemnation of the Central Government for their attitude towards the Bengal Government. It extols the Bengal Government, supports the *Bandh* movement and holds the Government of India responsible for all the ugly developments that have taken place there.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : If they do not mind it, why do you mind it?

SHRI J. MOHAMED IMAM : It is a wholesale condemnation of the Central Government. He has held the Home Minister entirely responsible for all these happenings. Why was such speech, which is not only pro-Communist but also anti-Indian and anti-government propaganda, allowed to be broadcast through the All India Radio? Since under the rules every script is scrutinised before broadcast it is clear that the All India Radio is actively helping the Communist philosophy.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : Should it help only the Swatantra Government.

SHRI J. MOHAMED IMAM : No. I did not say that. But I can assure you that the country is safe in the hands of the Swatantra Party but not in those of the Communist Party.

I do not know how such things can happen. The Central Government may think that it is chummy with Russia, they are great friends in spite of the fact that Russia is helping Pakistan with arms. The same thing happened to the friendship with China. You must understand the mentality of these people of the Communist countries. They are more loyal to their ideology than to their own country; they place the communist movement or ideology above the country. They condemn imperialist countries. But we must beware of the dangers of communist imperialism which is spreading its sphere of influence. It is attended with grave consequences and danger to the adjoining and neighbouring developing countries.

SHRI J. B. KRIPALANI : If it comes to that, the Ministers will join that party.

SHRI J. MOHAMED IMAM : The Government of India must realise that a grave situation has developed in one part of our country which is under communist domination. Communists owe allegiance more to their organisation and party than to the country. On account of your negligence and indifference it is not unlikely that a time may come when

a Communist bloc may be built under the suzerainty of China. This is not the first time that an attempt is being made in that direction.

What about Russia? It has become an imperialistic country. The whole of Eastern Europe has become the satellite of Russia.

It is because of their Communist imperialistic policy. 14 capitals have been wiped out and now they are satellites and dependencies. If they want to come back and adopt the democratic way of living, they are not allowed to do so. The same thing will happen here and we must take care. The Government should not flirt with the country which pretends to be a friend and under the guise of friendship which wants to spread its own doctrine here.

I now come to broadcasting by All India Radio. It is true that All India Radio has been doing good work. Its effect is being felt throughout but one or two things must be said about it for which I have been fighting. All India Radio is now entirely 'Owned by the Government' means owned by the ruling party and run by them. It must be quite impartial and just to every section of the people and to every party. This cannot be secured unless it is converted into a corporation. In fact, there has been a demand in this House that All India Radio must be converted into a corporation. The Chanda Committee has also recommended that it should be converted into a corporation. This demand is unanimous. There are ever so many recommendations in order to make it independent as AIR should be and as it is in England and other countries. In England the entire system is run by the British Broadcasting Corporation. But the Government still want to have their grip on the AIR. The reason is that the Government wants to impose its own policy on the people through the AIR. The All India Radio must be run on such lines that every party, every institution, every religion, every section will have confidence.

At present it may do harm or good. I will mention two or three instances to show how they can spoil the integrity of

this country; for example, the sudden switch-over of the timing of the news broadcast, advancing the Hindi news from 8.15 to 8 o'clock in the morning. From time immemorial the English news was broadcast at 8 A. M. and the Hindi news at 8.15. Why was that suddenly advanced to 8 A. M. and the English news transferred to the new timing? What was the advantage? What are the reasons? Are there any administrative difficulties, except that they wanted to give preference to Hindi?

SHRI S. XAVIER (Tirunelveli): The Madras Government has addressed the Central Government to change the timing to what it was originally and the Central Government has kept quiet so far. Let them change the timing.

SHRI J. MOHAMED IMAM: It created so much of unnecessary commotion and bitterness. Why did you do it? When you do a certain thing, when you aim at a certain policy, it must bring in some substantial results or benefit. What results or benefit did this bring, except it be to undermine the confidence of the people in the South, that the Central Government is only anxious to propagate Hindi, to promote and encourage Hindi?

Again, you must be impartial regarding the languages. All India Radio deals mostly with Hindi. That is the complaint. You must be judicious regarding other languages also.

Then, they must treat the employees of the All India Radio in the same way as they do other Central Government employees.

Regarding newspapers, our newspapers are really good ones; some of them can help a lot. They have been responsible in spreading culture and education throughout the country and for enlightening the public. The newspaper reading public, since independence, has gone up ten times. That means that there is greater responsibility on the papers and they must be fair to all these people.

Only one thing more. In these days, when the minorities are vulnerable, the

[Shri J. Mohamed Imam]

newspapers may spare them and not publish statements which may be prejudicial to them. For example, I read in one newspaper that the Muslims are a national misfortune in the country. That will have a very bad effect on the public. In another newspaper, we read that an elderly Muslim Minister had married a young girl. Such things involve a very vulnerable minority. I think, in the interest of national integrity and other things, such things should not be published. Of course, our newspapers are doing commendable work and, I hope, they will continue to do the same.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Nar Deo Snatak.

श्री प्रकाशबीर शास्त्री (हापुड़) :

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि इसके लिए केवल ठाई घंटे का समय है, इसलिए समय ऐसा रखें ताकि सबको अकोमोडेट किया जा सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are perfectly right. I would request Members on this side to take 5 to 7 minutes each. We have only about 3 hours. The Minister of State is also intervening. That time also will be debited to this side. So, only 5 to 7 minutes each.

श्री नरदेव स्नातक (हायरस) :

उपाध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना यह है कि इस वक्त देश में तीन बातों को बहुत बड़ी आजादी मिल गई है—पैन, प्लेटफार्म, और पेपर। आप जो चाहें पैन से लिख दें, चाहे जो आप प्लेटफार्म पर कह दें और जो चाहें आप अखबारों में लिख दें। इस प्रकार की इनको आजादी हमारे देश में है। परन्तु दुर्भाग्य है कि इसका परिणाम बहुत भयंकर निकलता है। मेरा आपसे निवेदन है, खासतौर से मंत्री महोदय से है, कि वह कम से कम इन तीनों चीजों के ऊपर कुछ न कुछ नियंत्रण रखें।

सबसे पहले तो मैं आपकी, जो आज-कल हमारे देश में फिल्में चल रही हैं, उनके बारे में बतलाना चाहता हूँ। सिनेमा शायद सबसे ज्यादा हमारे देश में हैं और इस सिनेमा के कारण जो हमारा चरित्र है, जो हमारा आचार-विचार है और जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसे आघात पहुँचा है, उसका दिन-प्रति-दिन प्रभाव हर एक व्यक्ति को मानूम पड़ता है। खास करके विदेशी फिल्में व अंग्रेजी फिल्में जो हमारे देश में आती हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार की फिल्में जो बदमाशी, चोरी, डकैती और भ्रष्ट कामों को सिखाती हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए। कहते हैं कि आप बच्चों को शिक्षित करते हैं, उनमें उत्साह पैदा करते हैं। पर उसका परिणाम यह होता है कि आये दिन हमारे स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले बच्चे इन्हीं चीजों को पढ़ते और देखते रहते हैं। मुझे मंत्री महोदय से निवेदन करना है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना है कि वह कम से कम इन सिनेमाओं के ऊपर अपना नियंत्रण रखें और खास करके यानी जिस दिन छुट्टी होती है, अवकाश होता है, उस दिन सारे सिनेमा चलते रहते हैं, इन सिनेमाओं को नहीं चलना चाहिए। उसका परिणाम यह है कि हमारे बच्चे आये दिन जो स्कूलों और कालेजों में पढ़ते हैं वे स्कूलों में हाजिरी देकर सिनेमाओं में चले जाते हैं या कभी हाजिरी भी नहीं करते और टिकट लेकर सिनेमाओं में बैठे रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम सिनेमा का जो समय है वह 4 बजे सायंकाल से रखिये। 12 घण्टे चलते रहते हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए और खास करके उन बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ने वाले हैं 4 बजे से पहले टिकट नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नियंत्रण होगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश का चरित्र और हमारे देश के बच्चे

ऊँचे उठेंगे। आज़ादी मिले हमें 20-22 साल हो गये, परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उस आज़ादी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, उसके भलावा आप देखते हैं, कि हम अंग्रेज़ों एवं अंग्रेज़ी के भक्त बनते जा रहे हैं। यह ठीक है कि सिनेमा द्वारा हिन्दी का प्रचार और प्रसार हुआ, परन्तु दुर्भाग्य यह है कि पहले कलाकारों के नाम अंग्रेज़ी में आ जाते हैं, देखने वाले चाहे वे गांव के हों या शहर के हों परन्तु उनके नाम पहले अंग्रेज़ी में आते हैं तो यह भी होना चाहिए कि जो फिल्में हिन्दी में हैं, उनके एक्टर्स का, कलाकारों का नाम हिन्दी में ही होना चाहिये। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम यह अंकुश तो उन पर होना ही चाहिए।

दूसरी बात मैं रेडियो के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। यह ठीक है कि हिन्दी के सम्बन्ध में रेडियो ने प्रचार और प्रसार किया है और वे साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में प्रगति की। परन्तु कुछ चीजें देखने में आती हैं जिनसे लगता है कि हिन्दी के साथ उनका काफी एक तरह से विरोध है। हमारे जो विशिष्ट व्यक्ति विदेशों में जाते हैं जैसे हमारे प्रधान मंत्री और राष्ट्र-पति विदेशों में जाते हैं, तो उनके साथ जो न्यूज़रील वाले, न्यूज़ देने वाले जाते हैं, वे जितने लोग जाते हैं वे सब अंग्रेज़ी वाले ही जाते हैं, हिन्दी वाला कोई नहीं जाता है। जितने भी समाचार होते हैं सब अंग्रेज़ी में होते हैं और उनका अंग्रेज़ी में ही प्रसारण किया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब विशिष्ट व्यक्ति विदेशों में जाते हैं—जैसे प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे मंत्री या सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री सिन्हा साहब जायें—तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ अंग्रेज़ी के भलावा हिन्दी के न्यूज़ वाले भी जायें। हमारे विशिष्ट व्यक्तियों के साथ

कम से कम हमारे जो न्यूज़ वाले हों, वे समाचार हिन्दी में दें जिससे देश के लोग उनको देख सकें और सुन सकें।

तीसरी बात यह है कि हमने यह देखा है कि रेडियो से अंग्रेज़ी में शिक्षा दी जाती है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 20-22 वर्ष हो गये हमारे देश को आज़ाद हुए, परन्तु प्रांतीय भाषाओं में शिक्षा नहीं दी जाती है। बी० बी० सी० लन्दन के माध्यम से हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी सिखायी जाती है। कितनी दुःख की बात है कि 20 वर्ष के बाद भी हम अंग्रेज़ी के गुलाम बने रहे और अंग्रेज़ियत हमारे अन्दर घुस गई। स्वाभाविक है कि यह मालूम पड़ता है कि यह देश आज़ाद होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों के अन्दर है। मेरा निवेदन यह है कि किसी भाषा को सिखाने की बात है तो कम से कम जो अन्य प्रांतीय भाषाएँ हैं उनको सिखाने के लिए प्रयत्न करें, हम लोग भी पढ़ें और बच्चों को भी उसका ज्ञान हो। लेकिन क्या हो रहा है कि बी० बी० सी० लन्दन के द्वारा अंग्रेज़ी का प्रचार हो रहा है। हिन्दी के लिए यदि कभी कहा जाता है तो उसके लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम उन भाषाओं को जो कि प्रांतीय भाषाएँ हैं उनको सिखाने के लिए यदि आप प्रयत्न करें तो बहुत अच्छा है अंग्रेज़ी के सिखाने को आप छोड़ दें।

एक अन्य बात मैं आपसे यह कहता हूँ कि बृज मण्डल जो करीब 3½ करोड़ की पापुलेशन वाला प्रदेश है बृज मण्डल में एक रेडियो स्टेशन है जो मथुरा में खुला है। उसकी इतनी कम पावर है वह एक यूनिट का है कि मथुरा शहर के व्यक्ति भी उसे अच्छी तरह से नहीं सुन सकते। बृज मण्डल में आगरा डिवीजन के जिले हैं, हरयाणा, और गुड़गाँव तथा दिल्ली आदि भी यह कवर करता है। साढ़े तीन करोड़ की

[श्री नरदेव स्नातक]

आबादी के लिए जो वहां पर रेडियो स्टेशन लगाया गया वह इतनी कम पावर का है कि उसे मथुरा शहर के लोग भी नहीं सुन सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि या तो उसे बन्द कर दिया जाये या अगर आप चाहते हैं कि वह कुछ काम करे तो उसे इतनी पावर का बनाइये कि वह 3-4 करोड़ की सारी पापुलेशन को कवर कर सके।

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ और वह यह है कि यह ठीक है कि रेडियो से हम प्रांतीय भाषाओं के गीत सुनते हैं। पर वेद-मंत्रों का पाठ रेडियो से नहीं होता है। वेद-मंत्रों का पाठ कम से कम प्रातःकाल हमारे हिन्दुस्तान की जनता को सुनने को मिले क्योंकि धर्म-प्रधान इस देश को माना जाता है और इसकी संस्कृति धर्म की है। वेद-मंत्रों का प्रातःकाल सस्वर पाठ हो और उसका कुछ अर्थ लोगों को बताया जाए। तीन मंत्रियों की आपस में वार्ता हो रही है और मंत्री महोदय मेरा निवेदन नहीं सुन रहे हैं।

मेरा आप से निवेदन है कि रेडियो से कम से कम वेद मंत्रों को प्रातः काल अवश्य, अवश्य सुनवाया जाय। यद्यपि और समय आप बोलने के लिए दे नहीं रहे हैं इसलिए मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदलों का समर्थन करता हूँ।

**श्री भारत सिंह चौहान (धार) :** उपाध्यक्ष महोदय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांगों का मैं विरोध करता हूँ क्योंकि इस विभाग ने देश की जनता के लिये, जो इस के अन्तर्गत काम सँपि गये हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। इस के अन्तर्गत आल इंडिया रेडियो, फिल्म डिबीजन, सॉण एंड ड्रामा डिबीजन और प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो, संचालित होते हैं

परन्तु मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि मंत्रालय का प्रशासन बिलकुल ही असन्तोषजनक है। इस मंत्रालय में भ्रष्टाचार, पक्षपात, नियुक्तियों में, पदोन्नतियों में और स्थानान्तरों में होते हैं। शासन ने चन्दा कमेटी स्थापित की थी परन्तु उन सिफारिशों पर अभी तक भ्रमल नहीं किया गया। उन सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि आल इंडिया रेडियो और टेलीविजन को एक पृथक भोटोमोशन कारपोरेशन बनाया जाय। परन्तु उस सुझाव को अभी तक भ्रमल में नहीं लाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कांग्रेस शासन आल इंडिया रेडियो से अपना प्रभुत्व हटाना नहीं चाहता। इन गत बीस वर्षों के कांग्रेस शासन ने सूचना तथा प्रसारण को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में लाने का कभी प्रयत्न नहीं किया इस से देश की जनता को निष्पक्ष समाचार तथा ज्ञान नहीं मिल पा रहा है।

वर्तमान समय में जबकि देश के कई राज्य भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों द्वारा शासित हैं, ऐसी परिस्थिति में आल इंडिया रेडियो का नियंत्रण एक राजनैतिक दल के नियंत्रण में रहे, यह उचित नहीं कहा जा सकता और इस को शीघ्र ही कारपोरेशन में परिवर्तित किया जाना चाहिये। आज आल इंडिया रेडियो विशेषतः कांग्रेस की नीतियों का प्रचार का साधन बना हुआ है क्योंकि केन्द्र में कांग्रेस का शासन है। मिसाल के तौर पर इस मध्यावधि चुनाव के समय आल इंडिया रेडियो ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया जबकि रेडियो का खर्च जनता के पैसे से चलता है।

उन्नतिशील तथा प्रजातांत्रिक देशों में रेडियो तथा टेलीविजन एक प्रथक भोटोमोशन कारपोरेशन है जिसका शासन के

नियंत्रण से सम्बन्ध नहीं होता है। पी० आई० बी० देश की विज्ञान, कला, शिक्षा, कृषि क्षेत्रों में जो वास्तविक स्थिति है जनता को बताने में बिलकुल असफल रही है। मिसाल के तौर पर कृषि जैसा महत्वपूर्ण विषय जिस पर संसद में उस की मांग को लेकर जब डिबेट हो रही थी तो उस का संसद समीक्षा में जिक्र तक नहीं किया। यह एक बहुत ही शोचनीय बात है। यह मंत्रालय एक व्यवस्थित और प्रभावशाली प्रैस बनाने में असफल रहा है। सरकार बड़े बड़े अखबारों को ही विज्ञापन आदि देती है और छोटे छोटे अखबारों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता कि कलाकारों की इस प्रकार की कान्ट्रैक्ट नियुक्तियों में मंत्रालयों के आफिसरों के मित्र आदि को रोजगार दिलाने के ही लिए यह सब कुछ किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, पक्षपात की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि एकता परिषद की बैठक में जो जून 1968 में हुई थी उस में विरोधी नेताओं के भाषणों का भ्राल इंडिया रेडियो ने कोई जिक्र नहीं किया केवल कांग्रेस के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के ही भाषण प्रसारित किये गये। अभी हाल में ग्वालियर नगर निगम के चुनाव में जब जनसंघ की जीत हुई तो भ्राल इंडिया ने उस का जिक्र नहीं किया परन्तु अहमदाबाद नगर निगम में जब कांग्रेस की जीत हुई तो भ्राल इंडिया रेडियो से ऐसा प्रतीत होता था कि समाचार कांग्रेस के दफ्तर से ही प्रसारित हो रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि निष्पक्ष रूप से तमाम सूचनाएँ प्रसारित की जायें। हमारे सारे कार्यक्रमों का आभार भारतीय संस्कृति और चरित्र निर्माण होना चाहिये। हमें ऐसे शक्तिशाली ट्रान्समीटर लगवाने चाहिए जोकि भिन्न देशों में हमारे स्वरूप को प्रभावी ढंग

से प्रचार कर सकें। इस मंत्रालय ने हमारी राष्ट्रीय भाषा के प्रचार तथा प्रसार के लिये भी उचित कदम नहीं उठाये। यह देश अन्तर्देशीय संस्कृति से परिपूर्ण है। इन संस्कृतियों का समन्वय करने में भी असफल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस विभाग के उस मांग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसके द्वारा भारत की नवपीढ़ी का निर्माण करने का दावा किया जाता है और वह विभाग है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन फिल्मस बनाई जाती हैं उस के बारे में मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। फिल्मों का प्रभाव आज के नवयुवक-नवयुवतियों व बच्चों पर अत्यन्त अधिक पड़ रहा है। आज के युग को फिल्म युग कहा जाये तो अतिशयोक्ति न होगी।

आज के बच्चे सम्राट अशोक के बारे में इतना नहीं जानते जितना ऐक्टर अशोक कुमार के बारे में जानते हैं। स्कूलों व कालेजों के लड़के, दिलीप कुमार, राजकपूर की नकल व लड़कियाँ सायराबानू व वहीदा रहमान की नकल करती हैं। वैसे ही हाव-भाव, वैसे ही बातचीत, वैसे ही पहनावा, यहाँ तक कि उन की सोचने की शक्ति पर भी फिल्मों का असर पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य जो देखता है उस का असर उसके मस्तिष्क पर 83 परसेंट के लगभग होता है।

मुझे दुःख है कि सरकार का ध्यान अभी तक सही रूप से फिल्मों की ओर नहीं है जबकि और देशों में बच्चों व नवयुवकों के लिए अच्छी-अच्छी शिक्षाप्रद फिल्में तैयार होती हैं जोकि सहायता करती हैं उन के अच्छे नागरिक बनने में।

13 hrs.

मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान एक खास व महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्रित

[श्री भारत सिंह चौहान]

करना चाहूंगा। विदेशों में ऐसी फिल्में बनती हैं जिनसे बच्चों में उन के देश व संस्कृति के प्रति गौरव जागे। पर हमारे यहां बाल चित्र समिति बनाती है—“जैसे को तैसा” जिसमें बदले की भावना को जगाया है “जवाब धायेगा” जिसमें दो बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के सम्बन्ध लेला मजनु जैसे दिखाये गये हैं। और अभी अभी एक फिल्म बन रही है नाम है—ब्लैक माउन्टेन। यह “ब्लैक माउन्टेन” एक बड़ा सा पर्वत के आकार जैसा काला घन्वा है देश के उज्ज्वल मुख पर। यह चांटा मारा गया है हमारी संस्कृति पर। यह थूका गया है हमारे गौरव पर। यह कहानी है एक हाथी की, पर इसकी झाड़ में बतलाया गया है कि भारत में राजा महाराजा, हाथी व शेर ही हैं। पचास करोड़ देशवासियों की गरदन नाली में डाल दी गई है। धरबों रुपये की सरकारी पंच-वर्षीय योजनाओं के बाद भी हमारे देश का यह रूप और देशों के बच्चों को जब दिखाया जाएगा तो क्या सोचेंगे वहां के लोग? वे कहेंगे यह ही है गांधी और नेहरू का मुल्क, इसी देश के लिए हमारे वित्त मंत्री करोड़ों रुपयों की सहायता लेने बाहर के देशों में जाते हैं। भयंकर बात तो यह है कि यह फिल्म बना रही है बाल-चित्र समिति जिसे देश की जनता से ही धन मिलता है। मसल है “मियां की झूती मियां के सर”। रूस के नामी डायरेक्टर के साथ मिलकर बाल-चित्र समिति ने यह जाल पिरोया है। आश्चर्य की बात है कि जब भी कोई फिल्म विदेश की सहायता से बनती है तो उस फिल्म की कहानी, संवाद, पट-कथा शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी देखते हैं, विचार करते हैं। संसद् के कुछ सदस्यों की भी राय ली जाती है। तब कहीं उस फिल्म को बनाने की अनुमति मिलती है। “ब्लैक माउन्टेन” बनाने की अनुमति देने में सूचना व प्रसारण

मन्त्रालय के अधिकारियों ने किसी से कुछ नहीं पूछा।

हमें जरूरत है उन फिल्मों की जो हमारे भावी देशवासियों को प्रेरणा दे सकें, उन का मनोरंजन कर सकें। पंडित हृदयनाथ कुंजरू व श्री दिवाकर की अघ्यक्षता में बाल-चित्र समिति ने अच्छी, देश-भक्ति की और भावनामय फिल्में बनाईं। बनाने वाले थे उस समय के सेक्रेट्री श्री महनेन्द्रनाथ। उन की देखरेख में “जलद्वीप” फिल्म बनी जिसे वेनिस में सर्वोत्तम बाल-चित्र का अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। “एकता” फिल्म में कौमी एकता का जिक्र है, “गुलाब का फूल” में सम्राट अकबर के बचपन की कहानी है, “ईद मुबारक” में एक बच्चे की अपनी नानी के लिए अपने खिलौने के त्याग की कहानी है, “राणा प्रताप” से सम्बन्धित “चेतक”, “मीराबाई”, “तुलसीदास” व “सम्राट अशोक” के बारे में फिल्में हैं। “दो टिकटों की कहानी” एक फिल्म थी “दिल्ली की कहानी”, जिस में खुद भूतपूर्व राष्ट्र-पति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने अभिनय किया था। “गुरु-भक्ति” में विद्यार्थी व शिक्षक के सही सम्बन्ध दिखाये गए थे। ऐसी शिक्षा-प्रद और सही फिल्में बनाई गई थीं। लेकिन 1962 से ही बाल-चित्रों का स्तर गिरता चला गया।

हमें जरूरत है उन फिल्मों की जो हमारे देशवासियों को प्रेरणा दे सकें, उन का मनोरंजन कर सकें। सिर्फ थोथी हंसी व शोर-गुल से तो देश प्रागे बढ़ेगा नहीं। फिल्मस डिवीजन ने लाला लाजपतराय के बारे में फिल्म बनाई। श्री सुब्रह्मण्य भारती, श्री भरविन्द घोष, देश के अन्य कितने ही शहीद हैं, यदि उनके बारे में फिल्में बनें तो बच्चों के और बड़ों के मन में देशभक्ति की भावना उजागर होगी और यह तोड़-फोड़ व हिंसा, जो हम देख रहे हैं, कम होगी। हमें ऐसी फिल्में बनवानी चाहिएं जिन्हें देखकर दर्शकों के मन में देश के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हो।

मुझे पूर्ण आशा है कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय के नए मंत्री श्री सत्य नारायण सिंह व उनके राज्य मंत्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल, अपना ध्यान इस ओर देंगे और एक कमेटी बनाएंगे जिसमें संसद् के कुछ सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक व फिल्म के कुछ लोग हों। यह कमेटी इस ढाढा की जांच करे कि कैसी फिल्में जनता के सामने लाई जायें जिनसे उनका मनोरंजन भी हो सके और जो देश के लिए हितकर हों तथा किस प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता है इस तरह की फिल्में बनाने के लिये।

अगर इस बारे में तवज्जह न दी गई तो देश का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा और हम कहेंगे कि :

इस घर को भ्रम लग गई,  
घर के चिराग से।

13.05 hrs.

*The Lok Sabha adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.*

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock.*

[SHRI THIRUMALA RAO in the Chair]

DEMANDS FOR GRANTS. *Cotd.*  
MINISTRY OF INFORMATION  
AND BROADCASTING *Contd.*

श्री तुलसीदास जाधव (बारामती) : सभापति महोदय, इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ऊपर जो बहस चल रही है, उसकी बाबत मैं थोड़े से अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। सब से पहली बात तो यह है कि रेडियो पर जो भाषण होते हैं, या दूसरे प्रोग्राम होते हैं, उन में ज्यादा से ज्यादा इस बात पर जोर देने की गंज है कि इस देश में जो दंगे फिसाद हो रहे हैं, जाति-जाति में वैमनस्य बढ़ रहा है और रिजनलिज्म बढ़ रहा

है, यह कम हो और इसको कम करने की दृष्टि से खास प्रोग्राम रखे जायें। आकाश-बाणी का जो पत्रक होता है उसको देखने से मालूम होता है कि लोगों को ऐन्टरटेन करने के लिये गानों की ज्यादा-से-ज्यादा सङ्कलित दी गई है। उनको कम किया जा सकता है और देश के भले के लिए देश को मजबूत बनाने के लिए जो आज की जरूरत है, ऐसी चीजों के लिए रेडियो पर ज्यादा वक्त देने की गंज है।

श्री स० मों० बनर्जी० (कानपुर) : लोग रेडियो बन्द कर देंगे।

श्री तुलसीदास जाधव : यह ठीक है कि आज के युग में जवान लड़के और लड़कियों का ध्यान ऐसी चीजों की तरफ जाता है, फिल्मी गानों की तरफ जाता है। उन्हीं गानों को वे घरों में भी गाते हैं और उन्हीं को सुनना भी चाहते हैं। उन गानों के साथ : साथ लोगों को यह जो बात मैंने बताई है, इसको भी पिलाने की जरूरत है। मां जिस तरह अपने बच्चे को थोड़ा हंसाकर और थोड़ा ऐन्टरटेनमेंट दे कर दूध पिलाती है उसी तरह से आपको गानों के तथा दूसरे ऐन्टरटेनमेंट के प्रोग्राम देने के साथ-साथ लोगों के अन्दर, इसको भी देखना चाहिए कि जाति-जाति में वैमनस्य जो फैल रहा है, उस पर रोक लगे, रिजनलिज्म न फैले ताकि देश की ताकत बढ़े, देश मजबूत हो। देश कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्ज को हाथ में लेने की तरफ, कंस्ट्रक्टिव मनोवृत्ति की तरफ बढ़े, इसको ध्यान में रख कर आपको प्रोग्राम ज्यादा बनाने चाहिए। मैं जहाँ तक देखता हूँ तो इसकी तरफ ख्याल कम है। जैसा एक भाई ने अभी कहा, श्री बैंजर्जी ने कि वह रेडियो फिर बन्द हो जाएँगे, बात तो सही है, आजकल जैसे पाकिस्तान के गाने सुनने में लोग ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं जिन को सीलोन का गाना कहते हैं। तो एक तो स्कूल में या बाहर आज के बच्चों को एक



[श्री तुलशी दास जाधव]

भ्रमण शिक्षा देने की गरज है। लेकिन वह तो एजुकेशन डिपार्टमेंट करता रहेगा। मगर यह रेडियो और इनफार्मेशन एण्ड ब्राड-कास्टिंग डिपार्टमेंट जो है इस में सिनेमा है, फिल्में हैं इन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दी जाय। कभी भ्राप देखें, धूप हो या बरसात हो, इतना बड़ा क्यू लगता है सिनेमा का टिकट लेने के लिए, इस के माने यह है कि जैसे स्टेशन पर कोई होटल रहता है या स्टाल रहता है तो जैसे गाड़ी से बाहर उतरे तो भ्रट चाय पी लेते हैं ऐसे ही इतना या इससे भी ज्यादा भ्राज लोगों को फिल्म भ्राकर्षण है। तो एसी हालत में उस फिल्म की तरफ से इस रीति से प्रचार हो कि जिससे जो चीज यहां पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बन्दोबस्त करने और उस की तरफ खर्च करने की जरूरत होती है वह कम हो जाय और लोगों के भ्रन्दर एक नई दृष्टि भ्रपने देश के लिए भ्रा जाए।

दूसरी बात यह है कि मुझे सिनेमा का कोई नाम नहीं मालूम लेकिन यह जमीन, यह धरती हमारी माता है, ऐसी एक फिल्म हमने बनी देखी थी। उस का बड़ा भ्रच्छ्रा भ्रसर लोगों पर होता है तो इस तरह की फिल्में बना कर इस रीति से लोगों के भ्रन्दर देश के प्रति प्रेम पैदा हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए।

एक बात भ्राजकल हो रही है कि पहले तो लोग मन्दिरों में जाते थे और कुछ पोथी पुराण सुनकर भ्राते थे, उससे कुछ भ्रच्छ्रे विचार उन्हें मिल जाते थे, लड़के और लड़कियां मां-बाप के विचार से सहमत होते थे वह जैसे कहें वैसे चलते थे। उस वक्त गुरुजी जो टीचर हैं, उनका भी कुछ भ्रादर रख कर चलते थे। लेकिन भ्राजकल सभी जगह पर इस भ्रादर्श को ठुकरा कर भ्राज के जवान भ्रलग रास्ते से जा रहे हैं। उनको रास्ते पर लाने के लिए फिल्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, यह मेरी

एक विनती है। दूसरे, इस वर्ष तो गांधीजी का शताब्दी वर्ष है, तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा, मैंने जो कहा इस रीति से फिल्म का उपयोग करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि खासतौर से गवर्नमेंट चाहे तो जो फिल्म निकालने वाली कम्पनियां हैं उससे भ्रस्पृश्यता के बारे में नये-नये तरीके से फिल्म निकालने की गरज से बात कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में हरिजनों की भ्रांपड़ियां जलाईं, लोगों को मारा पीटा। इसी तरह से भ्रान्ध में भी हुआ कि लड़के को जलाया। वैसे ही यू० पी० में भी एक भ्रातर थी, उसके दो बच्चे थे, उससे वह दोनों बच्चे लेकर के कुएं में डाल दिए। ऐसे ही महाराष्ट्र में उनकी नंगी भ्रातरों को हरिजनों के गांव में से धुमाया। तो यह बातें क्यों होती हैं क्योंकि भ्राज लोगों के पास कोई पोलिटिकल पार्टी हो या लीडर हो या मिनिस्टर हो वह जाने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे ज्यादा काम उनके पास हो या दिल में कोई और बातें हों। तो लोगों के पास जाकर एजुकेशन देने की हिन्दुस्तान के भ्रन्दर और इस डेमोक्रेसी में बड़ी जरूरत है और वह कम होती जा रही है। तो मेरी इस दृष्टि से विनती है भ्रपने मिनिस्टर साहब से कि वह ऐसी फिल्में निकालें। मैंने एक फिल्म देखी थी कि एक हरिजन का लड़का कुएं पर जाता है, एकनाथ महाराज उसकी मदद करते हैं और समाज में उसको भ्रपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह भी फिल्म बहुत दिन पहले मैंने देखी थी। भ्राजकल कहीं नजर भी नहीं घ्राती और न कहीं ऐसी फिल्म के बारे में हम सुनते हैं। ऐसे इन्स्टॉसेज जो हैं जो भ्रभी हरिजनों के लिए हुए, तो उसकी खासतौर से पार्टी बनाकर के कि किस-किस रीति से उनके साथ भ्रन्याय होता है और उसका समाज निषेध करता है, उसका तिरस्कार करता है, ऐसा उनको दिखाया जाय तो लोगों के दिल में यह बात भ्राए कि यह चीज बुरी है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो रवीन्द्र सरोवर में कलकत्ता में इंसीडेंट्स हुए, कल के अखबारों में उसकी पूरी हिस्ट्री आई, 40 वर्ष मुझको इस पोलिटीकल काम में हुए, आठ दस वर्ष जेल में रहा, बाहर भी घूमकर आया, लेकिन यह जो इंसीडेंट्स हुए, वह मैंने न कभी सुने न देखे ।

• श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : वहां की गवर्नमेंट को डिस्मिस करो ।

श्री तुलशीदास जाधव : गवर्नमेंट का ज्यादा ताल्लुक इसमें नहीं आता है । यह गवर्नमेंट तो कल आई । 20 वर्ष तक हमारा भी कुछ दोष है इस वक्त किसका दोष है यह मैं नहीं कहता । लेकिन जैसी कि हवा इस वक्त में है कि कोई भी कुछ करे उसके लिए कोई भी रेस्पॉसिबिलिटी किसी की नहीं है, यह एक हवा देश में फैली हुई है (व्यवधान).....वही कहा मैंने कि फिल्म किस रीति से हो जिससे इन बातों का निराकरण किया जा सके । और एक बात है कि जो साधू संत हुए पहले के उनके भी कुछ ऐसे चित्र हों और ऐसी उनकी तरफ से एजुकेशन हो समाज में कि जिस रीति से एक नया जमाना तैयार हो ।

दूसरी बात यह है कि यहां 750 एम० पी० पड़े हुए हैं । यहां राज्य सभा में और लोक सभा में 750 एम० पी० हैं । अभी तक मेरे को मालूम नहीं, कितने एम० पी० कविता करने वाले हैं, कितने स्पीच देने में माहिर हैं, कई संस्कृत में और हिन्दी में अच्छे हैं, तो ऐसे कितने लोगों का इस रेडियो पर कार्यक्रम होता है ? वही कार्यक्रम बार-बार आता है, बार-बार वही पार्टी आती है, मेरी समझ में नहीं आता यह क्यों होता है ? मैं मिनिस्टर साहब से कहता हूँ और सत्यनारायण सिन्हा तो बड़े जानकार आदमी हैं, वह रामायण जानते हैं और कभी बात करते-करते भी दस पांच दोहे बोल देते हैं । इतने होशियार और उनकी स्मृति इतनी

जबर्दस्त है तो इस रीति से यहां के एम० पी० में जो विशेषज्ञ हैं उनका ख्याल रख कर उनके भी कुछ प्रोग्राम करें तो उसमें रेस्पॉसिबिलिटी आ जाती है । उस एम० पी० के अन्दर भी रेस्पॉसिबिलिटी आ जाती है । तो वह भी एक करने की गरज है ।

खेती के प्रोग्राम जो होते हैं नये बीज से, नये-नये तरीके से उत्पादन बढ़ाने के तो वह किसान प्रोग्राम जो होता है उसके अलावा दूसरे प्रोग्रामों में भी यह प्रोग्राम आ जाय, एक मेरा कहना यह है ।

दूसरी बात यह है कि देहात में जो अखबार हैं, डिस्ट्रिक्ट पेपर्स उनके लिए भी इशतहारात देना और उनको संभालना यह काम भी जरूरी है । उनको भी विज्ञापन देना चाहिए और उसके लिए जो पोस्टेज ज्यादा किया है वह भी कम किया जाय । उनके लिए कागज की दिक्कत न हो । इस रीति से छोटे-छोटे पेपर्स को संभालने की जरूरत है ।

दूसरे, जो प्रोग्राम है प्राहीबीशन का उसका भी कुछ प्रोग्राम रेडियो पर हो, फिल्म से हो लेकिन यह आजकल होता ही नहीं है । कोई शराब की बोतल ले तो उससे जो खराबी होती है, घर बरबाद होता है ऐसा कुछ दिखाया जाय जिससे मालूम पड़े कि शराब पीना खराब बात है लेकिन वह भी आजकल होता नहीं है । तो यह चार पांच बातें मैंने कहीं इन पर मिनिस्टर साहब गौर करेंगे ।

आखीरी बात कहकर मैं बैठ जाता हूँ । न्यूज देने में हमारी बहनों का ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि कहीं-कहीं पुरुषों की आवाज इतनी बड़ी होती है कि न्यूज की बातें स्पष्ट रूप से सुनने में नहीं आती हैं । मेरा कहना यह नहीं है कि जहां उनका काम है, वहां उनको काम न मिले, उनको भी काम मिलना चाहिये, लेकिन जिस तरह से टेलीफोन में है, वहां पर आप लड़कियां

(श्री तुलशीदास जाधव)  
रखते हैं, इसलिए उनकी आवाज खुलासा  
आती है, उसी तरह से रेडियो के अन्दर  
उनको ज्यादा से ज्यादा चान्स देना चाहिए।

**श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) :** सदर  
साहब, इस मिनिस्ट्री का काम कितना अहम  
है, इसके बारे में सभी जानते हैं और मैं इस  
के बारे में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इन्फ-  
मेशन और ब्राडकास्टिंग सिर्फ हमारी एज-  
केशनल और कल्चरल एक्टिविटीज का ही  
जरिया नहीं है, बल्कि हमारे नेशनल इन्टी-  
ग्रेशन और पोलिटिकल नजरिये से भी उसकी  
इम्पोर्टेन्स बहुत ज्यादा है। भ्राल इण्डिया  
रेडियो का यह महकमा देश के अन्दर नेशनल  
इन्टीग्रेशन के लिए, कौमी एकता के लिए  
बहुत काम कर सकता है, सेंटर और स्टेट  
के ताल्लुकात को बहुत मजबूत बना सकता  
है और उनको खराब भी कर सकता है।  
मुझे ताज्जुब हुआ कलकत्ता रेडियो स्टेशन  
से एक तकरीर ब्राडकास्ट हुई—मैं चाहूंगा  
कि मिनिस्टर साहब इसको जरा गौर से सुनें  
चेयरमैन साहब, यह हकीकत है कि कांग्रेस  
अब गिर रही है, दो सूबों में नहीं, चार  
सूबों में नहीं, अनेक सूबों के अन्दर उसको  
अप्रोजीशन के सरकारों के साथ एडजस्ट  
करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा.....

**श्री जूलिफकार अली खां (रामपुर) :**  
श्री सेंटर में ?

**श्री इसहाक सम्भली :** 1972 तक यहां  
भी गायब हो जायगी। मैं अर्ज कर रहा  
था कि कलकत्ता रेडियो स्टेशन से मि० विष्णु  
दत्त की एक स्पीच ब्राडकास्ट हुई थी, जो  
टाइम्स आफ इण्डिया से ताल्लुक रखते हैं।  
उन्होंने अपनी स्पीच में वहां की सरकार के  
बारे में क्या-क्या कहा, इतना ही नहीं कि  
वे सब गलत बातें थीं, बल्कि वह सेंटर और  
स्टेट के ताल्लुकात को खराब कर देने वाली  
स्पीच थी। अगर आप कहें तो मैं उसको  
पढ़कर सुना सकता हूँ, लेकिन इसमें दो-तीन  
मिनट लग जायेंगे और मैं नहीं चाहता कि

मेरा टाइम इसमें जाया हो जाय, मैं उस  
तहरीर को मिनिस्टर साहब के हवाले कर  
देता हूँ। उन्होंने जिस तरह से बैस्ट बंगाल  
गवर्नमेंट को ब्लेम किया है, जिस तरह से  
उन्होंने इल्जाम लगाये हैं.....

**सूचना तथा प्रसारण, और संचार मंत्री  
(श्री सत्यनारायण सिंह) :** मैं एक बात  
आपकी जानकारी के लिए कह दूँ कि आप  
ता० 10 का पढ़ रहे हैं, अगर ता० 12 का  
पढ़ दिया जाय तो आपको पता चल  
जायगा.....

**श्री इसहाक सम्भली :** ता० 12 का  
किसका है ?

**श्री सत्यनारायण सिंह :** उसी तरह का  
जो रेडियो ब्राडकास्ट दिल्ली से हुआ है, उस  
से आपको पता चल जायगा कि दोनों तरफ  
क्या हालत है।

**श्री इसहाक सम्भली :** अगर आप इस  
का करेक्शन करलें तो मुझे खुशी होगी।  
आइन्दा इस तरह की तकरीरें बन्द हो जानी  
चाहिएँ।

चेयरमैन साहब, मैं अर्ज कर रहा था  
कि इतना ही नहीं हो रहा है, कलकत्ता  
रेडियो के लिये एक कमेटी बनाई जाती है।  
अभी-अभी मैंने अखबार में पढ़ा है—श्री  
ज्योति भट्टाचार्य जो वहाँ के इंफर्मेशन मिनि-  
स्टर हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि  
कलकत्ता रेडियो के लिये जो कमेटी बनी,  
उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट से कोई मश-  
विरा नहीं लिया गया। मुझे मालूम नहीं  
है कि इसके बारे में क्या सिस्टम है, लेकिन  
मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूँ। मैं  
वहाँ की लेजिस्लेटिव कौन्सिल का मेम्बर था,  
जब यहाँ पर भ्राल इण्डिया रेडियो के लखनऊ  
स्टेशन के लिए कमेटी बनी, मुझे मालूम  
है कि किस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट के  
रिकमेण्डेड लोगों को लिया गया था.....

श्री जूलिफकार अली खां : श्रीर अब भी लेते हैं ।

श्री इसहाक सम्भली : जी हाँ, अब भी लेते हैं, आपकी बात सही है ।

वेस्ट बंगाल सरकार से इसके बारे में कोई मशविरा नहीं लिया गया । चेयरमैन साहब, यह क्या किया जा रहा है ? क्या स्टेट और सेंटर के ताल्लुकात इस ग्रहम डिपार्टमेंट के जरिए नहीं बिगाड़े जा रहे हैं ? मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गौर करे और मिनिस्टर साहब इसका जबाब दें । यह कोई जवाब नहीं है कि 10 ता० को आपने ईंट मारी थी तो 12 ता० को दूसरे ने ईंट मारदी । यह सेन्टर की जिम्मेदारी है कि वह स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात अच्छी तरह से निभाये और स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि वह सेन्टर के साथ अपने को एडजस्ट करे, लेकिन पहला काम सेन्टर का है । अगर सेन्टर की तरफ से ऐसी चीज नहीं हुई होती जो हमारे ताल्लुकात को बिगाड़ने वाली है, सेन्टर के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली है, अगर ऐसी तकरीर नहीं हुई होती तो शायद दूसरी तरफ भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता । आपको बहुत से सूबों के साथ एडजस्ट करना है, शायद मध्य प्रदेश में भी फिर से चुनाव हों, विहार में भी फिर से चुनाव होने के इमकान दिखाई देते हैं और वहां पर फिर से अपोजीशन मैजोरिटी में आयेगी । जहां-जहां इलैक्शनज होंगे, मुझे मालूम है कि अब कांग्रेस हारती जायगी, इस लिये कांग्रेस को अपने आपको एडजस्ट करने के लिये तैयार हो जाना चाहिये ।

चेयरमैन साहब, जैसा मैंने अभी अर्ज किया था कि यह महकमा बहुत ग्रहम महकमा है, सारी दुनिया में शायद सब से बड़े रेडियो स्टेशनज में से है, लेकिन अगर मैं यह कहूँ तो गलत नहीं होगा कि साइज में बहुत बड़ा है, क्वालिटी में कुछ नहीं है ।

वहां के आर्टिस्टों की हालत को देखिये । चूँकि वक्त नहीं है, इस लिये बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक एकजाम्पल दूंगा—हम मिनिस्टर साहब के बहुत शुक्र-गुजार हैं कि आपने उन को पूरे टाइम के लिये कान्ट्रैक्ट दे दिया है—इस के लिये मैं आपका बार-बार शुक्रिया अर्दा करता हूँ—लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सेंद्रल गवर्नमेंट के रेग्युलर एम्पलाइज को जो फैंसिलिटीज दी जाती हैं, वे आप उन को क्यों नहीं देते हैं ? आपने उन के कान्ट्रैक्ट में लिखा है कि टाइम-बाइ-टाइम उन को वे फैंसिलिटीज, वे सुहूलियतें, वे सुविधायें दी जायेगी जो सेंद्रल गवर्नमेंट की रेग्युलर सर्विसिज को दी जाती हैं, लेकिन जब सेंद्रल गवर्नमेंट सर्विसिज का डी० ए० का मर्जर हुआ, उन्होंने भी मांगा कि हम को भी मिलना चाहिये, हम भी फुल-टाइम वर्कर हैं, पूरे टाइम के लिये हमारा कंट्रैक्ट है, लेकिन हमारे बुजुर्ग—मोरारजी देसाई साहब ने, जो हमेशा गरीबों का पेट काटने के लिये तैयार रहते हैं—शायद उनके डिपार्टमेंट ने इस की इजाजत नहीं दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान के अन्दर 2500 आर्टिस्ट इस से महरूम रहे । मुझे ताज्जुब है कि जहां पर ऐसे ऐसे एक्स-पीरियेंसड मिनिस्टर मौजूद हैं—गुजराल साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखने वाले इन्सान हैं—उनके सामने भी इतनी खुली हुई नाइन्सफ्री हो रही है और वह इस को बरदास्त किये जा रहे हैं ।

चेयरमैन साहब, कितनी बार यहां पर मांग की गई है कि इसका एक कारपोरेशन बनाया जाय । मेरी समझ में नहीं आता कि कारपोरेशन बनाने में, आटोनोमस कारपोरेशन बनाने में सरकार को क्या दुस्वारी है । चन्दा कमेटी ने स्टूडेंटली रिक्लेमण्ड किया था कि इस का कारपोरेशन बनाया जाय, लेकिन मालूम नहीं हमारी सरकार

### (श्री इसहाक सम्भली)

इस को अपने सीने के नीचे दबाये रखने में क्या फ़ख़ महसूस करती है। अगर कार-पोरेशन बन जाता है, उस हालत में भी जिस पार्टी की यहां पर मैजोरिटी रहेगी, उसी की वहां भी मैजोरिटी रहेगी, आपको इसमें क्या डर है? आज अपने साये से भी कांग्रेसी डरने लगे हैं—ऐसी हालत इन की हो गई है।

मैंने अभी अर्ज किया था कि हमारा यह महकमा नेशनल इन्टीग्रेशन, कौमी एकता के लिये बहुत ज्यादा काम कर सकता है। श्रीनगर में नेशनल इन्टीग्रेशन की कान्फ़्रेंस हुई थी, बहुत अच्छी कान्फ़्रेंस थी, मैं उस के लिये मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे फैसले वहां पर किये गये लेकिन उन फैसलों पर अमलदरामद करने के लिये आल इंडिया रेडियो ने कितना हिस्सा लिया? इस डिपार्टमेंट के खबर-वाले महकमे ने कितना हिस्सा लिया? अगर उस ने कोई हिस्सा लिया है तो यह कि उन अखबारों के खिलाफ जो कौमी एकता के लिए काम करते हैं, लेकिन मजलूमों के लिए आवाज भी उठाते हैं, उन पर घड़ाघड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन वे अखबार जो रात-दिन यहां पर नफ़रत का प्रचार करते हैं, नफ़रत का ज़हर लोगों को पिला रहे हैं, आग लगा रहे हैं—उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कौन नहीं जानता—आर्गनाइज़र क्या नहीं लिखता है, उसके हर ईशू में फ़र्जी स्टोरीज निकलती है। जो हिन्दू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करता है, हिन्दू और सिखों के दरमियान नफ़रत पैदा करता है—लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके इसके बारे में बतलायें कि ऐसे अखबारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, उनकी नज़र में सिर्फ वही अखबार क्यों आते हैं जो माइनोरिटीज के लिये, मजलूमों के लिए आवाज उठाते हैं।

एक खास चाज़ की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

इतिहास देने और पेपर का कोटा देने में आज जितनी नाइन्साफ़ी की जा रही है, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। मैं आसाम के पेपर को बतलाता हूँ जिसका दस हजार से ऊपर सर्कुलेशन है लेकिन आपको सुन कर ताज़्जुब होगा कि आजकल उसको पेपर का कोटा नहीं दिया गया। उसका क्या कुसूर है? एक ही कुसूर हो सकता है कि वह कांग्रेसी को अपोज़ करते हैं।

आल इण्डिया रेडियो का उर्दू प्रोग्राम इन्तहाई पसन्द किया जाता है। मैं देखता हूँ कि वे लोग जो पूरी तरह से उर्दू नहीं जानते वह भी उर्दू प्रोग्राम को पाबन्दी से सुनते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम के लिए टाइम कितना दिया जाता है? एक दिन में नहीं बल्कि एक हफ़्ते में सिर्फ साढ़े पांच घण्टे। मैं चाहूँगा कि आल इण्डिया रेडियो को पापुलर बनाया जाये। उर्दू और दूसरी रीजनल लैंग्वेज की ओर ज्यादा होसला अफ़जाई की जाये। वहां के कर्मचारियों के साथ जो नाइन्साफ़ियां हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाये।

मिनिस्टर साहब कम्युनिकेशन के भी मिनिस्टर हैं, मैं उनसे एक बात अर्ज करूँगा कि पी० एण्ड टी० के कितने ही मुलाजिम जो कि 19 सितम्बर की हड़ताल के सिलसिले में निकाले गए थे उनको काम पर वापिस नहीं लिया गया है, उनके बच्चे आज भूखों मर रहे हैं, जबकि यहां पर मिनिस्टर साहब का एलान हो चुका है। कल इन्वोरेन्स कमिटी ने फैसला किया कि आपका एश्योरेन्स था, एश्योरेन्सेज कमिटी उसको एग्जामिन करेगी कि वह इम्पलीमेंट क्यों नहीं हुआ। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से मांग करूँगा कि पी० एण्ड टी० के जितने ऐसे मुलाजिम हैं, इससे पहले कि एश्योरेन्सेज कमिटी इस चीज़ को ले करके यहाँ पर आये कि आपने एश्योरेन्स पूरा नहीं किया, उनको आप काम पर वापिस लें और उनके साथ जो नाइन्साफ़ियां हो रही हैं उनको ख़त्म करें।

سے مشر و شندوت کی ایک سچ براد کا سٹاپی  
تھی۔ جو ٹائمر آف انڈیا سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں  
نے اپنی سچ میں وہاں کی سرکار کے بارے میں  
کیا کیا کہا۔ اتنا ہی نہیں کہ وہ سب باتیں غلط  
تھیں۔ بلکہ سینئر اور سٹیٹ کے تعلقات کو  
خراب کرنے والی سچ تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں  
اسکو پڑھ کر سناسکتا ہوں۔ لیکن اس میں دو  
تین منٹ لگ جائیں گے۔ اور میں نہیں جانتا  
کہ یہ انڈیا میں ضائع ہو جائے۔ میں اس تقریر  
کو سن کر جب کے حوالے کر دیتا ہوں انہوں  
نے جس طرح سے ولیٹ بحال کرنا غلط کر لیم  
کیلئے۔ جس طرح سے انہوں نے انعام لگانے  
ہیں۔

سوچنا تھا پراسن اور سنچلہ مشری (شری  
سیتھ نارائن سنگھ) میں ایک بات آپ کی جانکاوی  
کے لئے کہہ رہی کہ آپ تاریخ ۱۰۔ کا پڑھ سے  
ہیں۔ اگر تاریخ ۱۱۔ کا پڑھ دیا جائے تو آپ کو  
پتہ چل جائے گا۔

شری اسحاق سنبھلی تاریخ ۱۲۔ کا کس کا ہے  
شری سیتھ نارائن سنگھ۔ اس طرح باجو ریڈیو  
براد کا سٹاپی سے ہوا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ  
چل جائیگا کہ دونوں طرف کیا حالت ہے  
شری اسحاق سنبھلی۔ اگر آپ اس کا کہیں

شری اسحاق سنبھلی (امروہہ)  
صاحب صدر! اس مشری کا کام کتنا ہم  
ہے اسکے بارے میں سمجھا جاتے ہیں اس لئے میں  
اسکے بارے میں زیادہ مائم نہیں لوں گا انفارمیشن  
اور براد کا سٹنگ صرف ہماری ایجوکیشن اور  
کلچرل ایکٹو ٹیز کا ہی ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے  
نیشنل انٹیگریشن اور پولٹیکل نظریہ سے بھی اسکی  
امپارٹنس بہت زیادہ ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کا  
یہ محکمہ دیش کے انڈر نیشنل انٹیگریشن کیلئے  
قومی ایکٹا کیلئے بہت کام کر سکتا ہے سینئر اور  
سٹیٹ کے تعلقات کو بہت مضبوط بنا سکتا  
ہے اور انکو خراب بھی کر سکتا ہے مجھے تعجب کچھ  
کلکتہ ریڈیو سٹیشن سے ایک تقریر براد کا سٹاپی  
ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ مشر صاحب اسکو ذرا غور  
سے سنیں چیئر مین صاحب یہ حقیقت ہے کہ  
کانگریس اب گر رہی ہے۔ دو صوبوں میں نہیں چا  
دوبوں میں نہیں۔ ایک صوبوں میں اسکو اپوزیشن  
کی سرکاروں کیساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لئے  
تیار رہنا پڑے گا۔

شری ذوالفقار علی خاں (ڈامپور) اور مشری  
شری اسحاق سنبھلی۔ ۱۹۷۲ تک یہاں بھی  
غائب ہو جائے گی۔

میں عرض کر رہا تھا کہ کلکتہ ریڈیو سٹیشن

کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ آئندہ اس طرح تقریریں بند ہو جانی چاہئیں۔

چیرمین صاحب! میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کلکتہ ریڈیو کیلئے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ ابھی ابھی میں نے اخبار میں پڑھا ہے شری جیوتی بھٹا چارہ جو دہاں کے انفارمیشن منسٹر میں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کلکتہ ریڈیو کیلئے جو کمیٹی بنی اسکے لئے دہاں کی گورنمنٹ سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس بارے میں کیا سٹیم ہے لیکن میں دہاں کی کونسل کو نہیں کھاتا۔ جب دہاں پر آل انڈیا ریڈیو کے کنکونیشن کے لئے کمیٹی بنی۔ مجھے معلوم ہے کہ کس سے دہاں کی گورنمنٹ کے رکنینڈیڈ وگوں کو کیا گیا تھا۔

شری ذوالفقار علی خاں۔ ادب بھی لیتے ہیں۔

شری اسحاق سنبھلی جی! اب بھی لیتے ہیں۔ آپ کی بات سچ ہے۔

ڈیٹ سبگال سرکار سے اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں لیا گیا۔

چیرمین صاحب! یہ کیلکٹا چارہ ہے۔ کیا میٹ

اور سینٹر کے تعلقات اس اہم ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ نہیں بگاڑے جا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ سرکار اس پر غور کرے۔ اور منسٹر صاحب اس کا جواب دیں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ کہ ۱۰ تاریخ کو آپ نے اینٹ ماری تھی تو ۱۲ تاریخ کو دوسرے نے اینٹ ماری۔ یہ سینٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ میٹ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھی طرح سے نبھائے اور اینٹ کی بھی ذمہ داری ہے۔ کہ وہ سینٹر کے ساتھ اپنے کو ایڈجسٹ کرے۔ لیکن پہلا کام سینٹر کا ہے اور سینٹر کی طرف سے ایسی چیز نہیں ہوئی ہوتی۔ جو ہمارے تعلقات کو بگاڑنے والی ہے۔ سینٹر کے خلاف نفرت پیدا کرنے والی ہے۔ اگر ایسی تقریر نہیں ہوئی تا شاید دوسری طرف بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ آپ کو بہت سے صوبوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے۔

شاید مدھیہ پردیش میں بھی پھر سے چاؤ ہوں بہا میں بھی پھر سے چاؤ ہونے کے امکان دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہاں پھر سے اپوزیشن بھاڑی میں آئے گی۔

جہاں جہاں ایکشن ہوئے گے مجھے معلوم ہے۔ کہ کانگریس اب ہارتی جائیگی اس لئے کانگریس کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے تیار ہو جانا چاہیے۔

چیرمین صاحب! جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا۔ یہ محکمہ بہت اہم محکمہ ہے۔ ساری دنیا میں شاید سب سے بڑے ریڈیوسٹیشنز میں سے ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سائنس میں بہت بڑا ہے لیکن کوالٹی میں کچھ نہیں ہے۔ وہاں کے آرسٹروں کی حالت کو دیکھئے چونکہ وقت نہیں ہے۔ اس لئے بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن ایک ایگزیمپل دوں گا۔ ہم منسٹر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں۔ کہ آپ نے ان کو پورے ٹائم کے لئے کانٹریکٹ دے دیا ہے اس کے لئے میں آپ کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں جانا چاہتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹ کے ریگولر ایمپلائز کو فیسلیٹیوز دی جاتی ہیں۔ وہ آپ ان کو کیوں نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے ان کے کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ ٹائٹھی ٹائم ان کو وہ فیسلیٹیوز۔ وہ سہولتیں۔ وہ سہولتیں دی جائیں گی۔ جو سینٹرل گورنمنٹ کی ریگولر سرورسز کو دی جاتی ہیں۔ لیکن جب سینٹرل گورنمنٹ سرورسز کا ڈیپارٹمنٹ کامرہ ہوا۔ انہوں نے بھی مانگا کہ ہم کو بھی ملنا چاہیے۔ ہم بھی نل ٹائم وکر ہیں۔ پورے ٹائم کے لئے ہمارا کانٹریکٹ ہے لیکن ہمارے بزرگ مرارجی دلیائی صاحب نے جو ہمیشہ غریبوں کا پیٹ کاٹنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ شاید ان کے ڈیپارٹمنٹ کو اس کی اجازت نہیں دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے

اندر ۲۵ آرٹسٹ اس سے محروم رہ گئے تھے تعجب ہے کہ جہاں پر ایسے ایسے ایکسپریٹس منسٹر موجود ہوں۔ گجرات صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں۔ پروگریسو ٹھنکنگ رکھنے والے انسان ہیں ان کے سامنے بھی اتنی کھلی ہوئی نا انصافی ہو رہی ہے۔ اور وہ اس کو برداشت کئے جاہے ہیں۔

چیرمین صاحب! کتنی بار یہاں پر مانگ کی گئی ہے کہ اس کا ایک کارپوریشن بنایا جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کارپوریشن بنانے میں سزکار کو کیا دشواری ہے چند اکٹھی لے کر سڑکی ریکینڈ کیا ہے۔ کہ اس کا کارپوریشن بنایا جائے لیکن ہم نہیں ہمارا سرکار کو اپنے سینے کے نیچے دبا رکھیں کیا فخر محسوس کرتی ہے اگر کارپوریشن بن جاتا ہے اس حالت میں بھی جس پابندی کی یہاں پر چھوٹی ہے گی۔ سبکی وہاں بھی چھوٹی ہے گی۔ آپ کو اس میں کیا فائدہ ہے۔ سچے سچے سے بھی کانگریسی ڈرنے لگے ہیں اس حالت لان کی بن گئی ہے

میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ محکمہ منسٹر اینڈ گورنمنٹ۔ تو ایکن کیلئے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے شری نگر میں منسٹر اینڈ گورنمنٹ کی کانفرنس ہوئی تھی بہت اچھی کانفرنس تھی۔ میں اس کے لئے مبارکباد دیتا ہوں بہت اچھے فیصلے وہاں پر کئے گئے لیکن ان فیصلوں پر عملدرآمد کرنے کیلئے آل انڈیا ریڈیو نے تمنا حاصل کی اس



ڈپارٹمنٹ کے خبردارے چکے نے کتنا حاصل کیا اگر اس نے کوئی حصہ لیا تو یہ کہ ان اخباروں کے خلاف جو قومی ایکٹ کیلئے کام کرتے ہیں لیکن مظلوموں کی آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ ان پر دھڑا دھڑا کمیشن لگے جائے ہیں لیکن جو اخبارات دن بہاں پر نفرت کا پرچار کرتے ہیں۔ نفرت کا زہر روگن کو بلا ہے۔ آگ لگا رہے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے کون نہیں جانتا۔ آرگنائز کیا نہیں مکھنٹا ہے۔

اس کے برائیسوں فرضی سٹوریز نکلتی ہیں جو ہندو مذہب والوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے۔ ہندو اور سکھوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے لیکن اس پر کوئی کمیشن نہیں لیا گیا میں چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب مہربانی کر کے اسکے بارے میں بتلائیں کہ ایسے اخباروں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا۔ انکی نظر میں صرف وہی اخبار کہیں آتے ہیں جو مذہبیز کیلئے مظلوموں کیلئے آواز اٹھاتے ہیں۔

ایک خاص چیز کی طرف میں منتری ہو رہے کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ اشتہار دینے اور سپر کا کوٹہ دینے میں آج جتنی نا انصافی کی جا رہی ہے اس کی مثال ملتی شکل ہے۔

میں آسام کے سپر کو بتلاتا ہوں جب کا دس ہزار سے اوپر سپر کمیشن ہے لیکن آکھو سنکر ٹیون بھگا کا کراچ تک آکھو سپر کا کوٹہ نہیں دیا گیا۔ اس کا کیا قصہ ہے۔ بیکہ

قصہ ہو سکتا ہے کہ وہ کانگریس کو اپوزر کرتے ہیں

آل انڈیا ریڈیو کا لہرو پروگرام انتہائی پسند کیا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پوری طرح اردو نہیں جانتے وہ بھی اردو پروگرام کو پابندی سے سنتے ہیں لیکن اس پروگرام کے لئے نام کتنا دیا جاتا ہے ایک دن میں نہیں بلکہ ایک ہفتہ میں صرف ساٹھ پانچ گھنٹے میں چاہو سکا۔ کہ آل انڈیا ریڈیو کو پاپولر بنایا جائے۔ اردو اور دوسری ریجنل لیٹگو مجز کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ دہاں کے کراچیوں کے ساتھ جو نا انصافیاں ہو رہی ہیں۔ ان کو ختم کیا جائے۔

منسٹر صاحب کو کمیشن کے بھی منسٹر ہیں۔ ان سے ایک بات عرض کروں گا۔ کپلی اینڈ ٹی کے لئے ہی ملازم 19 ستمبر کی ہڑتال کے سلسلے میں کالے گئے تھے انکو کم پڑا نہیں لیا گیا ہے۔ انکے پتے آج بھوکوں مر رہے ہیں جبکہ یہاں پر منسٹر صاحب کا اعلان ہو چکا ہے کل ایشیور سیزر سٹی نے فیصلہ کیا کہ آپکا وہ ایشیور سیزر تھا۔ ایشیور سیزر کیسی ایجو ایمن من کر گی۔ کہ وہ اسپلینٹ کیوں نہیں ہوا۔ اسلئے میں منسٹر صاحب سے مانگ کر ڈسکا کپلی اینڈ ٹی کے جتنے ایسے ملازم ہیں۔ اس سے پہلے ایشیور سیزر کی اس چیز کو لیکر کہ یہاں پر آئے کہ آپ نے ایشیور سیزر لیا نہیں کیا۔ انکو آپ کام پڑا نہیں۔ اور انکے ساتھ جو نا انصافیاں ہو رہی ہیں انکو ختم کریں۔

**SHRI INDER J. MALHOTRA** (Jammu) : Mr. Chairman, Sir, before I start with my observations regarding the Ministry of Information and Broadcasting, I would like to bring one thing to your notice. Though the Ministry is now known as the Ministry of Information, Broadcasting and Communications, I do not know why the demands of the Ministry of Information and Broadcasting and the demands of the Ministry of Communications are kept separate, so that we may not be able to make any observations regarding the demands of the Communications Ministry.

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL)** : I think I might remove this wrong impression. The Ministry is not one. It is known as the Ministry of Information and Broadcasting and a separate Department of Communications, so far as the Cabinet order goes. Only the Ministers are the same for both.

**SHRI INDER J. MALHOTRA** : I do not agree. The Ministry of the Government of India is a composite one and Ministers are put in charge of various subjects. When one Minister is in charge of so many departments ; we have got every right to make observations about all those departments under the charge of that Minister.

**SHRI SATYA NARAYAN SINHA** : You have every right to express your views. But do not expect me to reply to those points. That is all.

**MR. CHAIRMAN** : I am trying to understand the position. Is the Minister responsible for both the departments ?

**SHRI SATYA NARAYAN SINHA** : The demands are separate. When those demands come, we will answer those questions. How is it possible to refer to that department when the cut motions have not been moved ?

**MR. CHAIRMAN** : So, when the Department of Communications comes here for discussion, you will have an opportunity to discuss this.

**SHRI INDER J. MALHOTRA** : The Department of Communications will never come for discussion. I am sure it will be guillotined. That is why I have referred to it.

**MR. CHAIRMAN** : I can not help you there, because demands of so many Ministries will be guillotined for want of time. The Minister will reply only to those points which relate to the demands and cut motions which have been moved.

**SHRI INDER J. MALHOTRA** : So, with this protest, I will give my observations only on the department of Information and Broadcasting.

As my hon. friend has just now pointed out, the role which this Ministry of Information and Broadcasting can play in strengthening national integration and projecting the image of the country within the country and also outside through its various medias like All India Radio, Publications Division, Press Information Bureau and various others is very great.

Regarding the performance of the media units and of the Ministry as a whole, I think, to some extent they have done fairly well but I would certainly like to say that still much improvement can be made and with whatever money that we are spending on maintaining and on the working of the various media units, much useful work can be done.

As far as the administration of this Ministry is concerned, it is in a rotten state. I would, therefore, appeal to the senior Minister as well as to the Minister who is directly in charge of information and broadcasting. Shri Inder Gujral, that their first task should be to put the administration of the Ministry on the right lines.

A few years back this Ministry created the Central Information Service. This House was told at that time that this Service was being created so that the functioning and the efficiency of the Ministry's various media units could be improved.

[Shri Inder J. Malhotra]

Talented young men came into this cadre through competition through the UPSC and they were promised—this cadre was promised—that whatever emoluments and other facilities that are being given to the IAS and other Central cadres, this cadre would also get. But because in this Ministry there is a clique of bureaucrats at the top, this cadre has not functioned as it should have been functioning and this cadre has not received the proper, just and sympathetic treatment from those people who are in charge of administration in the Ministry.

They have created a system of *ad hoc* appointments. When this cadre has been created and people are there in this cadre who can man any kind of job in all the media units, I do not understand why you need this *ad hoc* appointment system and why you need people from outside the cadre. If a person to do a particular job is not available within the cadre, certainly you are at full liberty to have persons from outside the cadre. But there are examples when persons were available in the cadre and they were ignored. When the question of promotion comes, the cadre people are ignored. This is my information. I do not know. The hon. Minister knows better than I do. The Departmental Promotions Committee, I am told, has not met for the last seven years. I do not know how promotions were being decided upon in the Ministry. So I would request the hon. Minister that he should pay special attention to this because unless the administration of his own Ministry is improved and the Central Information Service personnel are satisfied to a reasonable extent, the efficiency of the Ministry which is suffering will suffer still more.

Now, I would like to come to the All India Radio. As I said in the beginning, the All India Radio has done fairly well in the past. It has considerably improved its performance in news coverage and in the presentation of other features. I am very happy to know that the commercial service has been started from the Delhi Station of AIR. I would like to urge upon the hon. Minister that

from other AIR stations also such commercial service should be started.

SHRI S. M. BANERJEE : It will be horrible.

SHRI INDER J. MALHOTRA : I would like to have a clarification on one or two points. Shri Jadhav also made a reference to one of them. Speakers to speak on special subjects from various walks of life are invited by the All India Radio to give talks. I would like to know on what basis it is done ; who is the authority who selects these people, who chooses that such-and-such a person should be invited by the All India Radio to give a talk on such-and-such a subject.

Then, I would certainly like to congratulate the Ministry for establishing an experimental television station in New Delhi. I do not know how far this period of experimentation will continue. I would like to request the hon. Minister to tell the House what is their future programme for expansion of television network in the country. I would urge upon him, as it has come in the newspapers, to set up a television station at Srinagar. The sooner they do, the better it will be.

Regarding the programmes on the television, there is one programme for which I have got great appreciation and that is about agriculture. Regarding other programmes, I think, much improvement can be effected and I would request the Minister to urge upon the television people to pay attention to this.

There is the Song and Drama Division of the All India Radio. I do not know what useful work they are doing.

AN HON. MEMBER : It is a racket.

SHRI INDER J. MALHOTRA : I have seen people who are connected with this Department moving around in New Delhi in big imported cars. I have never seen their performance equivalent to the facilities which they are enjoying.

श्री जार्ज फरनेन्डीज ( बम्बई दक्षिण ) :  
कर्मल गुप्ते बड़ा बदमाश आदमी है, उस

का हटाइये। क्या क्या बदमाशी नहीं करता है। हर किस्म की बदमाशी चल रही है।

MR. CHAIRMAN : Order, order.

SHRI RANDHIR SINGH : This is very bad.....(Interruption)

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : Is it proper ? (Interruptions)

SHRI RANDHIR SINGH : Is it parliamentary ? He should withdraw it.

MR. CHAIRMAN : You should not interrupt like this.

श्री आर्ज करनेन्दीज : क्षमा कीजिये।

MR. CHAIRMAN : I must tell you, you cannot interrupt like this. Please resume your seat. I do not think it is fair to use that word. You can be equally forceful without using that language. This is very unfair. It should not be repeated.

SHRI S. M. BANERJEE : He used the national language.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI (Bilhaur) : Sir, it is an aspersion on the national language.

श्री आर्ज करनेन्दीज : शालिनी पाटिल के बारे में भी प्राप सुनेगे इस सदन में, कर्नेल गुप्ते के बलावा।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : After Mr. Fernandes apologised.....

SHRI GEORGE FERNANDES : Apologised to whom ? अध्यक्ष की इजाजत नहीं ली इसलिए मैंने क्षमा मांगी। जो कहा उसके लिए नहीं।

MR. CHAIRMAN : I sit here as a representative of the House. Whatever is done is passed on to the House. Mr. Fernandes, you can be equally forceful without requisitioning the service of those words.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Sir, after that, Mr. S. M. Banerjee said that he was using the national language. That is an aspersion on the national language. He said that the word 'Badmash' is the national language. The word 'Badmash' cannot be called the national language.

श्री आर्ज करनेन्दीज : उनके कारनामों के बारे में, जितनी बदमाशी है, उसके बारे में सबूत इस सदन में दूंगा। प्राप मेरा साथ दोगी। वहां के कलाकारों विशेषकर लड़कियों की क्या-क्या हालत होती है उसको सदन के सामने रखूंगा तो प्राप गुस्से से खड़ी हो जायेंगी।

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of personal explanation.

MR. CHAIRMAN : That is over now.

SHRI S. M. BANERJEE : My respected sister said about the national language. I never meant any offence. Suppose he had used the word 'scoundrel' ?

MR. CHAIRMAN : I don't allow you to reopen it. The matter is closed now. You are cutting into his time.

SHRI INDER J. MALHOTRA : I would submit to you very humbly that when the points of order and interruptions go on it is the Chair's time, not my time. These interruptions are allowed by the Chair.

MR. CHAIRMAN : The time is fixed by the House. It is not anybody's time. Please try to conclude now.

SHRI INDER J. MALHOTRA : I made a mention about the functioning of the Song and Drama Division so that the Minister can pay his personal attention to see that if there is really something wrong, the house should be put in order.

I was still on All India Radio. There is a mention in the Report regarding broadcast to border areas. I come from

[Shri Inder J. Malhotra]

a State where we have always this border problem. There are two Radio Stations—one at Jammu and the other at Srinagar. The Jammu Radio Station is not that powerful to cover large areas not only within the territory of our borders but beyond our borders also, because, that is the real intention of this border broadcast. The Chinese Radio and especially the Pakistan Radio are so powerful that, all over Punjab & all over Jammu and Kashmir, their broadcast can be heard without any interruption and with a very good reception. Therefore, to counteract this, I would like to appeal to the hon. Minister that these Radio Stations in the border States should be made more powerful, so that our broadcasts can become more effective.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may conclude.

SHRI INDER J. MALHOTRA : Before I conclude, I would like to mention one thing. A few years back the employees of the community listening centres of Jammu and Kashmir State were taken over by the All India Radio and at that time those employees were promised that their emoluments and other things would be on par with the other employees of that nature under the All India Radio. But, for the last seven or eight years, nothing has been done in their case. They have sent hundreds of representations. I would appeal to the hon. Minister to pay attention to this.

In the end I would like to say that I am happy that Babu Satya Narain Sinha, who was previously also associated with this Ministry, has again taken charge of this Ministry. I am also happy that my young friend, Shri Gujral, who takes a lot of interest in Press, public relations and All India Radio, has joined that Ministry. Therefore, if I presume that henceforth something useful will come out of the media units of the Ministry of Information and Broadcasting, I think I am not wrong in presuming that.

SHRI K. ANRUDHAN (Chirayinkil) : I am constrained to oppose the

Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting. At the very outset, I would like to say that this Ministry is utilising all its cells, including the A. I. R., the Press Information Bureau, its D. A. V. P., the institution of Registrar of Newspapers and the Drama and other institutions for a particular type of propaganda. Allow me to say, Sir, that they have even started propagating against the elected democratic governments in some States inside the country. This Ministry has earned a very bad name—excuse me, Sir, for saying this—both inside as well as outside the country. This Ministry has now started even the propaganda—particularly a section of the Congress—about the intolerable and unpardonable activities of that section inside the Congress too. It has come to such a level in one of the biggest democracies of the world after 20 or 22 years of democracy. The Ministry with all these Departments, all these cells, like the DAVP and the Press Information Bureau are all doing the same. I am afraid I will not be able to go into details. But let me say something about one or two branches which I mentioned now.

Recently the Diwakar Committee submitted a very powerful report regarding small newspapers. It has recommended many things for preserving the freedom of press, and also the methods that Government should adopt for protecting the small newspapers. Moreover, the Government's declared policy is to curb the monopoly newspapers in this country which are having a stranglehold just like an octopus is having on the ordinary innocent population and also over small newspapers. These monopoly newspapers are connected with big business houses and most of them have already been linked with foreign agencies. Those foreign agencies have already an eye to molest the modesty of this country and these agencies are very particular of indulging in the internal affairs of the country utilising the influence that these big newspapers are having. The Diwakar Committee and some other powerful Committees have recommended for its curtailment and to see that these big

newspapers do not expand more and more.

In the past decade throughout the country—I do not have the exact latest figure with me—the Registrar of Newspapers has reported last year that not less than 800-900 periodicals including daily newspapers have ceased their publication. Even in a small State like Kerala from which I come, newspapers which were having their existence for the past so many years and which took part boldly in the Freedom Struggle have stopped their publication. An important newspaper entitled '*Malayalee*' which started its publication before 40 years stopped its publication very recently though it has been taken over by a leading personality, Mr. Mannath Padmanabhan who was awarded 'Padma Bhushan'. So many Chief Ministers of our State have started newspapers. Mr. Pattom Thanu Pillai who was once the Governor of Punjab and Andhra, had a newspaper entitled '*Kerala Janata*', but it is no more now. Another Chief Minister Shri R. Sankar, one of the leading congressmen, had a newspaper entitled '*Dinamony*'. But it is no more now. Our Law Minister, Shri Govinda Menon, had a newspaper from Ernakulam, called '*Deenabandhu*'. That has also died. Another important cashew king started a newspaper. That has also died.

More than one dozen daily newspapers stopped their publication during the past decade. Such is the type of help, such is the type of subsidy, such is the type of patronage that our DAVP and the Registrar of Newspapers and the Government are giving to the small newspapers, though the Diwakar Committee has recommended strongly for that.

AN HON. MEMBER : They may be selling the newsprint.

SHRI K. ANIRUDHAN : You are ignorant of the fact that the small newspapers are not selling the newsprint. During the last Budget session, even the Minister said that most of the newspapers are not even lifting the newsprint because they do not have enough attraction for it. The small newspapers are not interested in selling the newsprint. On the other

hand, the big newspapers are selling the newsprint. They are having a machinery also to sell it. I am afraid they may even sell newsprint to some other countries. It is regarding these newspapers, Sir, the Government should take particular attention. Sir, Government should be interested to see that at least the existing newspaper do not die due to financial difficulties.

Sir, therefore, I submit that we should declare that a newspaper having at least 10 years of continuous and uninterrupted publication shall not be allowed to die in this country for want of any type of positive assistance which can be given according to the recommendations of the committee and the declared policies of the Government.

Then, Sir, I want to point out that we should take steps for arresting the growth of monopoly newspapers in this country. This is a more dangerous phenomenon. Even though the D.A.V.P. has started releasing some advertisements to the small newspapers recently, I understand, more than 60% to 70% of the amount by way of advertisements are going to the big newspapers. They are a handful of 7 or 8 newspapers. They are managed by big business houses and subsidised by outside agencies. And their papers are thriving now. This matter should be viewed very carefully. I hope the hon. Minister will have a patient look in this matter.

The next thing, Sir, in this newspaper industry—especially the big newspapers—very recently, the workers—both working journalists as well as other employees—come forward with their legitimate demands. The small and medium newspapers, with their meagre income, satisfied the workers and paid their wages. But big newspapers refused to entertain their legitimate demands and refused to obey the decision of the Wage Board. Even then the Information and Broadcasting Ministry came in to their rescue by allotting more and more newsprint and giving more and more advertisement. It is an interesting phenomena. This attitude is to corrupt the newspapers. They

[Shri K. Anirudhan]

are purchasing these newspapers for their own political and personal ends.

Some years back, before Bombay State was divided into the two States of Gujarat and Maharashtra, one Mr. Sait started a crossword puzzle series enterprise. He earned enormous money by this. There was an entertainment tax due of not less than Rs. 16 lakhs. And this Mr. Sait knowing that Mr. Morarji Desai was the then Home Minister of Bombay and that he would be putting restrictions on the crossword puzzle, suddenly shifted his business from crossword puzzle to the newspaper industry. He started one newspaper in Ahmedabad and another in Baroda. One is *Loksatta* from Baroda and the other is *Jansatta* from Ahmedabad. Knowing that the new newspapers are supporting frantically the linguistic chauvinism for the division of Bombay into two States, Mr. Morarji Desai and his agents got hold of this man and asked him to be with Morarji Desai's group and support his congress friends. He changed his views subsequently. In that Rs. 16 lakhs due by way of entertainment tax, Morarji Desai agreed to give some concession and also allow instalments. Out of this, I understand that Rs. 8 lakhs is still due. Now he is coming with a new proposal for a loan or grant or subsidy or something else for Rs. 25 lakhs for the existence or for the continuous publication of these two small newspapers. Why? The Ministry has taken a decision to give him 25 lakhs of rupees without consulting either the Press Council or any other responsible organisation or even the Parliament. This is the type of help that is being given. This will affect the position, the prestige and the identity and the individuality of these newspapers, and this will also affect the freedom of expression of the Press, in a free and democratic country like ours.

Regarding the All India Radio, I want to point out...

15 hrs.

MR. CHAIRMAN : You have to conclude your speech now.

SHRI K. ANIRUDHAN : Regarding AIR, I want to point out...

MR. CHAIRMAN : I cannot give you further time. You have to conclude now.

SHRI K. ANIRUDHAN : Allow me to complete my sentence, Sir. Regarding AIR, lot of complaints have been received from Staff Artists about their pattern of work and working conditions. I hope Shri Satya Narayan Sinha will look into these complaints. Today decent workers find it difficult to work in some stations of the AIR. If they refuse to yield to the whims and fancies of the superior officers, they will get frequent transfers and even demotions. Sometimes their contracts also will not be renewed. This is how matters are going on in some of the stations of the AIR. Most heinous in certain cases.

I would once again request the Hon. Minister that in the interests of smaller newspapers, the growth of monopoly newspapers may be arrested. I also hope that the Hon. Minister will see to it that reasonable wages are paid to the workers who are working in the newspapers as well as in the AIR.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : Sir, I rise to intervene in this debate with a degree of anguish and that anguish is born out of a Cut Motion which I have noticed this morning. This is Cut Motion No. 98. It is something which I would like to read to the House for consideration. It reads thus :

Need to stop the spending of money and labour on Gandhi Centenary programmes.

Sir, in this year which we are proud to call as Gandhi Centenary Year...

AN HON. MEMBER : Who has given that Cut Motion ?

**SHRI I. K. GUJRAL :** This Cut Motion has been given by Mahant Digvijai Nath. In this country where we are privileged to live and which land was hallowed by that great man whose centenary we are celebrating this year and whose memory continues to illuminate our hearts and souls and of whom we all feel proud, the fact that somebody should have the courage to move a Cut Motion like that in this Parliament of ours, is indeed a matter of shame.

I would like to start with a statement about what this Ministry in its own humble way has been trying to do whatever it could to bring to light Gandhiji's blessings and feelings to this country and to this world. We have tried to project films on Gandhiji. There is a great and long film—many Hon. Members have seen it—on Mahatma Gandhi called "Mahatma" which lasts for 5½ hours and whoever has seen it has appreciated it. On the basis of that film, we are taking steps to make shorter films on Gandhiji. Not only we are making those films, we are taking steps and we have taken some steps to see that all these films on Gandhiji covering the entire national struggle are exhibited in every village and town for the benefit of the people. The Gandhi Centenary Year also coincides with the Fiftieth Anniversary of the Jallianwala Bagh and these will revive our memory about the heroic struggle for freedom undertaken in the past.

Talking of Gandhiji, I would like to say that not only are films being made, but in the Audio-Visual Publicity section we have brought out a number of publications like Gandhi Diary and twelve paintings on Gandhiji's life. We have also produced a number of books on Gandhiji. Publication of the complete works on Gandhiji, have been planned in 72 volumes. We have already published 30 volumes and we want to complete the work in 72 volumes—all on Gandhiji's works. Also, in addition to that we have published Mahatma Gandhi by Romain Rolland : The Message of Mahatma Gandhi, Babu ki Ashirvad, Mahatma Gandhi Album and The Gandhi Story.

**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** गांधी जी की जीवनी का क्या दाम रखा है ?

**SHRI I. K. GUJRAL :** I may not be able to give the price off-hand for this. But by the time this debate is over, I will be able to get the information.

**श्री रवि राय (पुरी) :** मेहरबानी करके प्राइस को घटाने की कोशिश करें।

**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** गांधी जी का विशेषकर करिये ताकि सब लोग उसको खरीद सकें।

**SHRI SAMAR GUHA (Contai) :** We are giving subsidy to so many things. If you subsidise this publication, it will be worth while.

**SHRI I. K. GUJRAL :** All these publications are subsidised publications. Some of the items which are still remaining to be released this year are Story of Gandhiji, Gandhi Album, etc. This I am mentioning to show that we are making concentrated efforts to make the Gandhiji Centenary Year a success. Not only these publications. Our Field Publicity organisations have gone round the villages and smaller towns in the country. 120 Seminars and Symposia have been held on Gandhiji. 307 film shows and 49 film festivals have been held. 96 Essay and Documentary Contests and also 37 lecture series have been held.

**MR. CHAIRMAN :** It is for the whole country ?

**SHRI I. K. GUJRAL :** Yes. I have said all this in order to draw your attention to the fact that this Ministry is paying particular attention to the Centenary Year. We are also paying special attention to the Jallianwala Ardha Shatabdi that is going on this year. We pay special attention to this because this was a turning point in the course of struggle for Independence and in our national life. From that time onwards the liberation of the country became possible, in the cause of which everyone



[Shri I. K. Gujral]

shared, in Amritsar as also elsewhere, the Radio, the T. V. and Films Division, the song and Drama Division, the Exhibitions Division—everyone of them individually-participated in the functions held to make this event a success.

Coming now to the Press, a mention has been made here of the press and its role. I am quite at one with the Members who expressed their views here that the dynamics of participation has to be in a way reflected through the functioning of the Press. The Stronger the Press is the stronger will be our democracy. We are all honour bound to see that not only our Press is strong but it should be free in expression, it should be free in such a way that no outside influence or inside influence which is non-journalistic will have any effect on it. We are keen that not only our Press grows but it is also protected from such influences.

I wish to inform this House that the number of periodicals and newspapers in this country is growing. The figures have been mentioned in the Report of the Registrar of Newspapers. In 1968, the total number of periodicals and newspapers was 11,678 as compared to 10,977 in the previous year. In 1966 the total combined circulation was 2.52 crores. The circulation of Dailies was only 67.5 lakhs. It has risen by 11.4% from 1962 to 1966.

Sir, my hon. friend just now mentioned about the common ownership of papers. I have mentioned repeatedly in this House that the Government is concerned with the common ownership question and it wants that this is somehow or other contained so that the smaller newspapers and medium newspapers can grow and the Editors and the working journalists can have more status. We are not so much bothered about the ownership of papers; we are bothered that the freedom can be preserved only if the working journalists and the Editors are able to get their status and are able to say what they want to say, without any hindrance from anybody else and without being influenced by those who control their salary etc. I am sure that the freedom of the press will grow fur-

ther. Although we are talking about the common ownership of the newspapers, I would like to point out here that the trend of common ownership of papers has been increasing. For instance, in 1967 it increased by 40% as compared to 1959. In 1967 it went up by 6.8%, a rate never achieved in the past five years. The number of papers owned by a common chain is also increasing. In 1962 it was 130 and it was 159 in 1967. Eight major units owning 30 Dailies controlled 67.3% of total circulation of all Metropolitan Dailies and 31.4% of total circulation of the entire Daily Press. I feel that this is something on which this House should pay attention. We had referred this to the Press Council so that they could make a study of this. They are making a study of this question. There are many ways of meeting this problem. One such way of strengthening the small and medium newspapers is by following a favourable policy in newsprint and also in giving advertisements. We have been trying to do our bit in this direction. Although my hon. friend has expressed a fear that smaller newspapers have been dying, and doubted if we are giving assistance to them in the way we should, I would like to point out that so far as Government are concerned, we are trying our bit to do something.

I will draw attention to our advertisement policy. The total expenditure on our display advertisement in big newspapers has been brought down from 47.7 per cent in 1966-67 to 34.71 per cent in 1968. Correspondingly, that for the medium and small newspapers has gone up from 52.3 per cent in 1966 to 65.29 per cent in 1968.

Not only that. We have also been paying attention to the papers brought out in Indian languages and have been reserving more advertisement quota for them. In 1966-67, we had paid a total of about Rs. 45 lakhs to English newspapers; this was brought down to Rs. 30 lakhs till 31st December in 1968-69. Hindi and other language newspapers which got about Rs. 32 lakhs advertisement from us in 1966-67 got Rs. 34 lakhs till the end of December, 1968-69.

We are keen that not only the small and medium size newspapers should grow; we are also anxious that more papers are brought out in Indian languages because it is only through this medium that people can get information, and the better informed the public the stronger will be the growth of democracy in the country.

Shri Mohamed Imam and Shri Sambhali brought to our attention the trend of communal press and communal utterances. Everyone will, I am sure, condemn any such tendency growing in this country which will result in building up communal hatred. Government have also been very keen to curb this trend. Particularly after the National Integration Conference in Srinagar, special steps have been taken. Special studies have been initiated. The Press Council has been receiving complaints against some newspapers which have indulged in such propaganda. But more than that, I am glad that the AINEC has adopted a code of ethics. Only three lines from which I will quote, which I think serves as a very good guideline for the growth of a national press.

"It is the duty of the press to help promote unity and cohesion in the hearts and minds of the people and refrain from publishing material tending to excite communal passion and inflame communal hatred."

Everyone in this House irrespective of party will agree with the need not to publish anything which rouses communal hatred and this is a thing which should not be encouraged, because if this tendency were to grow, it would constitute a very big danger to the unity and integration of the country. Only by curbing and eliminating this trend can we sustain our integration and the type of democratic institution we are trying to build up in this country.

As regards newsprint—to which reference has been made in some of the cut motions—I would like to state the position. The newsprint position is, unfortunately, difficult in the sense that we produce very much lesser than what we need. We have got only one

factory at Nepa which is producing newsprint in addition to some white printing and writing paper. Last year, we had to import 1,20,000 metric tonnes newsprint from abroad. Nepa give us about 30,000 tonnes of newsprint and 20,000 tonnes of printing and white writing paper which were made available and allocated.

The demand is considerable. We understand Nepa is going to increase its production by 40,000-45,000 tonnes. There are to new projects being considered, one in Kerala and another near Bhakra. If they come into being, it would be easier for us to meet the considerably growing demand for newsprint.

Some hon. members said that some small newspapers were ignored in the matter of allotment of news print quota. I strongly assert that the small and medium size newspapers receive preferential treatment so far as newsprint allocation is concerned.

And we are keen that small and medium newspapers should not starve in any case for want of newsprint. Therefore, if any particular case is brought to our notice, it will receive our attention.

Now I come to another aspect which has been mentioned here by my hon. friend Shri Imam. When he was speaking he mentioned about Novesti.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : But what about the Central Government's giving of quota to big monopolist papers ?

SHRI I. K. GUJRAL : I have just now given the figures in percentage.

SHRI E. K. NAYANAR : I want to know about the big monopoly Congress papers which are being given the newsprint quota.

MR. CHAIRMAN : He has already dealt with that before you came over here. If you want, you can ask him privately about that.

SHRI E. K. NAYANAR : This is not a private Affair.

**MR. CHAIRMAN :** He has already dealt with this.

**SHRI I. K. GUJRAL :** About Novosti ; a reference was made by Shri Imam. In fact this reference is being made from time to time. And so I want to utilise this occasion to clarify some doubts which may be in the minds of some hon. Members. An agreement was entered into between Novosti and the P. I. B. in 1967. The salient feature of the agreement are :

"In so far as the material received, by the P. I. B. from Novosti is concerned, this is not distributed by the P. I. B. but is placed in the Library for reference purposes only."

Any articles, any materials etc. received from Novosti by the P. I. B. are kept in the library for reference purposes only. Anyone can make use of them.

But, Sir, as regards the articles, photographs and other materials supplied by the P. I. B., Novosti has informed the P. I. B. that it is regularly including the material supplied by the P. I. B. in the International Information Bulletin circulated by Novosti to 900 Soviet newspapers and periodicals. Therefore, Sir, if there are any doubts on this accounts, they should be removed by what I have said.

Another aspect about which concern has been expressed from time to time is about foreign publications in this country. I would like to say something about the anxiety that has been expressed by hon. Members about the publication of various journals by foreign missions. In India, an exhaustive study on the subject has been undertaken by the Registrar of Newspapers. May I, at this stage, point out that out of 76 countries represented in India through Diplomatic Missions, twenty four brought out 103 periodicals in 1968 with a total circulation of 12,71,295. A large chunk that is, 11,65,775 is shared by the U. S. S. R. and U. S. Embassies. The U. S. S. R. had 46 journals with a circulation of 6,51,994 while fourteen publications of the U. S. A. had a circulation of 5,13,781. From 1963 to 1967, the circulation of Foreign Mission journals increased by 39.1%. During 1967, the circulation increa-

sed by 5.6%, that is, that went upto 67,189 as compared to 1967.

Another aspect which may be kept in mind is that the total circulation of foreign Mission publications which stood at 12,04,106 in 1966-67 is 5.5% in volume compared to total circulation of the entire national press during that year. Further studies continue and as I collected further information I shall be able to inform the House.

**श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) :** यू० एस० एस० द्वारा और यू० एस० ए० में अपने कितने पीरियोडिक्स निकलते हैं, कितना सर्कुलेशन है इसकी भी क्या कोई स्टडी की गई है ?

**श्री महाराजसिंह भारती (मेरठ) :** फ्री कितने सर्कुलेशन में है ?

**SHRI I. K. GUJRAL :** Since this Ministry does not look after the foreign publicity of India, it is difficult for me to give the figure. A study is being undertaken on this subject. Since some information has been received, that will be available. Further studies, as I said already, still continue. As studies will be completed, we shall be able to offer information. Hon. Members will appreciate that these studies involve considerable labour and information has to be collected from various sources where it may be readily available. We are keen that these studies should continue and we should be able to know how foreign influence is brought to bear in this country and how we can meet it.

I had mentioned about the small and medium newspapers last time when the question of *Loksatta* and *Jansatta* came up before the house. Some doubts were expressed as to whether Government should give direct aid. At that stage it was felt that we should take the opinion of the Press Council on this issue and the matter was referred to the Press Council which has sent its report. Government are studying it but have not come to any conclusions and as soon as some decision is reached, I shall state definitely what the position is.

I think Shri Sambhali and others referred to the role of the communal press. Any communal preaching by any press does cause strain to national integration and it has to be condemned by strong public opinion—not so much by Government action. I think all parties sitting here owe it to the nation to create an atmosphere in the country that only such papers that are good for the whole nation may flourish.

An hon. Member from Kerala referred to the report of the Diwakar Committee. By and large almost all the recommendations of that Committee have been implemented. One recommendation of that Committee comes to my mind and it is under consideration. It was suggested that for the benefit of smaller newspapers which are not in a position to contribute to news agencies, we should be able to give out a bulletin on the radio at dictation speed so that they are in a position to get Central news and publish it in their newspapers. After Examination if we find it possible, we might undertake it in the near future.

That is as far as the problems of the Press were concerned. About films, we feel that the film industry has a very vital role to play in the building of the nation. We have to realise the potentiality of the films. Unfortunately we have not been able to make full use of the medium. If we can do so both in the sphere of artistic expression and for other national purposes also I am sure a great deal of benefit will occur. Government have concentrated their energy on documentaries and small short films and those efforts have generally been well received. Last year eleven documentaries produced by the Films Division and its collaborators—some people who are making such films—received national awards. Generally speaking, wherever these films had been shown they had received appreciation. This year we are concentrating more on different types of films—motivational films. We try to associate scientists in this process. For instance, we want to make more and more agriculture oriented films so that with the help of those who are doing research work on agriculture, we can make more films

which would benefit the rural farmers. Last year we made some films and we hope to make about forty films so that there can be more and more motivational films. Now we are associating scientists and professors and those people who are actually associated with agricultural research and agricultural teaching.

श्री महाराज सिंह भारती : माप के एपीकल्चर फिल्मस की स्ट्रिक्ट लिखने वाले ठीक नहीं हैं ।  
15.25 hrs.

[MR. SPEAKER in the chair]

SHRI I. K. GUJRAL : Also, in the same sphere, I would like to say that we are concentrating more and more on films in the educational sphere, in the health sphere and in the sphere of family planning. I would also like to say that in this country, unfortunately, film, as I said, has not been made much use of, and we are, therefore, concentrating on creating such opportunities like encouraging film societies and Sunday cinema movement for the youth so that films can be made more use of. In Delhi and elsewhere, we are now undertaking the study : in the schools where projectors and halls are available, we should be able to appoint film officers who can take charge of special films for the schools so that these projectors can be made better use of : also, in the premises of those schools and in the college halls, we should be able to build a youth cinema movement for Sundays to make cheaper and good films available to young men of this country, so that they can see the films more conveniently than at the moment.

We are also this year going to have an international film festival in November and December and I think this festival will go a long way to create an atmosphere for making better films. Also, as I mentioned once before, we are considering very actively to bring before this House a legislative measure for the setting up of a Film Council, because he feel that a Film Council is very important not only to meet the problems of the films industry

[Shri I. K. Gujral]

but also to create possible opportunities so that better and more purposeful films could be made.

I have almost finished so far as films are concerned, and I would only like to take a few minutes more to say two things; one is about the Publications Division. In the Publications Division, the emphasis this year is to create and generate more and more activity in the regional and national languages and also Hindi. We are going to bring out next week or in ten days' time the Tamil version of *Yojana* magazine and it will be again followed by the Assamese and Bengali version of *Yajana*.

As a result of the recommendations of the National Integration Council, we are actively considering the possibility of publishing the *Indian Digest* in all the Indian languages so that this journal is made available to many in this country to build up popular interest in national integration.

You might recall some years ago we had set up the Indian Institute of Mass Communication. This institute has done a lot of good work in making special studies and imparting specialised education for the experts in mass media. Not only has this done good work, but we are now using the services more and more to undertake impact studies of the various mass media, because it is no use having films and radio only if we do not simultaneously undertake impact studies. With the help of this institute, we are undertaking many studies which are being made much use of.

One point more and I will have done. My friend Shri Inder J. Malhotra had mentioned about the Central Information Services and their conditions. I would only like to say one thing: that the Central Information Service constitute the backbone of this Ministry, and the Central Information Service is manned by persons who by and large are such, whose intelligence, capacity and equipment we very much value and are proud of. If there are any difficulties in their service conditions, we shall definitely

look into them with a great deal of care and also with a great deal of sympathy.

But this I can also say not only about the Central Information Services but about all the media cadres. And I think the type of jobs which the media cadres in this country have to undertake is very difficult, particularly because of the situation and circumstances which sometimes do come up before us.

Before I finish, I would only like to mention one point to which my friend Shri Ishaq Sambhali has drawn our attention, and that is regarding our talks with the Minister of Information of West Bengal. Day before yesterday, both my senior colleague and myself had talks with Mr. Bhattacharya and when we met and when we parted, we had the impression that we met in the most cordial atmosphere, and in the discussions that we had, we were always motivated by the basic theme that we should create an understanding between the functioning of the West Bengal Publicity Department and that of this Ministry, which can help in national integration.

SHRI S. M. BANERJEE : What about the advisory committee of AIR ?

SHRI I. K. GUJRAL : Every advisory committee of All India Radio has to have an all-India pattern. It is not possible for us to have one pattern for Bengal, another for Kerala, another for Punjab, etc. Last year, Mr. K. K. Shah the former Minister, undertook a rather arduous task. He discussed it with almost all the Information Ministers and Chief Ministers of the various States and evolved a pattern for the advisory committee, which was very different from the previous committees. For the first time it was accepted that the Information Minister of the State should be the Chairman and other members will consist of M. L. As, M. Ps. and about 12 experts in various activities like science, culture, art, etc. These committees have to be set up by the Government of India because whether we like it or not, All India Radio and the Information and Broadcasting Ministry is being run by the Government of India. Therefore, the

pattern which was largely acceptable has been evolved for the whole country. We pointed out to Mr. Bhattacharya that this is the pattern for the whole of India and we got the impression that he agreed to it. I only say, let him try it. He has not tried it. After seeing the results of its working, it can be re-examined. For the time being, this is the pattern for the whole country.

**श्री जाजं फरनेहीज :** सांग एंड ड्रामा डिवीजन के बारे में भी कुछ बताइये ।

**SHRI I. K. GUJRAL :** The Song and Drama Division came into existence only a few years ago. It has expanded as a result of its various activities. Obviously, where so many persons work together some tensions do arise and they can be looked into and resolved. I can assure the House that the purpose of the Song and Drama Division is to create a healthy atmosphere, where all the artistes can work in close collaboration. I can say to the credit of the Song and Drama Division that the latest performance they have put up in Jallianwalabagh in Amritsar has been very well received. Mr. George Fernandes brought to my notice some difficulties of some people. I am giving attention to them.

**MR. SPEAKER :** Hon. Members may now move their cut motions.

**SHRI PRAKASH VIR SHASTRI :** I beg to move :

That the demand under the head 'Broadcasting' be reduced by Rs. 100.

[Disregard of Hindi in the national programmes broadcast from A. I. R. (6)]

That the demand under the head 'Broadcasting' be reduced by Rs. 100.

[Lack of co-ordination in whatever Hindi programmes broadcast. (7)]

That the demand under the head

'Broadcasting' be reduced by Rs. 100.

[Inviting some particular individuals only for the programmes broadcast from the Delhi Station of A. I. R. (8)]

That the demand under the head 'Broadcasting' be reduced by Rs. 100.

[Failure to set up powerful transmitters so far. (9)]

That the demand under the head 'Broadcasting' be reduced by Rs. 100.

[Giving special encouragement to some particular ideologies in the news broadcasts. (10)]

That the demand under the head 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Information and Broadcasting' be reduced by Rs. 100.

[Heavy expenditure being incurred on personal transportation of employees on Delhi Station of A. I. R. (15)]

That the demand under the head 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Information and Broadcasting' be reduced by Rs. 100.

[Lack of definite policy regarding promotion of employees. (16)]

**SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH (Bhind) :** I beg to move :

That the demand under the head 'Ministry of Information & Broadcasting' be reduced by Rs. 100.

[Failure to create a separate subdivision for broadcast in Hindi. (19)]

That the demand under the head 'Ministry of Information & Broadcasting' be reduced by Rs. 100.

[Retention of anti-Indian elements in the Communication Service. (20)]

**SHRI OM PRAKASH TYAGI (Moradabad) :** I beg to move :

That the demand under the head

[Shri Om Prakash Tyagi]

Ministry of Information and Broadcasting  
be reduced by Rs. 100.

[Partiality shown by All India  
Radio in selection of birth anniversaries  
of National Leaders. (22)]

That the demand under the head  
Ministry of Information and Broadcasting  
be reduced by Rs. 100.

[Failure to set up powerful transmitting  
Centre for the benefit of  
Indians living abroad. (23)]

That the demand under the head  
Ministry of Information and Broadcasting  
be reduced by Rs. 100.

[Failure to stop the favouritism  
in All India Radio in regard to broadcast  
of news about various political  
parties. (24)]

That the demand under the head  
Ministry of Information and Broadcasting  
be reduced by Rs. 100.

[Failure to lay down any definite  
policy in regard to review of parliamentary  
proceedings instead of leaving  
it at the mercy of reporters. (25)]

That the demand under the head  
Ministry of Information and Broadcasting  
be reduced by Rs. 100.

[Failure to check the favouritism  
prevalent in All India Radio in  
regard to Hindi-English programmes (26)]

That the demand under the head  
Ministry of Information and Broadcasting  
be reduced by Rs. 100.

[Neglect in preaching Vedas over  
All India Radio. (27)]

SHRI YASHWANT SINGH KUSH-  
WAH : I beg to move :

That the demand under the head  
Broadcasting be reduced by Rs. 100.

[Failure to give adequate time and  
importance to Hindi broadcasts.  
(28)]

That the demand under the head  
Broadcasting be reduced by Rs. 100.

[Discriminatory policy towards the  
Hindi speakers while inviting them  
for giving a talk. (29)]

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I  
beg to move :

That the demand under the head  
Broadcasting be reduced by Rs. 100.

[Use of the words "All India  
Radio" in place of 'Akashvani' in the  
Urdu Programme of All India Radio.  
(34)]

That the demand under the head  
Broadcasting be reduced by Rs. 100.

[Use of the words 'Kashmir Radio'  
in place of 'Akashvani' from the  
Kashmir Broadcasting Station. (35)]

That the demand under the head  
Broadcasting be reduced by Rs. 100.

[Failure to set up radio stations  
in each linguistic and territorial unit.  
(36)]

That the demand under the head  
Broadcasting be reduced by Rs. 100.

[Failure to set up radio stations  
keeping in view the peculiar location  
of Indian Islands. (37)]

SHRI J. SHINKRE (Panjim) : I beg  
to move :

That the demand under the head  
Ministry of Information and Broadcasting  
be reduced to Re. 1.

[Need to allot more Government  
advertisements to Hindi newspapers  
in Western and Southern India and  
to Southern language papers in Eastern  
and Northern India. (40)]

That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced to Re. 1.

[Need to form a Committee of the parliamentarians belonging to the "Fourth Estate" to do a comprehensive study regarding the establishment of a corporation in Public Sector which can take the task of publishing dailies in all the States' capitals. (41)]

That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced to Re. 1.

[Need to provide long term Government loans to small language papers at low rates. (42)]

That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced to Re. 1.

[Need to provide, on credit, newsprint to small language newspapers, through newsprint cells. (43)].

That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced to Re. 1.

[Need to lay down definite policy to protect the small newspapers and particularly district newspapers against the competition from monopolist chain papers. (44)]

That the demand under the head Minister of Information and Broadcasting be reduced to Re. 1.

Need to lay down definite policy regarding allotment of advertisement to newspapers. (45)]

That the demand under the head Minister of Information and Broadcasting be reduced by Rs. 100.

Discrimination in allotment of programmes to the artists and scholars in A. I. R. Panaji, Goa. (47)].

That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced by Rs. 100.

[Need to make a thorough inquiry about the non-selection of Parliament Members and Goa Legislative assembly Members for broadcast through A.I.R. Panaji (48)].

That the demand under the head Minister of Information and Broadcasting be reduced by Rs. 100.

[Failure to issue commemorating stamps in the memory of Shri Dada Rane and Mr. Francisco Luis Gomes at the time of their birth centenary. (49)]

"That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced by Rs. 100."

Failure to issue a series of the stamps with the gravure of fauna and another one of flora of India. (50)].

That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced by Rs. 100.

Failure of the Government to take due note of the criticism levelled against the partiality of the authorities in A. I. R. Station at Panaji, Goa. [51)].

"That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced by Rs. 100."

[Need to transfer all the present staff of A. I. R., Panaji, Goa, and particularly Goan officers in view of their Partianship approach regarding linguistic controversies viz., Marathi and Konkani. (52)].

"That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced by Rs. 100."

[Need to provide the Radio Station at Panaji-Goa with a powerful transmitter. (53).]

"That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced by Rs. 100."

[Need to revise the decision regarding allotment of Government advertisements to "The Nav Hind



[Shri J. Shinkre]

Times", "Gomantak" and "Rashtra-mat" dailies of Goa belonging to Goan mine-owners, in view of the one sided propoganda carried by them over mining industry. (54)]

"That the demand under the head Broadcasting be reduced Re. 1."

Need to entrust A.I.R. Panaji with the work of broadcasting news and features in Portuguese and Spanish languages. (55)]

"That the demand under the head Broadcasting be reduced to Re. 1.

[Need to provide substantial time to broadcasts in Hindi at A.I.R. Panaji-Goa. (56)]

"That the demand under the head Broadcasting be reduced by Rs. 100."

[Need to allot 75 per cent. of the time to the broadcast in Marathi at A. I. R. Panaji of which the time for relays should not exceed by 25 per cent. (58)]

"That the demand under the head Broadcasting be reduced by Rs. 100."

[Need to give preference to Goan Artists and writers at A.I.R., specially in programmes regarding Goa's political and social life. (59)]

"That the demand under the head Broadcasting be reduced by Rs. 100.

[Need to provide sufficient funds to A.I.R. Panaji, Goa so that station can engage the services of the Goan artists residing outside Goa. (60)]

"That the demand under the head Broadcasting be reduced by Rs. 100."

Need to transform A.I.R. Panaji station into a first-class station as Goa is known all over India as a Home of Fine Arts. (61)]

MR. SPEAKER : The cut motions are also before the House.

श्री एस० एस० जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जो मांगें हैं उनको लेकर मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो मुझे यह कहना चाहिए कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण महकमा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस महकमे की उपेक्षा हो रही है। इस पर चर्चा करने के लिए जितना समय निर्धारित हुआ है, वह इतना कम है कि कोई चीज अगर कहनी हो तो चार छः मिनट में नहीं कही जा सकती है। मेरी दृष्टि से यह हमारे मुल्क की नीति हम निर्धारित करते हैं, उसको सामने रखकर लोगों का मानस बनाना और लोगों को उसको समझाना एक बड़ा काम इस मन्त्रालय का है। लेकिन उसके वास्ते जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दिया जा रहा है। उसकी उपेक्षा हो रही है। मैं देखता हूँ कि इस महकमे में जो मिनिस्टर आता है उसको बार बार बदल दिया जाता है। क्यों बदल दिया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

एक माननीय सदस्य : इनफर्मेशन ली और चले गये।

श्री एस० एम० जोशी : मैं यह नहीं कहूंगा कि इस महकमे के द्वारा हर एक चीज खराब हो रही है। कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। पहले मन्त्री श्री के० के० शाह ने बहुत अच्छा काम किया था। जब वह सेंटल हो गए, सेंट हो गए तो उनको वापिस बुला लिया गया और दूसरे को यहाँ भेज दिया गया.....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जो आए हैं, पुराने हैं, नए नहीं हैं।

श्री एस० एम० जोशी : मैं मानता हूँ कि वह अनुभवही हैं।

यह महकमा बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सी बातें हैं। सब को एक जगह

करना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है। पहली बात तो यह है कि महकमा दूसरे महकमों की तरह नहीं है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वैसे महकमा यह नहीं है। यह एक एकसपट महकमा है। यहाँ एकसपट काम को करने के लिए अगर हम जो हमेशा तौर तरीके अपनाते हैं ब्यूरोक्रेसी के, वे ही अपनायेंगे तो हमारा काम कार्यक्षमता के साथ नहीं चल सकेगा। चन्दा कमेटी ने सिफारिश की थी कि इसको एक कारपोरेशन का रूप दे दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम-अज-कम इसको आपको एक स्वायत्त संस्था के रूप में तो रखना चाहिए। इसके बारे में अभी तक हकूमत की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है।

जो प्रतिवेदन आपने दिया है उसको मैंने देखा है। उसमें आपने मजदूरों के बारे में सरसरी तौर पर कुछ बता दिया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मजदूर हैं, जो स्ट्राफ्फ आर्टिस्ट हैं, जो ट्रांसमिशन एग्जिक्यूटिव हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी काफी शिकायतें हैं। मसानी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। उस पर भी अभी पूरा अम्ल नहीं हुआ है। मैं यह भी देख रहा हूँ कि जो रिक्लूटमेंट होता है, वह चाहे एक मुश्किल काम है, लेकिन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ। विदेशी प्रसारणों के लिए आप विदेश प्रसारण सेवा में दूसरे देशों से जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको रिक्लूट करते हैं। ट्रांसलेशन करने के लिए, भाषण करने के काम के लिए आप इस्तहारात देकर लोगों को बुलाते हैं। अरबी जानने वालों को, फारसी जानने वालों को अफगानिस्तान वगैरह से आप लोगों को बुलाते हैं। मुझे जहाँ तक पता है—अगर मेरी जानकारी गलत हो तो मुझे इसमें खुशी होगी—उनको हम आने-जाने का किराया देते हैं, उनके साथ पाँच-पाँच साल का कान्ट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वे यहाँ टिक नहीं

पाते हैं। इसका कारण मुझे यह बताया गया है कि यहाँ भी गुटबन्दियाँ होती हैं और बाहर के लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है और इसका नतीजा होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। चार तो मुझे पता चला है कि चले गये हैं और पाँचवा भी जाने के लिए तैयार हो रहा है। किस तरह से इस संगठन का संचालन हो रहा है, इसको आपको देखना होगा। जैसे दूसरे महकमों में रिक्लूटमेंट होता है, वैसे ही यहाँ भी होता रहेगा तो यह काम ठीक तरह से चल नहीं सकेगा। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि चन्दा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में आप कुछ न कुछ फैसला जल्द से जल्द करें।

हम देश में प्लानिंग कर रहे हैं, सामाजिक तथा आर्थिक प्लानिंग कर रहे हैं, एक नए प्रकार से समाज की रचना करने की कोशिश कर रहे हैं उस अवस्था में हमारी जो नीति है उसको ठीक तरह से लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है। एक मित्र ने मुझे बताया है कि इसका उपयोग ठीक नहीं होता है। बंगाल का उदाहरण देकर मैं आपको बताना हूँ। वहाँ कुछ ऐसा भाषण हुआ जिससे केन्द्र और राज्य के ताल्लुकात खराब हो सकते थे। तब यह बताया गया कि दूसरे रोज दूसरा भाषण उलटी दिशा में दिया गया। इस तरह से कैसे काम होगा लोगों को पता कैसे चलेगा? यह बहुत ही महत्व की बात है। हमारी नीति पहले निर्धारित होनी चाहिए और उस नीति के अनुसार हमारा प्रचार कार्य चलना चाहिए, लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिये। केवल प्रोपेगंडा ही इससे नहीं होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र आज कसौटी पर है। बड़े बड़े नेता जब थे, महात्मा गाँधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार पटेल थे, तब बात भ्रमण थी। कोई भी तंत्र हम तब चला सकते थे। लोकतंत्र के झलावा जो भी तंत्र हो सकता था उसको भी चला

[श्री एस० एम० जोशी]

सकते थे। लेकिन अब उनकी तुलना में छोटे भ्रादमी हमारे बीच में हैं। उतने बड़े भ्रादमी अब नहीं हैं। इसको हमें मान लेना चाहिए। इन्हीं लोगों से हमको काम चलाना है। मैं देखता हूँ कि परचों में तथा यहां भी व्यक्ति विशेषों को बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है।

बड़े भ्रादमी पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता। उनको ज्यादा पब्लिसिटी देने से कोई बड़े भ्रादमी नहीं बनते हैं। जो चीज हमको करनी है वह यह करनी चाहिए कि हमारी नीति क्या है, सिद्धांत क्या है, लोगों को कैसे समझाना है और उनको कैसा बनाना है, इसके बारे में बताया जाय। लेकिन यह काम यहाँ होता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। इस देश के बारे में मालूमात भी यह ठीक तरह से नहीं देते हैं। अध्यक्ष जी मैं आपको आपकी अपनी स्टेट के बारे में उदाहरण दे सकता हूँ। पिछले महीने में 14-15 तारीख को मैं हैदराबाद गया था, वहाँ की जो हालत देखी और यहां 16 तारीख को वह जो बिल आ गया एक्सटेंशन वाला उसके अन्दर उसकी चर्चा सुनने का मुझे मौका मिला। मैंने घर जाकर रेडियो लगाकर देखा कि रेडियो वाले क्या दे रहे हैं लेकिन उसमें कुछ भी नहीं बताया जब कि चार घंटे यहाँ बहस हुई थी। तीसरे रोज जब प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा तो भट्ट वह आ गया। लोगों का मन ही जब तैयार नहीं है और ऐन वक्त पर आप कुछ कह देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इस तरह से अगर चलेगा तो जिसके लिए हम यह पैसा खर्च करते हैं, उसका पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा।

एक्सटर्नल सविसेज के बारे में, विदेश की जो सेवा है उसके बारे में, मुझे कुछ थोड़ा सा कहना है। इसमें यह बताया गया है विदेश प्रसारण सेवा के अन्तर्गत 21 भाषाओं में जिनमें 6 भारतीय भाषाएं हैं, वगैरह-वगैरह और एक बताया है दक्षिण और

दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में—सिंहली—30 मिनट, बर्मी-15 मिनट और थाई वगैरह का इसी तरह से दिया है। चीनी भाषा का प्रसारण 45 मिनट के लिए है। यानी चीनी भाषा में जो प्रसारण होता है वह सिर्फ 45 मिनट होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि चीन में कोई एक ही भाषा तो नहीं चलती है, उसमें मैडेरिन, कन्टेनीज आदि कई भाषाएं चलती हैं और ईस्ट एशिया में बहुत सारे करोड़ों लोग जो रहते हैं वह सिर्फ एक भाषा ही नहीं बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसकी कोई एनालिसिस तो आप बतायें कि क्या खबर देते हैं वहां के लोगों को, क्या सुनाते हैं। जैसे कश्मीर के बारे में कहा गया है, जम्मू के बारे में, मैं कहूंगा कि हमारा ईस्टर्न बोर्ड भी बहुत महत्व रखता है और वहां जो हम लोग प्रचार करते हैं उसका असर कुछ ठीक तरह से नेफा तक नहीं पहुंचता है। हमको खासतौर से ध्यान में रखना चाहिए चीन और पाकिस्तान को। यह हमारे पड़ोसी हैं। अगर हमारे ऊपर प्रेम करते हैं तो हम प्रेम का अतिसाद दे सकते हैं और अगर दुश्मनी करते हैं तो हमें भी कस कर कुछ कहना चाहिए और उसके लिए हमारे पास साधन होना चाहिए जो कि नहीं है, तो कैसे करेंगे। मैंने सुना है कि चीनी भाषा में जो प्रसार होता है उसको भी कुछ कम किया है, इसी तरह से इन्डोनेशियन लैंग्वेज में जो प्रसार होता है उसको कम करके अंग्रेजी में बढ़ा दिया गया है। यह चीज गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो यह देखने की बात है। जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में प्रसारण का काम कर रहे हैं, इसे और अच्छे ढंग से, और कार्य-क्षमता से और अच्छे साधन लगा कर, और ज्यादा वक्त देकर करना चाहिए यह मेरा सुझाव है।

एक बात और कहना चाहता हूँ। यहां गठबन्धन हो रहा है, कितने आपके टुकड़े-टुकड़े एक-एक विभाग हैं, उसमें फील्ड पब्लिसिटी एक है, लेकिन उसके लिए मैंने

मुना कि जो हमारे प्रिंसिपल इन्फार्मेशन आफिसर हैं वह अपने दूसरे आफसरों के साथ बोर्डर एरिया पर चले गए देखने के लिए कि फील्ड पब्लिसिटी का काम कैसे हो रहा है। वहाँ भी एक अपना विभाग है। तीन-चार आदमियों को लेकर चले गए और रोड से नहीं गए, शिलांग से हेलीकोप्टर से गए। वहाँ जाकर क्या इन्स्पेक्शन किया? यह जो बनाया है यह क्या इधर उधर सैर करने के लिए बनाया है? यह जो काम चल रहा है, यह कैसा चल रहा है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ।

एक बात और मुझे कहनी है कि यहाँ हिन्दी में जो काम करते हैं या जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, चाहे दूसरी भाषाएं भी क्यों न हों, उनको अनिवार्य है कि अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान उनके लिए अनिवार्य है। मगर जो लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं उनको हिन्दी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। मैं यह नहीं कहूंगा कि जबर्दस्ती उनको सिखाइए। अगर नहीं सीखना चाहते हिन्दी तो मैं तो नहीं कहूंगा कि सीखना ही चाहिए क्योंकि उससे भगड़े होंगे। मगर जो हिन्दी भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है कम से कम दो भाषाएं जानने वाला जो कोई भी आदमी वहाँ पर है, आफसर है उसका दर्जा सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले से कम होना चाहिए? यहाँ पर तो उसको दूसरे दर्ज में रखा है और जो सिर्फ अंग्रेजी जानता है उसको नम्बर एक रखा है यह चीज अच्छी नहीं है। इसको दूर करना चाहिए।

आखीर में मैं मजदूरों के बारे में एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूँ यह जो मर्जर का मामला है डीअरनेस एलावेंस का पे के साथ यहाँ एक जगह बताया गया है कि उन्हें दूसरे पूरक भत्ते, महंगाई भत्ते सब मिलते हैं और यह भी तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं, यह भी गवर्नमेंट का एक हुकमा है, उनका भी मर्जर क्यों नहीं किया

गया है, यह मैं जानना चाहता हूँ। मसानी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? ट्रांसमीशन एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या हो रहा है इसे भी बताएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

MR. SPEAKER : Shri Samar Guha.

श्री प्रेमचन्द वर्मा : मेरी अर्ज यह है कि तीन घंटे आपने टाइम दिया है। उसमें से डेढ़ घंटे कांग्रेस पार्टी को मिले जिसमें से एक घंटा मिनिस्टर ले जायेंगे...

अध्यक्ष महोदय : तो मैं क्या करूँ ?

श्री प्रेमचन्द वर्मा : वह तो ठीक है लेकिन हमें भी टाइम मिलना चाहिए। आप टाइम बढ़ा दीजिए।

SHRI RANDHIR SINGH : (Roh-tak) : This is something very reasonable. We have nothing to say against the Ministers. Kindly take into consideration a very genuine request.

MR. SPEAKER : As to what Shastriji said, from what I see here only two people have spoken from the Congress Party Shri Tulshidas Jadhav and Shri Nardeo Snatak.

SHRI PRAKASH VIR SHATRI : Shri Inder Jit Malhotra also.

MR. SPEAKER : All right; three have spoken from the Congress side. I am exhausting the list of Opposition speakers by giving them 5-6 minutes each. If two Ministers take one hour, they take the Congress time; I cannot give the Opposition time to the Ministers.

SHRI RANDHIR SINGH : Our time may be reduced but we may be given a chance.

श्री प्रेमचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज है कि इसमें टाइम आप बढ़ा दीजिए।

MR. SPEAKER : All right. Later on let us see.

SHRI S. M. BANERJEE : I have only one suggestion. Shri Verma wants to speak and Chaudhuri Randhir Singh wants to speak.

MR. SPEAKER : What about Seth Achal Singh ? His name is first now.

SHRI S. M. BANERJEE : If they are not allowed time to speak, at least it should be announced by All India Radio that they were not allowed.

SHRI RANDHIR SINGH : That is too much.

MR. SPEAKER : The Minister must take care to see to that.

SHRI RANDHIR SINGH : We may be allowed to put questions in case we are denied time.

MR. SPEAKER : All right; I will do that.

श्री प्रेम चंद वर्मा : प्रत्यक्ष महोदय, क्वेश्चन की बात नहीं है। मेरा सबजेक्ट है यह। मुझे तो टाइम चाहिए इसके लिए। इसमें भी टाइम घाप बढ़ाए। ऐश्रीकल्चर में घापने बढ़ा दिया तो इसमें भी बढ़ाए और मुझे टाइम दीजिए।

MR. SPEAKER : How can I help him ? Before his name there are three other names. Let us not lose time now. Shri Samar Guha.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : Mr. Speaker, Sir, I want to begin with a word of thanks to the Minister of Information and Broadcasting, particularly to Shri K. K. Shah, the former minister, because he did a service by bringing out in 14 Indian languages the brochure on Netaji and Azad Hind Fauj on the occasion of the Azad Hind Fauj Silver Jubilee celebrations.

He also arranged for a special programme on that occasion. I mention this because I had information from very res-

possible officers of the All India Radio that for the last 22 years the instructions were there with the officers not to include any speech or song or any item about Netaji Subhash Chandra Bose in the programmes. But it is good that the Government has changed its attitude. I request the present Minister and also the Minister of State to follow the line that has been accepted by their predecessor.

I have also got information that with the Simla monitoring office there are many speeches of Netaji Subhash Chandra Bose made during the time of Azad Hind Fauj struggle. They were going to destroy them last April but some officer intervened. I am told that these documents are still there. I would request the Government to collect and preserve those speeches of Netaji and, if possible, publish them.

During the time of Sardar Patel, a documentary film on Netaji, that was based on the documents collected from South-East Asia and Japan, was shown all over the country. That is the only documentary film on Netaji. But, unfortunately, that is missing. I would request the Government to see whether that film—there is no other copy—can be restored. I do not know where it is missing.

I would also request the Government to have a documentary film on Netaji and on Azad Hind struggle in South-East Asia and Germany. There are still many important documents on Netaji and Azad Hind struggle lying in the Archives with different Governments, like, Japan, Germany, etc. I would request the Government to send a team and collect the documents and, possibly, publish them through their Publication Department.

Sir, the Ministry of Information and Broadcasting commands the most powerful media to influence public opinion in our country. But, unfortunately, it is not being properly used. The words used just now by Mr. Gujral were that their main objective is to build the nation for a constructive purpose. But the films, the radio, the Publications and other Departments are lacking in positive perspective, effective organisation and also the drive that is necessary to create a sense in the

minds of the people that they must build a new nation with a new perspective in our modern era. That is lacking.

There are many aspects to deal with. I will not be able to deal with all of them because the time at my disposal is limited. I would draw the attention of the Government to one aspect. It is the opinion of all the psychologists that at least 50 per cent of the audio-visual effect on the young mind is retained. The most powerful impact is that of cinema and the radio. One of the reasons of the students unrest and other mass unrest that we are witnessing today is, I should say, the disastrous effect of the vulgar-type Western films and also of the Bombay films and the cinema posters.

I have been a member of the Central Educational Advisory Board and I have seen, Vice-Chancellor after Vice-Chancellor, professor after professor, expressing alarm about the effect of the films and the cinema posters on the mind of the youth. I think, the Government of India, taking in view the anxiety expressed, have framed a questionnaire about the procedure of censorship. That has been circulated to Members of Parliament also for opinion. I found that the whole objective of this questionnaire is to introduce an element of emotional realism in the films and the radio. I do not know what is meant by realism. I am sorry to say that if I quote the sentences and words from the questionnaire, the Members will feel ashamed. Realism in reality is animalism of the jungle age. Culture means expansion of mental horizon; and culture further means elevation of moral, aesthetic and spiritual tastes. Unless the Government have a very strict censorship of the films, they will spell disaster in the minds of the youths of our country.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : He is only philosophising ; he is out of touch with reality.

SHRI SAMAR GUHA : In the name of introducing emotional element, they are just giving, I should say, encouragement to erotic aspects and others several urges. I know, everybody of us is an animal in

some sense but that animality should not be encouraged.

SHRI I. K. GUJRAL : It is a questionnaire only.

SHRI SAMAR GUHA : If you formulate a certain questionnaire in a way that you wanted to drive the person to answer in a certain pattern it clearly reflects then the mind of the person who has framed the questionnaire.

SHRI I. K. GUJRAL : Some Members of Parliament are on the Committee.

SHRI SAMAR GUHA : What is the production of Western aspects of vulgarity ? They are Hippies, Gippies and Beatles.

We do not want to encourage growth of hippies and Gippies in our country. In this aspect I would request the Government to institute an inquiry to see that children's films and the radio programme are effectively adopted to influence the minds of our children, the students and the youth in a particular way, in a way for building our nation with a constructive outlook, with a positive outlook of creativity and national cultural heritage.

I would, in this context, say that there is an association called the Children's Film Society. I am really alarmed about the report of its activities. This has been sent to me by no less a person than Dr. Kunzru. Government has under-taken, in collaboration with Russia, a film for children called 'Black Mountain'. Such scripts are usually passed through the Education Ministry, the Ministry of Information and Broadcasting and the External Affairs Ministry. I have been told that this script has not been approved by any of these Ministries. Government is offering Rs. 2 lakhs for the production of 'Black Mountain' film for children. The entire script goes to show that India is still a land of Maharajas, elephants and tigers and poverty in villages and among the Mahuts ; cruelty and bloodshedding go hand in hand. If such films are shown all over the world, I think, those people

[Shri Samar Guha]

will think that the image that was drawn by Mr. Kipling and Miss Mayo is still existing in India. This 'Black Mountain' will be a black spot in our children's films. I would request the Government to scrap this script.

I would also like to say that 50 per cent of the amount of Rs. 35 lakhs which have been sanctioned for the Children's Film Society of Bombay, are being used for administrative purposes, and a number of irregularities have also crept in—misappropriation of money and all that. There is one Mr. Jain who misappropriated many projectors worth about Rs. 20,000 given by Russia; but I do not know why no steps have been taken against him.

I would like to draw the attention of the House to one or two more points. I have gone through the report of the Ministry of Information and Broadcasting. I am constrained to say that the attention of the publication and the advertisement departments has been equitably given to all Indian languages. I would quote a few figures. Rs. 20 lakhs have been spent on advertisement out of which only Rs. 13 lakhs have been spent for the 13 Indian languages while Rs. 6.4 lakhs have been spent for Hindi only. After April 1968, 96 publications have been brought out by the Department, of which 38 are in Hindi and only 58 in the other 13 Indian languages. For family planning Rs. 4.6 crores have been spent and I have been told that such advertisements have not been distributed all over the country on population basis.

About Vividh Bharati programme, complaints have been raised from many quarters of our country against over-emphasis on Hindi songs and Hindi programmes and about not paying attention to programmes covering other languages.

MR. SPEAKER : He may conclude.

SHRI SAMAR GUHA : I will just finish.

Our broadcast, particularly in East Bengal, is very important. I am one of the regular listeners of the programme, and I would say that the programme needs overhauling and guidance. I would request the Government to appoint a com-

mittee of experts so that they can guide the programme in a purposive and also effective way.

श्री प्रेमचन्द बर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस माँग पर बोलने का मौका दिया है, मैं मिनिस्ट्री आफ इन्फॉर्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग की बजट माँगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मंत्रालय को जिस रास्ते पर पिछले साल श्री के० के० शाह ने डाला और इसमें जो कुछ परिवर्तन उन्होंने किये—वे आज इसके इन्चार्ज नहीं हैं, लेकिन मैं उनको मुबारकवाद देता हूँ कि उन्होंने सही ढंग से इस मिनिस्ट्री को चलाने की कोशिश की थी। अब मैं समझता हूँ कि माननीय श्री सत्यनारायण सिंह और श्री गुजराल जी भी उन्हीं लाइनों पर, उसी नीति पर आगे चलाने की कोशिश करेंगे। मंत्रालय ने बहुत अच्छा और तसल्लीबक्शा काम किया है लेकर अगर हम यह कहें कि सभी कुछ ठीक है तो वह बात गलत होगी। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मंत्रालय की यह रिपोर्ट है। मैं इसका दोष मंत्री महोदय को नहीं देता क्योंकि यह रिपोर्ट उनके आने से पहले की तैयार की हुई है। इस रिपोर्ट के पेज 149 पर एक टोटल में 20,000 का फर्क है। इसमें इन्होंने बताया है कि पब्लिसिटी रिलीजेज कितनी की हैं। ये कहते हैं कि 45,555 पब्लिसिटी रिलीजेज की हैं जिसमें अंग्रेजी और भारतीय सभी भाषायें शामिल हैं लेकिन एकचुबली इसका टोटल आता है 65,555। इसमें बीस हजार का फर्क है। मैं समझता हूँ यह बहुत गलत बात है। सदन के सामने जो भी चीज पेश की जाये वह सही और दुरुस्त होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई गलत-फहमी पैदा न हो।

16 hrs.

एक बात मुझे पब्लिकेशन्स के बारे में कहनी है। बहुत सारी पब्लिकेशन्स रद्दी

की हैसियत में जाती हैं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है :

“The departments concerned do not give adequate publicity regarding the availability of publications.”

फिर प्रागे कहते हैं :

“The physical verification of the stock of publications and the reconciliation between the quantity ledgers and the price ledgers are not done regularly.”

इससे साफ जाहिर होता है कि इनमें डुप्लिकेशन होता है। पब्लिकेशन्स बिकती भी नहीं हैं और वे रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि पब्लिकेशन्स के बारे में देखा जाये कि उन पर कितना खर्चा आता है। जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में उसमें इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने मंत्रालय के बारे में इस बात में ध्यान दें और देखें कि क्या मामला है।

एक जगह पर यह बताया गया है कि न्यूजपेपर एजेन्सीज को पी० टी० आई०, यू० एन० आई० को 65 लाख रुपया लोन दिया गया है। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, उनको मदद देनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपस में डिस्क्रिमिनेशन न हो। अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे और सारे केसेज देखेंगे तो मालूम होगा कि उसमें थोड़ा-बहुत फर्क है। इसके भलावा हम जो मदद करते हैं उसमें राष्ट्रीय पालिसी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

एडवर्टाइजमेंट के सम्बन्ध में जो आप बजट बनाते हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 65-66 66-67 और 67-68 के जो आपने बजट बनाये थे उसमें से कितना खर्च

हुआ और कितना बचा। इसके फीगर्स मन्त्री महोदय देने की कृपा करेंगे। इसके साथ ही मुझे यह कहना है कि भ्रखबारों के बारे में आपने बहुत कोशिश की है, पिछले दस महीने में आपने कोशिश की है लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। खास तौर पर जो छोटे भ्रखबार हैं जोकि 8 हजार से अधिक हैं उनमें से बहुत सारे तो बन्द होते जा रहे हैं। उनकी कीमत दस-बारह पैसे की ही है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस बारे में यहां पर यकीन दिलायें कि वे पूरी कोशिश करेंगे। उनकी हमदर्दी हमारे साथ है, गुजराल साहब की भी हमारे साथ हमदर्दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के अन्दर ही, जो पुरानी कोशिश रही है उसको बहाल करेंगे क्योंकि उसके बिना, खास तौर पर जो छोटे पेपर्स हैं वे चल नहीं सकते हैं।

इसके भलावा न्यूज ब्यूरो, रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स और प्राल इण्डिया रेडियो के बारे में भी मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। डी० ए० वी० पी० को नये ढंग से आर्गनाइज करना चाहिए। वहां पर स्टाफ थोड़ा है। उसको सही ढंग से चलाया जाना चाहिए। इन्फार्मेशन ब्यूरो को भी नये ढंग से चलाने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तानी भाषाओं के भ्रखबारों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि आप अंग्रेजी वालों के लिए करते हैं, ध्यान देना होगा।

एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रखबारों पर कन्ट्रोल के लिए आपने रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर्स को बताया है। लेकिन भ्रखबारों के मामले में रजिस्ट्रार की जो सिफारिशें होती हैं उनको दूसरे मंत्रालय टर्न-डाउन कर देते हैं। मशीनरी के बारे में एक कमेटी की बात आई थी। लेकिन फारेन ट्रेड की मिनिस्ट्री है वह इस मंत्रालय से एग्री नहीं करती है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि भ्रखबारों के मामले में मशीनरी, पेपर्स



[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

और दूसरी सहूलियतें देने के लिए जो रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर्स की सिफारिशें होती हैं और उसके ऊपर मंत्री महोदय जो फंसला लेते हैं वह फाइनल होना चाहिए—दूसरी किसी मिनिस्ट्री का उसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। मंत्री महोदय इस मामले को कैबिनेट में ले जायं ताकि यह मिनिस्ट्री प्रेसेज को पूरी तरह से सहयोग दे सके।

अन्त में मुझे यह निवेदन करना है कि इस मंत्रालय में 26 कमेटीज हैं। उनके सम्बन्ध में कुछ भी बताया नहीं गया है। उन पर गौर करने की आवश्यकता है। उन कमेटीज को कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भी कमेटीज बनाई जायं वह एफेक्टिव होनी चाहिए जोकि काम कर सकें। केवल इसलिए कोई कमेटी नहीं बननी चाहिए कि किसी को धौन्लाइज करना है। मुझे उम्मीद है मंत्री महोदय इस सिलसिले में भी गौर करेंगे।

आपने जो मौका मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सबसे पहले मैं मंत्री महोदय का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रोहतक में आल इण्डिया रेडियो स्टेशन खोलने की बात कही है। जो और प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें हरियाणा रागिनी भी शुरू की जाये। दूसरी बात यह है कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में साइंटिस्ट्स के लेक्चर्स सीइस की नयी-नयी वेराइटीज के सम्बन्ध में और दूसरी नयी-नयी बातों के बारे में कराये जायं ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। इसके अलावा जो पंचायती प्रोग्राम है वह खास तौर पर देहात के लिए इनीशिएट किया जाये। वह प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है लेकिन उसका टाइम सिर्फ 40 मिनट का ही है। इसका टाइम एक्सटेण्ड करके कम से कम एक घण्टे का रखें। इसके

अलावा पंच, सरपंच जोकि पंचायतों में काम करते हैं उनको भी इस प्रोग्राम के अन्तर्गत भाषण देने के लिए बुलाया जाये।

इसके अलावा अन्टचेविलिटी की जो बात है, हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज में उसको मिटाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जाये। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत व्याह-शादी, और दूसरी जो बातें हैं उनका प्रचार रेडियो से किया जाये ताकि आजकल शंकराचार्य जो कुछ कर रहे हैं उसका उलटा असर रेडियो के जरिये से डाला जा सके।

औरतों और बच्चों का जो प्रोग्राम है, वह बहुत सुन्दर है लेकिन मैं उसमें थोड़ी-सी तब्दीली चाहूंगा। जो पेपर्स ज्यादा से ज्यादा देहात के किसानों, हरिजनों मजदूरों की बातों को रखते हों उनको स्पेशल इंस्टिट्यूट देना चाहिए, मिसाल के तौर पर आप उनका पोस्टेज कम कर दीजिए। इस तरह के जो छोटे और बड़े पेपर्स हों उनको प्राप स्पेशल इंस्टिट्यूट दें।

इसके अलावा फौजी भाइयों के प्रोग्राम में खास तौर पर देश-भक्ति, भगवान-भक्ति और करेक्टर के गाने और बहादुराना गाने होने चाहिए जिससे कि हमारे बहादुरों में जोश और बहादुरी का जज्बा पैदा हो। फिल्मों के इश्किया गाने शोभा नहीं देते हैं।

हिन्दुस्तान के खिलाफ जो चीन का प्रोग्राम चलता है उसको मैंने सुना है और हिन्दुस्तान की तरफ से जो उसका जवाब है वह भी सुना है लेकिन वह बहुत थोड़ा सा है। हमारा जवाब नहले पर दहला होना चाहिए। ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हर एक लैंग्वेज में आप दें ताकि पता लगे कि हिन्दुस्तानी भी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। जरूरत पड़े तो उर्दू, फ़ारसी में भी होना चाहिये।

आखिरी बात यह है कि लाल किले की जो कहानी चलती है उसमें नेताजी का नाम और हरियारण के जो आई. एन. ए. के जो 40,000 जवान देश के लिए मरे हैं उन्हें उसमें शामिल करें। मोबाइल वान सूचना विभाग के देहातों के नजदीक जायें जिनके जरिये से तस्वीरें आप दिखायें। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातों पर गौर करेंगे।

**श्री अक्षय सिंह (भागरा) :** मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि जो अश्लील फिल्म और गाने होते हैं उसकी वजह से हमारे देश के कर्रक्टर का बड़ा पतन होता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इसको बन्द किया जाए और राष्ट्रीय गान सुनाए जाएं। हम को जो आजादी और प्रजातन्त्र मिला है उस के वास्ते नैतिकता और अच्छी-अच्छी बातों की बहुत जरूरत है ताकि हम उसको कायम रख सकें। फिल्मों का इतना बुरा असर पड़ता है बच्चों पर कि उससे बच्चे भ्रष्टाचार और डाकू हो जाते हैं। इसलिए अच्छी-अच्छी फिल्में बनायी जाएं।

साथ ही मैं चाहूंगा कि आगरा में एक रेडियो स्टेशन का होना बहुत ही जरूरी है।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) :** अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं और दो बातें कहना चाहता हूं।

पहला प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह सही है कि यह दिल्ली रेडियो स्टेशन से इंग्लिश के ही पाठ ब्राडकास्ट किए जाते हैं यह सारे के सारे बी.बी.सी. से तैयार होकर आप के यहां भेजे जाते हैं? आज भी 22 वर्ष के बाद क्या भाल इण्डिया रेडियो बी. बी. सी. का दिमागी गुलाम है? यह निर्णय विभागीय है या मंत्रि-परिषद् का निर्णय है?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप के हिन्दुस्तान के सारे रेडियो

स्टेशन “यह भाल इण्डिया रेडियो है” इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो श्रीनगर के रेडियो स्टेशन से “यह रेडियो कश्मीर है” ऐसा कहकर के कश्मीर को भारत से पृथक दिखाने की बात कहां तक सही है? क्यों नहीं एक ही सी घोषणा श्रीनगर के रेडियो में भी की है? इसका क्या कारण है?

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो समाचार समिति हैं पी. टी. आई., यू. एन. आई., इस विवरण में यह दिया हुआ है कि पी. टी. आई. को 55 लाख रुपया सरकार ने इमारत बनवाने के लिए दिया है यू. एन. आई. को चार लाख ६० दिया है। लेकिन “समाचार भारती” और “हिन्दुस्तान समाचार” जो भारतीय भाषाओं के माध्यम से जैसे तामिल और तेलगू के माध्यम से समाचार देने का कार्यक्रम चला रहे हैं उनको किसी को 50 हजार, किसी को 75 हजार रु. इस किस्म से जो भीख सी दे रहे हैं, यह कहां तक सही है। इस प्रकार से जो भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन न देने की प्रवृत्ति है यह आप की नीति के कहां तक अनुकूल है?

एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आप के यहाँ से जो समाचार प्रसारित होते हैं क्या यह सही है कि उसके लिए कोई विशेष नीति निर्धारित है। क्योंकि अभी रोटरी क्लब में मान्यवर, आप का एक भाषण हुआ। प्रातःकाल के न्यूज बुलेटिन में उस भाषण के कुछ अंश प्रसारित किए गए और उसके बाद उस पर विभाग के एक अधिकारी ने समाचार बुलेटिन के ऊपर आपत्ति की कि लोक सभा के अध्यक्ष का यह भाषण क्यों प्रसारित किया गया। परिणाम यह हुआ कि फिर अंग्रेजी के किसी बुलेटिन में वह भाषण प्रसारित नहीं हुआ। (अध्यक्ष)। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें वास्तविकता क्या है? और कौन वह इस प्रकार का अधिकारी है जो लोक सभा

के अध्यक्ष के भाषण को भी हटवा सकता है। इस तरह की स्थिति क्यों झाल इंडिया रेडियो के भन्दर आज चल रही है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह अखिल भारतीय कार्यक्रम हिन्दी के प्रसारित करके एक झोर तो हिन्दी को आपने सम्मान दिया। लेकिन क्या यह सही है कि इसको जो इंग्लिश के अखिल भारतीय कार्यक्रम तैयार करते हैं, उनके हाथों में दिया हुआ है। जिनको किसी प्रकार की जानकारी हिन्दी की नहीं है। क्यों इस प्रकार से उस कार्यक्रम के साथ मसौदा किया जा रहा है।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ यह यह कि 1962 में आप के विभाग ने यह निर्णय लिया था कि हिन्दी के कार्यक्रम, प्रसारण, इन सब के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र यूनिट बनायी जायेगी। उसके लिए कुछ अधिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। लेकिन बचत के नाम पर सारी की सारी वह योजना ठप्प कर दी गई और उस की अपेक्षा अंग्रेजी के अधिकारी बढ़ा दिये गये। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब यहां पर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि लोक सभा के हिन्दी के भाषणों की रिपोर्टिंग आकाशवाणी पर हिन्दी में जानी चाहिये ताकि उस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। लेकिन यहां पर केवल एक सम्वाददाता झाल इंडिया रेडियो का है और उसको भी कोई स्टेनोग्राफर नहीं मिला हुआ है। जब कि अंग्रेजी के 11 सम्वाददाता और एक डिप्टी डायरेक्टर ए० आई० आर० का यहां बैठता है। तो यह जो पक्षपात हिन्दी के साथ है इस को कब तक आप जारी रखना चाहते हैं ?

**श्री जाबं फरनेशबीब :** माननीय प्रकाशवीर शास्त्री जी ने अध्यक्ष महोदय के भाषण के बारे में जो कहा है उसका खुलासा हम सरकार से चाहते हैं।

**SHRI S. M. BANERJEE :** Sir, I don't want to put any question. But, I would like to say that if the script was there and it had been cut down, then serious action must be taken against those who had done this.

**SHRI I. K. GUJRAL :** I am in agreement with the hon. Member. But, I don't think that anybody in the Department would have the audacity or courage of being disrespectful to you and to this House. We will look into this.

Secondly, a reference has been made here about the film, THE BLACK MOUNTAIN. This is being produced by the Children's Film Society in collaboration with Russians; the Russian Director, Mr. Zguridi is directing this film.

Sir, you may remember that the PAC had passed some strictures on the accounts of the Children's Film Society and on account of that some cases had to be instituted. Some of the office bearers of the Society, I think, are passing on some information to the Members. I would request them to be a little careful in this matter.

When there was Russian Film Festival here, one film depicted the motherliness in animals. It was appreciated much here. The central theme of the Film, THE BLACK MOUNTAIN, is the discipline and devotion of the community as revealed in an elephants' herd. This is being pictured in Mysore jungles. As my hon. friends are aware, it is nothing new to our country to tell most effective stories through animal characters. The entire PANCHANG TANTRA is full of such stories. Telling story through the character of elephants is not derogatory to our national life. The script has been written by an Indian, Mr. Khwaja Ahmad Abbas. The film will be distributed throughout the world. Whatever earnings are obtained in India will go to the Society and the earning abroad will be on 50 : 50 basis. It will be exhibited in Russia and other countries.

**SHRI J. MOHAMED IMAM :** Why should it be partly shot in Mysore and elsewhere ?

SHRI I. K. GUJRAL : It will be shot in Mysore.

MR. SPEAKER : You can also witness the shooting.

16.18 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)  
BILL\*

[Amendment of Article 39 (Bill No. 33 of 1969)]

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में भागे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India"

*The Motion was Adopted*

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक पेश करता हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL\*

[Amendment of Article 39 (Bill No.32 of 1969)]

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में भागे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

MR. SPEAKER : The question is ;

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India"

*The Motion was adopted*

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

IDENTITY CARD BILL \*

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभी मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the issue of identity cards to all the voters"

*The Motion was Adopted*

श्री महाराज सिंह भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

SALARIES AND ALLOWANCES  
OF MEMBERS OF PARLIAMENT  
(AMENDMENT) BILL\*

(Amendment of sections 4, 5, etc.)

श्री पन्नालाल बारूपाल (गंगानगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में भागे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. SPEAKER ; Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954",

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : It is my painful duty to oppose the introduction of this Bill. Let not Shri Barupal or anybody else in the House misunderstand me.

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : Was it painful for him to accept the enhanced salary ?

SHRI S. M. BANERJEE : I am one of those who are already suffering. I was a Child of adversity and I am still facing the same adverse circumstances (Interruptions).

You remember that a Committee was appointed under your guidance which went into this question and submitted a report. The representative of my group, Shri

Vasudevan Nair, and Shri Rabi Ray have among others, appended minutes of dissent. I will quote from Shri Vasudevan Nair's minute of dissent :

"As far as amenities and facilities are concerned, I could not agree with many of the recommendations such as Rs. 100 per month for stenographer, first class pass with P.T.Os. and attendants' passes and still further concession in house rent, water and electricity charges".

I am convinced that there is justification only for such amenities and facilities which are absolutely essential to help members to discharge their public duties more effectively. I was assured by my hon. friends that if any legislation was brought in, it would have in it only the agreed recommendations of the Committee. Now in the statement of objects and reasons of the Bill sought to be introduced by Shri Barupal, it is observed :

"A Joint Committee on Salary, allowances and other amenities to members of Parliament was nominated by the Speaker of Lok Sabha and the Chairman of Rajya Sabha to get into the question of providing further amenities and facilities to members of Parliament in pursuance of a motion adopted by Lok Sabha on the 26th April 1968".

Perfectly right.

"The Committee, in their report presented to Lok Sabha on the 7th August 1968, have made a number of recommendations in respect of amenities and facilities to be provided to members of Parliament".

He has not mentioned that notes of dissent were appended. I am glad that Shri Barupal in his Bill has not sought to raise the allowance from Rs. 31 to Rs. 51.

MR. SPEAKER : Do not go into details at this stage.

SHRI S. M. BANERJEE : I have two or three objections.

He says :

"A member shall be provided with a free furnished A type flat with a servant quarter and a garage".

Members of Parliament come from rural and urban areas and represent the common people.

MR. SPEAKER : He wants something and does not want something else.

AN HON. MEMBER : He can forgo what he does not want.

SHRI S. M. BANERJEE : That is not the point. I am making an objective analysis.

He says that a free A class type flat should be given. Then he wants a servant quarter and a garage. Members are so poor that they cannot pay Rs. 16 or Rs. 17 so he wants a garage. For keeping what? Goat? If you can purchase a car, you can pay Rs. 16.

MR. SPEAKER : No details at this stage.

SHRI S. M. BANERJEE : I am only trying to convince the House. I am not repeating anything.

Then he says :

"Every member shall be provided with one free non-transferable pass of the highest class which shall entitle him to travel at any time by bus in his State".

SHRI RANGA (SriKakulam) : Why should he be allowed to take such a long time, going into such details at this stage ?

MR. SPEAKER : I know it. If prof. Ranga is opposing introduction of a Bill, he can also take three or four minutes. I allow only one member to oppose introduction. I do not want to be taught procedure. I know rules (*Interruptions*).

SHRI S. M. BANERJEE : "Every Member shall be provided with one free

non-transferable pass of the highest class which shall entitle him to travel at any time....."

MR. SPEAKER : Don't bring this at this stage.

SHRI S. M. BANERJEE : There are only two classes—one is the highest class and the other is the lowest class. Highest-class can only mean on the top of the bus.

Sir, I oppose this Bill.

MR. SPEAKER : We do not want any discussion please. (*Interruptions*).

श्री आर्ज करनेजीब (बम्बई दक्षिण) :  
अध्यक्ष महोदय, आप इस पर बोल लेने दें।  
हम इस विषयक के पेश होने का विरोध  
करते हैं।

MR. SPEAKER : Nobody will be allowed at this stage to speak. Only one has been allowed according to rules to oppose.

Now I put it to the vote of the House.

The question is :—

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954".

I think 'ayes' have it.

SOME HON. MEMBERS : The 'Noes' have it.

MR. SPEAKER : Division. Let the Lobbies be cleared.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, let us hear the Finance Minister.

SEVERAL HON. MEMBERS : No, no.

MR. SPEAKER : The doors are closed. Not even the Prime Minister can come now.

The Lobby has been cleared.

The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954".

*The Lok Sabha divided.*

Division No. 13 ]

[ 15-32 hrs.

AYES

Achal Singh, Shri  
Amin, Shri R. K.  
Anjanappa, Shri B.  
Arumugam Shri R. S.  
Babunath Singh, Shri  
Barua, Shri Bedabrata  
Barupal, Shri P. L.,  
Besra, Shri S. C.  
Bohra, Shri Onkarial  
Chandrika Prasad, Shri  
Chatterjee, Shri N. C.  
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh  
Dasappa, Shri Tulsidas  
Deo, Shri K. P. Singh  
Deo, Shri P. K.  
Deshmukh, Shri Shivajirao S.  
Dinesh Singh, Shri  
Dixit, Shri G. C.  
Dwivedi, Shri Nageshwar  
Gopalan, Shrimati Suseela  
Gupta, Shri Lakhna Lal  
Kamble, Shri  
Katham, Shri B. N.  
Kavade, Shri B. R.  
Khan, Shri H. Ajmal  
Kinder Lal, Shri  
Koushik Shri K. M.  
Kushok Bakula, Shri  
Kushwah, Shri Y. S.  
Lakshmikanthamma, Shrimati  
Laskar, Shri N. R.  
Mahadeva Prasad, Dr.  
Majhi, Shri M.  
Malhotra, Shri Inder J.

Marandi, Shri  
 Master, Shri Bhola Nath  
 Mody, Shri Piloo  
 Pahadia, Shri Jagannath  
 Pandey, Shri Vishwa Nath  
 Partap Singh, Shri  
 Parthasarathy, Shri  
 Poonacha, Shri C. M.  
 Pramanik, Shri J. N.  
 Prasad Shri Y. A.  
 Radhabai, Shrimati B.  
 Raghu Ramaiah, Shri  
 Raj Deo Singh, Shri  
 Raju, Shri D. B.  
 Raju, Dr. D. S.  
 Ram Dhan, Shri  
 Ram Swarup, Shri  
 Randhir Singh, Shri  
 Ranga, Shri  
 Rao, Shri Thirumala  
 Rao, Dr. V. K. R. V.  
 Raut, Shri Bhola  
 Reddy, Shri M. N.  
 Reddy, Shri R. D.  
 Saigal, Shri A. S.  
 Sayeed, Shri P. M.  
 Sayyad Ali, Shri  
 Sen, Shri Dwaipayana  
 Sequeira, Shri  
 Shambhu Nath, Shri  
 Sharma, Shri Modhoram  
 Shashi Bhushan, Shri  
 Shastri, Shri Sheopujan  
 Sheo Narain, Shri  
 Siddheshwar Prasad, Shri  
 Singh, Shri D. N.  
 Snatak, Shri Nar Deo  
 Somani, Shri N. K.  
 Sonar, Dr. A. G.  
 Sonavane, Shri  
 Supakar, Shri Sradhakar  
 Suraj Bhan, Shri  
 Suryanarayana, Shri K.  
 Swell, Shri  
 Tiwary, Shri K. N.  
 Tula Ram, Shri  
 Verma, Shri Balgovind

Verma, Shri Prem Chand  
 Virbhadra Singh, Shri  
 Viswanatham, Shri Tenneti  
 Vyas, Shri Ramesh Chandra

## NOES

Anirudhan, Shri K.  
 Badradduja, Shri  
 Banerjee, Shri S. M.  
 Bharati, Shri Maharaj Singh  
 Fernandes, Shri George  
 Gopalan, Shri P.  
 Joshi, Shri S. M.  
 Kalit, Shri Dhireswar  
 Khan, Shri Latafat Ali  
 Menon, Shri Vishwanatha  
 Mulla, Shri A. N.  
 Nihal Singh, Shri  
 Rajaram, Shri  
 Ray, Shri Rabi  
 Reddy, Shri Eswara  
 Roy, Shri Bishwanath  
 Sambhali, Shri Ishaq  
 Satya Narain Singh, Shri  
 Subravalu, Shri

MR. SPEAKER : The result of the division is : *Ayes 84; Noes. 19.*

*The motion was adopted*

SHRI P. L. BARUPAL : Sir, I introduce the Bill.....(*Interruptions*).

16.32 hrs.

ENLARGEMENT OF THE APPELLATE (CRIMINAL) JURISDICTION OF THE SUPREME COURT BILL

MR. SPEAKER : We shall now take up Shri Mulla's Bill. Shri Mulla may continue his speech.

16.32½ hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair.*]

SHRI A. N. MULLA (Lucknow) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I had just opened my lips on the last day when this House adjourned. I consider it a privilege to move this Bill for in its scope and im-

port it is an attempt to give to the citizens of this country that liberty which they were promised under the Constitution but which was unfortunately snatched away from them perhaps under the pressure of those who dominated the Home Ministry. It was snatched away by the ruling group within a few years of the passing of our Constitution. It is a privilege to move this Bill not only because it will to a certain extent restore the civilised rule of law but also because it is a crusade to fight for the rights of the dumb millions of this country. When I say 6 millions, I mean millions; I am not using a figure of speech—those dumb millions who cannot coherently voice their pain or fight their battles. To the hon. Members I wish to say that this Bill is a test for them also—whether they believe in liberty or not.

Because liberty is not endangered only on our frontiers. System of law which leads to the curtailment of our liberties is also and perhaps a great danger to our liberty. We all understand when the danger comes from the frontiers. . . . We face that danger. But when insiduously the rights of the people are taken away, then you are taking away their liberty in a manner which is very difficult for the citizens to find unless they are very vigilant.

Before I enter into the merits of this Bill and the points of grievance. I would like to place the existing state of law so that Members may get themselves acquainted as to what is the system of law under which we are living at the moment. In 1947, when we became independent, then, in the Criminal Procedure Code, there was a section which was known as section 417 of the Criminal Procedure Code, under which a right of appeal against acquittal was given to the State, but in practice, that right was very seldom exercised. I can say it from my own personal experience at least in my province. I cannot say about what was happening in other provinces. It was a very rare occurrence that an appeal against acquittal was brought forward by the State. But although our first elections under the

Constitution were held in the year 1952, within three years, in 1955, we amended section 417 to the extent that we added the words "in any case" to the existing words of the statute which empowered the State to file an appeal against the order of acquittal in all cases, wherever and whenever case they felt inclined to do so. Obviously, either of these words are redundant, but one of the axioms of interpreting the statutes is that no word is uselessly used and therefore the addition of the words "in any case" by itself indicates that the existing words of the law were not enough to give that scope to the State to file appeals which they wanted by adding the words "in any case."

I wanted to collect the figures of the number of appeals that were filed before 1965 and what was the rising spiral of filing these appeals against acquittals after 1965, but I was not given this information. Therefore, it is for the Members want to satisfy themselves whether they would like to secure this information or not, as to what was the rise in the spiral of appeals and as to how this addition of these words "in any case" has changed the aspect of our criminal procedure.

I believe after this addition was made, almost in every case of acquittal appeals began to be filed. There are always two parties to a case there is the complainant and there is the accused—if the accused has been acquitted, then the complainant either through real grievance or through vindictiveness wants that the matter should be taken to a higher court, whatever the reason might be. After the insertion of these words, when the State instead of taking up this action, only in extremely rare cases, where real, grave injustice has been committed, directed a large number of appeals to be filed. There is very frequently a deal between the complainant and the police. After this deal is reached, the police succeeds in persuading the representatives of the Home Ministry to take up the case and file an appeal on their behalf. I do not know when the State exercises its mind and discretion whether this is a case in which an appeal should be filed or not. I have hardly come across a case in which the State has exer-



[Shri A. N. Mulla]

cised its mind and refused to file an appeal where the prosecuting counsel or the prosecuting inspectors have managed to approach the State through their higher authorities that an appeal should be filed in that case. The procedure to day has become such that almost in every case of acquittal there is a move that an appeal should be filed against the order of acquittal.

Formerly an acquittal was supposed to be a final order so far as the prosecution was concerned.

If you look up the English law, the American law or the law of any European country, there is very little scope for filing an appeal against an order of acquittal. In English law, there is no provision. But through a curious line of reasoning, I am sorry to say that even the eminent members of our Law Commission ignored two basic facts and they thought there is nothing wrong with this approach, that what is prevalent in the Privy Council should be applied to the procedure which is prevalent here. They forgot that in English law, the findings on facts are reached by a jury and not by a judge. When a jury gives a particular finding, a fair trial is assured for the accused. Again, they forgot that when the Privy Council does not accept any appeal on facts against the judgment of a lower court, it is also conscious of the fact that there is no appeal against an order of acquittal in the English Law.

In our case, only two very learned High Court judges sit together and decide that the finding reached by perhaps an equally eminent mind, because that judge may become a High Court judge within a few months, is wrong. The exercise of these two minds is supposed to be sufficient to inspire confidence that on facts, a fair trial has been given to the accused person and the chances of error have been eliminated. I believe that all of you would agree that it is one of the postulates of a democratic State that a fair trial should be ensured for the accused. Otherwise, we are not functioning as a civilised State.

What is the scope of a fair trial? I received some months ago a copy of a book in which were incorporated the

lectures given by a judge of the Supreme Court of America, Mr. William W. Douglas, who came to give lectures in the Tagore series at Calcutta. He has said about what man has been fighting for since the dawn of creation :

“I think that man's struggle to be free is in a large degree a struggle to be free from oppressive procedures the right to be free from torture, the right to know the charge and to have a fair opportunity to defend, the right to have a system of laws that is not a pitfall for the innocent.”

A full opportunity to defend oneself is one of the basic human rights. When the United Nations adopted the Charter of Human Rights in 1950, the right to defend was one of the basic rights considered to be a human right. Therefore, we have to see whether under the existing law of this country, we have been given this right to defend ourselves or not.

The right to defend includes the right to defend at the appellate stage also. The definition of trial is not only trial in the trial court but it includes the appellate court. The appellate court is only an extension of the trial and the facts are therefore heard in appeal also.

Therefore, where the right to defend is given the right to defend is given not only in the trial court but also in the appellate court. It is a legal axiom, I think, which cannot be challenged. If the right extends up to the appellate stage, let us see what provisions have been made in our laws. For a person who for the first time is sentenced, not only sentenced, to a small imprisonment but to imprisonment for life, it is extraordinary that even in those cases where a person is convicted for the first time and sentenced to imprisonment for life by setting aside the orders passed in his favour by the trial court he is debarred from claiming that as a matter of right he has a right to go to a superior court to be heard in appeal. I am very much conscious of the fact that many of the restrictions placed on the rights of an accused person are explained away by saying that the Supreme Court is overworked and it is not right that we should add to the labours of the Supreme Court

by sending more cases when they are already over-worked. But it seems to me that, at the same time, when this argument is advanced, those persons who advance this argument seem to forget that when the High Courts are also suffering under extreme pressure of work they are adding burden to the work of the High Courts by filing so many appeals against orders of acquittal passed by trial courts. Why are they doing that? Are they not adding and unnecessarily adding more work to the already over-worked High Courts? But under the old law this was very seldom exercised (*Interruption*).

There are two reasons given by the Law Commission as to why an enlargement of the appellate right of an accused person should not be made. One I have already discussed, namely, that it is procedure of the Privy Council which has been followed by the Supreme Court. The other reason given by them was that we have to protect the importance of the High courts and we should not do anything which would reduce the image of the High Courts in the people's minds as if they are likely to err and their findings are questionable. I place it before the hon. Members of this House what type of reasoning is this. Does it speak high of those eminent men who have advanced this reasoning? They are out to protect the image of the High Court. At what cost do they want to do it? Such protection cannot be given and such an edifice cannot be created on the grave-yard of the rights of the people. Therefore, if there is a conflict between the rights of the people and the image of the High Court which should be protected? It is extraordinary that we should sacrifice the rights of the people so that the image of the High Courts should be protected.

Sir, I have been a Judge. I have functioned as a lawyer also. Therefore, I have a soft corner for the Judges. But at the same time, there is a responsibility cast on all of us who are here as representatives of the people to see that where such a conflict arises the priority is for the rights of the people and the priority is not for the reputation of the judges. Therefore those learned members of the Law Commission who were so much concerned with protecting the prestige of the

High Court have to quote in the words of Burke—"they pitied the plumage but they forgot the dying bird". It is for the dying bird that we are most concerned. We cannot permit the dying bird to die because it has not been given a right to go against a decision given by two judges of the High Court, who are as much prone to human error as any other trial court.

There is another point which I would like to place before you. There are two articles in our Constitution—articles 133 and 134. Article 133 deals with the rights of appeal in civil cases. Article 134 deals with the right of appeal in criminal cases. Under the provisions of article 133, wherever there is a dispute of Rs. 20,000 IPSO EACTO the right of appeal arises in favour of the aggrieved party. He can immediately take the case to the Supreme Court. Here again, we only talk of liberty, but we seem to be property conscious and not liberty conscious. Where a question of Rs. 20,000 comes in a right of appeal is given by our lawmakers in their wisdom, but where a sentence of 20 years is given, no right is given. As a matter of right, he could not go in appeal. I suppose if we judge it from the point of human values, if we come to brass tacks as to what system of law we want to live under, we must protest against this un-called for and quite ununderstandable discrimination that a person whose Rs. 20000 is in few poverty has an unfettered right to go in appeal and a person whose 20 years of life are being taken away from him has no such right to go in appeal.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON): May I ask whether he has given a fair meaning of article 133? It is only in a case of reversal in a civil case...

SHRI A. N. MULLA: Am I not arguing a case of reversal in a criminal case here?

SHRI GOVINDA MENON: In a case of reversal it will lie.

SHRI A. N. MULLA: Am I not arguing a reversal case?

SHRI GOVINDA MENON: You did not say that.

SHRI A. N. MULLA : I think I am arguing a case of reversal against acquittal. Therefore, they are exactly at parity. Read the two articles together and you cannot but come to the conclusion that we want to protect a person if his property is involved but we do not care where the High Court might have committed a mistake.

SHRI GOVINDA MENON : In a case of acquittal by the High court, there is an appeal from the High Court to the Supreme Court.

SHRI A. N. MULLA : The prosecution cannot make an appeal in a case of that nature to the Supreme Court because under the criminal law the benefit of doubt has to be given to the accused. It is one of the cardinal principles of criminal law and, therefore, where the High Court has come to that conclusion it would be going against the basic principles of criminal jurisprudence if the State goes in appeal.

SHRI GOVINDA MENON : When the High Court acquits.....

SHRI PILOO MODY (Godhra) : If the Law Minister wishes to learn some law, he can have private tuition outside.

SHRI GOVINDA MENON : I am not learning; I am only teaching.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : When pertinent questions are put, why should he object ?

SHRI GOVIADA MENON : Because section 417 speaks of appeal from an order of acquittal to the High Court, not to the Supreme Court. So any reference to section 417 was absolutely irrelevant.

SHRI A. N. MULLA : I think the two cases which are sought to be equated by the law Minister cannot possibly be equated. When the High Court passes an order of conviction, there are two ways—one, when it confirms the order of the lower court; the other when it sets aside the order of acquittal. But where the High Court acquits the accused person, as I said before, it shows that the trial court,

even if it had convicted him by making one assessment of evidence, the High Court can assess the evidence in a different manner. Therefore, the legal position is that two assessments are possible of the same evidence. The judge at the trial court may be a little less experienced but he exercises his independent mind in assessing that evidence and, well, he may come to the conclusion that the accused is guilty. The High Court being more experienced and two Judges sitting together exercise their mind and they think that reasonable doubt has to be given to the accused and he should be acquitted.

Therefore what the law Minister is saying is that even this giving of the benefit of the doubt should not be considered as final and even in those cases an appeal should be given.

SHRI GOVINDA MENON : No ; I said, it is final. What I said, is that the reference to section 417 of the Code of Criminal Procedure was not relevant to the matter before us because under section 417 there will be an appeal to the High Court in matters of acquittal, not to the Supreme Court.

SHRI A. N. MULLA : It seems that we cannot agree or understand each other on this point.

SHRI RABI RAY (Puri) : There is a qualitative difference.

SHRI A. N. MULLA : Now I would place another point as to how the dice is heavily loaded against an accused person. Normally where two courts come to a particular conclusion it is supposed to close that case because the juristic concept is that there is a likelihood of error by one court and if the conclusions are confirmed by another court then reasonably that likelihood of error is eliminated. But under section 417—I come to it again—the right to the State to go in appeal is not only against the trial court's order but also against the appellate court's order. Therefore, so far as the State is concerned, even where two courts come to a conclusion that the case is not proved against an accused person, the State is the

particular favourite. of the Law and for it can challenge even that case.

And look at the gross inequality in the two positions. In those cases in which to the High Court it goes in appeal the maximum sentence that can be given is only four years because it is only those cases which are tried by the assistant sessions judge which would come up in appeal before the sessions judge.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member's time is up.

SHRI A. N. MULLA : What about those days, those months, those years of my silence ?

Therefore, as I said, you find that an assistant session judge can give a sentence of only four years. Now the State has been given a right to go in appeal even against these trivial cases if it feels that the judgement must be set aside. But even in a sentence of imprisonment for life an accused person is not given this chance and the only plea that the Law Minister is taking is that the High Court's decision is final. Those decisions were given by the lower courts ; they were not given by the High Court. Therefore, there is a distinction, that what the High Court does is infallible and we cannot to challenge what the High Court has done. I have already said that that was a pitfall into which the Law Commission fell when it said that we have to protect the image of the High Courts.

I have already placed the English law before you. Now I will place the American law before you. It varies from State to State. Normally there are States where there is no right of appeal against acquittal but there are a few States in which this right of appeal is given against the order of acquittal. If you collect the figures, you will find that very rarely such appeals are filed. The right exists in the statute to file an appeal but very rarely such appeals are filed.

As I said, it has become a common occurrence, so far as we are concerned, that such appeals are being filed again and again. I put this argument both ways. If there are very few appeals in

which this interference is being made by the High Court, it does not matter at all; the present strength of the Supreme Court can safely deal with these added appeals because there would be only a few additional appeals. It would only be because a large number of cases are being disturbed by the High Court that an occasion would arise to say that work in the Supreme Court would increase. What an alarming situation that in such a large number of cases our High Courts are disturbing the orders of acquittal. Is our liberty worth having when the High Courts are disturbing it in such a large measure ?

As I have said, I have also a regard for the High Courts. But I cannot infallibly place reliance on the correctness infallibility of the findings reached by the High Court. Anybody who says that the High Courts are infallible is pleading a point which cannot be maintained. In the interests of the liberties of the people, it is necessary that there should be higher tribunal. Where there are two different judgments which are conflicting with each other, there should be a third court which should hear all facts and decide whether the case is there or not.

17 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion Moved :

"That the Bill to enlarge the appellate jurisdiction of the Supreme Court in regard to criminal matters, be taken into consideration."

There is a motion for circulation by Shri Vishwa Nath Pandey—he is not here.

SHRI N. C. CHATTERJEE (Burdwan) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, if you look at article 134, it says :

"An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of India if the High Court—

(Shri N. C. Chatterjee)

- (a) has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death ; or
- (b) has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death ; or
- (c) certifies that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court :"

Now, my learned friend, Mr. Mulla, is pointing out that clause (c) is really inconsistent with the principles of justice. Grant of an appeal under article 134(c) is not a matter of course. About article 136, I must also say, that article has practically reached the vanishing point of jurisprudence. That is practically wiped out in criminal cases. This is what the Supreme Court had said, in 1950. AIR 1950 S. C. on p. 169 :

"Generally speaking, Supreme Court will not grant special leave to appeal in criminal cases unless it is shown that exceptional and special circumstances exist, that substantial and grave injustice has been done and that the case in question presents features of sufficient gravity to warrant a review of the decision appealed against."

If says, firstly, exceptional and special circumstances must exist ; secondly, it must be substantial and grave injustice and, thirdly, there must be features of sufficient gravity to warrant an appeal.

Sir, the House should consider it carefully. When a trial judge has heard the witness, has seen the witnesses and heard the facts and acquits him, should we be content only with one appeal if that appellate court who has not heard the witnesses, has not seen the witnesses and has not direct touch with the witnesses, comes to a different conclusion ? Then, as a matter of course, there should be an appeal to the highest Court in the country. I think that is only proper. I do not know why the Law Minister intervened in regard to that. Section 417 of the Criminal Procedure Code says :

"The State Government may direct the public prosecutor to present an appeal to the High Court from original or appellate order of acquittal passed by any court other than a High Court".

Eyen after two courts' findings, the public prosecutor may lodge an appeal against acquittal. If that is so, I think, there is a good deal of force in what my learned friend says.

In England, you know, there is no appeal against acquittal that is in the Colonies and in the Dominions. Unfortunately, we have got it. I think, the time has come to seriously think over it.

We have given so many elections cases to the Supreme Court. The Supreme Court is burdened, to some extent, with them. But that does not mean the Supreme Court should be relieved of all the responsibility in regard to election cases. If you can do that, why don't you admit this ? The only thing he has asked is that clause (c) should be altered and certificates should be granted whenever there is an imprisonment for life or imprisonment which extends to ten years or more than ten years.

I think, it is a very good suggestion and we will be justified in accepting it. The House should consider it very carefully. Even if it goes to any Select Committee, I do not mind ; it should be thoroughly delt with...

SHRI PILOO MODY : Pass it here and now.

SHRI N. C. CHATTERJEE : Yes ; it will be very good.

My friend has pointed out that against acquittal, there should not be only one appeal. If that appellate court reverses that, the Supreme Court should, as the highest court in the country, review it.

SHRI HANUMANTHAIYA (Bengalore) : Two learned members who are well-versed in matters relating to law have spoken. Personally I have got great respect for them. What I want to place

before the House is not the point of view of the profession of law or the jurisdiction of the judges, but the position of the litigant.

My learned friend, Mr. Mulla, quoted the famous phrase about sympathy more for the plumage than for the bird. Following the implication of this phrase, let us analyse who is the bird and who is the plumage.

When one comes to the Supreme Court, please consider the procedure that we have to follow. I have got great respect for the independence of the judges whether of the High Court or of the Supreme Court. I have no evidence to contradict the position that our judges and our courts are discharging their functions with commendable impartiality. Therefore, I am not quarrelling with the judges personally, either of the High Court or of the Supreme Court. But I want to present the position of the diets. We have such a system of judicature that one has to come here to Delhi all the way from every corner of India. How much the travelling and staying here cost, any one of you can imagine. To live in Delhi for a day costs a considerable sum of money. Then we have to engage two sets of lawyers the senior lawyers and the advocate on record. We have to pay two sets of fees. Nowadays fees in the Supreme Court are so high that the minimum is Rs. 1,000 per day.....

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) :  
The barest minimum.

SHRI HANUMANTHAIYA : Yes.

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) :  
He can keep quiet, if he cannot afford.

SHRI HANUMANTHAIYA : Then the records have to be printed. Even if it is a case of not much consequence, the amount involved in a case comes to a high figure. The client cannot afford it; he will have to pledge, borrow or sell his property in order to have recourse to these legal procedures. This is the position. There is a famous saying in my language about a man who goes to court of law, in this system of delay and expenses "he who

succeeds is as good as defeated and he who is defeated is as good as dead".

AN HON. MEMBER : Say that in your language.

SHRI HANUMANTHAIYA : In my language they say (*Spoke a few words in Kannada*).

I am speaking with full knowledge, as I have myself been in the profession and I know the condition of the clientele. Now if you extend the jurisdiction of the Supreme Court, I do not question the wisdom of the court in doing justice, but, in actual practice, who is benefited? It is the legal profession that gets more employment or engagement. And the Judges will have better satisfaction of having bigger jurisdiction. Therefore, the plumage in this case is the Bench and the Bar, and the bird is the clientele.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Apart from the cost of litigation and other factors, as Mr. Chatterjee put it very succinctly as a matter of principle where the State is permitted a right of appeal straightaway, the private citizen in such cases is debarred. That principle is involved. I am putting it in brief.

SHRI HANUMANTHAIYA : I am putting forward a new point of view. I am not concerned with the technicalities. The question is jurisdiction of the Supreme Court. Here whether the State has the right or some other person has the right, that is a question which relates to only jurisdiction. It is not that I am so much interested in the legal niceties as in seeing that the poor man is protected. The extension of the jurisdiction on any matter under the present system of judicial system means that more birds will have to die for the sake of plumages.

We are so much immersed in the existing systems. If you begin to live in a fish market, you begin to relish the smell of even the rotten fish. There is much to be done in the judicial system in order to protect the bird and fix the plumage in its proper place. The reverse process of limiting the jurisdiction, and limiting the number of appeals has to be

[Shri Hanumanthaiya]

devised and adopted. Justice cannot be done in isolation. Justice can only be done effectively and properly if there is a great speed in the disposal of cases and if it is as near the spot as possible. If you remove the judicature more and more away from the spot, theoretical considerations will weight more and more in judgments.

The extension of the jurisdiction of the Supreme Court is a formality which may satisfy the requirements of niceties. I am seeing how it will profit the client. In fact we have to devise a judicial system where there is only one trial and one appeal, not a series of appeals. I would say perchance, as some people used to ask in the olden days, if we had allowed the jurisdiction of the Privy Council in London to continue, I am sure there would have been any number of appeals from the Supreme Court to the Privy Council. This spirit of litigation knows no end. I want this spirit of litigation to be limited as far as possible (*Interruptions*) at the level of the High Court. If at all if there is any imbalance in favour of the State, as you have pointed out, it should rather be curtailment and not extension of the jurisdiction of the Supreme Court. The client has to be saved from ruination.

श्री भोल्सू प्रसाद (बाँसगाँव) : क्या जो दृष्टिकोण यह प्रकट किए हैं क्या माल के मुकदमे में भी यही दृष्टिकोण रखेंगे ?

MR. DEPUTY SPEAKER : As I tried to put it, a basic principle is involved. There is a certain amount of discrimination between the State's right and the citizen's right to go to the Supreme Court. The cost of litigation and other things are extraneous matters. I would like the hon. Member to stick to the principle only.

SHRI K. M. Koushik (Chanda) : I rise to support the Bill introduced by my honourable colleague, Mr. Mulla and I am in agreement with the arguments advanced by Shri N. C. Chatterjee and Shri Mulla. But the only point that I wish to say is this.

As you said, with apologies to Mr. Hanumanthaiya, the question we are considering is not as to what would be the cost and whether the man would be able to bear the cost and all that. We are not here to consider that aspect. I would only say this : You give the right of appeal only in a particular case under, Act. 134 of constitution. You have fixed it arbitrarily in the case of death sentence. But, why cannot it be for 10 years' imprisonment ? After all, 10 years' punishment means the person will be confined in jail for such a long time and it is slow death, for that fellow. It is worse than being condemned.

Therefore, this arbitrary limit should be relaxed in favour of a sentence like transportation for life or for 10 years punishment or more. This is what I have to submit. This arbitrariness has to be removed and it should be liberalised I see that Mr. Mulla's Bill is a little conservative and it should have been a little more liberal.

That is all that I want to submit on this Bill.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : My hon. friend Mr. Mulla has done yeoman service to the Bench and the Bar and to the litigent public by bringing forward this Bill and I support it wholeheartedly.

To me it appears to be a denial of equality of opportunity. Under Section 323 I.P.C. one can be convicted for Rs. 51 by a petty magistrate. He can go on appeal to the session judge and get the orders rescinded. So is the case under Section 427 I.P.C. If the executive magistrate responds, under Section 107, 109 or 110 there is right of appeal to the session judge. Then the orders can be rescinded or can be set aside. But there is absolutely no right of appeal for a sentence of transportation for life or in regard to rigorous imprisonment of 10 years etc. by a High Court. This is a very serious lacuna.

We are a progressive society. How could we apply the British law to our

condition in India? Here the sessions judge is there; he is the boss of the whole situation. The analogy of the British law to the situation in India is most untenable. They are having trial by jury, the judge being the presiding court.

Another point is this. It is not in keeping with the principles of natural justice, equity and good conscience.

There is a right of defending oneself or by counsel which is enshrined in the Constitution itself. The accused person can defend either by himself or by his counsel. If the case is withdrawn from the session court or if the case is acquitted by the session court and an appeal is filed to the High Court, and conviction is made by the High Court while trying such a case, there is no appeal from such a case to the Supreme Court when the sentence is transportation for life or imprisonment for life. We have to take note of this situation.

Shri Mulla has very rightly stated that people manipulate. They conspire with the agency of investigation with the staff in the States. Somehow they contrive or manipulate to get the appeal filed in the High Court. The cases are multiplied. They go on multiplying. By the time they go on multiplying, what would be the number of people who are to be denied justice? That also gets multiplied. But, if a person is innocently convicted, if one person is acquitted who should not be acquitted, it is worse than one thousand prisoners released from jail. That is what a Persian quotation says. If a man is given certain right under the Constitution, it is a breach of Fundamental Right as such not to provide such opportunity.

This is how I put it. There are certain remedies and solutions given to a citizen in the Constitution itself. They are being denied to him. What I feel is that Justice Mulla has raised a pertinent point in saying that property is more important than liberty. A person may be sentenced for life and he has no right of appeal. This power is exercised only very sparingly. Within five minutes his special appeal is thrown out. How humbly

the lawyer may feel when moving a special leave application? There is no intention to cast any reflection on Supreme Court Judges. Certainly the idea is that the Supreme Court cannot be converted into an ordinary appeal court. Why? The fundamental liberty and freedom of people is much more important than the Supreme Court itself. We may have to employ any number of Supreme Court Judges. But justice should not be denied to the citizens.

I, therefore, fully endorse the views expressed by Justice Mulla. If you feel necessary, you can send it to the Select Committee. Otherwise, eliciting public opinion is a prolonged and long procedure. That will mean delay in passing the Bill and to that extent denial of justice to citizens.

I would appeal to the Treasury Benches and the Law Minister himself to give a second thought to this. This is a lacuna not only in the Constitution itself but in the procedure of the Supreme Court itself. This is something which affects the very fundamental rights of the citizens of this country.

SHRI HUMAYUN KABIR (Basirhat): I also wholeheartedly support Shri Mulla's Bill. I would say that he has made two points very clear. First, that there is a distinction between the right given to the State and the right given to an individual. The State can appeal even when there have been two appeals already. In spite of that, the State can go to the Supreme Court. But in the case of an individual, this right is denied to him. This is a very clear distinction. Secondly, there seems to be greater concern for property than liberty. These two points Shri Mulla has established very clearly.

My Hon. friend Shri Hanumanthaiya who is usually very persuasive and logical has not been able to meet any one of these arguments. The analogy of plumage and bird got mixed up. We want to safeguard the life of the bird. In order to save expenditure on plumage, he wants to have the person condemned and sentenced for life. If a



[Shri Humayun Kabir]

man is condemned to 10 years or 14 years of imprisonment, what is it but life in death? In order to save the plumage a few rupees he has condemned the bird. I think there is a very simple answer to that.

I am reminded of a gentleman from the city where my hon. friend Shri Mulla comes from and he, Mirza Abu Talib Khan, about 170 years ago—he was not a lawyer himself—made one of the remarkable anticipations of the findings of Marx. As early as 1793 he said that all over the world at one time Judges used to be paid by litigants. Very often it was so. In Shakespear's references are found as to how the Judges used to join this side or that side and therefore State realised that Judges should be paid by the State and the State started paying Judges. In 1793 Mirza Abu Talib suggested that Advocates must be paid by the State and not by the parties. This would meet to a very large extent the point made by my hon. friend, Shri Hanumanthaiya. But the final and clinching argument is this that nobody is compelling anybody to go to the Supreme Court. After all it is only a right you are giving that if a man feels aggrieved, if he feels that injustice has been done to him, he should have the right to go to the Supreme Court of the land. I think it would be travesty of justice to deny him that right. I would appeal to the Hon. Law Minister, even at this late stage, if possible to accept a motion for Select Committee. I am not in favour of passing an Important Bill like this on the spur of the moment. It is always better to have a small Select Committee for a brief period to examine the actual implications of the wording. But I would request him to accept the principle. The moment the Bill is referred to a Select Committee, it means that the Government has accepted the principle. My hon. friend who spoke last has very eloquently supported this Bill, and the temper of the House is that the principle should be accepted, I hope the hon. Minister will support it. The actual words and phrases can be examined by the Select Committee. I am sure that my hon. friend, Shri Mulla, will accept the

Motion for reference to Select Committee, if you permit it.

श्री रवि राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मुल्ला जी के द्वारा जो विधेयक पेश किया गया है, मैं उसका जोरदार समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ जब मुल्ला जी अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, हमारे कानून मंत्री जी बड़े तिल-मिलाये और घबराहट में खड़े होकर उनको टोकते रहे, लेकिन उनके तर्क में कोई तथ्य नहीं था।

मुल्ला साहब ने एक बड़ा मौलिक सवाल उठाया है, यह एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ नागरिकों का सवाल है। राज्य और नागरिक दोनों में सदियों से झगड़ा चला आ रहा है और वह राज्य जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वह सचमुच प्रजातान्त्रिक राज्य है, गणतान्त्रिक राज्य है। मुल्ला साहब ने अपने दिल में इसी मानवता के सवाल को उठाया है, इसमें पैसे और सम्पत्ति को गौण रखा गया है। मैं इसके लिए मुल्ला साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

जिस समय हमारा संविधान बनाया गया था, उस समय संविधान बनाने वालों के दिमाग में—चूँकि वे लोग बड़े वकील थे, इसलिए उनके दिमाग में सम्पत्ति की रक्षा ने जितना प्रभाव डाला था, मनुष्य की स्वाधीनता और आजादी की रक्षा की बात उनके दिमाग में नहीं आई थी। मैं इसीलिए मुल्ला साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संविधान की जो गलती थी, खास कर जबकि राज्य को अपील करने का अधिकार दिया जाता है, नागरिक को नहीं दिया जाता है—इस अन्याय का उन्होंने पर्दाफास किया है और भांडा फोड़ किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दंग रह गया—ला कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया था—चूँकि सुप्रीम

कोर्ट के केसेज बहुत बढ़ जायेंगे, केसेज की तादाद बढ़ जायगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की अपील नहीं लेनी चाहिए-- कितना अजीब तर्क है। ला कमीशन और सरकार के दिमाग में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का विचार जाना चाहिए था, लेकिन ला-कमीशन ने ऐसा नहीं किया। मैं ला मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वह ठण्डे दिल से इसके बारे में पुनः सोचें। यह मनुष्य की शहरी आजादी और उसके मौलिक अधिकारों का सवाल है। इसलिए अगर वह इसको सिलैक्ट कमेटी को भेजने की बात भी मानली जाय तो अच्छा होगा।

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): Sir, in offences the State is supposed to be the aggrieved party and that is the reason why the Criminal Law is weighted in favour of the State. That is the reason why the States are given certain rights of appeal, which are denied to the private party. That is why Section 117 of the Criminal Procedure Code is worded in the way it has been worded. The most important thing is that the right of appeal is a very valuable right enshrined in our Constitution. So far as criminal matters are concerned, we just copied simply the old Government of India Act and the previous procedures and the essence of certain judgments given by the Privy Council. The Privy Council did not entertain criminal appeals and it is separated here that the Supreme Court shall not be made a court of criminal appeal.

As has been pointed out by Shri Mulla, the reason offered is that it would appear that the image of the High Court would be spoiled if the right of appeal to the Supreme Court is given. Its image is not going to be spoiled in matter involving Rs. 20,000, if its judgment is appealed against. In several matters it will be 20,000 in these days of devaluation and in these days of currency depreciation, even two acres of land either in Malabar or in Andhra will now cost Rs. 20,000.

I shall read out the particular clause in the Constitution because there seems to be some confusion :

"An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil procedure of a High Court in the territory of India if the High Court certifies that the amount or value of the subject matter of the dispute in the court of first instance and still of dispute on appeal was and is not less than twenty thousand rupees..."

And where the judgment is a confirming judgment, there should be a substantial question of law involved, if it is a reversing judgment, it automatically goes. But in this case, where the right of appeal is a valuable right of the citizen, it is denied in criminal matters. There was no substantial principle involved in the provision here excepting that the State should have superior rights over the private citizen. Therefore, the law was overweighted in criminal matters in favour of the state. The previous society was overweighted in favour of property. The property concept has been there. But now things are changing and we are evolving a new concept of society. Property may be there; but liberty is also valuable.

Then art. 134 (1) (a) says :

"...if the High Court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused and sentenced him to death".

That is only in case of a sentence of death can the private citizen have the right to go to the Supreme Court. It is this that Shri Mulla seeks to enlarge. It is really enlarging the right of the accused, not the jurisdiction of the Supreme Court. Even ten years imprisonment, as Shri Kabir has said, becomes a living death, if not sentence of death altogether.

Therefore, I suggest there is nothing here which the Law Minister can with conscience object. He may object because the Bill is sponsored by the Opposition, by a private Member. It has been suggested to us that on the spur of the moment we should not pass legislation.

[Shri Tenneti Visvanatham]

I say on the spur of the moment we should not also reject legislation. Therefore, let us have a select committee. I have no objection. But the principle is quite clear. In these days, when the right of appeal is one of the valued rights of the citizen, to deny him this right except when he is sentenced to death, is something which does not appeal to civilised conscience. Therefore, I heartily support the Bill.

SHRI SHIVAJI RAOS, DESHMUKH (Parbhani) : I propose to add my humble voice in support of the Bill moved by the senior jurist and respected lawyer of this House. The Mover has done literally yeoman service to the criminal law of the country.

If I may say so, our Constitution suffers from a little basic deformity. On the one hand, it has been most liberal in conferring fundamental rights and enshrining them in a special chapter therein. It has even provisions for the enforcement of fundamental rights against the State. The same chapter has got a series of articles on proprietary rights also. Further freedom of man has been upheld, freedom from imprisonment has been safeguarded, freedom from exploitation has been granted. No citizen can be deprived of movement and certain basic human freedoms except under the authority of law. The same Constitution, when it comes to the appellate jurisdiction of the court, is a little bit conservative. And as has been pointed out by a series of Members here, the Constitution has been interpreted more in favour of proprietary classes and landlords that in favour of those who may be faced with a charge of criminal offence. I think, Sir, that it is time to consider liberally the sense of the term of jurisprudence. A most innocent person can be charged with a most heinous offence and under the law, the most respected, the most considerate and the most liberal court can come to a conclusion to convict an innocent person of the offence charged with. The law ordinarily should prescribe protection against such unlawful convictions. So, is it not strange that under the Indian Penal Code when a High Court is supposed to be empowered

to confirm the sentence of death passed by a Sessions Court, the same High Court hears the appeal against conviction and also confirms the death sentence? Under what law can it be supposed that the original court, in any case, passed the sentence of death? Even within the limited sphere, the High Court ordinarily should be expected to be an ordinary court of appeal under the criminal jurisprudence of the term. And yet we find that even in cases of death sentences, the Supreme Court may come to a conclusion that it is a case of grave injustice or as error of law.

Now, thanks to the legal profession that what ever may be the judgment of the trial court, the least injustice that can be attributed is to the errors of law. Even there an innocent man who has no recourse to learning of law is presumed to go in appeal. Is it not therefore strange that even if the law courts convict the person, the law prescribes that on the basis of error of judgment, there can be no right of appeal?

Right of appeal is a fundamental right and under Article 134 as has been pointed out by Shri Mulla, even in cases falling under sub-clauses (a) and (b), sub-clause (c) becomes operative and the High courts in India are unanimous, this, even though they are conservatives, in awarding the certificate of leave. Under the rules followed by various high courts, it is a fact that the litigant has to approach the same Bench for a certificate of leave to appeal to the Supreme Court. Is it not humane that the same eminent judge who, according to his own conscience, if he passes a certain judgment, would see the light of the day one day and would say that his judgment was wrong—there was a grave error of law and he did not bring the facts properly.

Even allowing for liberal interpretations that our judges are eminent enough to concede that if there is any error pointed out to them, they are humane enough not to resist stubbornly that they have committed the error. Unless the jurisdiction of the Supreme Court is enlarged, on the basis of the present Bill,

I think that the litigant on the criminal side would stand to lose. They stand to lose some fundamental freedoms which our Constitution has conferred on them.

So, I support Shri Mulla's Bill which seeks to correct the sort of imbalance which is inherent in the present arrangement of articles of the Constitution. Therefore, Sir, while wholeheartedly supporting this Bill, I beg of Shri Mulla to specifically bring forward an amendment at the appropriate time that in cases where a death sentence has been passed, *ipso facto* the right to go in for a certificate for leave to appeal should be given to the person.

With these words, I support this Bill.

**SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) :** Mr. Deputy Speaker, Sir, I heartily welcome and support this Bill moved by Shri Mulla who has been an experienced judge and jurist. No less a person than Shri N. C. Chatterjee himself supported this Bill. All the other hon. Members supported this Bill except Shri Hanumanthaiya, whose speech was a little amusing to me because he has substituted economic argument for a legal proposition. That was the point I took exception to. Only rarely such occasions arise in the High Courts. But even for the rarest occasion we should have provision in the Constitution under criminal jurisprudence. It is time we had a salutary provision in our constitution. The evolution of law takes place only by experience and wherever there is a lacuna it should be corrected. Since this matter had been raised by an experienced jurist who had dealt with such cases, it is welcome heartily. The addition of work to the Supreme Court consequent upon the passing of this Bill could not be a ground for the refusal of this amendment. The late Pandit Nehru had said in this Parliament when referring to the retirement age of Judges of the Supreme Court that the number of 11 Judges fixed for the Supreme Court could be increased when there was more work; there is a Constitutional provision for the appointment

of *ad hoc* judges. Luckily they retire at 65 and some Judges are always available for work after retirement.

Section 417 of the Cr. P. C. was substantially amended in 1955 by Parliament. A complainant has been given the additional right of appeal against acquittal before a High Court. Normally under criminal jurisprudence whether a complaint is filed by a private party or by the Government, the moment conviction takes place and the sentence is given by way of fine or imprisonment, that becomes the responsibility of the Government. But an additional right had been given to the complainant. In non-cognizable petty offences, normally the sentence would not be more than a few days of imprisonment or Rs. 50 fine. Even in such cases this Parliament has considered it proper to amend section 417 in 1955. As a trial court lawyer still practising, not like Mr. Hanumanthaiya who gave up practice long ago, I submit this. In a case I defended the accused was acquitted of the charges under section 302 IPC. But an appeal was filed against him and he was convicted and sentenced by the High Court. No appeal should have been filed in this case and the appeal would have been untenable. Normally where poor people become accused and they are acquitted by the Sessions Court, appeals are filed by the Government. What type of *amicus curiae* is appointed and what type of assistance is given to the High Court we all know; depending upon the pressure of work sometimes, justice is not done. Therefore, as a matter of right there should be appeal to the Supreme Court and the criteria should not be the amount of work. We can add some more judges but we cannot do away with a valuable right of a citizen. I support this Bill and I hope in all fairness the hon. Minister of Law would accept at least the motion for reference to the Select Committee.

**SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) :** Mr. Deputy-Speaker, Sir, Mr. Mulla has made a very convincing case for the Bill. He has also made a very forceful case in favour of the liberties of the persons who are involved. The only note of dissent came from Shri Hanumanthaiya. When

[Shri S. M. Krishna]

he was speaking, even though he was throwing considerable force in the arguments that he advanced, about the cost of litigation in this country which is becoming increasingly high, whereby we are reaching a stage or a situation wherein a man without the proper means cannot get justice, and that would be a dangerous situation if it goes unchecked, in spite of it, I am sure that even Shri Hanumanthiya, if the cost of litigation is reduced and if the accused is not forced to pay so much money to an advocate or a lawyer, would in principle agree with this Bill. After all, what are we conferring upon the accused or anybody in this case? It is yet another chance for him either to get justice or to go scot-free.

The point has been made out by more than one speaker in the debate that some of the present laws are more property-oriented rather than freedom-oriented or liberty-oriented. Even in the face of two concurrent judgments by two courts below, the right of appeal lies to the Supreme Court when the subject-matter is property. But whereas the subject-matter—

SHRI GOVINDA MENON : Under what article, when there is a concurrent judgment?

SHRI S. M. KRISHNA : 133 (a) and (b). Even where there are two decisions then there is a right of appeal,—

SHRI GOVINDA MENON : If the two decisions are concurrent, there is no appeal.

SHRI S. M. KRISHNA : If the amount is Rs. 20,000 or more. In this country we have to treat the liberties of the people as much more precious than even the property rights of the people. The Supreme Court is rather allergic and many of the high courts are rather allergic to grant the special leave certificate and in more than one case it has been said that the Supreme Court has also held that the conditions pre-requisite for the exercise of the discretionary power to grant a certificate under article 134 (1) (c) cannot be precisely formulated but it should be exercised sparingly and

not to convert the Supreme Court into an ordinary court of criminal appeal. I do not see anything wrong if in the ultimate analysis the Supreme Court were to be the ultimate court for criminal appeal in this country.

If the image of the high court has to be maintained or has to be restored, naturally, there should not be any miscarriage of justice also. If there is for some reason some miscarriage of justice, then the image of the high court stands shattered. So, we will have to guard ourselves against this also. So, I see no reason why the hon. Law Minister should be hesitant to look at the whole thing.

SHRI GOVINDA MENON : I only corrected your statement regarding civil appeals.

SHRI S. M. KRISHNA : *de novo*, with an open mind and, therefore, I earnestly appeal to him that he should agree that the whole matter should be entrusted to a small Select Committee which should go thoroughly into every aspect of the matter.

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA (Marmagoa) : Mr. Deputy-Speaker Sir, I shall neither appear at the Bar nor sit on the Bench. My only potential is as a defendant. Please allow me therefore to add the voice of the layman in support of the considerable legal expertise that has been on display in this House today.

Two points have been made repeatedly, logically, and emphatically. The first point is that a difference exists between the State and the individual in the matter of an appeal from judicial decision. This needs correction.

The State may be considered the aggrieved party in a criminal case, but unfortunately the State cannot rot in jail, and the defendant can.

Secondly, Mr. Mulla has said that there is more respect for property than for liberty. This unfortunately is very true in this country. If the principle of this Bill is to help to reverse this,—I am sure it will help—I would like to congratu-

tulate Mr. Mulla for bringing this Bill forward, and knock myself on the head, for not having done it myself.

I support the motion for referring the Bill to a Select Committee, if you allow it. I would say that I would like to see the jurisdiction of the Supreme Court considerably liberalised. For example, clause 2 (b) could say—

“If the High Court has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority...”

I think the jurisdiction of the Supreme Court should include this, because a case may arise where the High Court's decision is the only and the final decision at the same time, and it may not be a fair decision.

Mr. Hanumanthaiya raised the question of our justice being expensive. I agree justice is very expensive and that the expenditure should be reduced, so that the jurisdiction of the Supreme Court is enlarged and people are able to take advantage of it.

With these words, I support the Bill.

श्री जार्ज फरनेन्डो (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस विधेयक का समर्थन मेरे दल के नेता ने किया है मैं भी उसका पूरा समर्थन करता हूँ। इस अवसर पर मैं एक, दो बातों के ऊपर मंत्री महोदय का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

नम्बर 1 यह कि इस सदन में और इस सदन के बाहर एक भ्रष्ट से यह बहस चल रही है कि अदालतों में वर्षों तक मुकद्दमे पड़े रहते हैं और जिनको कि हल करने में काफी समय लगता है। इसके लिए जजों की संख्या बढ़ाने वाली बात इस सदन में कही गई है और बाहर भी कही गई है लेकिन अफसोस होता है इस बात को देखकर कि पिछले कई वर्षों से इसको लेकर बहस तो यहाँ पर चलती रही लेकिन उधर अदालतों में मुकद्दमों भी ऐसे ही बढ़ते गये। अग्नेजी

में जैसे कहावत है : जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वह पुरानी हालत चलती रही। मैं चाहता हूँ आज मंत्री महोदय इस अवसर पर इस प्रश्न के बारे में गम्भीरता से सोचें और तत्काल कोई एक फैसला लेने का काम करें।

दूसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वह जजों की तनखाह के बारे में है। आज सुबह यहाँ पर चीफ जस्टिस श्री बी० पी० सिन्हा के मामले को लेकर प्रश्न उठाया गया जिसमें कि हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस यहाँ से रिटायर होने के बाद श्री हरिदास मूंदड़ा की एक कम्पनी में अफसर बनकर चले गये। अब यह सिर्फ उनकी ही जात का सवाल नहीं है बल्कि यह पूरे इस व्यवसाय को भी शोभा देने वाली चीज नहीं है। आपको मालूम होगा कि बम्बई उच्च न्यायालय के एक जज श्री एच० आर० गोखले ने इस बात को उठाकर बाद में इस्तीफा दे दिया कि उन्हें बतौर जज के जो तनखाह मिलती है वह कम मिलती है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि जजों को यह 3000 या 5000 की तनखाह कम है, वह तर्क मेरा नहीं है, लेकिन इनकमटेक्स के काटने के बाद जिस किस्म का जीवन उनको चलाना होता है उन सारी चीजों को देखकर यह जजों की तनखाह के बारे में सोचा जाना चाहिए। विशेष कर रिटायरमेंट बेंनीफिट के बारे में इस ढंग से सोचना चाहिए कि जजों के रिटायर होने के बाद उन्हें बाद में नौकरी वगैरह खोजने की जरूरत न पड़े।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अदालतों में जो काफी खर्चा होने की बात यहाँ पर माननीय सदस्यों द्वारा आम-तौर पर उठाई गई तो उस और अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं अभी-अभी अदालत से दो वर्ष की परेशानी के बाद बाहर आया हूँ। बम्बई की अदालत में बम्बई की जनता के फैसले को बचाने के

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

लिए मुझे, श्री एस० के० पाटिल ने जो मुकद्दमा दायर किया था, उसके लिए मुझे एक लाख रुपये खर्च करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में मुझे 50,000 रुपये खर्च करने पड़े। अब मुझे जैसे आदमी के लिए जोकि बम्बई की सड़कों पर जाकर लोगों से पैसा मांग सकता है और मेरे जैसे आदमी के लिए वकील लोग भी अपना समय देने को तैयार हो जाया करते हैं मुझे जब काफी परेशानी का सामना करना पड़ा तो सामान्य आदमी की तो बात ही क्या है? सामान्य आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है लेकिन बिलफर्ज भ्रगर वह ऐसे पूंजीपतियों के जो दलाल हैं उनके मुकाबले में जीत भी जाय तो उनके द्वारा उसे अदालत में ले जाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद करने और परेशान करने का काम किया जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि यह जो खर्च वाला मामला है इस पर नये ढंग से सोचा जाय।

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : Sir, I have to admit at the very outset that there is a very good deal of weight principle in the amendment brought by Shri Mulla. When I interrupted him once or twice it was thought that I am going to say that there is nothing good in what he has brought. That was not my intention in interrupting. For example, one hon. friend said with respect to appeal in civil matters that even when two courts have concurred there is an appeal to the Supreme Court where the subject matter is Rs. 20,000 or more. I interrupted only to say that is not the correct position. That is all that I wanted to do.

I will put Shri Mulla's case—I cannot do it better than he has done—this way. He referred to Section 417 of the Criminal Procedure Code I think for this purpose. Suppose there is a sessions case, say, for a capital offence—murder and the accused is acquitted by the sessions court, then it is open under Section 417 of the Code of Criminal Procedure—not under an amendment made in 1955 as pointed by

Shri Reddy because it was there all along.....

SHRI M. N. REDDY : I pointed out only in the case of the complainant, a private person.

SHRI GOVINDA MENON : There is a provision in the Code under which the State may go in appeal to the High Court from the order of acquittal by the Sessions Judge, and hon. friend Shri Viswanatham reached the crux of the matter when he said that in every matter, in every criminal matter the State is presumed to be the complainant and if there is aberration of justice or failure of justice in a case of acquittal the State is given a residuary power to appeal to the Supreme Court under Section 417. That is what Shri Viswanatham rightly pointed out. It may be there are occasional abuse of the power vested with the State in filing appeal. As a result of an appeal under Section 417 if in a case of acquittal by the Sessions Court in a murder case the High Court convicts him, say, for imprisonment for life, under the Constitution as it is, there is no right of appeal to the Supreme Court. In a case like that the accused has to take recourse to two provisions, either under article 134 (c) seek a certificate from the High Court and, if that is not available go to the Supreme Court under article 136. It may be in many cases they may get justice. But should there not be a right of appeal in a case where the accused is sentenced for life by the High Court in reversal of an acquittal order by the Sessions Court when right of appeal is there? If the High Court had cared to pass a sentence of death on the accused then there is a right of appeal. If anybody had said that the Supreme Court is not a court of criminal appeal, whether it be the Law Commission or anybody I would not have agreed with them. The Supreme Court is also a court of criminal appeal because in cases falling under article 133 where there is a reversal etc., there is a right of appeal and the Supreme Court is exercising powers as a court of criminal appeal. In other cases they make a special leave to appeal and that.

Shri Mulla's amendment would come to this. Where there is a right of appeal today, when the High Court as an original court after withdrawing from the Sessions Court or in appeal, for the first time gives a sentence of ten years or more, should there not also be a right of appeal? That is the question raised by him. I think there is considerable weight in what he has said. What I objected to was regarding the interpretation of section 417 Cr. P. C. which provides for an appeal to the High Court. There no distinction is made between a State and an individual. Because, the State is supposed to look into the matter and where in the opinion of the State an offence has been committed against the community and there has been acquittal which was wrong, there should be an appeal to the High Court.

18 hrs.

But I would request Shri Mulla and other members of this House to remember this. I see that all sections of the House have supported this Bill. What vested interest have I in this matter? Government have no vested interest in this matter. All the same, I wish to tell him that the present Law Commission has been requested by me to completely amend the existing Code of Criminal Procedure. I had a talk with the Chairman two days back and he was telling me that the report would be in my hands in the next few days. This is a matter which can fall under the amendment of the Code of Criminal Procedure, because under article 138 the Code of Criminal Procedure will be a parliamentary legislation. Article 138 says that other jurisdiction can be conferred on the Supreme Court than what is contained in articles 132 and 133. If the hon. Members think that they can wait till I introduce a new Code of Criminal Procedure in amendment of the existing Code of Criminal Procedure, if the House thinks so—I would put it that way—I would request him not to press it now. But if the House thinks that it is important enough meriting immediate consideration, I would not stand in the way of the matter being referred to the Select Committee. That is my position.

SHRI RANDHIR SINGH : Sir, under rule 388 I beg to move :

“That rule 75 (2) (a) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires the moving of the amendment that the Enlargement of the Appellate (Criminal) Jurisdiction of the Supreme Court Bill, 1968 by Shri Anand Narain Mulla be referred to a Select Committee at an earlier stage, be suspended.”

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That rule 75 (2) (a) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires the moving of the amendment that the Enlargement of the Appellate (Criminal) Jurisdiction of the Supreme Court Bill, 1968 by Shri Anand Narain Mulla be referred to a Select Committee at an earlier stage, be suspended.”

• *The motion was adopted.*

SHRI RANDHIR SINGH : I beg to move :

“That the Bill to enlarge the appellate jurisdiction of the Supreme Court in regard to criminal matters by Shri Anand Narain Mulla, be referred to a Select Committee consisting of 22 members, namely, Shri N. C. Chatterjee, Shri Krishna Kumar Chatterjee, Shri C. C. Desai, Shri Shivajirao S. Deshmukh, Shri Shri-Chand Goyal, Shri K. Hanumanthaiya, Shri S. M. Jhoshi, Shri S. M. Krishna, Shri Krishnan Manoharan, Shri Vikram Chand Mahajan, Shri Bhola Nath Master, Shri P. Govinda Menon, Shri Bakar Ali Mirza, Shri H. N. Mukarjee, Shrimati Sharda Mukerjee, Shri Anand Narain Mulla, Shri K. Ananda Nambiar, Shri Mrityunjay Prasad, Shri K. Narayana Rao, Shri Sheo Narain, Shri Tenneti Viswanatham, and Chaudhuri Randhir Singh, with instructions to report by the first day of next session.”



**SHRI SONAVANE (Pandharpur) :** On a point of order, Sir. I would like to know whether the hon. Mover of the motion for reference of the Bill to the Select Committee has obtained the consent of Members who are included in this. Under the rule their consent is necessary.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** Will the hon. Member resume his seat ? I am myself going to ask that question. I presume that he has obtained the consent of all the Members concerned.

**SHRI RANDHIR SINGH :** The names are included with the consent of the different party leaders and of the Minister of Parliamentary Affairs.

**SHRI SONAVANE :** Individual consent is necessary.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** That is all right. I shall now put the motion to the vote of the House.

The question is :

"That the Bill to enlarge the appellate jurisdiction of the Supreme Court in regard to criminal matters by Shri Anand Narayan Mulla, be referred to a Select Committee consisting of 22 members, namely, Shri N. C. Chatterjee, Shri Krishna Kumar Chatterjee, Shri C. C. Desai, Shri Shivajirao S. Deshmukh, Shri Shri Chand Goyal, Shri K. Hanumanthaiya, Shri S. M. Joshi, Shri S. M. Krishna, Shri Krishnan Manoharan, Shri Vikram Chand Mahajan, Shri Bhola Nath Master, Shri P. Govinda Menon, Shri Bakar Ali Mirza, Shri H. N. Mukerjee, Shrimati Sharda Mukerjee, Shri Anand Narain Mulla, Shri K. Ananda Nambiar, Shri Mrityunjay Prasad, Shri K. Narayana Rao, Shri Sheo Narain, Shri Tennetti Viswanatham, and Chaudhuri Randhir Singh, with instructions to report by the first day of next session."

*The motion was adopted.*

18.07 ½ hrs.

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 75, 164 etc.)

**श्री कामेश्वर सिंह (खगरिया) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में संविधान की धारा 75, 164, 336 के संशोधनों के लिए प्रस्ताव पेश करता हूँ। मैं कुछ कहने के पहले इसमें से कुछ अंश को पढ़ूंगा। हमारे बिल के मुताबिक :

"In articles 75 of the Constitution, in clause (1), for the words "The Prime Minister shall be appointed" the words "The Prime Minister, who shall be an elected member of the House of the people, shall be appointed" shall be substituted."

दूसरा है इसमें धारा 164 में संशोधन :

"In article 164 of the Constitution in clause (1), for the words "The Chief Minister shall be appointed" the words "The Chief Minister, who shall be an elected member of the Legislative Assembly, shall be appointed" shall be substituted."

18.08 ½ hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

और तीसरा जो मैंने संशोधन पेश किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है देश में जो स्थिति जा रही है उस को देखते हुए। मैं वह भी पढ़ कर सुनाता हूँ :

"In article 326 of the constitution. for the word "twenty-one", the word "eighteen" shall be substituted."

चेयरमैन साहब ! अपने बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में मैंने इसको साफ कर दिया है। वह भी मैं पढ़ कर सुना देता हूँ :

"It is highly undemocratic that persons not directly elected by the suffrage of the people should head the

popular Governments in the country. Therefore the Prime minister and Chief Ministers should always be elected Members of the lower Houses."

दूसरा अंग है :

"Discontentment prevails among youth in the country that they are not entitled to vote in the elections to the House of the people and to the Legislative Assemblies of State before 21 years of age, Reduction in the age of adult suffrage from 21 years to 18 years will inculcate the spirit of discipline and responsibility among them."

मैं इस संशोधन में पहले धारा 75 और 164 को लेता हूँ। मैं सदन का ध्यान संविधान के आर्टिकल 164 और 175 की ओर खींचना चाहता हूँ। धारा 75 है केन्द्र के लिए और 164 है राज्यों के लिए। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, अभी तक जो भी हमारे प्रधान मंत्री हुए हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रधान मंत्री तो नहीं हुए हैं परन्तु इन्दिरा जी भी जो इस सदन में प्रधान मंत्री बनी पहली बार, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, परन्तु एक कट्टर सत्य है, उसे कहना ही पड़ता है। उनको भी अपर हाउस की यानी राज्य सभा की शरण लेनी पड़ी। आज बहुत जरूरत है कि हम देश के अन्दर स्वास्थ्यकर परिपाटी चलायें, लेकिन हमारे ये जितने कांग्रेसी मित्र बैठे हुए हैं, इनकी कभी भी ऐसी नीति नहीं रही है कि ये या इनकी सरकार स्वयं ऐसे विधेयक लाए जिस से स्वास्थ्यकर और हितकारी परिपाटी इस देश में चल सके।

सभापति महोदय, हमारा देश संसार में सब से बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। दुनिया भर की निगाह हिन्दुस्तान पर जमी रहती है कि वहाँ पर जनतन्त्र में क्या होता है। जब यहाँ पर इलैक्शन होते हैं, दुनिया हमारी ओर देखती है कि यहाँ पर किस तरह से इलैक्शन होते हैं। बाहर से लोग

हमारे इलैक्शन देखने आते हैं। लेकिन इलैक्शन के बाद क्या होता है—जो सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। ऐसा राज्यों में ही नहीं केन्द्र में भी हो चुका है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। ऐसी स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी सरकार इस विधेयक को क्यों नहीं मान लेती। जहाँ तक डिफेक्शन कमेटी का सवाल है, उस कमेटी ने भी यही सिफारिश की है कि मुख्य मंत्री विधान सभा का सदस्य और प्रधान मंत्री लोक सभा का सदस्य होना चाहिए। ...

श्री हुकमचन्द कछवाय (उज्जैन) : सभी मंत्री चुन कर आने चाहिए।

श्री कामेश्वर सिंह : इस कमेटी में सभी पार्टियों के सदस्य थे, इसलिए सभी पार्टियों की रजाबन्दी के बाद भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव के बाद अभी जिस नई मिनिस्ट्री का गठन हुआ है, उस में भी एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। उनकी पार्टी के संसद सदस्य जब यहाँ बैठकर डिफेक्शन कमेटी में तय करते हैं कि हर मंत्री को सदस्य होना चाहिए, लेकिन जब दो-तीन महीने के बाद इलैक्शन हुआ तो वे भूल गए। इसलिए आवश्यक है कि इस किस्म की चीजों को रोकने के लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए और अविलम्ब होना चाहिये।

जहाँ तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है, जिस समय हमारी कांस्टीच्यूएंट असेम्बली के सदस्य संविधान को बना रहे थे, तो हर बात के लिए वे लोग ब्रिटेन के संविधान की ओर देखते थे। यहाँ तक कि इस समय भी संविधान की बहुत सी बातों के लिए रोज-मर्रा जो उदाहरण हम देते हैं, न केवल इस ओर के सदस्य, बल्कि कांग्रेसी सदस्य भी,

[श्री कामेश्वर सिंह]

मेज-पार्लियामेन्टी प्रेक्टिस को कोट करते हैं। आखिर वह क्या है? हर दिन ब्रिटेन का उदाहरण देते हैं, हाउस आफ कामन्स का उदाहरण देते हैं, लेकिन उसमें भी जो अच्छी बातें हैं उसके लिए आप कभी भी किसी से सहमत नहीं होते हैं—हाउस आफ कामन्स तो बहुत दूर की बात है।

1902 में लाड सैलिसवरी के त्याग-पत्र के बाद दूसरा कोई भी व्यक्ति जो कि हाउस आफ लाड का सदस्य रहा हो, इंग्लैंड का प्रधान मन्त्री नहीं हुआ। 1923 में जब इस बात की जरूरत पड़ी तो यह कानून ही बन गया। जब सर अलेक डगलस ह्यूम प्रधान मंत्री बने तो वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसी समय मैकमिलन साहब ने कहा था :

Humes does not belong to any House. 'Humes' is homeless.

हाउस आफ कामन्स की ऐसी परिपाटी थी और जबकि हम हर दिन हर बात में वहाँ के उदाहरण इस सदन में देते हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि उस परिपाटी को वहाँ पर मानने में क्या आपत्ति है। हाउस आफ कामन्स के सदस्यों ने उस समय के बाद बहुत आगे तक जो परिपाटी चलाई उसका अनुकरण कॅनेडियन पार्लैमेंट में भी हुआ। डिफेन्स कमेटी की जो रिक्मेंडेशंस हैं उसमें भी है कि हर मन्त्री को सदस्य होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो कुछ और ही बात है। वहाँ पर जितने मंत्री किसी डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं सभी को हाउस आफ कामन्स का सदस्य होना है। जो मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो होते हैं वह अपर हाउस के भी सदस्य हो सकते हैं। कॅनेडा के अलावा न्यूजीलैंड में और भी ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर एक ही सदन है। हमारे कुछ साथी कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड तो बहुत छोटा मुल्क है लेकिन इसमें छोटे या बड़े मुल्क का सवाल नहीं है। सवाल यह है निकालना बड़ा आसान रहता है, मैं भी दूसरों

की सौ गलतियाँ कि जो अच्छी परिपाटी हो, जो भी बातें हमारे देश के लिए अच्छी हों, कोई छोटा देश भी यदि उन बातों को कर रहा हो तो भी उन बातों का अनुसरण करने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बराबर हमारे देश में डिग्नेटरीज आते हैं लेकिन हमारे मंत्रियों के दिमाग में कभी यह बात नहीं आती कि ये कैसे लोग हैं। मैं जर्मनी का उदाहरण आपके सामने दे सकता हूँ। वहाँ भी जो चांसलर होता है वह बुइसटाट का मेम्बर होता है। ऐसे बहुत से देश हैं, जहाँ भी जनतंत्र है वहाँ पर लोगों ने सोचा है और तभी वे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आयरलैंड में भी यही परिपाटी है। निचले सदन के सदस्य ही प्राइम मिनिस्टर और इक्विवलेंट पोस्ट्स पर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जबसे हमारा संविधान बना, 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ लेकिन अभी तक लोगों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे साथियों ने सोचा होगा कि कुछ ऐसा हिसाब-किताब बनाकर रखा जाये कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य न भी हो फिर भी उसको प्रधान मन्त्री बनने का मौका मिल सके। खैर मंत्री बनना तो छोड़िए, अभी तक इस बारे में कोई भी संविधान का संशोधन नहीं आया है और मुझे पता नहीं कि अब इस विधेयक को पेश करने के बाद भी जबकि इस पर बहस जारी है, सरकार का क्या रुख होगा। लेकिन मैं फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि ये लोग प्रगतिशील विधेयक नहीं लायेंगे इस सदन में तो देश में हाहाकार मच जायेगा जोकि अब मचना शुरू भी हो गया है और फिर स्थिति इनके हाथ से बाहर चली जायेगी। यह तो केन्द्र के बारे में बात हुई बाद में इस सम्बन्ध में और भी कहूँगा।

जहाँ तक राज्यों का सवाल है, वहाँ हालत और भी खराब है। वहाँ पर तो मनमाना काम होता है। दूसरों की गलतियाँ निकालना बड़ा आसान रहता है, मैं भी दूसरों की सौ गलतियाँ

बता सकता हूँ। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता था कि मद्रास में श्री राज गोपालाचारी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जब कि उनको राज्यपाल ने विधान परिषद् में मनोनीति किया, आज वह स्वतंत्र पार्टी के बड़े नेता हैं, और माननीय श्री प्रकाशजी ने उनको शपथ दिलायी। क्या यह अच्छा काम किया? मैं समझता हूँ कि श्री प्रकाशजी में यदि हिम्मत होती और भारतीय संविधान में आस्था होती तो वह कभी भी राजा जी को शपथ दिलवाना मन्जूर नहीं करते। परन्तु मुझे आज तक कोई भी ऐसा राज्यपाल देखने में नहीं आया है जिसने हिम्मत के साथ यह कहा हो कि मैं ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री के लिए शपथ ग्रहण नहीं करवाऊंगा जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। आखिर परिषदी तो चलायी कांग्रेस ने मद्रास से। बम्बई में भी कुछ ऐसी घटनायें हुईं और मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ये घटनायें जब एक बार शुरू हो जाती हैं तो उनका रिपेक्शन कभी रुकता नहीं है।

**श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) :** मोरारजी देसाई बुलसर में चुनाव हारे और तत्काल उनको मंत्रि मंडल में ले लिया गया।

**SHRI ERASMODO SEQUEIRA (Masmagoa) :** I have to make a request. I have a motion for reference to the Select committee. Before you pass on to the next item, I want just to speak for a minute.

**MR. CHAIRMAN :** It would not be completed to-day. You can speak next time.

**श्री कामेश्वर सिंह :** मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन चूँकि मोरारजी भाई का नाम माननीय जार्ज फरनेन्डीज ने ले लिया तो मुझे कहना जरूरी हो गया कि एक बार बम्बई के मुख्य मंत्री बनकर संविधान का अपमान किया और जिसके लिए अभी तक

उन्होंने माफी नहीं माँगी है। आप कहेंगे कि संविधान का अपमान उन्होंने किस तरह से किया? संविधान के अनुच्छेद 164 (2) में यह साफ है कि :

“The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.”

अब आप ही बताइये कि जब साफ लिखा हुआ है कि काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिल होंगे स्टेट की लेजी-स्लेटिव असेम्बली को तब ऐसा व्यक्ति मुख्य मंत्री बने जो कि जिम्मेवार हो लोअर हाउस के प्रति और वह किसी सदन का सदस्य भी न हो, तब बताइए कि क्या यह संविधान का अपमान नहीं है?

**MR. CHAIRMAN :** Does the Constitution provide for that?

**SHRI KAMESHWAR SINGH :** Yes, Sir.

आईन है क्या आपके लिये। मोरारजी भाई ने अभी तक माफी नहीं माँगी।

दूसरा डर मुझे यह है कि एक बार बम्बई के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और अभी तक माफी नहीं माँगी और 1972 में जब लोक सभा का चुनाव हारेंगे तो उनकी इसी तरह से बैंक डोर से, चोर दरवाजे से प्रधान मंत्री बनाने का प्रयास किया जायेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि संविधान में संशोधन बहुत ही आवश्यक है।

जब बड़े नेता यह काम कर बैठते हैं तो फिर जो छोटे लोग, आम लोग हैं वह ऐसा करने में क्यों झिझकेंगे?

मैं अब बिहार के ऊपर आता हूँ। 1967 में चुनावों के बाद जब वहाँ संविद की सरकार बनी, हम लोगों की सरकार बनी तो उसके बाद कांग्रेसियों के दिल में डर पैदा हुआ। जब हम लोगों ने कहना शुरू किया कि यह घूसखोरी है, इन्होंने सरकार का पैसा

[श्री कामेश्वर सिंह]

खाया है, जनता का पैसा खाया है और जब जांच कमीशन की बात होने लगी तो पैसा देकर सरकार को गिराया गया जिसका कि अभी तक चैक मौजूद है। उसके बाद मुख्य मंत्री कौन बना ? श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल, सदस्य लोक सभा। आखिर यह मुख्य मंत्री कैसे बने ? उनके मुख्य मंत्री बनने का सबसे बड़ा आधार हमारे श्री प्रकाश जैसे दूसरे राज्यपाल का था। कम-से-कम श्री कानूनगो को सोचना चाहिए था कि श्री श्री प्रकाश ने जो एक गलती की हमको वह गलती नहीं करनी चाहिए। कम-से-कम श्री कानूनगो को कहना चाहिए था कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ परन्तु गृह-मंत्री श्री चव्हाण के दबाव के कारण उन्होंने विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल को शपथ ग्रहण करवायी। शपथ ग्रहण करवाने के बाद आखिर उनका नाम कैसे आया ? उन्होंने मनोनीत किया। उनका आखिर नाम कैसे आया ? कारण कोई मुख्य मंत्री ऐसा होना चाहिए जो विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल की मुठ्ठी का आदमी हो, उनके कब्जे का आदमी हो। उसके लिए 72 घंटे के लिए एक मुख्य मंत्री को शपथ ग्रहण करवायी गयी। उस 72 घंटे में उस मुख्य मंत्री ने क्या-क्या काम किया ? आज तक जो भी मुख्य मंत्री होते रहे हैं सब कोई जनहित के लिए होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं परन्तु जन-तंत्र के इतिहास में बिहार में एक इस तरह से मुख्य मंत्री बनाया गया जोकि संबंधा भ्रवांछनीय था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे कोई ऐसा मुख्य मंत्री नहीं होगा। जैसा मैंने कहा वहाँ ऐसा मुख्य मंत्री हुआ और सिर्फ इसलिए कि वह विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल के नाम की राज्यपाल के पास सिफारिश करे और बाद में राज्यपाल उसे कबूल करे। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल की चर्चा इस सदन

में काफी हो चुकी है और हमारे साथी श्री नाथपाई ने भी इस सदन में वह बहस उठाई थी और मैंने सोचा कि शायद लोगों का दिमाग काफ़ी साफ हो गया होगा परन्तु मुझे यह देखकर अफसोस हुआ कि बैसा नहीं हो पम्मा है। पिछली फरवरी में जो मध्यावधि चुनाव हुए हैं उसके अनुसार बंगाल की क्या स्थिति है ? श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, को मंत्री बनाया गया। मैं किसी पार्टी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ कि वह किस पार्टी की हैं लेकिन हमारे साथी लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि यह अन्याय है, यह देश के संविधान के साथ और जनता के साथ अन्याय है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो उस पार्टी के सदस्य डिफेन्संस कमेटी में थे क्या उन लोगों ने अपने राज्यपाल को इस बात का ख्याल नहीं दिलवाया ? हकीकत यह है कि जहाँ अपने फायदा का सवाल उठता है तो वहाँ सब कोई भूल जाते हैं। चाहे किसी पार्लियामेंटरी कमेटी में कोई स्टैंड रहा हो अगर कुछ फायदा होता है उलटा काम करने से या संविधान को जला देने से तो हम लोग जलाने के लिए तैयार हो जाया करते हैं और वह इसलिए है कि पहले हम लोग किसी पार्टी के व्यक्ति हैं और तब उसके बाद हम हिन्दुस्तानी हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे कम्युनिस्ट भाई यहाँ पर बड़ी-बड़ी बात कहते हैं, बड़ी-बड़ी दलीलें देते हैं परन्तु उनको यह कबूल नहीं है कि वह राष्ट्रहित में कोई भी काम कर सकें। अगर उनमें थोड़ी सी भी राष्ट्रीय भावना होती तो वे जनहित और संविधान के लिए थोड़ी भी कद्र कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के हृदय में तो वह आज ही पश्चिम बंगाल के अपने पार्टी के नेताओं को यह आदेश दे कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अविजम्ब इस्तीफा दे।

MR. CHAIRMAN : The Hon. Member will continue his speech on the next non-official day for Bills.

18.3 ¼ hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION  
PER CAPITA AVAILABILITY OF  
POWER IN BIHAR

MR. CHAIRMAN : I will now take up Half-an-Hour Discussion. Shri Bhogendra Jha who is to raise the discussion is

not present in the House. I, therefore, adjourn the House to meet at 11 A. M. on Monday.

18.31 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 21, 1969/Vaisakha 1, 1891 (Saka).*

---